रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128

REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

HBL 25/7/89

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 29, 1989/ वैशाख 9, 1911

No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 29, 1989/VAISAKHA 9, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1989

का. आ. 829.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ) के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को जिनके कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है।

[सं. 12022/80/87--रा. भा. (ख-2)]
वी. अ. कोहली, उप सचिव (कार्यान्वयन)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Department of Official Language)

New Delhi, the 16th February, 1989

S.O. 829.—In pursuance of sub-rule (4) of the rule 10 of the (Official Language Purpose of the Union) Rule 1976, the Central Government hereby notifies the Ministry of Programme Implementation, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi.

[No. 12022/80/87-OL(B-II)]
V. A. KOHLI, Dy. Secy. (Imp)

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1989

आयकर

का. आ. 830.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में तथा भारत सरकार, राजस्व विभाग के दिनांक 4-2-1985 की अधिसूचना संख्या 6131 (फा. सं. 398/36/84—आ. कर (ब.) के अतिक्रमण में/आंशिक संशोधन में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री जी. एस. पटवर्धन को, केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम के अन्तर्गत श्री आर. ए. वैशंपायन के स्थान पर कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 28-9-88 से प्रभावी होगी, जिस तारीख को श्री जी. एस. पटवर्धन ने कर वसूली अधिकारी के पद का कार्य-भार ग्रहण किया था।

[संख्या 8168/फा. सं. 398/9/88-आयकर (ब.)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 30th January, 1989

INCOME-TAX

S.O. 830.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession|partial midification of Notification if the Givernment of India in the Department of Revenue No. 6131 [F. No. 398/36/84-IT(B)] dated 4-2-85, the Central Government hereby authorises Shri G. S. Patwardhan, being a Gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act in place of Shri R A. Vaishampayan.

2. This Notification shall come into force with effect from 28-9-88 the date on which Shri G. S. Patwardhan took over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 8168/F. No. 398/9/88-IT(B)]

आयकर

का. आ. 831.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में नीचे स्तम्भ 2 में उल्लिखित व्यक्तियों को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी है, एतद्द्वारा केन्द्रीय सरकार के कार्योत्तर प्राधिकरण की सूचना दी जाती है जिसके तहत वे नीचे स्तम्भ 3 में उल्लिखित अलग-अलग तारीखों से उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर-वसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

क्रम सं.	उन व्यक्तियों के नाम जो कर वसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।	वह तारीख जिस तारीख से स्तम्भ 2 में उल्लिखित व्यक्तियों ने कर उसूली अधिकारियों के पद का कार्यभार संभाला।
1	2	3
1.	श्री पी. जी. वागल	21-1-88
2.	श्री एन. ए. थाले	28-1-88
3.	श्री बी. बी. पराब	—यथोक्त—
4.	श्री सी. बी. हिरे	—यथोक्त—
5.	श्री ई. पी. पाटिल	25-1-88
6.	श्री बी. एन. वाकोडे	—यथोक्त—
7.	श्री ए. के. पटेल	26-7-88

[सं. 8170/फा. सं. 398/9/88-आयकर (ब.)]

INCOME-TAX

S.O. 831.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), Ex-post-facto authorisation of the Central Government is hereby conveyed to the persons mentioned below in column 2 being a Gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act for the dates mentioned against each below in column 3.

S. No.	Name of the persons who exercises the powers of T.R.Os.	The dates from which the persons mentioned in Col. 2 have assumed charge as T.R.Os.
1	2	3
1.	Shri P.G. Wagal	21-1-88
2.	Shri N.A. Thale	28-1-88
3.	Shri B.B. Parab	-do-
4.	Shri C.B. Hire	-do-
5.	Shri E.P. Patil	25-1-88
6.	Shri B.N. Wakode	-do-
7.	Shri A.K. Patel	26-7-88

[No. 8170/F. No. 398/9/88-IT(B)]

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1989

(आयकर)

का. आ. 832.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) के अनुसरण में नीचे स्तंभ 2 में उल्लिखित व्यक्तियों, को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी है, एतद्द्वारा केन्द्रीय सरकार के कार्योत्तर प्राधिकरण की सूचना दी जाती है जिसके तहत वे नीचे स्तंभ (3) में प्रत्येक व्यक्ति के नाम के सामने विनिर्दिष्ट तारीखों से उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर-वसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

क. सं.	उन व्यक्तियों के नाम जो कर वसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।	वह तारीख जिससे स्तंभ 2 में उल्लिखित व्यक्तियों ने कर-वसूली अधिकारियों के पद का कार्यभार संभाला।
1	2	3
1.	श्रीमती चन्द्रा राम कृष्णन	28-11-1988
2.	श्री ए. के. गुप्ता	2-11-1988
3.	श्री वी. जे. भगत	2-11-1988
4.	श्री आर. बी. शिकर	7-11-1988

[सं. 8235/फा. सं. 398/9/88-आ. कर (बजट)]

बी. ई. एलेक्जेंडर, अवर सचिव

New Delhi, the 13th March, 1989

INCOME-TAX

S.O. 832.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) Ex-post-facto authorisation of the Central Government is hereby conveyed to the persons mentioned below in column 2 being a Gazetted Officer of the Central Government

to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act from the dates mentioned against each below in column 3:

SCHEDULE

S. No.	Name of the persons who exercises the powers of T.R.O.s.	The dates from which the persons mentioned in Col. 2 have assumed charge as T.R.Os.
1	2	3
1.	Smt. Chandra Ramkrishnan	28-11-1988
2.	Shri A.K. Gupta	2-11-1988
2.	Shri V.J. Bhagat	-do-
4.	Shri R.B. Shinkar	7-11-1988

[No. 8235 (F. No. 398/9/88—IT(B))]

B. E. ALEXANDER Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1989

स्टाम्प

का. आ. 833.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो की हाउसिंग एंड अर्बन डिवलेपमेंट कारपोरेशन लि., नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले मात्र अठारह करोड़ रु. के मूल्य के "11.5% ऋणपत्र—2008 XXXIII श्रृंखला" के रूप में यथा विनिर्दिष्ट ऋणपत्रों के स्वरूप के बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है।

[संख्या 13/89-स्टाम्प—फा. सं. 33/26/89—वि. क.]

एन. पी. रुस्तगी, उप सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th March, 1989

STAMPS

S.O. 833.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of debentures described as "11 5 percent Debentures—2008 XXXIII Series" to the value of rupees eighteen crores to be issued by the Housing and Urban Development Corporation Limited, New Delhi, are chargeable under the said Act.

[No. 13|89-Stamps—F. No. 33|26|89-ST]

N. P. RUSTGI, Dy. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1989

स्टाम्प

का. आ. 834.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय रेलवे वित्त निगम द्वारा (प्रत्येक) 1000 रु. के मात्र छः सौ करोड़ रु. मूल्य के 9 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्रों (तृतीय श्रृंखलों) के रूप में उल्लिखित ऋणपत्रों के रूप में जारी किए जाने वाले बंध पत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य शुल्क को माफ करती है।

[सं. 12/89 स्टाम्प—फा. सं. 33/88/88-वि. क.]

बी. आर. मेहमी, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th March, 1989

STAMPS

S.O. 834.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of debentures described as 9 per cent tax free Bonds of Rs. 1000 each (third series) of the value of rupees six hundered crore only to be issued by Indian Railway Finance Corporation are chargeable under the said Act.

[No. 12|89—Stamps—F. No. 33|88|88-ST.]

B. R. MEHMI, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1989

का. आ. 835.—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (बैंककारी, सरकारी वित्तीय संस्थाएं और परक्राम्य लिखित विधि (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का 66) द्वारा यथा संशोधित) की धारा 6 की उपधारा 4क के उपबंधों के आधार पर निम्नलिखित व्यक्ति 15 मार्च, 1989 से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बोर्ड में निदेशक के पद पर नहीं रहेंगे:

1. श्री एच. एस. सिंघानिया, अध्यक्ष, जे. के. आर्गेनाइजेशन, "नेहरू हाउस", 4, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
2. श्री सुरेन्द्र पाल, अध्यक्ष, ए पी जे सुरेन्द्र ग्रुप, प्रगति भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली।

[सं. एफ. 7/1/87—बी. ओ. 1]

(Department of Economic Affairs)

(Banking Divison)

New Delhi, the 10th March, 1989

S.O. 835.—By virtue of the provisions if sub-section 4A if Section 6 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (as amended by the Banking Public Financial Institutions and Negotiable Instruments Laws (Amendment) Act, 1988) (66 of 1988) the following shall cease to hold the office of Director on the Board of Industrial Development Bank of India with effect from 15-3-1989 :

1. Shri H. S. Singhania, President, J.K Organisation, 'Nehru House', 4, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi
2. Shri Surrendra Paul, Chairman, Apeejay Surrendra Group, Pragati Bhavan, Jai Singh Road, New Delhi.

[Ni. F. 7|1|87-B.O. I]

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1989

का. आ. 836.—निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारन्टी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47) की धारा 6 की उपधारा (1 के खण्ड (घ) के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारती

रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करने के पश्चात् एतद्द्वारा श्री बी. डी. शाह, प्रबन्ध निदेशक, भारतीय साधारण बीमा निगम को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और 14 दिसम्बर, 1991 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के निदेशक के रूप में नामित करती है।

[संख्या एफ. 7/1/88-बी. ओ.-1]

New Delhi, the 31st March, 1989

S.O. 836.—In pursuance of the provisions of clause (d) of sub-section (1) of Section 6 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby nominates Shri B. D. Shah, Managing Director General Insurance Corporation of India as a Director of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation for a period beginning with the date of issue of the notification and ending with 14th April, 1991.

[No. F. 7/1/88-B O. I]

का. आ. 837.—राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (बैंककारी, लोक वित्तीय संस्था और पराक्राम्य लिखित विधि (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का 66) द्वारा यथासंशोधित) की धारा 7 की उपधारा 2 के उपबन्धों के अनुसार, डा. जे. सी. राउत सहकारी एवं कृषक, ग्राम व डाकघर-बांकी, जिला कटक, उड़ीसा तत्काल राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के बोर्ड में निदेशक के पद पर नहीं रहेंगे।

[संख्या एफ. 9/67/88-बी. ओ-1]
एम. एस. सीतारामन, अवर सचिव

S.O. 837.—By virtue of the provisions of sub-section 2 of section 7 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (as amended by the Banking, Public Financial Institutions and Negotiable Instruments Laws (Amendment) Act, 1988) (66 of 1988) Dr. J. C. Rout, Co-operator and Farmer, at P.O. Banki, District, Cuttack, Orissa shall cease to hold the office of Director on the Board of National Bank for Agriculture and Rural Development with immediate effect.

[No. F. 9/67/88-BO. I]
M. S. SEETHARAMAN, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1989

का. आ. 838.—औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) की धारा 23 के खण्ड (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विकास बैंक की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को निम्नलिखित कारोबार अर्थात् भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, के दिनांक 12 अप्रैल 1988 के संकल्प संख्या 1/44/एसई/86 द्वारा वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), भारत सरकार द्वारा गठित एक प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड को समय-समय पर ऐसी सहायता, जैसा निगम उचित समझे, प्रदान करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. 10(66)/आई एफ-1/88]

ORDER

New Delhi, the 28th March, 1989

S.O. 838.—In exercise of the powers conferred by clause (o) of section 23 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948), the Central Government, on the recommendation of the Development Bank, hereby authorises the Industrial Finance Corporation of India to do the following kind of business, namely, the grant of such assistance from time to time a the Corporation may deem fit, to the Securities and Exchange Board of India, an authority constituted by the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) by Resolution Number 1/44/SE/86 dated the 12th April, 1988 of the Ministry of Finance, Government of India.

[F. No. 10(66)/IF.I/88]

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1989

का. आ. 839.—केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 17 (4खख) (ख) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेने के प्रयोजन के लिये भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लिमिटेड द्वारा जारी किए जाने वाले 34.00 करोड़ रुपए के मूल्य के बांडों के सम्बन्ध में मूलधन की वापसी अदायगी और 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) वार्षिक के हिसाब से ब्याज की अदायगी की गारंटी लेती है लेकिन यह गारंटी बांड जारी करने की तारीख से 24 महीने तक की अवधि के लिये प्रभावी रहेगी।

[एफ. संख्या 3 (9)/आईएफ आई/89]
एच. एस. कुमार, उप सचिव

New Delhi, the 31st March, 1989

S.O. 839.—The Central Government hereby guarantee the repayment of the principal and payment of interest at the rate of 10 per cent (ten per cent) per annum in respect of bonds of the value of Rs. 34 crores to be issued by the Industrial Credit and Investment Corporation of India Limited, for the purpose of borrowing from Reserve Bank of India in terms of Section 17(4BB) (b) of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) provided that the Guarantee wil remain in force for a period of 24 months from the date of issue of the bonds.

[F. No. 3(9)/IFI/89]
H. S. KUMAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1989

का. आ. 840.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित चार्टर्ड लेखाकारों की फर्मों को वर्ष 1988-89 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा परीक्षक नियुक्त करती है, अर्थात्:—

1. मैसर्स खन्ना एण्ड अन्नाधानम, चार्टर्ड लेखाकार,
706, आकाशदीप,
26-ए, बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली—110001।

2. मैसर्स मुखर्जी बिस्वास एण्ड पाठक, चार्टर्ड लेखाकार,
5 और 6, फैन्सी लेन,
5वीं मंजिल,
कलकत्ता—700001

3. मैसर्स अमित राय एण्ड कंपनी, चार्टर्ड लेखाकार,
5-बी, सरदार पटेल मार्ग,
इलाहाबाद—21001।

4. मैसर्स सोराब एस. इंजीनियर एण्ड कंपनी, चार्टर्ड लेखाकार,
इस्माइल बिल्डिंग
38, डा. डी. एन. रोड, फोर्ट,
बंबई—400003

5 मैसर्स एस. विश्वनाथन एण्ड कंपनी,
चार्टर्ड लेखाकार,
26 कालेज रोड,
नंगमबक्कम, मद्रास—600006

6 मैसर्स एस. के. कपूर एण्ड कंपनी,
चार्टर्ड लेखाकार,
16/98, एल. आई. सी. बिल्डिंग, माल,
कानपुर।

[संख्या 1 (2) / 89—लेखा]
प्राण नाथ, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd April, 1989

S.O. 840.—In exercise of the powers conferred by Section 50 of the Reserve Bank of India Act, 1934, (2 of 1934), the Central Government hereby appoint the following firms of Chartered Accountants as Auditors of the Reserve Bank of India for the year 1988-89, namely :—

1. M/s. Khanna & Annadhanam, Chartered Accountants, 706, Akash Deep, 26-A Barakhamba Road, New Delhi-110001.
2. M/s. Mookherjee Biswas & Pathak, Chartered Accountats, 5 & 6 Facy Lane, 5th Floor, Calcutta-700001.
3. M/s. Amit Ray & Co., Chartered Accountants, , 5-B, Sardar Patel Marg, Allahabad-211001.
4. M/s. Sorab S. Engineer & Co., Chartered Accountants, Ismail Building, 38, Dr. D. N. Road, Fort, Bombay-400003.
5. M/s. S. Vishwanathan & Co. Chartered Accountants, 26, College Road, Nungambakkam, Madras-600006.
6. M/s. S. K. Kapoor and Co. Chartered Accountants, 16/98, LIC Building The Mall, Kanpur.

[No. F. 1(2)89/Accts.]
PRAN NATH, Under Secy.

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1989

का.आ. 841—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित कार्यालय को, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:—

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि. का मुख्य कार्यालय, 10वां और 11वां तल, 'विकास दीप' 22, स्टेशन रोड, लखनऊ-226019

[सं. ई-11011/18/89-हिन्दी]
ओ.पी. कालड़ा, उप सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 30th March, 1989

S.O. 841.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for Official Purposes of the Union), Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the ing office under the Ministry of Textile whereof more than 80 per cent staff have acquired working knowledge of Hindi—

Office of the National Handloom Development Corporation Ltd.

10-11th Floor, "Vikas Deep", 22, Station Road, Lucknow-226019.

[No. E-11011/18/89-Hindi]
O. P. KALRA, Dy. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1989

का. आ. 842.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956का 102) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसरण में, मराठवाड़ा, विश्वविद्यालय की सीनेट द्वारा डा.पी.आर. कुलकर्णी को इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का सदस्य निर्वाचित किया गया है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसरण में भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 138 (सं. 5-13/59-एम 1) तारीख 9 जनवरी, 1960 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में, "धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निर्वाचित शीर्षक के अधीन क्रम सं. 23 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :—

"23 डा.पी.आर. कुलकर्णी
सीनेट सदस्य और
नगरपालिका पार्षद,
मजलेगांव नगरपालिका परिषद,
आनन्द अस्पताल मंजलेगांव,
जिला बीड़ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय।"

[सं. वी. 11013/7/88-एम ई (पी)]
आर. श्रीनिवासन, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 20th March, 1989

S.O. 842.—Whereas in pursuance of the provision of clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) Dr. P. R. Kulkarni has been elected by the Senate of Marathwada University to be a member of the Medical Council of India with effect from the date of issue of this Notification.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Govt. of India in the late Ministry of Health S.O. 138-(No. 5-13/59-Ml), dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (b) of sub-section (1) of section 3" for serial number 23

and the entry relating thereto the following serial number and entry shall be substituted, namely :—

"23 Dr. P. R. Kulkarni
Senate Member and
Municipal Councillor,
Manjlegaon Municipal
Council, Anand Hospital,
Manjlegaon, District Beed.
Marathwada University."

[No. V-11013/7|88-ME|(P)]
R. SRINIVASAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1989

का. आ. 843:—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 4723 तारीख 19 सितम्बर, 1985 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, डा. आर.एस. शर्मा, सहायक निदेशक, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, 22 शामनाथ मार्ग, दिल्ली को जो सरकार के एक राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त संस्था के स्वामीत्वाधीन या उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उसके द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर लिए गए स्थानों के संबंध में अपने क्षेत्राधिकार की सीमाओं के अंतर्गत उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन संपदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे।

[सं. टी. 15020/1/85-पी एच (सी डी एल)/पी एच]

New Delhi, the 27th March, 1989

S.O. 843.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health), No. S.O. 4723, dated the 19th September, 1985, except as respects things done or omitted to be done before such sueprsession, the Central Government hereby appoints Dr. R. S. Sharma, Assistant Director, National Institute of Communicable Disseases, 22-Sham Nath Marg, Delhi, being a gazetted officer of the Government to be estate officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on estate officer by or under the said Act, within the limits of his jurisdiction in respect of the premises under the administrative control or belonging to or taken on lease by or on behalf of the said Institute.

[No. T-15020/1/85 PH(CDL)|PH]

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1989

का. आ. 844:—केन्द्रीय सरकार द्वारा दन्त चिकित्सा अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 3 के खण्ड (च) के अनुसरण में, मेजर जनरल पी.एन. मायर के स्थान पर मेजर जनरल एस.एन. पुरी, अपर महानिदेशक, दन्त चिकित्सा सेवा, सेना दन्त कोर, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली को 22 नवम्बर, 1988 से भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद का सदस्य नामनिर्दिष्ट किया गया है;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा (3) के खण्ड (च) के अनुसरण में, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 430, तारीख 24 जनवरी, 1984 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में धारा 3 के परन्तुक के साथ पठित खण्ड (च) के अधीन नामांकित शीर्षक के नीचे क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"मेजर जनरल एस.एन. पुरी, दन्त चिकित्सा सेवा, अपर महानिदेशक, सेना दंत कोर, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली	केन्द्रीय सरकार	22 नवम्बर, 1988 से 30 सितम्बर, 1991 तक।"

(संख्या वी. 12013/6/88-पी.एम.एस.)
जी.जी.के. नायर, अवर सचिव

New Delhi, the 28th March, 1989

S.O. 844.—Whereas in pursuance of clause (f) of section 3 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), Maj. Gen. S. N. Puri, Additional Director General, Dental Services, Army Dental Corps, Ministry of Defence, New Delhi has been nominated to be a member of the Dental Council of India by the Central Government with effect from the 22nd November, 1988, vice Maj Gen. P. N. Mayar;

Now, therefore, in pursuance of clause (f) of section 3 read with sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare, No. S.O. 430 dated the 24th January, 1984 namely :—

In the said notification, under the heading "Nominated under clause (f) read with the proviso to section 3", for serial number 3 and the entries relating thereto, the following shall be substitued, namely :—

"Maj. Gen S.N. Puri, Additional Director General Dental Services. Army Dental Corps, Ministry of Defence, New Delhi.	Central Govt.	22nd November, 1988 to 30th September, 1991."

[No. V.12013/6/88-PMS]
G. G. K. NAIR, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1989

का. आ. 845:—बहुराज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1984 (1984 का 51) जिसे इसमें उसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 30 की उपधारा (1) के खंड (क) में यह उपबन्ध है कि किसी बहुराज्य सहकारी सोसायटी के बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन, यदि कोई हों, उसके सदस्यों की साधारण बैठक में किए जायेंगे,

बहुराज्य सहकारी सोसायटी (रजिस्ट्रीकरण, सदस्यता, निदेश और प्रबंध, विवादों का निपटारा, अपील और पुनरीक्षण नियम, 1985

(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है, के नियम 27 के खंड (1), नियम 28 और उनकी अनुसूची में किसी बहुराज्य सहकारी सोसायटी में निर्वाचनों के संचालन की प्रक्रिया के लिए उपबंध है ;

और रेलवे एम्प्लॉईज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड मद्रास (जिसे बहुराज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1984 के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत बहुराज्य सहकारी सोसायटी समझा जाएगा) की उपविधि 19,20,21 और उपविधि 22 के अनुसार, सोसायटी के कार्य-कलाप का प्रबन्ध, निदेशक बोर्ड में, जिसमें पदेन अध्यक्ष और 16 निर्वाचित निदेशक होंगे, निहित होगा और अध्यक्ष दक्षिण रेल के लेखा विभाग का पदेन पदाधिकारी होगा जो दक्षिण रेल के महाप्रबंधक द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा;

और निदेशकों के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए, सोसायटी की सम्पूर्ण अधिकारिता बारह विभागों में विभाजित की गई है और प्रत्येक विभाग के लिए निदेशक उस विभाग के सदस्यों द्वारा उस विभाग के सदस्यों में से निर्वाचित किए जायेंगे,

और सोसायटी, किसी भी पदेन हैसियत में अपने अध्यक्ष के रूप में किसी रेल पदधारी का सहयोजन और संबंधित विभागों द्वारा निदेशकों के निर्वाचनों की विद्यमान पद्धति को उपयोगी समझती है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 99 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेलवे एम्प्लाईज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मद्रास को उक्त अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के और किसी उक्त नियमों के नियम 27 के उपनियम (1) नियम 28 और उनकी अनुसूची के उपबंधों से छूट देती है जिससे कि उक्त सोसायटी को सोसायटी के साधारण निकाय के संयोजन किए बिना अपनी उपविधियों में अधिकथित रीति से मतपत्र द्वारा बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचनों का संचालन करने में समर्थ बनाया जा सके और उक्त सोसायटी को उक्त सोसायटी के अध्यक्ष के रूप में रेल प्रशासन द्वारा किसी रेल पदधारी को नाम निर्दिष्ट करने की विद्यमान प्रक्रिया को बनाए रखने में भी समर्थ बनाया जा सके।

[सं. एल. 11011/23/86-एल एण्ड एम]

जे.एन.एल. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agricultural and Cooperation)

New Delhi, the 16th March, 1989

S.O. 845.—Whereas clause (e) of sub-section (1) of section 30 of the Multi-State Cooperative Societies Act, 1984 (51 of 1984) hereafter referred to as the said Act provides that elections, if any, of the members of the board of a multi-State co-operative society shall be held in the general meeting of its members;

And whereas sub-rule (1) of rule 27, rule 28 and the Schedule to the Multi-State Co-operative Societies (Registration, Membership, Direction and Management, Settlement of Disputes, Appeal and Revision) Rules, 1985 (hereafter referred to as the said Rules) provide for the procedure for conduct of elections in a multi-State co-operative society;

And whereas as per bye-laws 19, 20, 21 and 22 of the bye-laws of the Railway Employees' Co-operative Credit Society Limited, Madras (a multi-State cooperative society deemed to be registered under the said Act), the management of the affairs of the society shall vest in the Board of Directors consisting of the ex-officio Chairman and 16 elected directors and the Chairman shall be an ex-officio official of the Accounts Department of Southern Railway, nominated by the General Manager of the Southern Railway;

And whereas for the purposes of election of directors, the entire jurisdiction of the society is divided into twelve departments and the directors for each department shall be elected from amongst the members of respective department by the members of that department;

And whereas the society considers useful the association of a Railway official as its Chairman in an ex-officio capacity and the existing system of elections of the directors by the respective departments.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 99 of the said Act, the Central Government hereby exempt the Railway Employees' Cooperative Credit Society Ltd., Madras, from the provisions of clause (e) of sub-section (1) of section 30 of the said Act and sub-rule (1) of rule 27, rule 23 and the Schedule to the said rules, so as to enable the said society to conduct the elections of members of the board by ballot in the manner laid down in its bye-laws without convening the general body of the society and also to enable the said society to continue the existing procedure of having a Railway official nominated by the Railway Administration as the Chairman of the said society.

[No. L-11011/23/87-L&M]

J. N. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1989

का. आ. 846:—चलचित्र प्रमाणन नियमावली, 1983 के नियम 9 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार आदेश देती है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, कलकत्ता के अधीक्षण पुरातत्वविद, डा. एस.एम. विश्वास अपने सामान्य दायित्वों के अतिरिक्त 27-2-89 से 17-3-89 तक छुट्टी पर गए क्षेत्रीय अधिकारी, श्री डी. सेन गुप्ता के स्थान पर, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, कलकत्ता में क्षेत्रीय अधिकारी के पद का कार्य भी देखें।

[सं. 801/38/87-फिल्म प्रमाणन]

अंशु वैश्य, उप सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Culture)

New Delhi, the 16th March, 1989

S.O. 846.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (ii) of Section 5 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952) read with Rule 9 of the Cinematograph Certification Rules, 1983, the Central Government is pleased to order that Dr. S. S. Biswas, Superintending Archaeologist, Archaeological Survey of India, Calcutta, will perform the duties of the Regional Officer, Central Board of Film Certification, Calcutta in addition to his normal duties, with effect from 27-2-89 to 17-3-89, vice Shri D. Sengupta, Regional Officer, granted leave.

[No. 801/38/87-FC.]
MRS. ANSHU VAISH, Dy. Secy.

(शिक्षा विभाग)

राजभाषा एकक

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1989

का. आ. 847:—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग के निम्नलिखित सार्वजनिक उपक्रम को जिसके 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

एजुकेशनल कन्सल्टेंटस इंडिया लिमिटेड,
ए-1/III
सफदरजंग एन्क्लेव,
नई दिल्ली-110029

[सं. डी. 11011/44/87-रा.भा.ए.]
भगत सिंह, निदेशक (राजभाषा)

(Deptt. of Education)

O.L. Unit

New Delhi, the 27th March, 1988

S.O. 847.—In pursuance of sub Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for the official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the undermentioned Public Undertaking of Ministry of Human Resource Development (Deptt. of Education), 80% staff of which has acquired the working knowledge of Hindi.

"Educational Consultants India Ltd.
A-1/III, Safdarjung Enclave.
New Delhi-110029.

[No D-11011/44/87-OLU]
BHAGAT SINGH, Director (O.L.)

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

धर्मार्थ दान अधिनियम, 1890 (1890 का 6) के संबंध में

और

राष्ट्रीय बाल कोष, नई दिल्ली के संबंध में

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1989

का. आ. 848—धर्मार्थ दान अधिनियम, 1890 (1890 का 6) के खंड 4 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय बाल कोष के प्रबन्ध बोर्ड के निवेदन पर तथा उसकी सहमति से एतद्द्वारा आदेश जारी करती है कि पांच वर्षीय सावधि जमा लेखा में पुनर्निवेश की गई रु. 1,00,000.00 (केवल एक लाख रुपए) जिसकी अवधि 28-3-89 को पूरी हो रही है, की धनराशि भारत सरकार के तत्कालीन समाज कल्याण विभाग की दिनांक 2 मार्च, 1979 की समय-समय पर संशोधित अधिसूचना संख्या एस.ओ. 120(ई) के साथ प्रकाशित राष्ट्रीय बाल कोष, नई दिल्ली के प्रशासन के लिए योजना के अनुसार विनियोग किए जाने के लिए भारतीय धर्मार्थ निधि के कोषाध्यक्ष के अधीन होगी।

[फा.सं. 2-1/89-टी आर]
सुमन नायर, अवर सचिव

(Department of Women & Child Development)

In the matter of the Charitable Endowments

Act 1890 (6 of 1890)

In the matter of the National Children's Fund

New Delhi

New Delhi, the 31st March, 1989

S.O. 848.—On the application made by and with the concurrence of the Board of Management of the National Childrens Fund, New Delhi as in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Charitable Endowments Act 1890 (6 of 1890), the Central Government doth hereby order that the sum of Rs. 1,00,000.00 (Rupees one lakh only) maturing on 28-3-89 be reinvested in 5 Years Post Office Time Deposit Account shall vest in the Treasurer of Charitable Endowments of India to be held by him for being applied in accordance with the scheme for the administration of the National Children's Fund, New Delhi, published with the notification of the Government of India in the then Department of Social Welfare No. S.O. 120(E) dated the 2nd March, 1979, as amended from time to time.

[F. No. 2-1/89-TR]
SUMAN NAYAR, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

(पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1989

का. आ. 849:--राजभाषा (संघ शासकीय के प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 8 (4) के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष यह अधिसूचित करते हैं कि पूर्ति विभाग के सचिवालय में सामान्य अनुभाग दिनांक 1 मार्च, 1989 से अपना शतप्रतिशत कार्य हिन्दी में करेगा।

[सं. ई-11017/3/88-प्रशासन]

एस. बालासुब्रमणियन, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Supply)

New Delhi, the 28th February, 1989

S.O. 849.—In pursuance of Rule 8(4) of Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the President is pleased to notify that the General Section in the Secretariat of Department of Supply, New Delhi, will do 100 per cent of its work in Hindi with effect from 1st March, 1989.

[No. E-11017/3/88-Admn.]

S. BALASUBRAMANIAN, Under Secy.

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1989

का. आ. 850:--आयात और निर्यात नीति खण्ड--1 (1985-88) के पैरा 114 (1) के अन्तर्गत स्टाक एवं बिक्री के लिए स्पेयर्स के आयात हेतु मै. खेमका इन्स्ट्रूमेन्टस प्राइवेट लि., 613-614 सोमदत्त चैम्बर्स 11-9, भीकाजी कामा पलेस, नई दिल्ली-110066 को रु. 44,64,832/- (चवालीस लाख चौसठ हजार, आठ सौ बत्तीस रुपये मात्र) का एक लाइसेंस सं. पी./एफ./1096677 दिनांक 30-4-1988 मंजूर किया गया था।

2. पार्टी ने उपर्युक्त लाइसेंस की दूसरी प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस उनसे खो गया है इसे किसी सीमाशुल्क प्राधिकारी के यहां पंजीकृत नहीं कराया गया है या इसका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने आयात-निर्यात प्रक्रिया पुस्तक 1985-88 के अध्याय-2 के पैरा 86 के अन्तर्गत अपेक्षित एक हलफनामें का निष्पादन भी किया है। दूसरी लाइसेंस प्रति रु. 44,64,832/- (चवालीस लाख, चौसठ हजार आठ सौ बत्तीस रुपये मात्र) के लिए अपेक्षित है । पार्टी ने यह भी सहमति दी है कि उनका मूल लाइसेंस अगर बाद में मिल गया तो उसे इस कार्यालय को लौटा दिया जाएगा।

3. मैं सन्तुष्ट हूं कि मूल लाइसेंस सं. पी./एफ/1096677 दिनांक 30-4-88 खो गया है। 7-12-1955 के यथासंशोधित आयात नियंत्रण आदेश, 1955 की उपधारा 9 (घ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा 30-4-88 के आयात लाइसेंस सं. पी/एफ/1096677 को रद्द करता हूं। रु. 44,64,832/- की अप्रयुक्त राशि के लिए एतद्द्वारा रद्द किए गए मूल लाइसेंस के बदले में पार्टी को दूसरी प्रति जारी की जा रही है।

[सं. 5-के./स्पेयर्स/ए. एम.-88/ए. एल. एस.]

एम. पी. आइसक, उप मुख्य नियंत्रक आयात- निर्यात

Office of the Chief Controller of Imports and Exports

ORDER

New Delhi, the 10th March, 1989

S.O. 850.—M/s. Khemka Instruments Pvt. Ltd. 613-614 Som Dutt Chambers 11 9, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 were granted an Import Licence No. P/F/1096677 dated 30-4-1988 for Rs. 44,64,832 (Rupees Forty four lakhs sixty four thousand eight hundred and thirty two only) for import of spare for stock and sale under para 114(1) of Import and Export Policy Vol. I (1985-88).

2. The party has now applied for issue of a duplicate copy of the above-mentioned licence on the ground that the original licence has been lost by them without having been registered with any Custom Authority or utilised at all. In support of their contention they have executed an affidavit as required under para 86 of Chapter-II of Hand Book of Import and Export Procedures 1985-88. The duplicate licence is required for Rs. 44,64,832 (Rupees forty four lakhs sixty four thosuand eight hundred and thirty two only). The party have agreed and undertaken to return the original licence if traced later to this office.

3. I am satisfied that the original Licence No. P/F/1096677 dated 30-4-88 has been lost. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(d) of Import Control Order. 1955 dated 7-12-55 as amended, I hereby cancel the Import Licence No. P/F/1096677 dated 30-4-88 A duplicate licence is being issued to the party in lieu of the original licence cancelled hereby for the unutilised amount of Rs 44,64,832.

[No. 5-K/Spares/AM-88/ALS]

M. P. ISSAC, Dy. Chief Controller of Imports and Exports

आदेश

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1989

का. आ. 851:--मैसर्स इण्डियन मैटल एण्ड फैरो अलाय लिमिटेड, भुवनेश्वर को वाणिज्यक ऋण के अन्तर्गत पंजीगत माल के आयात के लिए 3,15,80,000/-रुपये (197,37,456 नार्वे क्रोनर) तीन करोड़ पन्द्रह लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का एक आयात लाइसेंस सं. पी/सी. जी./20/75673/डी/एन डब्ल्यु/72/एच/78, दिनांक 25-9-79 प्रदान किया गया था।

फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस की विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई है अथवा गुम हो गई है? आगे यह भी उल्लेख किया गया है कि लाइसेंस की विनिमय नियंत्रण प्रति कलकत्ता सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत थी तथा सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति के मूल्य का पूरी तरह उपयोग कर लिया गया था। उक्त आयात लाइसेंस की विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति की अनुलिपि की जरूरत केवल 11,62,456 नार्वे क्रोनरों (18,59,900 रुपये) तक के परेषण के उद्देश्य के लिए है।

2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक दिल्ली के समक्ष विधिवत शपथपत्र लेकर एक शपथपत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं संतुष्ट हूं कि फर्म से मूल आयात लाइसेंस सं. पी./सी. जी./2075673 दिनांक 25-9-79 की मूल विनियम नियंत्रण प्रति खो गई अथवा गुम हो गई है। समय-समय पर यथासंशोधित 7-12-1955 के आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 के उपखण्ड (ग ग) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स इण्डियन मैटलस एण्ड फैरो अलाय लिमिटेड को 25-9-79 को जारी मूल विनिमय

नियंत्रण प्रति सं. पी/सी. जी /2075673 एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

3. केवल धनप्रेषण के प्रयोजन के लिए 11,62,456 नार्वे क्रोनर (18,59,900 रुपये) के मूल्य के लिए उक्त लाइसेंस की विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति की अनुलिपि पार्टी को अलग से जारी की जा रही है।

[सं. सी. जी.-1/197/1/79-80]

पाल बैक, उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

ORDER

New Delhi, the 16th March, 1989

S.O. 851.—M/s. Indian Metals and Ferro Alloys Ltd., Bhubaneshwar were granted an import licence No. P|CG|2075673|D|NW|72|H|78, dated 25-9-79 for Rs. 3,15,80,000 (Nr. Kr. 1,97,37,456) (Rupees Three Crores Fifteen Lakhs Eighty Thousand only) for import of capital goods under Commercial Loan.

The firm has applied for issue of Duplicate copy of Ex. Control purposes copy of the above mentioned licence on the ground that the original Ex. Control copy of the licence has been lost or misplaced. It has further been stated that the Ex. Control copy of the licence was registered with Calcutta Customs Authority and the value of Customs Purpose copy has been utilised fully. The duplicate Exchange Control copy of said Import Licence is required only for remittance purpose to the extent of Norwegian Kr. 11,62,456 (Rs. 18,59,900).

2. In support of their contention, the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary Public Delhi. I am accordingly satisfied that the original Ex. Control copy of import licence No. P/CG/2075673 dated 25-9-79 has been lost or misplaced by the firm. In exercise of the powers concerned under sub-clause 9(cc) of the Imotr (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original Ex. Control copy No. P/CG/2075673 dt. 25-9-79, issued to M/s. Indian Metals and Ferro Alloys Ltd. is hereby cancelled.

3. A duplicate Ex. Control copy of the said licence is being issued to the party separately for a value of NOK 11,62,456 Rs. 18,59,900 for remittance purpose only

[No. CG. I/197|1|79-80]

PAUL BECK, Dy. Chief Controller of Imports and Exports

आदेश

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1989

का. आ. 852.—मैसर्स स्टील अथारिटी आफ इंडिया (भिलाई स्टील प्लांट) को मुक्त विदेशी मुद्रा के अंतर्गत पूंजीगत माल के आयात के लिए 29,83,600/- रुपये (उनतीस लाख तिरासी हजार छः सौ रुपये मात्र) के लिए आयात लाइसेंस सं० आई/सीजी/2042987, दिनांक 11-3-88 दिया गया था।

फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति खो गई गई या अस्थानास्थ हो गई है। आगे यह भी कहा गया है कि लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति सहायक सीमाशुल्क समाहर्ता (सीमाशुल्क सदन), बम्बई के पास पंजीकृत थी और सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति के मूल्य का 12,35,434/- रुपये तक उपयोग कर लिया था।

2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक, दुर्ग के सामने विधिवत् शपथ लेकर स्टाम्प कागज पर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं संतुष्ट हूं कि आयात लाइसेंस सं० आई/सीजी/242987, दिनांक 11-3-88 की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति फर्म से खो गया या अस्थानस्थ हो गई है। यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955, दिनांक 7-12-55 की उप-धारा 9(गग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मै० स्टील अथारिटी आफ इंडिया (भिलाई स्टील प्लांट) को जारी किए गए आयात लाइसेंस सं० आई/सीजी/242987, दिनांक 11-3-88 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

3. उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति पार्टी को अलग से जारी की जा रही है।

[सं० सीजी-2/स्टील/36/87-88]

ORDERS

New Delhi, the 17th March, 1989

S.O. 852.—M/s. Steel Authority of India (Bhilai Steel Plant) were granted an import licence No. I/CG/2042987 dated 11-3-88 for Rs. 29,83,600 (Rupees twenty nine lakhs eighty three thousand and six hundred only) for import of capital goods under free foreign exchange.

The firm has applied for issued of Duplicate copy of Customs purposes copy of the above mentioned licence on the ground that the original Customs purposes copy of the licence has been lost or misplaced. It has further been stated that the Customs purposes copy of the licence was registered with Asstt. Collector of Customs (Custom House) Bombay and as such the value of Customs purpose copy has been utilised for Rs. 12,35,434.

2. In support of their contention, the licensee has filed an adaffivit on stamped paper duly sworn in before a Notary Public Drug. I am accordingly satisfied that the original Customs purposes copy of import licence No. I/CG/2042987 dated 11-3-88 has been lost or misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original Customs Purposes copy No. I/CG/2042987 dt. 11-3-88 issued to M/s Steel Authority of India (Bhilai Steel Plant) is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs Purposes copy of the said licence is being issued to the party separately.

[No. CG-II/Steel/36/87-88]

का० आ० 853.—मै० स्टील अथारिटी आफ इंडिया बोकारो स्टील प्लांट, जिला धनबाद को मुक्त विदेशी मुद्रा के अन्तर्गत संलग्न सूची के अनुसार एक नग लाइनिंग ब्रेकिंग मशीन के आयात के लिए 46,42,920/ रु० (छियालीस लाख ब्यालीस हजार नौ सौ बीस रुपये) मूल्य के लिए एक आयात लाइसेंस सं० आई/सी जी/2044530/सी एक्स एक्स/10/एच/88/सी जी 2/एल एस दिनांक 24-10-88 दिया गया था। के फर्म ने ऊपर उल्लिखित लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति के साथ-साथ मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति के साथ-साथ मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई या अस्थानस्थ हो गई है। आगे यह भी कहा गया है कि लाइसेंस किसी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं करवाया गया था और इसकी सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति के मूल्य का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है।

2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक दिल्ली के सामने विधिवत् शपथ लेकर स्टाम्प कागज पर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं संतुष्ट हूं कि आयात लाइसेंस सं० आई/सी जी/2044530 दिनांक 24-10-88 की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति के साथ

मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति भी फर्म द्वारा खो गई या अस्थानस्थ हो गई है। यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-55 की उप-धारा 9(गग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै० स्टील अथारिटी आफ इंडिया (बोकारो स्टील प्लांट) को जारी किए गए आयात लाइसेंस सं० आई/सीजी/2044530 दिनांक 24-10-88 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति के साथ-साथ मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

3. उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति के साथ-साथ मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रति पार्टी को अलग से जारी की जा रही है।

[सं० सी जी 2/स्टील/9/88-89]

शफात अहमद, उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

S.O. 853.—M/s. Steel Authority of India, Bokaro Steel Plant, Distt. Dhanbad were granted an import licence No. I/CG/2044530/C|XX|10|H|88|CGII|! S. dated 24-10-88 for Rs. 46,42,920 (Rupees forty six lakhs forty two thousand nine hundred and twenty only) for import of one No. lining braking machine as per list attached under free foreign exchange.

The firm has applied for issue of Duplicate copy of Customs purposes copy as well as exchange control copy of the above mentioned licence on the ground that the original Customs purpose copy as well as Exchange Control copy of the licence have been lost or misplaced. It has further been stated that the licence was not registered with the customs authtority and as such the value of customs purpose copy has not been utilised at all.

2. In support of their contention, the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary Public Delhi. I am accordingly satisfied that the original Customs Purpose copy as well as Exchange Control copy of import licence No. I/CG/2044530 dated 24-10-88 have been lost or misplaced by the firm. In exercise of the power conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original Customs Purposes copy as well as Exchange Control copy of import licence No. I|CG|2044530 dated 24-10-88 issued to M/s. Steel Authority of India (Bokaro Steel Plant) is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs Purposes copy as well as Exchange Control copy of the said licence is being issued to the party separately.

[No. CGII/Steel/9/88-89]

SHAFAAT AHMED, Dy. Chief Controller of Imports and Exports

[ई पी (एम पी) डिवीजन]

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1989

का. आ. 854.—केन्द्रीय सरकार, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 3 और नियम 4 के साथ पठित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 (1972 का 13) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 824 (अ) तारीख 3 नवम्बर, 1986 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 7 और 8 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7 निदेशक, वित्त प्रभाग (एम पी ई डी ए से संबंधित) वाणिज्य मंत्रालय — सदस्य

8 निदेशक/उप सचिव, ई. पी. (समुद्री उत्पाद) वाणिज्य मंत्रालय — सदस्य

[सं. 1/19/85-ई. पी. (एम पी)]

जी. कृष्णामूर्ति, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, सं. 452 तारीख 4 नवम्बर, 1986 में का. आ. 824 (अ) तारीख 3 नवम्बर, 1986 के अधीन प्रकाशित की गई थी और उसके पश्चात्वर्ती संशोधन अधिसूचना सं. 1/11/85—ई पी (एम पी), तारीख 15 जून, 1987 और तारीख 11 अप्रैल, 1988 द्वारा किए गए थे।

[EP (MP) Division]

New Delhi, the 27th March, 1989

S.O. 854.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972 (13 of 1972), read with rules 3 and 4 of the Marine Products Export Development Authority Rules, 1972, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 824(E) dated the 3rd November, 1986, namely :—

In the said notification, for serial number 7 and 8 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"7. Director of Finance Division (dealing MPEDA) Ministry of Commerce. — Member

8. Director|Deputy Secretary, EP (Marine Products), Ministry of Commerce. — Member"

[No. 1/19/85-EP(MP)]

G. KRISHNAMURTHY, Under Secy.

Note : The principal notification was published under S.O. 824((E) dated the 3rd November, 1986 in the Gazette of India Extraordinary No. 452 dated 4th November, 1986 and subsequent amendments vide notifications No. 1/19/85-EP(MP) dated 15th June, 1987 and dated 11th April, 1988.

आदेश

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1989

का.आ. 855—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए लिनोलियम को निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण के अधीन लाने के लिए कतिपय प्रस्ताव निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश स. का. आ. 3064 तारीख 15 अक्तूबर, 1988 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप खंड-(II) तारीख 15 अक्तूबर, 1988 में प्रकाशित किए गए थे।

और ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 26-10-1988 को उपलब्ध करा दी गई थीं।

ग्रौर उक्त प्रस्तावों पर जनता से ग्राक्षेप ग्रौर सुझाव प्राप्त हुए ग्रौर उन पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है।

ग्रत: ग्रब, केन्द्रीय सरकार की निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण ग्रौर निरीक्षण) ग्रधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्रौर भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की ग्रधिसूचना सं. का.ग्रा. 3751 तारीख 15 सितम्बर, 1969 को ग्रधिक्रांत करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श करने के पश्चात् यह राय लेने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना ग्रावश्यक ग्रौर समीचीन है, इसके द्वारा :—

(1) ग्रधिसूचना करती है कि लिनोलियम निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण ग्रौर निरीक्षण के ग्रधीन होगा ;

(2) (i) राष्ट्रीय या ग्रन्तरराष्ट्रीय मानकों को, ग्रौर

(ii) उपाबंध-1 में यथानिर्दिष्ट न्यूनतम विनिर्देशों के ग्रधीन क्रेता ग्रौर विक्रेता के मध्य हुए करार के ग्रनुसार संविदाजात विनिर्देशों को ;

(3) ऐसे लिनोलियम के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देती है। लिनोलियम के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण ग्रौर निरीक्षण) नियम, 1989 के ग्रनुसार क्वालिटी नियंत्रण ग्रौर निरीक्षण के प्रकार को क्वालिटी नियंत्रण ग्रौर निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो निर्यात से पूर्व ऐसे लिनोलियम पर लागू होगा ;

(4) ग्रन्तरराष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसे लिनोलियम के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करती है जब तक कि उसके प्रत्येक परेषण के साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण ग्रौर निरीक्षण) ग्रधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के ग्रधीन स्थापित या मान्यताप्राप्त किसी एक ग्रभिकरण द्वारा जारी किया गया निर्यात निरीक्षण प्रमाण पत्र न हो।

3. इस ग्रादेश की कोई भी बात भावी क्रेताग्रों को समुद्र, भूमि या वायु मार्ग द्वारा लिनोलियम के नमूनों के निर्यात को लागू नहीं होगी परन्तु यह तब जब कि ऐसे नमूनों का पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य 500- रुपए से ग्रधिक न हो ;

4. इस ग्रादेश में "लिनोलियम" से ग्रभिप्रेत हैसियन ग्रस्तरण पर सम्पीडित ग्रपेक्षाकृत मोटी घिसी हुई सतह द्वारा विशिष्टताग्रों को ग्रावृत करते हुए, एक कठोर लचीली फर्श है जिसकी घिसी हुई सतह तेलों, ग्राक्सीकृत या पोलिमरकृत शुष्क तेलों के बाईंडर या सीमेंट तथा कार्क या लकड़ी के बुरादे के खनिज भरक या भरकों तथा वर्णकों का सम्मिश्रण होगी ;

5. यह ग्रादेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

उपाबंध-1

लिनोलियम के लिए विनिर्देश

1. साधारण ग्रपेक्षाएं :—

1.1 लिनोलियम, क्रेता ग्रौर निर्यातकर्ता के मध्य करार पाए गए डिजाइन ग्रौर नमूने के ग्रनुसार विनिर्मित किए जाएंगे :

2. सामग्री :—

2.1 लिनोलियम की सतह, निम्नलिखित सामग्री के उपयुक्त ग्रनुपात में, उपयोग द्वारा बनाई जाएगी :—

(क) ग्रावश्यक शुष्कों के साथ ग्राक्सीकृत या पालिमरीकृत ग्रलसी का तेल या ग्रन्य उपयुक्त शुष्क तेल ;

(ख) बेरोजा (रोजिन) या राल या उनके सम्मिश्रण ;

(ग) कार्क बुरादा या लकड़ी का बुरादा या दोनों ;

(घ) खनिज भरक ; ग्रौर

(ङ) रंजित सामग्री या वर्णक।

2.2 ग्रस्तरण के लिए प्रयुक्त हैसियन की न्यूनतम ग्रपेक्षाएं भा. मा. 2818 (भाग-II)—1971 के प्रकार-II के ग्रनुरूप होंगी

3. विमाएं तथा सह्यताएं :

3.1 चद्दर की मोटाई :—चद्दर का ग्रौसत मूल्य क्रेता ग्रौर निर्यातकर्ता के मध्य करार पाए गए मूल्य के ± 3 मि.मी. से ग्रधिक भिन्न नहीं होगा।

3.2 मोटाई :—जब तक कि क्रेता ग्रौर निर्यातकर्ता के मध्य ग्रन्यथा करार न पाई जाए लिनोलियम चद्दर की मोटाई का ग्रौसत मूल्य करार पाए गए मूल्य के + 1.5 मि.मी. से ग्रधिक भिन्न नहीं होगा।

4. फिनिश :—

4.1 लिनोलियम की सतह चिकनी, एक सार होगी तथा कटावों, सिकुड़नों दरारों तथा बचे हुए ग्रवशेषों से मुक्त होगी।

5. कटाव :—

5.1 जब मानक प्रणाली द्वारा परीक्षित हों, तब ग्रवशिष्ट कटाव संपूर्ण मोटाई पर मूल के 10 प्रतिशत से ग्रधिक नहीं होगा।

6. लचीलापन :—

6.1 जब मानक प्रणाली के ग्रनुसार परीक्षित होंगे तब नमूना टुकड़े में से लम्बे ग्रौर ग्राड़े 50 × 200 मि.मी. माप वाले कटे हुए परीक्षित टुकड़े, टूटन दरारों या ग्रन्य क्षतियों की ग्रपेक्षाग्रों को पूरा करेंगे।

7. जल ग्रवशोषण :—

7.1 जब मानक प्रणाली द्वारा परीक्षित हों, जब ग्रवशोषण निम्नलिखित से ग्रधिक नहीं होगा।

मोटाई के लिए	जल ग्रवशोषण
मि. मीटर	प्रतिशत ग्रधिकतम
4.5	5.5
3.2	6.5
2.0	10.0
1.6	11.5

टिप्पण :—छपी हुई लिनोलियम के लिए उपरोक्त विनिर्देश लागू नहीं है। इस क्वालिटी के लिए क्रेता ग्रौर विक्रेता के मध्य करार पाए गए संविदाजात विनिर्देश ग्रपनाए जाएंगे।

[फाईल सं. 6(5) 88-ईग्राई एण्ड ईपी]

पाद टिप्पण :

का. ग्रा. 3751 तारीख 15-09-1969

ORDER

New Delhi, the 22nd April, 1989

S.O. 855.—Whereas for the development of the export trade of India certain proposals for subjecting Linoleum to quality control and inspection prior to export were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 15th Octo-

ber, 1988 under the order of the Govrnment of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 3064 dated the 15th October, 1988 ;

And whereas the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby within 45 days of the publication of the said order in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 26th October, 1988 ;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said proposal have been considered by the Central Government ;

Now, therefore, the Central Government after consultation with the Export Inspection Council being of opinion it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 3751 dated 15th September, 1969, hereby;

(1) notify that Linoleum shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) recognises—

(i) national or International Standaids; and

(ii) contractual specifications as agreed to between the buyer and the seller subject to the minimum specifications as referred to in Annexure, as the standard specification for such linoleum.

(3) specifies the type of quality control and inspection in accordance with the Export of Linoleum (Quality Central and inspection) Rules, 1989 as the type of quality control and inspection which shall be applied to such linoleum prior to export;

(4) prohibit the export, in the case of international trade of such Linoleum, unless every consignment thereof is accompanied by an inspection certificate of export issued by any one of the Agencies established or recognised under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

3. Nothing in this Order shall apply to the export by land, sea or air of bonafide trade samples of linoleum to the prospective buyers, provided that the f.o.b. value of such samples shall not exceed Rs. 500.

4. In this Order "Linoleum" means a hard surfaced floor covering, characterized by relatively thick wearing surface compressed on a hessian backing, the wearing surface of which shall consist of a composition containing a binder or cement of oxidised or polymerised drying oils and resins intimately mixed with cork or wood flour and mineral fillers or combination of fillers and pignments

5 This Order shall come into force on the date of publication in the Offic;al Gazette.

ANNEXURE

SPECIFICATION FOR LINOLEUM

1. General Requirements

1.1 The linoleum shall be manufactured as per design of pattern as may be agreed to between the buyer and the exporter.

2. Materials

2.1 The wearing surface of the linoleum shall be made by use of suitable pioportion of the following materials :

(a) Oxidized or polymerized linseed oil or other suitable drying oil with necessary driers;

(b) Rosin or resin or their combination;

(c) Cork flour or wood flour or both;

(d) Mineral fillers; and

(d) Colouring material or pignments.

2.2 The minimum requirement of hessian used for backing shall conform to Type-II of IS : 2818 (Part-II) 1971.

3. Dimensions and Tolerances

3.1 Width of Sheet : The average value of the sheet shall of vary by more than 3 mm of the value agreed to between the buyer and the exporter.

3.2 Thickness—Unless otherwise agreed to between the buyer and the exporter, the average value of the thickness of linoleum sheet shall not vary by more than ±. 15mm to the agreed value.

4. Finish.

4.1 The surface of linoleum shall be smooth, uniform and shall be free from indentations, wrinkles, cracks and protruding particles.

5. Indentation.

5.1 When tested by the standard method, the residual indentation shall not exceed 10 per cent of the original overall thickness.

6. Flexibility.

6.1 Test pieces measuring 50×200mm cut from sample piece longitudinally and transversely when tested as per standard method shall pass the requirement for breaks, cracks or other damages.

7.1 Water Absorption

7.1 When tested by the standard method, the water absorption shall not exceed the following :

for thickness	water Absorptio
mm	*Maximum percent*
4.5	5.5
3.2	6.5
2.0	10.0
1.6	11.5

NOTE : For printed Linoleum, the above specifications, are not applicable. For this quality, the contractual specifications as agreed between the buyer and the seller shall be followed.

[F. No. 6(5)/88-EI&EP]

Foot Note :

S.O. 3751 dated 15-9-1969.

का.आ. 856.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लिनोलियम का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1969 को अधिक्रान्त करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लिनोलियम का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1989 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :—

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है ;

(ख) "परिषद" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद अभिप्रेत है ;

(ग) "अभिकरण" से उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण के अधीन प्रमाणन करने और परेषणानुसार निरीक्षण के लिए स्थापित

मान्यताप्राप्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरण में से कोई एक अभिप्रेत है ;

(घ) "लिनोलियम" से अभिप्रेत है ऐसे हैसियन अस्तरण पर सम्पीडित अपेक्षाकृत मोटी घिसी हुई सतह द्वारा विशिष्टताओं को आवृत करते हुए एक कठोर सतही फर्श, जिसमें किसी सतह तेलों, आक्सीकृत या पोलीमरकृत शुष्क तेलों के बाइंडर रिम सीमेंट तथा कार्क या लकड़ी के बुरादे के खनिज पूरक या पूरकों तथा वर्णकों का सम्मिश्रण भी अन्तर्विष्ट है ;

(ङ) "उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण" (जिसे इसमें इसके पश्चात् आई. पी. क्यू. सी. कहा गया है) से क्वालिटी नियन्त्रण की वह प्रणाली अभिप्रेत है जिसके द्वारा विनिर्माण एकक यह सुनिश्चित करता है कि लिनोलियम का विनिर्माण परिषद् द्वारा अधिकथित ढंग से क्रय की गई सामग्री तथा संघटकों, विनिर्माण, निरीक्षण परिरक्षण तथा पैकिंग के विभिन्न प्रक्रमों पर नियंत्रणों का प्रयोग करके मानक विनिर्देशों के अनुसार किया गया है;

(च) "परेषणानुसार निरीक्षण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिससे यह निर्धारित होता है कि क्या निर्यात के लिए आशयित लिनोलियम का परेषण परिषद् द्वारा अधोकथित ढंग से अभिकरण द्वारा निरीक्षण और परीक्षण करके मानक विनिर्देशों को पूरा करता है;

(छ) "अनुमोदित एकक" से अभिकरण द्वारा अनुमोदित वह विनिर्माण एकक अभिप्रेत है जो आई. पी. क्यू. सी. की सभी अपेक्षाओं की पूर्ति करता है।

(ज) "कालिक दौरों" से अनुमोदित एकक में नियमित अन्तरालों पर अभिकरण के अधिकारियों के वह दौरे अभिप्रेत हैं जिनके द्वारा वे यह सुनिश्चित करते हैं कि एकक में आई. पी. क्यू. सी. की अपेक्षाओं का पूर्णतः पालन होता है; तथा

(झ) "स्थल पर जांच" से अभिकरण द्वारा निर्यात परेषण का निरीक्षण अभिप्रेत है जिसके द्वारा परिषद् द्वारा अधिकथित ढंग से मानक विनिर्देशों से इसकी अनुरूपता सुनिश्चित की जाती है ।

3. निरीक्षण का आधार :—

निर्यात के लिए आशयित लिनोलिम का निरीक्षण यह देखने की दृष्टि से किया जाएगा कि वह अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है;

या

(1) यह सुनिश्चित करते हुए कि उत्पाद, निरीक्षण की उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले एककों के संबंध में इस अधिसूचना के परिशिष्ट-क में विनिर्दिष्ट उत्पादन के दौरान अनिवार्य क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग करते हुए विनिर्मित किया गया है;

या

(2) निरीक्षण की परेषणावार निरीक्षण प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले एककों के बारे में इन नियमों के परिशिष्ट-ख में विनिर्दिष्ट ढंग से किए गए निरीक्षण तथा परीक्षण के आधार पर ।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया :—

(1) लिनोलियम के परेषण का निर्यात करने का इच्छुक निर्यातकर्ता, निर्यात संविदा या आदेश की एक प्रति संविदाजात विनिर्देशों का ब्यौरा देते हुए अभिकरण को लिखित रूप में सूचना देगा ताकि अभिकरण नियम 3 के उपबन्धों के अनुसरण में निरीक्षण करने में समर्थ हो सके।

(2) परिशिष्ट-क में अधिकथित के अनुसार उत्पादन के दौरान पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग करते हुए, विनिर्मित लिनोलियम के निर्यात के लिए तथा इस प्रयोजन के लिए परिषद द्वारा गठित विशेषज्ञों के पेनल द्वारा यह न्यायनिर्णित कर लेने पर कि विनिर्माण एकक के पास उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण की पर्याप्त द्विस्में है, निर्यातकर्ता उप नियम (2) में उल्लिखित सूचना के साथ यह घोषणा भी करेगा कि निर्यात के लिए आशयित लिनोलियम का परेषण परिशिष्ट-क में अधिकथित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग करते हुए विनिर्मित किया गया है तथा यह इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है ।

(3) निर्यातकर्ता, अभिकरण को निर्यात किए जाने वाले परेषण पर लगाए जाने वाले पहचान चिह्न देगा ।

(4) उपरोक्त उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना, निर्यातकर्ताओं के परिसर से परेषण के भेजे जाने से कम से कम सात दिन पूर्व देगा, जबकि उपनियम (2) के अधीन घोषणा के साथ सूचना देने के मामले में, विनिर्माता के परिसरों से परेषण भेजे जाने से कम से कम तीन दिन पूर्व देगा ।

(5) उप नियम (1) के अधीन सूचना तथा उप नियम (2) के अधीन घोषणा यदि कोई हो, प्राप्त होने पर, अभिकरण :—

(क) (1) अपना यह समाधान कर लेने पर कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान विनिर्माता ने परिशिष्ट-क में अधिकथित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग किया है और इस प्रयोजन के लिए उत्पादन का विनिर्माण मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप करने के लिए परिषद् या अभिकरण द्वारा जारी किए गए अनुदेशों, यदि कोई हों, का पालन किया है, तीन दिन के भीतर यह घोषणा करने वाला प्रमाण पत्र जारी करेगा कि लिनोलियम का परेषण निर्यात योग्य है।

(2) जहां विनिर्माता, निर्यातकर्ता नहीं है, वहां परेषण की अस्तव्य जांच की जाएगी तथा ऐसी जांच तथा ऐसी जांच और निरीक्षण, यदि आवश्यक हो, अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि उपरोक्त शर्तों का पालन किया गया है।

(3) अभिकरण निर्यात के लिए आशयित कुछ परेषणों का स्थल पर ही निरीक्षण करेगा और एकक द्वारा अपनाई गई क्वालिटी नियंत्रण प्रणाली की द्विस्मों की पर्याप्तता को बनाए रखने की जांच करने के लिए नियमित अन्तरालों पर विनिर्माण एककों में जाएगा।

(4) यदि यह पाया जाता है कि विनिर्माण एकक ने विनिर्माण के किसी भी प्रक्रम पर अपेक्षित क्वालिटी नियंत्रण उपायों को नहीं अपनाया है या उसने परिषद् या अभिकरण की सिफारिशों का पालन नहीं किया है तो यह घोषित कर दिया जाएगा कि एकक के पास उत्पादन के दौरान पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण द्विस्में नहीं है और ऐसे मामले में, यदि एकक ऐसा चाहता है तो वह उत्पादन के दौरान पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण को बनाए रखने के अधिनियम के लिए नए सिरे से आवेदन कर सकेगा ।

(ख) जहां, नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन, निर्यातकर्ता ने यह घोषित नहीं किया है कि परिशिष्ट-क में अधिकथित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग किया गया है, वहां वह अपना यह समाधान करने पर कि लिनोलियम का परेषण इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है, परिशिष्ट-ख में अधिकथित के अनुसार किए गए निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर, ऐसा निरीक्षण करने के सात दिन के भीतर यह घोषणा करने वाला प्रमाण पत्र जारी करेगा कि परेषण निर्यात योग्य है।

परन्तु जहां अभिकरण का ऐसा समाधान नहीं हो पाता है वहां वह उक्त सात दिनों की अवधि के भीतर निर्यातकर्ता को ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार कर देगा और ऐसे इंकार की सूचना उसके कारणों सहित निर्यातकर्ता को दे देगा ।

(ग) (i) ऐसे मामलों में जहां विनिर्माता उपनियम (5) (क) के अधीन निर्यातकर्ता नहीं है या उपनियम (5) (ख) के अधीन परेषण का निरीक्षण किया गया है, वहां अभिकरण निरीक्षण की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् परेषण के पैकेजों को इस ढंग से सील बन्द करेगा कि जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि सील किए हुए पैकेजों के साथ छेड़छाड़ न की जा सके।

(ii) परेषण की अस्वीकृति के पश्चात् यदि अभिकरण ऐसा चाहे तो परेषण को अभिकरण द्वारा सीलबन्द नहीं किया जाएगा परन्तु ऐसे मामलों में निर्यातकर्ता अस्वीकृति के विरूद्ध कोई अपील करने का हकदार नही होगा ।

5. निरीक्षण का स्थान :—

इन नियमों के अधीन प्रत्येक निरीक्षण या तो (क) ऐसे उत्पादों के विनिर्माताओं के परिसरों पर, या (ख) ऐसे परिसरों पर, जहां निर्यातकर्ता ने निरीक्षण के लिए माल प्रस्तुत किया है, किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि वहां इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों ।

6 निरीक्षण फीस :—

निर्यातकर्ता द्वारा अभिकरण को निम्नानुसार फीस दी जाएगी :—

(क) उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण प्रणाली के अन्तर्गत निर्यात करने के लिए न्यूनतम 20.00/- रु. प्रति परेषण के अधीन रहते हुए पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य के 0.2 प्रतिशत की दर से।

(ख) परेषणावार निरीक्षण के अन्तर्गत निर्यात करने के लिए प्रति परेषण न्यूनतम 20.00/- रु. के अधीन रहते हुए पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य के 0.4 प्रतिशत की दर से ।

7. अपील :—

(1) ऐसा कोई व्यक्ति जो नियम 4 के उपनियम (5) के अधीन प्रमाण पत्र जारी करने के अभिकरण के इंकार किए जाने से व्यथित है, ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित ऐसे विशेषज्ञों के पैनल को अपील कर सकेगा जिसमें कम से कम तीन और अधिक से अधिक सात व्यक्ति होंगे ।

(2) विशेषज्ञों के पैनल मे कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य गैर सरकारी होंगे ।

(3) विशेषज्ञों के पैनल की गणपूर्ति तीन की होगी।

(4) अपील प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर निपटा दी जाएगी।

[फाइल सं. 6(5)/88-ई आई एण्ड ई पी]

पाद टिप्पण :—

का. आ. 3751 तारीख : 15-9-1969

परिशिष्ट—क

उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण

निर्यात के लिए आशयित लिनोलियम का क्वालिटी नियंत्रण इस दृष्टि से किया जाएगा कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिए गए नियंत्रण के स्तरों सहित नीचे अधिकथित उत्पाद के विनिर्माण, परिरक्षण तथा पैकिंग के विभिन्न प्रक्रमों पर निम्नलिखित नियंत्रणों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है ।

1. आने वाली सामग्री पर नियंत्रण :—

(क) विनिर्माण/प्रसंस्करण एकक में विनिर्मित लिनोलियम के विनिर्माण/प्रसंस्करण के लिए आशयित सभी सामग्री क्रय दस्तावेजी विनिर्देशों के अनुकूल होगा तथा उनकी स्वीकृति उपयुक्त नमूना लेने के प्लान तथा मान दण्डों के अनुसार निरीक्षण तथा परीक्षण के पश्चात् दी जाएगी।

(ख) स्वीकृत परेषणों के साथ क्रय विनिर्देशों की अपेक्षाओं को समाविष्ट करते हुए, प्रदायकर्ता का परीक्षण तथा निरीक्षण प्रमाणपत्र होगा, जिस मामले में, किसी विशिष्ट प्रदायकर्ता के लिए क्रेता द्वारा कम से कम 10 परेषणों में से एक ही लिनोलियम के विनिर्माता द्वारा यदा कदा जांच की जाएगी। स्वीकृति परेषणों के साथ प्रदायकर्ता का परीक्षण प्रमाण पत्र लगा होगा या क्रय विनिर्देशों की अपेक्षाओं को समाविष्ट करते हुए निरीक्षण प्रमाण पत्र होगा, जिस मामले में किसी विशिष्ट प्रदायकर्ता के लिए लिनोलियम के विनिर्माता द्वारा उपयुक्त परीक्षण या निरीक्षण प्रमाण पत्रों की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए 10 परेषणों में से कम से कम एक की यदा कदा जांच की जाएगी या क्रय की गई सामग्री का क्रय करने से पहले फैक्ट्री की प्रयोगशाला या फैक्ट्री का प्रयोगशाला सदन के बाहर नियमित रूप से निरीक्षण तथा परीक्षण किया जाएगा । निरीक्षण और परीक्षण की ऐसी जाच के अभिलेख रखे जाएंगे ।

(ग) निरीक्षण/परीक्षण के लिए किए जाने के पश्चात् स्वीकृत और अस्वीकृत सामग्री का पर्थक्करण तथा अस्वीकृत सामग्री के निपटान करने हेतु व्यवस्थित पद्धतियां अपनाई जाएंगी।

2. प्रसंस्करण/विनिर्माण नियंत्रण :—

(क) विनिर्माण के विभिन्न प्रक्रमों पर विनिर्माता द्वारा ब्यौरेवार प्रक्रिया विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे ।

(ख) विनिर्माण विनिर्देशों में अधिकथित प्रक्रियाओं पर नियंत्रण रखने के लिए पर्याप्त उपकरण, उपस्करण व सुविधाएं होंगी ।

(ग) विनिर्माता द्वारा, विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान प्रयुक्त नियंत्रणों की जांच की संभावना को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अभिलेख रखे जाएंगे ।

3. उत्पाद नियंत्रण :—

(क) अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद का परीक्षण करने हेतु, विनिर्माता के पास या तो अपनी परीक्षण सुविधाएं होंगी या वह वहां तक जा सकेगा जहां ऐसी परीक्षण सुविधाएं विद्यमान हों;

(ख) परीक्षण के लिए नमूना लेना (जहां कहीं अपेक्षित हों) अभिलिखित अन्वेषणों पर आधारित होगा ।

(ग) किए गए परीक्षण के बारे में पर्याप्त अभिलेख विनिर्माता द्वारा नियमित व व्यवस्थित रूप से रखे जाएंगे ।

4. परिरक्षण नियंत्रण :—

(क) विनिर्माता द्वारा उत्पाद को मौसमी दशाओं के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए ब्यौरेवार विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे।

(ख) उत्पादन को भण्डारण और पोत पत्तन को परिवहन दोनों के दौरान पर्याप्त रूप से परिरक्षित किया जाएगा ।

5. पैकिंग नियंत्रण :—

(क) निर्यात के लिए आशयित लिनोलियम निर्यात संविदा में अधिकथित या कपड़े की सामग्री में पैक किया जाएगा। उसकी अनुपस्थिति में विनिर्माता द्वारा, निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा विधिवत अनुमोदित ठोस व्यापारिक कुशलता के अनुसार पैकेजों के लिए अपने ब्यौरेवार पैकिंग विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे;

(ख) जब तक कि क्रेता द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न हों, सभी पैकेजों पर विनिर्माता का नाम, मात्रा, पोतपत्तन तथा पोतवहन का चिह्न अंकित होगा।

अनुसूची

लिनोलियम के लिए नियंत्रण के स्तर

क्रम सं. विशिष्टताएं	अपेक्षाएं	परीक्षण किए जाने वाले नमूनों की संख्या	आवृत्ति	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1. डिजाइन तथा नमूना	इस प्रयोजन के लिए मान्यता-प्राप्त मानक विनिर्देश	प्रत्येक रोल/कालीन	100%	--
2. फिनिश	--यथोक्त--	--यथोक्त--	100%	--
3. हैसियन अस्तरण	--यथोक्त--	--यथोक्त--	प्रति बैच	--
4. विमाएं :				
क. चौड़ाई	--यथोक्त--	प्रत्येक रोल/कालीन	100%	--
ख. मोटाई	--यथोक्त--	--यथोक्त--	100%	--
ग. लम्बाई	--यथोक्त--	--यथोक्त--	100%	--
5 रंग तथा इसके नमूने की एकसारता	--यथोक्त--	प्रत्येक रोल/कालीन	100%	जब कभी भी लागू हो
प्लेन तथा इन लेड प्रकार के लिए किए जाने वाले परीक्षण :--				
6. काट परीक्षण	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	--
7. जल अवशोषण	--यथोक्त--	एक	प्रति बैच	--
8. लचीलापन	--यथोक्त--	एक	प्रति बैच	--

परिशिष्ट-"ख"

परेषणवार निरीक्षण :—

1. लिनोलियम का परेषण अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यता-प्राप्त विनिर्देशों से इसकी अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण तथा परीक्षण के अधीन किया जाएगा।

2. अनुरूपता के लिए नमूना लेना तथा मानदण्ड*के संबंध में निर्यात संविदा में अनुबंध के अभाव में, एक बैच में से विनिर्मित एक ही प्रकार मोटाई के लिनोलियम की शीट के सभी रोल एक लॉट या गठन करने के लिए एक साथ बांधे जाएंगे।

2.1 इस विनिर्देशों से लॉट की अनुरूपता निर्धारित करने के लिए लॉट में से यदृच्छ चुने गए रोलों की संख्या लॉट के आकार पर निर्भर होगी तथा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 1 और 2 के अनुसार होगी।

सारणी :—चद्दरों की अनुरूपता के लिए नमूना आकार तथा मानदण्ड:

लॉट में रोलों की संख्या	नमूनों में चुने जाने वाले रोलों की संख्या	त्रुटि पूर्ण रोलों की अनुज्ञेय संख्या
(1)	(2)	(3)
50 तक	3	0
51 से 150	5	0
101 से 300	8	0
301 से 500	13	0
501 से 1000	20	0
1000 तथा इससे अधिक	32	1

2.2 अनुरूपता के लिए मानदण्ड :—2.1 के अनुसार चुने गए रोलों/चद्दरों की संख्या इस विनिर्देशों की सभी अपेक्षाओं के लिए परीक्षित की जाएगी एक या अधिक अपेक्षाओं के संबंध में फेल हुए रोल चद्दर को त्रुटिपूर्ण रोल/चद्दर कहा जाएगा। यदि नमूनों में दोषी रोलों/चद्दरों की संख्या उपरोक्त सारणी के स्तम्भ 3 में दिए गए अनुज्ञेय संख्या से कम या उसके बराबर है, लॉट को इन विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप समझा जाएगा। यदि दोषी रोलों/चद्दरों की विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं समझा जाता है।

3. लम्बी अवधि के लिए परीक्षण/प्रकार परीक्षण.—जहां निर्यात संविदा में शेल्फ/निष्पादन परीक्षण/गारन्टी मानदण्ड से संबंधित परीक्षणों में दिए गए हों और उसके लिए अनुबंधित अवधि (सात दिन या जैसा भी हो) के भीतर परीक्षण नहीं किया गया। 10 परेषणों में से एक ही आवृत्ति नमूना पोस्ट पैकटों के आधार पर परीक्षित किया जाएगा और निरीक्षण का प्रमाणपत्र पूर्व निष्पादन के आधार पर जारी किया जा सकता है तथापि अभिकरण का अपना समाधान कर लेने पर कि जो परीक्षण पोस्ट पैकटों के आधार पर किया गया है, निर्यातकर्ता विनिर्माता द्वारा पूर्णतः ही किया जा चुका है तथा परेषण को निर्यात के लिए अनुमत किया जाएगा परन्तु जब तक कि निर्यातकर्ता/विनिर्माता द्वारा किया गया परीक्षण निर्यात संविदा की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

S.O. 856.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), and in supersession of the Export of Linoleum (Quality Control and Inspection) Rules, 1969, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Linoleum (Quality Control and Inspection) Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Difinition.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" menas the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act;

(c) "Agency" means any one of the Export Inspection Agencies established under section 7 of the Act for certification under In-process Quality Control and established/recognised for consignmentwise inspection;

(d) "Linoleum" means a nard surfaced floor covering characterized by relatively thick wearing surface compressed on a hessian backing, the wearing surface of which shall consist of a composition containing a binder or cement of oxidized or polymerised drying oils and resins intimately mixed with cork or wood flour and mineral fillers or combination of fillers and pigments.

(e) "In process Quality Control" (hereinafter referred to as IPQC) means a system of quality control by which a manufacturing unit ensures that linoleum are manufactured to confrorm to the standard specifications by exercising controls at different stages of purchase of materials and components, manufacture, inspection, preservation and packing, in a manner as laid down by the Council;

(f) "Consignmentwise Inspection" means the process of determining whether a consignment of linoleum meant for export complies with the standard specifications, by inspections and testing by the Agency in a manner as laid down by the Council.

(g) "Approved Unit" means a manufacturing unit approved by the Agency as having satisfied the requirements of IPQC.

(h) "Periodic Visit" means a visit made by officer(s) of the Agency to the approved unit at intervals to ensure compliance of the requirement of IPQC in the unit; and

(i) "Spot Checks" means an inspection by the Agency of export consignment to ensure its conformity to the standard specifications in a manner as laid down by the Council.

3. Basis of Inspection.—Inspection of linoleum intended for export shall be carried out with a view to seeing that the same conforms to the standard specifications recognized by the Central Government under section 6 of the Act.

either

(i) by ensuring that the products have been manufactured by exercising necessary in process quality control specified in Appendix-A to this notification in respect of units coming under in-process quality control system of inspection.

or

(ii) on the basis of inspection and testing carried out in the manner specified in Appendix-B to these rules in respect of units coming under consignmentwise system of inspection.

4. Procedure of Inspection

(1) An exporter intending to export consignment of linoleum shall give an intimation in writing to the agency furnishing therein details of the contractual specification alongwith a copy of the export contract or order to enable the agency to carry out inspection in accordance with the provisions of rule 3.

(2) For export of linoleum manufactured by exercising adequate in-process quality control as laid down in Appendix-A and the manufacturing unit adjudged as having adequate in-process quality control drills by a panel of experts constituted by the Council for this purpose, the exporter shall also furnish alongwith the intimation mentioned in sub-rule (1), a declaration that the consignment of linoleum intended for export has been manufactured by exercising adequate quality control as laid down in Appendix-A and that the consignment conforms to the standard specifications recognised for the purpose.

(3) The exporter shall furnish to the agency the identification marks applied to the consignment to be exported.

(4) Every intimation under sub-rule (1) above shall be given not less than seven days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises. While in the case of intimation alongwith declaration under sub-rule (2) shall be given not less than three days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises;

(5) On receipt of the intimation under sub-rule (1) and the declaration, if any, under sub-rule (2) the agency—

(a) (i) On satisfying itself that during the process of manufacture, the manufacturer had exercised adequate quality controls as laid down in Appendix-A and followed the instructions, if any, issued by the Council or Agency in this regard to manufacture the product to conform to the specifications recognised for the purpose, shall within three days issue a certificate declaring the consignment of linoleum as exportworthy;

(ii) In case where the manufacturer is not the exporter, however, the consignment shall be physically verified and such verification and inspection if necessary, shall be carried out by the Agency to ensure that the above conditions are complied with.

(iii) The Agency shall, however, carry out the spot checks of some of the consignments meant for export and shall visit the manufacturing unit at regular intervals to verify the maintenance of the adequacy of in-process quality control drills adopted by the unit.

(iv) If the manufacturing unit is found not adopting the required quality control measures at any stage of manufacture or does not comply with the recommendations of the Council or Agency, the unit shall be declared as not having adequate in-process quality control drills and in such cases, the unit if so desired shall apply afresh for adjudgement of the maintenance of adequacy of in-process quality control drills.

(b) In case where the exporter had not declared under sub-rule (2) of rule 4 that adequate quality control as laid down in Appendix-A had been exercised, on satisfying itself that the consignment of linoleum conforms to the standard specifications recognised for the purpose, on the basis of inspection and testing carried out as laid down in Appendix-B shall, within seven days of carrying out such inspection, issue a certificate declaring the consignment as exportworthy.

Provided that where the agency is not so satisfied, it shall within the said period of seven days refuse to issue a certificate to the exporter and shall communicate such refusal to the exporter alongwith the reasons.

(c) (i) In case where the manufacturer is not the exporter under sub-rule (5) (a) or consignment is inspected under sub-rule (5) (b), the agency shall immediately after completion of the inspection seal the packages in the consignment in the manner so as to ensure that the sealed packages cannot be tampered with.

(ii) In case of rejection of the consignment, if the exporter so desires the consignment may not be sealed by the agency but in such cases, however, the exporter shall not be entiled to prefer any appeal against the rejection.

5. Place of Inspection.—Every inspecton under these rules shall be carried out either,—(a) at the premises of the manufacturer of such product, or (b) at the premises at which the goods are offered by the exporter for inspection, provided adequate facilities for the purpose exist therein.

6. Inspection Fee.—Inspection fee shall be paid by the exporter to the agency as under :

(a) for exports under in-process quality control scheme at the rate of 0.2 per cent of the f.o.b. value subject to a minimum of Rs. 20 per consignment.

(b) for exports under consignmentwise inspection at the rate of 0.4% of f.o.b. value subject to a minimum of Rs. 20 per consignment.

7. Appeal

(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule (5) of rule 3, may within ten days of the receipt of communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons as may be constituted by the Central Government.

(2) Out of the total membership of the panel referred to in sub-rule (1), atleast two thirds of membership shall consist of non-officials.

(3) The quorum for the panel of experts shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within fifteen days of its receipt.

[F. No. 6(5)/88-EI&FP]

Foot Note :

S.O. 3751 dated 15-9-1969.

APPENDIX-A

In-process Quality Control

The quality control of the linoleum intended for export shall be done with a view to seeing that the same conforms to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act by effecting the following controls at different stages of manufacture, preservation and packing of products as laid down below together with the levels of control as set out in the Schedule appended hereto.

1. Incoming Material Control

(a) All purchase of materials meant for manufacturing/processing of the linoleum in the manufacturing/processing unit shall be against documented specification and their acceptance shall be made only after carrying out inspection and testing as per appropriate sampling plan and criteria.

(b) The accepted consignments shall be either accompanied by the supplier's test or inspection certificate corroborating the requirements of the purchase specifications in which case, occasional checks shall be conducted atleast once in 10 consignments by the manufacturer of linoleum for a particular supplier to verify the correctness of the aforesaid test or inspection certificates or the purchase materials shall be regularly inspected and tested before purchase either in a laboratory within the factory or in outside laboratory or testing house. Records of such checks of inspection and testing shall be maintained.

(c) After the inspection/test is carried out, systematic methods shall be adopted in segregating the accepted and rejected materials and in disposal of rejected materials.

2 Process/Manufacturing Control

(a) Detailed process specifications shall be laid down by the manufacturer for different processes of manufacture.

(b) Equipment, instrumentation and facilities shall be adequate to control the processes as laid down in the process specification.

(c) Adequate records shall be maintained by the manufacturer to ensure the possibility of verifying the controls exercised during the process of manufacture

3 Product Control

(a) The manufacturer shall either have his own adequate testing facilities or shall have access to such testing facilities existing elsewhere to test the product as per the specifications recognised, under section 6 of the Act ;

(b) Sampling (where required) for testing shall be based on a recorded investigation ;

(c) Adequate records in respect of tests carried out shall be regularly and systematically maintained by the manufacturer.

4. Preservation Control

(a) A detailed specification shall be laid down by the manufacturer to safeguard the product from adverse effects of weather conditions.

(b) The product shall be adequately preserved both during storage and transit to the port of shipment.

5. Packing Control

(a) The lionleum meant for export shall be packed with film or textile material as laid down in the export contract. In the absence of the same, the manufacturer shall lay down his own detailed packing specifications for the packages in accordance with the sound commercial practice duly approved by the Export Inspection Council.

(b) Unless otherwise stipulated by the buyers, all packages shall be suitably marked with the name of the manufacturer, quantity, port of shipment and sliping mark,

THE SCHEDULE

Levels of control for Linoleum

Sl. No.	Characteristics	Requirement	No. of samples to be tested	Frequency	Remarks
1.	Design and Pattern	Standard specification recognised for the purpose	Each roll/Carpet	100%	
2.	Finish	-do-	-do-	-do-	--
3.	Requirement of Hessian Backing	-do-	One sample	Per batch	
4.	Dimensions				
	(a) Width	-do-	Each roll/carpet	100%	-
	(b) Thickness	-do-	-do-	-do-	-
	(c) Length	-do-	-do-	-do-	—
5.	Colour and its pattern Uniformity	-do-	-do-	-do-	Whenever applicable
	Tests to be conducted for plain and in-laid types				
6.	Indentation Test	-do-	One	-do-	--
7.	Water Absorption	-do-	-do-	-do-	—
8.	Flexibility	-do-	-do-	-do-	—

APPENDIX-B

Consignmentwise Inspection

1. The consignment of linoleum shall be subjected to inspection and testing to ensure conformity of the same specifications recognised under section 6 of the Act.

2. In the absence of stipulation in the export contract as regards sampling and criteria of conformity, all rolls of sheet linoleums of the same type, thickness and manufactured from same batch shall be grouped together to constitute a lot.

2.1 The number of rolls to be selected at random from the lot for determining the conformity of the lot to this specification shall depend upon the size of the lot and shall be in accordance with Col. 1 and 2 of the Table given below :—

Table—Sample size and Criterion for Conformity of Sheets

No. in Rolls in the lot	No. of rolls to be selected in the sample	Permissible No. of defective rolls
1	2	3
Upto 50	3	0
51 to 150	5	0
151 to 300	8	0
301 to 500	13	0
500 to 1000	20	0
1001 and above	32	1

2.2 Criteria for Conformity.—The number of rolls/sheets selected in accordance with 2.1 shall be tested for all the requirements of this specification. A roll/sheet failing in respect of one or more of the requirements shall be called a defective roll/sheet. If the number of defective rolls/sheets in the sample is less than or equal to the corresponding permissible number given in col. 3 of the Table above, the lot shall be considered as conforming to the requirements of this specification. If the number of defective rolls/sheet be considered as not conforming to the requirements of this specification.

3. Long duration tests/type tests.—Where export contract provide for tests relating to shelf life|performance test|guarantee criteria and the test for the same cannot be performed within the stipulated period (seven days or so) samples at a frequency of one in ten consignments and tested on post-facto basis and the certification of inspection may be issued based on the past performance. However, the agencies, shall satisfy themselves that the test which will be carried out on post-facto basis has already been conducted by the exporter/maufacturer and the consignment will be allowed for export provided the tests carried out by the exporter/manufacturer meets the requirements of the export contract.

का. आ. 857:—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मैसर्स मारुति उद्योग लिमिटेड, पालम गुड़गाव रोड, गुड़गांव—122015 (हरियाणा) में विनिर्मित, उपाबंध-I और II में दिए गए मोटर गाड़ी के पुर्जों संघटकों तथा उपसाधनों का निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए मैसर्स मारुति उद्योग लिमिटेड, पालम गुड़गांव रोड, गुड़गाव—122015 (हरियाणा) को जिनका सम्मिलित कार्यालय जीवन प्रकाश, 25, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001. में है इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, अभिकरण के रूप में मान्यता देती है, अर्थात् :—

1 कि मैसर्स मारुति उद्योग लिमिटेड, पालम गुड़गाव रोड, गुड़गांव—122015 (हरियाणा) में विनिर्मित उपाबन्ध-I और II में दिए गए मोटर गाड़ी के पुर्जों संघटकों और उपसाधनों का मैसर्स मारुति उद्योग लिमिटेड, निर्यात से पूर्व निरीक्षण करेगी और वह ऐसे अधिकारी के तकनीकी नियंत्रण में किया जाएगा जो निर्यात निरीक्षण अभिकरण, दिल्ली के अपर निदेशक से कम न हो और इस प्रयोजन के लिए मैसर्स मारुति उद्योग लिमिटेड, पालम गुड़गांव रोड, गुड़गांव-122015 (हरियाणा) से निर्यात की गई वस्तुओं का पोत-पर्यन्त नि:शुल्क (फ्रि ऑन बोर्ड) मूल्य के 0.1% की दर से राशि निर्यात निरीक्षण अभिकरण, दिल्ली को देगा जो एक वर्ष में कम से कम दो हजार पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक एक लाख रुपए होगी।

2. मैसर्स मारुति उद्योग लिमिटेड इस अधिसूचना के अधीन अपने कृत्यों के पालन में ऐसे निर्देशों द्वारा आबद्ध होगा जो निदेशक (निरीक्षण और क्वालिटी नियंत्रण) समय-समय पर लिखित रूप में दें।

स्पष्टीकरण :— इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, "मोटर गाड़ी के पुर्जों संघटकों तथा उपसाधनों से" मोटर गाड़ियों और ट्रेलरों में (चाहे वे यान से संलग्न हों या न हों) प्रयुक्त विनिर्मित उत्पाद है जिसमें वे उत्पाद भी सम्मिलित है जो इस अधिसूचना के उपाबन्ध-I और-II में दिए गए मूल उत्पाद के प्रतिस्थापन पुर्जों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं।

[फाइल सं. 5(7)/88-ई.आई. एण्ड ईपी.]

उपाबंद – I

1. पिस्टन पिन
2. अन्तः दहन इंजिनों के लिए अन्तर्गम और निस्कासक वाल्व
3. नट और बोल्ट सहित संयोजक शलाका
4. पम्प ईंधन अन्तः क्षेपण के लिए इकहरे सिलेंडर
5. आटोमोबाइल विद्युत हार्न (कम्पन प्रकार के और वायु टोन प्रकार के)
6. प्रज्वलन कुण्डली
7. स्टार्टर मोटर और इसके आर्मेचर (केवल 24 वोल्ट डी सी तक)
8. स्पार्किंग प्लग
9. आटोमोबाइल डायनामों, इसके आर्मेचर और फिल्ड क्वाइल
10. हैड लाईट समुच्चय (बल्ब सहित तथा रहित)
11. आटोमोबाइल लैम्प (बल्ब)
12. धुरी शाफ्ट
13. आटोमोटिव ब्रेक अस्तरण
14. ब्रेक ड्रम
15. किंग पिन
16. पत्ती कमानी और इसकी पत्तियां
17. शैकल पिन
18. आटोमोबाईल सस्पेंशन के लिए कुंडलिनी कमानी
19. ऐमीटर
20. आटोमोटिव हाइड्रोलिक प्रघात अवशोषक
21. ब्लेडों सहित वाइपर समुच्चय तथा इसकी कमानी

उपाबंध – II

1. पिस्टन, पिस्टन रिंग, सरक्लिप,
2. क्रैंक शाफ्ट
3. कैम शाफ्ट
4. संदोलक भुजा
5. वाल्व स्प्रिंग, वाल्व गाईड, वाल्व लॉकिंग पिन, वाल्व सीट, वाल्व पुश रॉड,
6. सिलेंडर हैड, सिलेंडर ब्लाक
7. सिलेंडर के लिए लाइनर
8. क्लच समुच्चय, क्लच दाब प्लेट, क्लच फेसिंग, क्लच डिस्क, क्लच स्प्रिंग, क्लच लीवर
9. नोजल, आटोमाइजर, ऐलीमेंट फिल्टर, पम्प ऐलीमेंट, चूषण वाल्व, डिलीवरी वाल्व, गवर्नर डायाफ्राम, हस्त चालित पम्प डायाफ्राम और डिबरी पम्प ईंधन अन्तः क्षेपण के लिए निप्पल नटों सहित पाईप
10. वायु फिल्टर समुच्चय और इसके फिल्टर एलिमेंट
11. ईंधन पम्प, स्नेहक तेल पम्प, तेल फिल्टर समुच्चय, ईंधन फिल्टर समुच्चय और इसके पुर्जे
12. जल पम्प और इसके पुर्जे
13. स्पीडोमीटर तेल दाब यंत्र, ईंधन गेज, थर्मोमीटर
14. स्पीडोमीटर के लिए केबील, क्लच और ब्रेक
15. ब्रेक समुच्चय मास्टर सिलेंडर, पहिया सिलेंडर उनके पुर्जे और सुधार किट
16. कार्बुरेटर समुच्चय तथा इसके संघटक
17. रेडियेटर तथा इसके क्रोड
18. वितरक और इसके पुर्जे
19. स्टार्टर मोटर और डायनामों के लिए कार्बन ब्रुश और स्प्रिंग
20. हार्न रिले, हार्न डायाफ्राम तथा हार्न संयोजक
21. फ्लेशर यूनिट
22. वोल्टता नियामक
23. नोदक शाफ्ट
24. सर्वदिश जोड़ और इसके भाग
25. संचरण जंजीरें
26. हब
27. अग्र और पश्च स्प्रिंगों के लिए हैंगर ब्रैकिट, शैकल
28. प्रघात अवशोषक योग
29. ब्रेक बूस्टर के लिए चमड़े का वाशर, स्प्रिंग पैकिंग और संयोजक तथा सिलेंडर सुधार किट
30. बूस्टर संपीडक प्रकार हेतु पिस्टन, पिस्टन रिंग, वाल्व प्लेट और चूषण वाल्व कैप
31. अग्र धुरी को बांधने हेतु सिरे, ड्रैग सिरे, किंग पिन सुधार किट
32. रिम का पहिया और प्लेट समुच्चय
33. अवरोधी निष्कासक और उपरोधी नियंत्रक ट्यूब
34. दरवाजे के ताले
35. उत्थापन जैक
36. ग्रीस निप्पल
37. सभी प्रकार के गैस्केट
38. सभी प्रकार की तेल सील
39. सभी प्रकार के बैयरिंग
40. सभी प्रकार के गियर
41. सभी प्रकार का धातु और रबर बुशिंग
42. सभी प्रकार के कीलक अर्थात बोल्ट, स्टड, पेच रिवेटों और वाशर।

S.O. 857.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises M/s. Maruti Udyog Limited having their corporate office at Jeevan Prakash, 25, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001 as the Agency, for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette for inspection of automobile spares, components and accessories manufactured at M/s. Maruti Udyog Limited, Palam Gurgaon Road, Gurgaon 122015 (Haryana) prior to export subject to the following conditions, namely :—

1. That M/s. Maruti Udyog Limited shall carryout the inspection of automobile spares, components and accessories as per annexure-I and II manufactured at M/s. Maruti Udyog Limited, Palam Gurgaon Road, Gurgaon-122015 Haryana) prior to export under the technical control of an officer not below the rank of Additional Director of the Export Inspection Agency, Delhi and for this purpose M/s. Maruti Udyog Limited shall pay to the Export Inspection Agency, Delhi an amount at the rate of

0.1 per cent of the F.O.B. (free on board) value of the items exported from their unit at M/s. Maruti Udyog Limited, Palam Gurgaon Road, Gurgaon-122015 (Haryana) subject to a minimum of rupees two thousand five hundred and maximum of rupees one lakh in a year.

2. M/s. Maruti Udyog Limited in the performance of its functions under this notification shall be bound by such direction as the Director (Inspection and Quality Control) may give to it in writing from time to time.

Explanation.—For the purpose of this notification 'automobile spares, components and accessories' means the manufactured products used in automobiles and trailers (whether attached to the vehicle or not) including that used as a replacement part for the original product given in Annexure-I and II of this Notification.

[F. No. 5(7)|88-FI&EP]

ANNEXURE-I

1. Piston Pin.
2. Inlet and exhaust valves for internal combustion engines.
3. Connecting rod including its nuts and bolts.
4. Single cylinder fuel injection pump.
5. Automobile electric horn (vibrating type and wind tone type).
6. Ignition coil.
7. Started motor and its armature (upto 24 volts D.C. only).
8. Sparking plug.
9. Automobile dynamo, its armature and field coils.
10. Head Light Assembly (with or without bulb).
11. Automobile lamp (bulb).
12. Axle shaft.
13. Automotive brake lining.
14. Brake drum.
15. King pin.
16. Leaf spring and its leaves.
17. Shackle pin.
18. Helical spring for automobile suspension.
19. Ammeter.
20. Automotive Hydraulic shock absorber.
21. Wiper assembly including its arm and blade.

ANNEXURE-II

1. Piston, Piston rings, Circlips.
2. Crankshaft.
3. Camshaft.
4. Rocker arm.
5. Valve Springs, Valve guides, Valve locking pins, Valves seat, Valve push rod.
6. Cylinder head, Cylinder block.
7. Liners for cylinder.
8. Clutch assembly, Clutch pressure plate, clutch facing, Clutch disc, Clutch spring, Clutch levers.
9. Nozzels, Automiser, Filter elements, Pumps elements, Suction Valves, Delivery valve, Governor diaphragm, hand priming pump diapharagm and pipes with nuts, nipples for fuel, injection pump.
10. Air filter assembly and its filter elements.
11. Fuel pump, lubricating oil pump, oil filter assembly, Fuel filter assembly and their parts.
12. Speedometer oil pressure gauge, Fuel gauge, Thermometers.
13. Cables for speedometer clutch and Brake.
14. Water Pumps, including its parts.
15. Brake assembly, Master Cylinder, Wheel Cylinder, their parts and repairs kits, Brake springs.
16. Carburettor assembly and its components.
17. Radiator and its core.
18. Distributor and its parts.
19. Carbon brushes and springs, for starter Motor and Dynamo.
20. Horn relay, Horn diaphragm and Horn contact.
21. Flasher units.
22. Voltage regulator.
23. Propeller shaft.
24. Universal joint and its parts
25. Transmission chains.
26. Hubs.
27. Hanger Brackets, Shackles for front and rear spring.
28. Shock absorber link.
29. Leather washer, springs, packings and Connections and Cylinder repair kit for Brake Booster.
30. Piston, Piston rings, valve disc and Suction valve cap for Booster compressor type.
31. Front exle tie rod ends, Drag link ends, King pin repair kit.
32. Wheel rim and disc assembly.
33. Throttle control and Throttle control tube.
34. Dear Locks.
35. Lifting jacks.
36. Grease nipples.
37. All types of Gaskets.
38. All types of oil seals.
39. All types of bearings.
40. All types of gears.
41. All types of metal and rubber bushings.
42. All types of fasteners i.e. bolts, studs, screws, nuts and washers.

का. आ. 858—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स जे. बी. बोडा, सर्वेयर्स प्रा. लिमिटेड, एम. एम. एम. बिल्डिंग, नं० 5, वालाजा रोड, मद्रास-600002 को इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिज तथा अयस्क ग्रुप-II के निर्यात के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए इन शर्तों के अधीन अभिकरण के रूप में मान्यता देती है और अभिकरण मैंगनीज तथा अयस्क ग्रुप-II के निर्यात (निरीक्षण) (नियम, 1965 के नियम 4 के उप नियम (4) के अंतर्गत निर्यात निरीक्षण परिषद/अभिकरण द्वारा अपनाई गई निरीक्षण पद्धति की जांच करने के लिए इस संबंध में मद्रास में नामित किसी भी अधिकारी को निरीक्षण प्रमाण-पत्र देने के लिए पर्याप्त सुविधाएं देगा।

अनुसूची

1. मैंगनीज डायक्साईड
2. क्रोम अयस्क, क्रोम चूर्ण सहित
3. बाक्साइट
4. सिलिमेनाइट

5. संकेन्द्रित जिंक सहित कच्चा जिंक
6. परिदग्ध और निस्तप्त मैगनेसाइट सहित मैगनेसाइट
7. बैराईटिस
8. लाल आक्साईड
9. पीला गैरिक
10. सेलखड़ी
11. स्फतीय (फेल्डस्पार)

[फाइल सं. 5(15)/88–ई आई एण्ड ई पी]

S.O. 858.—In exercise of the powers conferred by sub-section 1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a period of one year from the date of publication of this notification M/s. J. B. Boda Surveyors Private Ltd., M.L.M. Bldg., No. 5 Wallahjah Road, Madras-600002 as an agency for the inspection of the Minerals and Ores Group-II specified in schedule annexed hereto prior to export at Madras subject to the condition that the said agency shall give adequate facilities to any officer nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by the said agency in granting the certificate of inspection under sub-rule (4) of rule 4 of the Export of Minerals and Ores Group-II (Inspection) Rules, 1965.

SCHEDULE

1. Manganese Dioxide.
2. Chrome ore, including chrome concentrates.
3. Kyanite.
4. Sillimanite.
5. Zinc ores, including zinc concentrates.
6. Magnesite, including dead-burnt and calcined magnesite.
7. Barytes.
8. Red Oxide.
9. Yellow Ochre.
10. Steatite.
11. Feldspar.

[File No. 5(15)/88-EI&EP]

का० आ० 859—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स जे० बी० बोडा सर्वेयर्स प्रा० लि०, मेकर भवन नं० 1, सर विठ्ठलदास ठाकरसे मार्ग, बम्बई-400 020 को उससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिज तथा अयस्क के निरीक्षण के लिए इस अनुसूची के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए इन शर्तों के अधीन अभिकरण के रूप में मान्यता देती है और अभिकरण मैगनीज तथा अयस्क के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 के उप नियम (4) के अंतर्गत निर्यात निरीक्षण परिषद/अभिकरण द्वारा अपनाई गई निरीक्षण पद्धति की जांच करने के लिए इस संबंध में बम्बई नामित किसी भी अधिकारी को निरीक्षण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं देगा।

अनुसूची

1. फेरोमैगनीज के धातुमल सहित फेरोमैगनीज
2. निस्तप्त बोक्साइड सहित बोक्साइड
3. मैगनीज डायक्साइड
4. कायनाइट
5. सिलिमेनाइट
6. संकेन्द्रित जिंक सहित कच्चा जिंक
7. परिदग्ध और निस्तप्त मैगनेसाइट सहित मैगनेसाइट
8. बैराइटिस
9. लाल आक्साइड
10. पीला गैरिक
11. सेलखड़ी
12. स्फतीय (फेल्डस्पार)

[फाइल सं० 5(15)/88-ई० आई० एड ई० पी०]

S.O. 859.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a period of one year from the date of publication of this notification M/s. J. B. Boda Surveyors Private Limited Maker Bhawan No. 1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Bombay-400020 as an agency for the inspection of the Minerals and Ores specified in schedule annexed hereto prior to export at Bombay subject to the condition that the said agency shall give adequate facilities to any officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by the said agency in granting the certificate of inspection under sub-rule (4) of rule 4 of the Export of Minerals and Ores (Inspection) Rules, 1965.

SCHEDULE

1. Ferromanganese, including ferromanganese slag.
2. Bauxite, including calcined bauxite.
3. Manganese Dioxide (other than natural)
4. Kyanite.
5. Sillimanite.
6. Zinc Ores, including Zinc concentrates.
7. Magnesite, including dead burnt and calcined magnesite.
8. Barytes.
9. Red Oxide.
10. Yellow Ochre.
11. Steatite.
12. Feldspar.

[File No. 5(15)/88-EI&EP]

का. आ. 860.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते, मैसर्स जे. बी. बोडा सर्वेयर्स प्रा. लि., मेकर भवन नं. 1, एस. वी. ठाकरसे मार्ग, बम्बई-400 020 को इसमें उपाबद्ध अनुसूची-I तथा II में विनिर्दिष्ट कार्बनिक रसायनों तथा अकार्बनिक रसायनों के निरीक्षण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए इन शर्तों के अधीन अभिकरण के रूप में मान्यता देती है और अभिकरण कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायनों के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 के नियम 4 के उप नियम (4) के अंतर्गत निर्यात निरीक्षण परिषद/अभिकरण द्वारा अपनाई गई निरीक्षण पद्धति की जांच करने के लिए इस संबंध में बम्बई में नामित किसी भी अधिकारी का निरीक्षण प्रमाण पत्र जारी करने लिए पर्याप्त सुविधाएं देगा।

अनुसूची - I

1. एसिटिक एसिड,
2. हाईड्रोक्वीनोन,
3. ऑक्जेलिक एसिड,
4. बैनजीन,
5. एथिल एल्कोहल,
6. आइनिन,
7. सोडियम सार्इट्रेट।

अनुसूची - II

1. सोडियम डाइक्रोमेट,
2. सोडियम सल्फेट,
3. मैंगनीज डायक्साइड (प्राकृतिक से अलग)
4. हाईड्रोक्लोरिक ऐसिड
5. कापर सल्फेट,
6. सोडियम कार्बोनेट,
7. फैरिक एल्यूम,
8. एल्यूमिनियम सल्फेट, (नोन फैरिक)
9. अमोनियम क्लोराईड
10. पोटाशियम डाइक्रोमेट
11. मैंगनीज सल्फेट
12. सोडियम डाईकार्बोनेट,
13. एल्यूमिनो फैरिक,
14. एल्यूमिनियम क्लोराईड
15. बैरियम क्लोराइड,
16. कैल्शियम कार्बोनेट
17. पोटाशियम परमैंगनेट
18. जिंक सल्फेट
19. अमोनियम एल्यूमिनियम,
20. पोटाश एल्यूम,
21. एल्यूमिनियम ऑक्साईड
22. ब्लीचिंग पाउडर
23. बोरेक्स
24. कास्टिक सोडा,
25. कास्टिक पोटाश,
26. पोटाशियम कार्बोनेट,
27. पोटाशियम क्लोरेट,
28. सोडियम सिलिकेट,
29. सोडियम हाईड्रो सल्फेट।

[फाइल सं. 5 (15)/88-ई आई एंड ई पी]

ए. के. चौधरी, निदेशक

S.O. 860.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a period of one year from the date of publication of this notification M/s. J. B. Boda Surveyors Private Ltd., Maker Bhawan No. 1, S. V. Thackersey Marg, Bombay-400020 as an agency for the inspection of the Organic Chemicals and Inorganic Chemicals specified in schedule-I and Schedule-II annexed hereto prior to their export at Bombay subject to the condition that the said agency shall give adequate facilities to any officer nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by the said agency in granting the certificate of inspection under sub-rule (4) of rule 4 of the Export of Organic and Inorganic Chemicals (Inspection) Rules, 1966.

SCHEDULE-I

1. Acetic acid,
2. Hydroquinone,
3. Oxalic acid,
4. Benzene,
5. Ethyl Alcohol,
6. Xylene,
7. Sodium Citrate,

SCHEDULE-II

1. Sodium Dichromate
2. Sodium Sulphate
3. Manganese Dioxide other than natural)
4. Hydrochloric Acid
5. Copper Sulphate
6. Sodium Carbonate
7. Ferric Alum
8. Aluminium Sulphate (non-ferric)
9. Ammonium Chloride
10. Potassium Dichromate
11. Manganese Sulphate
12. Sodium Dicarbonate
13. Alumino Ferric
14. Aluminium Chloride
15. Barium Chloride
16. Calcium Carbonate
17. Potassium Permanganate
18. Zinc Sulphate
19. Ammonium Alum
20. Potash Alum
21. Aluminium Oxide
22. Bleaching Powders
23. Borax
24. Caustic Soda
25. Caustic Potash
26. Potassium Carbonate
27. Potassium Chlorate
28. Sodium Silicate
29. Sodium Hydro Sulphate.

[F. No. 5(15)/88-EI&EP]

A. K. CHAUDHURI, Director

उद्योग मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग)

नई दिल्ली, 17 मार्च 1989

का० आ० 861—पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अधिग्रहण), अधिनियम 1962 (1962 का 50) के खंड 2 की धारा (अ) का अनुपालन करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित अनुसूची के कालम (1) में उल्लिखित प्राधिकारी को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह उक्त अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची के कालम (3) में प्रविष्ट क्षेत्रों में सक्षम अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

अनुसूची

व्यक्ति का नाम	पता	क्षेत्रीय सीमा
(1)	(2)	(3)
श्री डी एन टारे	:—इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० महाराष्ट्र गैस क्रेकर काम डिविजन, जुहू विले पार्ले डिवलपमेन्ट स्कीम कार्मशियल कांपलैक्स यूनिट नं 1 ब्लाक बी- गुलमुहर क्रास रोड नं 9, विले पार्ले (पश्चिम) बम्बई-400049	महाराष्ट्र प्रदेश

[फाइल संख्या 34027/1/87-पी सी III (पी टी)]

एस के गुप्ता, डेस्क आफीसर

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

New Delhi, the 17th March, 1989

S.O. 861.—In pursuance of Clause (a) of Section 2 of the Petrochemicals and Minerals (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby authorises the Authority mentioned in Column (1) of the Schedule below to perform the function of the Competent Authority under the said Act, within the areas mentioned in the corresponding entry in the column (3) of the said Schedule.

SCHEDULE

Name of Person	Address	Territorial Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
Shri D.N. Tare	Indian Petrochemicals Corpn. Limited, Maharashtra Gas Cracker Complex Division, Juhu-Vileparle Development Scheme, Commercial Complex, Unit No. 1, Block B, Gulmohar Cross Road No. 9. Vile Parle (W), Bombay-400 049.	State of Maharashtra

[F. No. 34027/1/87-PC III(PT)]
S.K. GUPTA Desk Officer

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1989

का.आ. 862:—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कोरस (इन्डिया) लि., जिसका पंजीकृत कार्यालय कोरस हाऊस, पो.बा. नं. 6558, आफ डा. ई. मोसिस रोड, वोरली, बम्बई-400018 में है, के पंजीकरण के / निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है, क्योंकि उक्त उपक्रम ऐसे उपक्रमों में से है जिन पर उक्त अधिनियम के भाग "क" अध्याय-III के उपबन्ध अब लागू नहीं होते है। (पंजीकरण संख्या 2292/85)

[सं. 16/9/89-एम -3]

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 20th March, 1989

S.O. 862.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Kores (India) Limited having its registered office at Kores House, Post Box No. 6558, Off. Dr. E. Moses Road, Korli, Bombay-400018 the said undertaking being undertaking to which the provisions of Part A Chapter III of the said Act no longer apply. (Registration No. 2292/85)

[No. 16/9/89-M. III]

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1989

का.आ. 863:—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना के अनुलग्नक में उल्लिखित उपक्रमों के पंजीकरण के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है, क्योंकि उक्त उपक्रम ऐसे उपक्रमों में से है जिन पर उक्त अधिनियम के अध्याय-3 के भाग क अध्याय के उपबन्ध अब लागू नहीं होते हैं।

एम.-3 का अनुलग्नक

क्रम संख्या	उपक्रम का नाम	पंजीकृत कार्यालय	पंजीकरण संख्या
1.	मैसर्स वी.एस. डेम्पो एंड कंपनी लिमिटेड	डेम्पो हाऊस, कम्पाल, पणजी-403001	957/74
2.	मैसर्स नवहिंद पेपर्स एंड पब्लिकेशन्स, लिमिटेड	--यथोपरि--	953/74
3.	मैसर्स वैस्ट कोस्ट होटल्स लि.,	--यथोपरि--	952/74
4	मैसर्स डेम्पो मन्ग प्राइवेट लि.,	--यथोपरि--	948/74
5	मैसर्स डेम्पो इंजीनियरिंग वर्क्स, लि.,	--यथोपरि--	947/74
6.	मैसर्स जुआरी रीयल एस्टेट्स, कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	रुओ अफोन्सो, डी. अल्बूकर्क पणजी, गोआ	951/74
7.	मैसर्स मिनरो एस्टेट्स प्रा. लि.,	--यथोपरि--	954/74
8.	मैसर्स डेम्पो मार्केटिंग कारपोरेशन, प्रा. लि.,	डेम्पो हाउस, पी.बी.नं. 166 पणजी-403001, गोआ	946/74
9.	मैसर्स डेम्पो ट्रेडर्स प्रा.लि.,	पोस्ट बाक्स नं. 84, मोती महल, जे टाटा मार्ग, चर्चगेट, बम्बई-400020	955/74

[सं. 16/9/89-एम.-3]
एस.बी. सिंह, उप सचिव

New Delhi, the 28th March, 1989

S.O. 863.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of the undertakings mentioned in the Annexure of this notification, the said undertakings being undertakings to which the provisions of Part A Chapter III of the said Act no longer apply.

ANNEXURE TO M-III

Sl. No.	Name of the Undertaking	Registered Office	Registration No.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	M/s. V.S. Dempo & Co. Limited.	Dempo House, Campal, Panaji-403 001, Goa.	957/74.
2.	M/s. Navhind Papers & Publications Limited.	Dempo House, Campal, Panajim-Goa.	953/74.
3.	M/s. West Coast Hotels Limited.	Dempo House, Campal, Panajim-Goa.	952/74.

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	M/s. Dempo Sons Pvt. Limited.	Dempo House, Campal, Panaji-403 001 Goa.	948/74.
5.	M/s. Dempo Engineering Works Limited. (Shipbuilders, Ship-repairers & Engineers)	Dempo House, Campal, Panaji-403 001 Goa.	947/74.
6.	M/s. Zuari Real Estate Co. Pvt. Limited.	Rua Afonso De Albuquerque, Panajim, Goa.	951/74.
7.	M/s. Siridao Estates Pvt. Limited.	Rua Afonso De Albuquerque, Panajim, Goa.	954/74.
8.	M/s. Demo Mining Corpn. Pvt. Limited.	Dempo House, Campal, Post Box No. 166, Panaji-403 001. Goa.	946/74.
9.	M/s. Dempo Brothers Pvt. Limited.	Post Box No. 84, "Moti Mahal", J. Tata Road, Churchgate, Bombay-400 020.	955/74.

[No. 16/9/89-M. III]

S. B. SINGH, Dy. Secy.

खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1989

शुद्धि पत्र

का.आ. 864.—भारत के राजपत्र के भाग 2 खण्ड 3(ii) में का.आ. संख्या 2209 के रूप में 2 जुलाई, 1977 को प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना, दिनांक 6-6-1977 में निम्नलिखित शुद्धियां की जाएं :

आदेश में क्रम सं.	की जाने वाली शुद्धि
34	स्तम्भ-2 में "कृष्ण चन्द" के स्थान पर "किशन चन्द" पढ़ें।

[संख्या 52/21/68-एफ.सी.-3 (भाग 7)]

ओ.पी. गुप्त, अवर सचिव

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Food)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 7th February, 1989

S.O. 864.—The following correction shall be made in this Department's Notification dated 6-6-1977 published as S.O. No. 2209 in Part II Section 3(ii) in the Gazette of India dated 2nd July, 1977 :—

S. No. in the order	Correction to be carried out
34	For the words "Krishan Chand" in Col.2, read "Kishan Chand".

[No. 52/21/68 F.C. III (Vol. VII]

O. P. GUPTA, Under Secy.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1989

का.आ. 865.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 1576 तारीख 6-5-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

नोर्थ कड़ी सी.टी.एफ. से सरखेज तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : दशक्रोई

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर	सेंटीयर
फतेवाड़ी	393	0	12	40
	394	0	11	00
	396	0	00	45
	395	0	23	20
	398	0	11	60
	400	0	12	15
	399	0	03	45
	336	0	09	40
	339	0	29	40
	534	0	01	45

[सं. ओ-11027/111/88-ओ एन जी-डी-III]

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 16th March, 1989

S.O. 865.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 1576 dated 6-5-88 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of

Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared it's intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM NORTH KADI CTF TO SARKHEJ.

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Dascroi

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Cen-tiare
1	2	3	4	5
Fatevadi	393	0	12	40
	394	0	11	00
	396	0	06	45
	395	0	23	20
	398	0	11	60
	400	0	12	15
	399	0	03	45
	336	0	09	40
	339	0	29	40
	534	0	01	45

[No. O-11027/111/88-ONG-D-III]

का.आ. 866.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में इलाव-2 से एस डब्ल्यू एम बी तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्‌पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्‌द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एलाव-2 से एस डब्ल्यू एम बी तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : हांसोट

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टर	आर	सेंटीयर
अनीयारडा	117	00	14	95

[सं. ओ-11027/34/89-ओ एन जी-डी-III]

S.O. 866.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from ELLAV-2 to SWMB in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquired that right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-(390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM ELLAV-2 TO SWMB

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Hansot

Village	Block No.	Hect-are	Are	Cen-tiare
1	2	3	4	5
Aniyarda	117	00	14	95

[No. O-11027/34/89-ONG-D-III]

का.आ. 867.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जालोरा जी जी एस I से जंक्शन पाइन्ट तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्‌पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्‌द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत।

अनुसूची

झालोरा जी.जी.एस. 1 से जंक्शन बिन्दु तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कडी

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
मेरडा	290/1	0	28	05
	290	0	07	05
	283	0	02	10
	284/पी	0	16	85
	265/1	0	00	50
	264	0	05	25
	263	0	05	25
	262/1	0	07	20
	कार्ट ट्रैक	0	00	90
	259	0	09	90
	258	0	02	60
	257	0	08	65
	11/पी	0	22	05
	12	0	03	00
	14	0	04	95
	13	0	10	20
	56	0	04	13
	59	0	14	47
	57	0	05	70
	58	0	01	80
	61	0	07	95
	68	0	17	80
	70/1	0	06	00
	70/2	0	04	50
	71	0	04	95
	207	0	14	85
	198	0	05	40
	197	0	01	35

[सं. ओ. 11027/36/89-ओ एन जी-डी-III]

S.O. 867.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Zalora G.G.S.I to Jr. Point in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-(390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM ZALORA GGS I TO JN. POINT.

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Cen-tiare
1	2	3	4	5
Merda	290/1	0	28	05
	290	0	07	05
	283	0	02	10
	284/P	0	16	85
	265/1	0	00	50
	264	0	05	25
	263	0	05	25
	262/1	0	07	20
	Cart track	0	00	90
	259	0	09	90
	258	0	02	60
	257	0	08	65
	11/P	0	22	05
	12	0	03	00
	14	0	04	95
	13	0	10	20
	56	0	04	13
	59	0	14	47
	57	0	05	70
	58	0	01	80
	61	0	07	95
	68	0	17	80
	70/1	0	06	00
	70/2	0	04	50
	71	0	04	95
	207	0	14	85
	198	9	05	40
	197	0	01	35

[No. O-11027/36/89-ONG-D-III]

का.आ. 868.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कलोल-2 से एस. डब्ल्यू.एस.बी. तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एलाव-2 से एस डब्ल्यू एम बी तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका: हांसोट

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टयर	आर	सेंटीयर
सुनेव खर्द	117	0	03	90

[सं. ओ.-11027/33/89-ओ एन जी-डी-III]

S.O. 868.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from ELLAV-2 to SWMB in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-(390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner

SCHEDULE

PIPELINE FROM ELLAV-2 TO SWMB.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Hansot

Village	Block No.	Hect-are	Are	Cen-tiare
Sunev Khurd	117	0	03	90

[No. O-11027/33/89-ONG-D.III]

का.आ.सं. 869.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जालोरा जी जी एस-1 से जंक्शन पाइंट तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्‌पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्‌द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत।

अनुसूची

जालोरा-1 से जंक्शन बिन्दु तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कड़ी

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
लक्ष्मनपुरा	461	0	12	75
	458	0	11	25
	457	0	18	75
	183	0	09	00
	185	0	27	00
	186/4	0	00	30
	186/3	0	11	55
	186/2	0	14	40
	186/1/पी	0	05	55
	186/1/पी	0	14	25
	187	0	41	00
	200	0	00	20
	196	0	00	20
	194	0	09	00

[सं. ओ.-11027/35/89-ओ एन जी-डी-III]

S.O. 869.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Zalora GGSI to Jr. Point in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-(390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner

SCHEDULE

PIPELINE FROM ZALORA GGS I TO JN. POINT

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Cen-tiare
1	2	3	4	5
Laxmanpura	461	0	12	75
	458	0	11	25
	457	0	18	75
	183	0	09	00
	185	0	27	00
	186/4	0	00	30
	186/3	0	11	55
	186/2	0	14	40
	186/1/P	0	05	55
	186/1/P	0	14	25
	187	0	41	00
	200	0	00	20
	196	0	00	20
	194	0	09	00

[No. O 11027/35/89-ONG-D.-III]

नई दिल्ली 28 मार्च, 1989

का.आ. सं. 870.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में के 27 से के० जी.जी एस. तक पैट्रोलिय के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

के-27 से के.जी.जी.एस. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : खेड़ा तालुका : बोरसद

गांव	सर्वे न.	हैक्टेयर	आर.	सेंटीयर
कंकापुरा	569/1 तथा 2	0	03	10
	576	0	06	00
	578	0	07	45
देवान	566/पी	0	05	70
	568/1	0	08	20

[सं. ओ.-11027/31/89-ओ एन जी डी.-III]

New Delhi, the 28th March, 1989

S.O. 870.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from K-27 to KGGS in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-(390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM K-27 TO K GGS

State : Gujarat Distt. : Kheda Taluka : Borsad

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Cen-tiare
1	2	3	4	5
Kankapura	569/1&2	0	03	10
	576	0	06	00
	578	0	07	45
Devan	566/P	0	05	70
	568/1	0	08	20

[No. O-11027/31/89-ONG-D-III]

का.आ.सं. 871.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एनाथ-2 से एम. डब्ल्यू.एम.बी. तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत

अनुसूची

ऐलावव-2 से एस.डब्ल्यू.एम.बी. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : हासोट

गांव	सर्वे न.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
बालोटा	695	0	02	60

[सं. ओ-11027/22/89-ओ एन जी-डी-III]

S.O. 871.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from ELLAV-2 to SWMB in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-(390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM ELAV-2 TO SWMB.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Hasot

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Balota	695	0	02	60

[No. O 11027/22/89-ONG-D-III]

का.आ. 872—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कलोल नवागाम से कोयाली फेस-II तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

कलोल-नवागाम-कोयाली फेस II की पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : खेड़ा तालुका : मातर

गांव	सर्वे. नंबर	हेक्टर	आर.	सेंटीयर
कठवाड़ा	463	0	40	00
	464	0	32	00
	465	0	12	20

[सं. ओ-11027/23/89-ओ एन जी-डी-III]

S.O. 872.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Kalol-Nawagaon to Koyali Phase-II in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-(390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

PMIPELINE FROM K.N.K. PHASE II.

State: Gujarat District : Kheda Taluka : Matar

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Karhawada	463	0	40	00
	464	0	32	00
	465	0	12	20

[No. O-11027/23/89-ONG.D.-III]

का.आ. 873—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में वासखेड़ा से रिलायन्स इन्डस्ट्रीज तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

चांदखेड़ा से रिलायन्स इण्डस्ट्रीज तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : दसक्रोई

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
मुठीया	100	0	08	50

[सं. ओ.-11027/24/89-ओ एन जी डी-III]

S.O. 873.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Chand Kheda to Reliance Ind. in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-(390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM CHANDKHEDA TO RELIANCE INDUSTRIES

State : Gujarat Distt. Amadavad Taluka : Dascroi

Village	Block No.	Hect are	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Muthiya	100	0	08	50

[No.O -11027/24/89-ONG-D-III]

का.आ. सं. 874.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जालोरा जी जी एस-I से जंक्शन बिन्दु तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

जालोरा जी.जी.एस.-1 से जंक्शन बिन्दु तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कड़ी

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
बावलु	1146	0	07	00

[सं. ओ.-11027/21/89-ओ. एन. जी.-डी-III]

S.O. 874.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Zalora GGSI to Jnt. Point in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquired that right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-(390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM ZALORA GGS I TO JN. POINT.

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No	Hect-are	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Bavlu	1146	0	07	00

[No. O- 11027/21/89-ONG-D-III]

का.आ. 875.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में नाडा-1 से गंधार-10 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

नाडा-1 से गंधार-10 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : जम्बुसर

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
नाडा	1513	0	09	30
	1469	0	18	30
	1468	0	00	72
	1228	0	15	75
	1210	0	03	90
	1211	0	04	35
	1214	0	08	40
	1215	0	08	40
	1213	0	00	12
	1198	0	13	50
	1208	0	00	90
	1205	0	03	72
	1206	0	09	00
	1207	0	04	73
	1199	0	00	40
	1200	0	04	50
	1201	0	04	80
	1179	0	07	50
	1640	0	11	35
	1178	0	00	10
	894	0	03	45
	893	0	02	10
	892	0	01	20
	891	0	01	50
	890	0	03	75
	889	0	03	45
	887	0	07	50
	888	0	04	50
	928	0	20	25
1	2	3	4	5
	929	0	00	20
	932	0	09	00
	930	0	11	10
	895	0	00	10
	896	0	08	55
	906	0	09	60
	907	0	04	50
	908	0	15	45
	910	0	13	95
	912	0	00	20
	911	0	03	00
	913	0	01	50
	914	0	01	15
	915	0	00	50
	916	0	01	60
	917	0	03	45
	918	0	03	30
	922	0	05	70
	926	0	08	55
	927	0	06	60
	712	0	04	50
	713	0	00	85
	711	0	05	25
	710	0	02	65
	709	0	15	75
	707	0	00	20
	706	0	11	55
	705	0	00	40
	703	0	09	75
	702	0	11	40
	680	0	04	50

[सं. ओ.-11027/28/89-ओ एन जी-डी-III]

S.O. 875.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from NADA-1 to GANDHAR-10 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-(390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM NADA 1 TO GANDHAR-10

State : Gujarat Distt. Bharuch Taluka : Jambusar

Village	Block No.	Hect-are	Are	Cen-tiare
1	2	3	4	5
Nada	1513	0	09	30
	1469	0	18	30
	1468	0	00	72
	1228	0	15	75
	1210	0	03	90
	1211	0	04	35
	1214	0	08	40
	1215	0	08	40
	1213	0	00	12
	1198	0	13	50
	1208	0	00	90
	1205	0	03	72
	1206	0	09	00
	1207	0	04	73
	1199	0	00	40
	1200	0	04	50
	1201	0	04	80
	1179	0	07	50
	1640	0	11	35
	1178	0	00	10
	894	0	03	45
	893	0	02	10
	892	0	01	20
	891	0	01	50
	890	0	03	75
	889	0	03	45
	887	0	07	50
	888	0	04	50
	928	0	20	25
	929	0	00	20
	932	0	09	00
	930	0	11	10
	895	0	00	10
	896	0	08	55
	906	0	09	60
	907	0	04	50
	908	0	15	45
	910	0	13	95
	912	0	00	20
	911	0	03	00
	913	0	01	50
	914	0	01	15
	915	0	00	50
	916	0	01	60
	917	0	03	45
	918	0	03	30
	922	0	05	70
	926	0	08	55
	927	0	06	60
	712	0	04	50
	713	0	00	85
	711	0	05	25
	710	0	02	65
	709	0	15	75
	707	0	00	20
	706	0	11	55
	705	0	00	40
	703	0	09	75
	702	0	11	40
	680	0	04	50

[No O-11027/28/89-ONG-D-III]

का. आ. 876.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में नाडा-1 से गंधार-10 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए। और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत

अनुसूची

नाडा—1 से गंधार—10 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य: गुजरात जिला : भरूच तालुका : जंबुसर

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आर	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
टंकारी	342	0	93	30
	341	0	09	00
	328	0	31	80
	309	0	20	55
	306	0	01	17
	305	0	01	00
	304	0	02	20
	303	0	01	20
	302	0	02	25
	301	0	01	50
	300	0	01	50
	299	0	03	00
	291	0	02	85
	292	0	15	75
	275	0	02	00
	276	0	18	18
	274	0	00	40
	277	0	35	70
	278	0	00	40
	197	0	03	00
	196	0	03	45
	195	0	03	90
	200	0	02	55
	185	0	03	90
	181	0	25	90
	182	0	04	25
	176	0	13	50

1	2	3	4	5
	148	0	17	25
	147	0	03	15
	146	0	03	30
	145	0	03	45
	144	0	03	30
	2425	3	06	00

[सं. ओ. 11027/29/89—ओ एन-जी डी-III]

S.O. 876.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from NADA-1 to GANDHAR-10 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-(390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM NADA-1 TO GANDHAR-10

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Jambusar

Village	Block No.	Hect-are	Are	Cen-tiare
1	2	3	4	5
Tankari	342	0	93	30
	341	0	09	00
	328	0	31	80
	309	0	02	55
	306	0	01	17
	305	0	01	00
	304	0	02	20
	303	0	01	20
	302	0	02	25
	301	0	01	50
	300	0	01	50
	299	0	03	00
	291	0	02	85
	292	0	15	75
	275	0	02	00
	276	0	18	25
	274	0	00	40
	277	0	35	70
	278	0	00	40
	197	0	03	00
	196	0	03	45
	195	0	03	90
	200	0	02	55
	185	0	03	90
	181	0	25	90

1	2	3	4	5
	182	0	04	25
	176	0	13	50
	148	0	17	25
	147	0	03	15
	146	0	03	30
	145	0	03	45
	144	0	03	30
	2425	3	06	00

[No. O-11027/28/89—O.N.G. D.III]

का. आ. 877.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3486 तारीख 10-11-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है। कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जे. एन. ए. ड्यू. से टी. जिंदु तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : जंबुसर

गांव	ब्लाक नं.	हैक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
कुम्बाल	9	0	03	60
	7	0	05	70

[सं. ओ. 11027/22/88—ओ एन जी–डी-III]

S.O. 877.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 3486 dated 10-11-88 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared it's intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification ;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM GNAQ TO T POINT

State : Gujrat Distt. : Bharuch Talukia : Jambusar

Village	Block No.	Hect-are	Are	Cen-tiare
1	2	3	4	5
Kundal	9	0	03	60
	7	0	05	70

[No. O -11027/22/88-O.N.G.-D.-III]

का. आ. 878--यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3485 तारीख 10-11-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

जे. ऐस. ते. क्यू. से टी. बिन्दु तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला :- भरुच तालुका :- - जंबुसर

गांव	ब्लोक सं.	हेक्टेयर	आर	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
मगनाद	253	0	15	00
	258	0	06	00
	259	0	03	90
	260	0	04	20
	265	0	07	80
	266	0	00	16
	268	0	09	90
	269	0	02	70
	270	0	03	30
	271	0	10	56
	220	0	25	20
	274	0	02	70
	276	0	07	80
	277	0	09	90
	278	0	05	70
	281	0	09	30
	282	0	08	97
	280	0	05	65
	283	0	06	24
	293	0	06	96
	294	0	09	60
	292	0	00	08
	291	0	21	84
	288	0	01	36
	290	0	05	70
	289	0	11	40
	360	0	08	00
	359	0	07	98
	358	0	08	10
	362	0	00	06
	366	0	10	20
	367	0	06	90
	365	0	04	35
	369	0	05	45
	368	0	19	65
	375	0	05	15
	380	0	12	60
	381	0	02	08
	388/ए	0	07	20
	388/बी	0	04	02
	389/ए	0	02	21
	392	0	11	60
	393	0	28	80
	396/बी	0	01	80
	267	0	02	50
	287	0	00	50

[सं. ओ.-11027/23/88-ओ.एन.जी.-डी.-II

S.O. 878.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 3485 dated 10-11-88 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Government declared its intention to acquire the right of Government declared it's intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM GANQ TO T POINT

State : Gujarat Distt. Bharuch Taluka : Jambusar

Village	Block No.	Hect-are	Are	Cen-tiare
1	2	3	4	5
Magnad	253	0	15	00
	258	0	06	00
	259	0	03	90
	260	0	04	20
	265	0	07	80
	266	0	00	16
	268	0	09	90
	269	0	02	70
	270	0	03	30
	271	0	10	56
	220	0	25	20
	274	0	02	70
	276	0	07	80
	277	0	09	90
	278	0	05	70
	281	0	09	30
	282	0	08	97
	280	0	05	65
	283	0	06	24
	293	0	06	96
	294	0	09	60
	292	0	00	08
	291	0	21	84
	288	0	01	36
	290	0	05	70
	289	0	11	40
	360	0	08	00
	359	0	07	98
	358	0	08	10
	362	0	00	06
	366	0	10	20
	367	0	06	90
	365	0	04	35
	369	0	05	45
	368	0	19	55
	375	0	05	15
	380	0	12	60
	381	0	02	00
Magnad (Contd.)	388/A	0	07	20
	388/B	0	0,	02
	389/A	0	02	24
	392	0	11	60
	393	0	28	80
	396/B	0	01	80
	267	0	02	50
	287	0	00	50

[No. O-11027/23/88-ONG-D-III]

का.आ. 879.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 1897 तारीख 8-6-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाईनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन में की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

के.एन.के. फेस II की पाइप लाइन बिछाने के लिए।

गांव	ब्लाक नं.	हैक्टेयर	आर	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
हरीयाला	636	0	13	00
	637	0	13	90
	638	0	12	90
	640/2	0	09	40
	641/2	0	22	80
	643	0	10	80
	648	0	09	20
	688/3	0	07	50
	683/1	0	19	00
	682	0	03	00
	681	0	04	20
	680/1	0	09	90
	679	0	12	50
	677/1	0	01	40
	675	0	05	00
	670	0	17	60
	668	0	16	50
	666	0	14	00
	664/2	0	08	50

1	2	3	4	5
हरियाला (जारी)	663/2	0	15	50
	660	0	06	70
	661/1	0	18	20
	497	0	22	00
	496	0	04	00

[सं.ओ.-11027/135/88-ओ एन जी-डी-III]

S.O. 879.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 1897 dated 8-6-88 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FOR K.N.K. PHASE II

State : Gujarat District : Kheda Taluka : Matar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Hariyala	636	0	13	00
	637	0	13	90
	638	0	12	90
	640/2	0	09	40
	641/2	0	22	80
	643	0	10	80
	648	0	09	20
	688/1	0	07	50
	683/1	0	19	00
	682	0	03	00
	681	0	04	20
	680/1	0	09	90
	679	0	12	50
	677/1	0	01	40
	675	0	05	00
	670	0	17	50
	668	0	16	50
	666	0	14	00
	664/2	0	08	50
	663/2	0	15	50
	660	0	06	70
	661/1	0	18	20
	497	0	22	00
	496	0	04	00

[No. O—11027/135/88—ONG.D-III]

का. आ. 880.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3484 तारीख 26-11-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जे. एन. ए. क्यू से टी. बिन्दु तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य :—गुजरात जिला : भरूच तालुका : जंबुसर

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आरे	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
जंबुसर	1807	0	04	81
	1805	0	16	79
	1802	0	00	70
	1801	0	12	56
	1795	0	17	40
	1796	0	16	50
	1793	0	22	80
	1794	0	02	85
	1790	0	24	67
	1791	0	00	72
	1766	0	07	20
	1765	0	22	74
	1763	0	22	17
	1762	0	29	20
	1760/1	0	21	30
	1849	0	23	40
	1848	0	10	64
	1847	0	12	82
	1846	0	04	50
	1841+1852	0	24	30
	1853	0	11	10
	1854	0	14	70
	1876	0	27	90

1	2	3	4	5
जंबुसर (जारी)	1877	0	09	00
	1879	0	15	90
	1880	0	21	00
	2013	0	08	56
	2014	0	02	43
	2015	0	12	17
	2016	0	14	10
	2018	0	14	10
	2019	0	41	70

[सं. ओ.-11027/24/88-ओ. एन. जी.-डी.-III]

S.O. 880.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 3484 dated 26-11-88 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, submitted report Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances

SCHEDULE

PIPELINE FROM GNAQ TO T CONNECTION

State : Gujarat Dist : Bharuch Taluka : Jambusar

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Jambusar	1804	0	04	81
	1805	0	16	79
	1802	0	00	70
	1801	0	12	56
	1795	0	17	10
	1796	0	16	50
	1793	0	22	80
	1794	0	02	85
	1790	0	24	67
	1791	0	00	72
	1766	0	07	20
	1765	0	22	74
	1763	0	22	17
	1762	0	29	20
	1760/1	0	21	30
	1849	0	23	40
	1848	0	10	64
	1847	0	12	82
	1846	0	04	70
	1841+1852	0	24	30
Jambusar (Contd.)	1853	0	11	10
	1854	0	14	70
	1876	0	27	90
	1877	0	09	00
	1879	0	15	90
	1880	0	21	00
	2013	0	08	56
	2014	0	02	43
	2015	0	12	17
	2016	0	14	40
	2018	0	14	10
	2019	0	41	70

[No. O-11027/24/88—ONG D-III]

का.आ. 881.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2480 तारीख 7-9-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

ननवा जी. जी. ऐस. III से कलोल डी. जी. ऐम. एवम् सी. टी. एफ. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य :—गुजरात जिला :—मेहसाणा तालुका :—चाणसमा

गाँव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आरे	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
कमोडा	172	0	02	00
	173	0	14	25
	174	0	28	50
	कार्ट ट्रैक	0	03	30
	208	0	24	00

1	2	3	4	5
कनोडा (जारी)	कार्ट ट्रैक	0	04	40
	251	0	14	20
	249	0	26	30
	248	0	00	25
	247	0	19	00
	246	0	16	70
	कार्ट ट्रैक	0	02	70
	277	0	07	70
	278	0	17	30
	283	0	15	50
	284	0	29	30
	290	0	17	25
	291	0	21	15
	293	0	04	40
	75	0	06	00

[सं. ओ.-11027/162/88-ओ.एन.जी.-डी.-III]

S.O. 881.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2480 dated 7-9-88 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM LANVA GGS III TO BALOL GGS/CTF

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Chanasma

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Kanoda	172	0	02	00
	173	0	14	25
	174	0	28	50
	Cart track	0	08	30
	208	0	24	00
	Cart track	0	04	40
	251	0	14	20
	249	0	26	30
	248	0	00	25
	247	0	19	00
	246	0	16	70

1	2	3	4	5
Kanoda (contd.)	Cart track	0	02	70
	277	0	07	70
	278	0	17	30
	283	0	15	50
	284	0	29	30
	290	0	17	25
	291	0	21	15
	293	0	04	40
	75	0	06	00

[No. O—11027/162/88—ONG-D.III]

का. आ. 882 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2019 तारीख 14-6-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

चांदखेड़ा से रिलाइन्स इंडस्ट्रीज तक लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : व तालुका : गांधीनगर

गांव	ब्लाक नं०	हैक्टेयर	आर	सेन्टीयर
कराई	156	0	26	70
	132	0	45	20
	130	0	04	12
	129	0	26	00
	135	0	17	20
	126	0	21	40
	125	0	26	75
	122	0	17	30
	123	0	11	30
	कार्ट ट्रैक	0	02	62
	109	0	39	80
	103/1	0	13	24
	108/2	0	00	56

[सं. ओ-11027/142/88-ओ एन जी- डी-III]

S.O. 882.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2019 dated 14-6-88 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline:

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM CHANDKHEDA TO RELIANCE IND.

State : Gujarat District & Taluka : Gandhinagar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Karai	156	0	26	70
	132	0	45	20
	130	0	04	12
	129	0	26	00
	135	0	17	20
	126	0	21	40
	125	0	26	75
	122	0	17	30
	123	0	11	30
	Cart track	0	02	62
	109	0	39	80
	108/1	0	13	24
	108/2	0	00	56

[No. O—11027/142/88—ONG—D.III]

का.आ.सं. 883—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 3479 तारीख 4-11-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

गेलाव-2 से एम.डब्ल्यू.एम.बी. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : हांसोट

गांव	ब्लाक नं.	हैक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
अणीमायरा	171/ई	0	02	47
	234	0	23	85
	176	0	07	25
	173	0	00	14
	233/ए बी	0	08	56
	232	0	15	21
	160/बी/1	0	01	17
	कार्ट ट्रैक	0	01	43
	162	0	02	47
	185	0	22	90
	186	0	09	39
	163/ए-बी	0	07	29
	118/ए-बी	0	14	43
	111	0	02	40
	113	0	07	70
	112	0	07	48
	109/ए-बी	0	14	63
	102/ए	0	10	40
	27	0	18	20
	59/ए-बी	0	10	72
	60	0	08	35
	58	0	15	86
	45	0	10	25
	46/ए-बी	0	13	39
	51/ए-बी	0	19	89
	50	0	06	63
	48/8	0	06	80

[सं.ओ. 11027/180/88-ओ एन जी डी-III]

S.O. 883.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 3479 dated 4-11-88 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared it's intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM ELLAV-2 TO SWMB

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Hansot

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Aniyadra	171/B	0	02	47
	234	0	23	85
	174	0	07	25
	173	0	00	14
	233/A-B	0	08	56
	232	0	15	21
	180/B/1	0	01	17
	Cart track	0	01	43
	182	0	02	47
	185	0	22	50
	186	0	09	49
	168/A-B	0	07	29
	118/A-B	0	14	43
	111	0	02	40
	113	0	00	70
	112	0	07	48
	109/A-B	0	14	63
	102/A	0	10	40
	27	0	18	20
	59/A-B	0	10	72
	60	0	08	35
	58	0	15	86
	45	0	10	25
	46/A-B	0	13	39
	51/A-B	0	19	89
	50	0	06	63
	48/B	0	06	89

[No.O—11027/180/88—ONG -D.III]

का.आ. 884.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 3733 तारीख 8-12-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप से, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

ई.पी.एस. नन्दासन से एन.के.सी.टी.एफ. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कड़ी

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
1	2	3	4	5
कैयल	552	0	03	00
	553	0	06	40
	558	0	00	40
	551/पी	0	15	58
	551/पी	0	26	00
	563	0	10	00
	564	0	08	00
	594	0	30	40
	कार्ट ट्रेक	0	01	20
	596	0	13	80
	598	0	30	60
	599	0	27	80
	कार्ट ट्रेक	0	02	80
	604	0	10	80
	603	0	10	00
	606	0	01	50
	608	0	12	80
	607	0	12	50
	612	0	12	60
	613	0	31	67
	कार्ट ट्रेक	0	09	80
	581	0	04	20
	कार्ट ट्रेक	0	02	00
	617	0	01	60
	618	0	32	00
	628	0	03	75
	627	0	28	00
	636	0	09	70
	637	0	09	50
	638	0	18	80
	649/1	0	33	00
	649/3	0	12	60

[सं. ओ—11027/196/88—ओ एन जी-डी-III]

S.O. 884.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 3733 dated 8-12-88 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central

Government declared it's intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM EPS NANDASAN TO NK. CTF.

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Kaiyal	552	0	03	00
	553	0	06	40
	558	0	00	40
	551/P	0	15	58
	551/P	0	26	00
	563	0	10	00
	564	0	08	00
	594	0	30	40
	Cart track	0	01	20
	596	0	13	80
	598	0	30	60
	599	0	27	80
	Cart track	0	02	80
	604	0	10	80
	603	0	10	00
	606	0	01	50
	608	0	12	80
	607	0	12	50
	612	0	12	60
	613	0	31	67
	Cart track	0	09	80
	581	0	04	20
	Cart track	0	02	00
	617	0	01	60
	618	0	32	00
	628	0	03	75
	627	0	28	00
	636	0	09	70
	637	0	09	50
	638	0	18	80
	649/1	0	33	00
	649/3	0	12	60

[No. O-11027/196/88-ONG-D-III]

का.आ. 885:—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 3741 तारीख 8-12-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

ई.पी.एस. नन्दासन से एन.के.सी.टी०एफ. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कडी

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
सुरज	923	0	11	60
	921	0	06	84
	925/पी	0	12	60
	925/पी	0	17	60
	928/1	0	15	40
	929	0	28	00
	कार्ट ट्रेक	0	02	10
	916/पी	0	21	00
	916/पी	0	21	50
	904	0	04	50
	914	0	13	60
	913	0	12	40
	906	0	10	60
	907	0	16	80
	892	0	00	25
	893	0	30	00
	894	0	14	00
	891/पी	0	11	80
	891/पी	0	15	50
	कार्ट ट्रेक	0	08	00

[सं. ओ-11027/194/88-ओ एन जी-डी-III]

S.O. 885.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 3741 dated 8-12-88 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared it's intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from EPS Nandasan to NK CTF

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Suraj	923	0	11	60
	924	0	06	84
	925/P	0	12	60
	925/P	0	17	60
	928/1	0	15	40
	929	0	18	00
	Cart track	0	02	10
	916/P	0	21	00
	916/P	0	21	50
	904	0	04	50
	914	0	13	60
	913	0	12	40
	906	0	10	60
	907	0	16	80
	892	0	00	25
	893	0	30	00
	894	0	14	00
	891/P	0	11	80
	891/P	0	15	50
	Cart track	0	08	00

[No. O-11027/194/88-ONG-D. III]

का. आ. 886:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 3480 तारीख 4-11-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

ऐलाव-2 से एस.डब्ल्यू.एम.बी. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : —गुजरात जिला : भरूच तालुका : हांसोट

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आर	सेंटीयर
सूनेव खुर्द	104	0	05	46
	105	0	08	45
	107	0	08	19
	108	0	19	93
	109	0	06	95
	116	0	11	12

[सं. ओ-11027/179/88-ओ एन जी-डी-3]

S.O. 886.—Whereas by notification of the Government India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3480 dated 4-11-88 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipline from ELLVAVE-2 to SWMB.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Hansot

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Sunev Khurd	104	0	05	46
	105	0	08	45
	107	0	08	19
	108	0	19	93
	109	0	06	94
	116	0	11	12

[No. O-11027/179/88-ONG-D. III]

का.आ. 887 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 150 तारीख 5-1-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

ई.पी.एस. नंदासन से एन.के.सी.टी.एफ. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : —गुजरात जिला : —मेहसाणा तालुका : कडी

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
1	2	3	4	5
धनाली	14	0	21	00
	15	0	17	80
	17	0	13	20
	18	0	28	00
	17	0	00	23
	7	0	08	80
	12	0	10	60
	9	0	24	50
	11	0	00	33
	10	0	17	50
	कार्ट ट्रेक	0	02	00
	256	0	00	45
	257/3	0	08	00
	257/2	0	08	00
	257/1	0	07	00
	260/[illegible]	0	12	20
	260/पी	0	02	16
	262/3	0	12	20
	262/2	0	01	20
	262/1	0	14	40
	261/2	0	01	00
	264/पी	0	08	60
धनाली	264/पी	0	18	80
	263	0	00	50
	कार्ट ट्रेक	0	13	20
	268	0	15	60
	245	0	08	75
	194	0	02	97
	195	0	02	43
	196	0	01	56
	197/2	0	00	40
	241	0	05	12
	243	0	20	20
	242	0	25	20
	239	0	26	05
	कार्ट ट्रेक	0	01	40
	238/पी	0	27	40
	238/पी	0	09	00
	कार्ट ट्रेक	0	02	40

[सं. ओ-11027/1/89-ओ एन जी-डी-3]

S.O. 887.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 150 dated 5-1-89 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from EPS Nandasan to NK CTF.

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
1	2	3	4	5
Dhanali	14	0	21	80
	15	0	17	00
	16	0	13	20
	18	0	28	00
	17	0	00	23
	7	0	08	80
	12	0	10	60

1	2	3	4	5
Dhanali	9	0	24	50
	11	0	00	33
	10	0	17	50
	Cart track	0	02	00
	256	0	00	45
	257/3	0	08	00
	257/2	0	08	00
	257/1	0	07	00
	260/P	0	12	20
	260/P	0	02	16
	262/3	0	12	20
	262/2	0	01	20
	262/1	0	14	40
	261/2	0	01	00
	264/P	0	08	60
	264/P	0	18	80
	263	0	00	50
	Cart track	0	13	20
	268	0	15	60
	245	0	08	75
	194	0	02	97
	195	0	02	43
	196	0	01	56
	197/2	0	00	40
	244	0	05	12
	243	0	20	20
	242	0	25	20
	239	0	26	05
	Cart track	0	01	40
	238/P	0	27	40
	238/P	0	09	00
	Cart track	0	02	40

[No. O-11027/1/89--ONG-D. III]

का. आ. 888.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 303 तारीख 24-1-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार कर के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

लनवा जी.जी.एस.-1 से लनवा जी.जी.एस.-3 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : —गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : चाणसमा

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
मुलथानिया	9	0	13	05
	11	0	05	10
	10	0	00	50
	22	0	08	80
	23	0	16	00
	34	0	04	00
	33	0	13	20
	47	0	09	00
	40/3	0	03	30
	42/1	0	11	45
	45	0	12	40
	44	0	10	40
	43	0	00	02

[सं. ओ-11027/146/88-ओ एन जी-डी-3

S.O. 888.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 303 dated 24-1-89 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from LANVA GGS I to LANVA GGS III.

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Chanasma

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Multhaniya	9	0	13	05
	11	0	05	10
	10	0	00	50
	22	0	08	80
	23	0	16	00
	34	0	04	00
	33	0	13	20
	47	0	09	00
	40/3	0	03	30
	42/1	0	11	45
	45	0	12	40
	44	0	10	46
	43	0	00	02

[No. O-11027/146/88-ONG-D. III]

का. आ. :889—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 412 तारीख 7-1-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

के.एन.के. फेस-2 की पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : खेड़ा तालुका : मातर

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
1	2	4	4	5
राघवनाज	38	0	03	50
	37	0	7	10
	31	0	19	00
	कार्ट ट्रेक	0	00	80
	30	0	04	80
	734	0	04	60
	733	0	04	50
	735	0	04	40
	730	0	05	50
	729	0	16	00
	720	0	03	30
	717	0	01	20
	716	0	06	00
	699	0	06	50
	698	0	03	50
	701	0	02	10
	702	0	02	50
	704	0	02	00
	कार्ट ट्रेक	0	00	60
	705	0	03	20
	682	0	03	70
	648	0	04	25
	649	0	03	00
	650	0	02	20
	651	0	04	30
	657	0	05	40
	656	0	14	50
	658	0	10	00
	605	0	14	50
	64	0	09	30
	684	0	00	30
	39	0	12	50
	40	0	04	00

[सं. ओ-11027/43/87-ओ एन जी-डी-3]

S.O. 889.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 412 dated 7-1-88 under sub-section (1) of Section 6 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline for KNK Phase II.

State : Gujarat District : Kheda Taluka : Matar

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Raghwanaj	38	0	03	50
	37	0	07	10
	31	0	19	00
	Cart track	0	00	80
	30	0	04	80
	734	0	04	60
	733	0	04	50
	735	0	04	40
	730	0	05	50
	729	0	16	00
	720	0	03	30
	717	0	01	20
	716	0	06	00
	699	0	06	50

1	2	3	4	5
	698	0	03	50
	701	0	02	10
	702	0	02	50
	704	0	02	00
	Cart track	0	00	60
	705	0	03	20
	682	0	03	70
	648	0	04	25
	649	0	03	00
	650	0	02	20
	651	0	04	30
	657	0	05	40
	656	0	14	50
	658	0	09	00
	684	0	00	30
	39	0	12	50
	40	0	04	00

[No. O-11027/43/87-ONG-D. III]

का.आ. 890:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 2949 तारीख 7-9-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

लनवा जी.जी.एस.-3 से बलोल जी.जी.एस. सी.टी.एफ. तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : मेहसाना

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
1	2	3	4	5
कनोडा	कार्ट ट्रेक	0	02	25
	534	0	01	75
	535	0	17	90
	536पी	0	03	20
	536	0	16	80
	538	0	08	20
	539	0	06	50
	553	0	19	40
	551/1	0	24	70
	557	0	17	90
	562	0	25	00
	577	0	05	00
	576	0	06	00
	578/पी	0	26	05
	578	0	12	80
	573/पी	0	00	25
	573	0	22	35
	574	0	00	36

[सं. ओ-11027/170/88-ओ एन जी-डी-3]

S.O. 890.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2949 dated 7-9-88 under sub-section (1) of Seciton 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from LANWA GGS III to BALOL GGS/CTF.

State : Gujrat District - Mehsana Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Kanoda	Cart track	0	02	25
	534	0-0	01	75
	535	0	17	90
	536/P	0	03	20
	536	0	16	80
	538	0	08	20
	539	0	06	50
	553	0	19	40
	551/1	0	24	70
	557	0	17	90
	562	0	25	00
	577	0	05	00
	576	0	06	00
	578/P	0	26	05
	578	0	12	80
	573/P	0	00	25
	573	0	22	35
	574	0	00	36

[No. O-11027/170/88-ONG-D-III]

का.आ. 891.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 134 तारीख 5-1-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

गंधार से धुवारण तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : --गुजरात   जिला : बडोदरा   तालुका : पादरा

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टर	आर	प्र आर
चोकारी	50	0	06	00
	51	0	02	00
	53	0	01	00

[सं. ओ-11027/3/89-ओ एन जी-डी-3]

S.O. 891.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 134 dated 5-1-89 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification,

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipline from Gandhar to Dhuvaran

State : Gujarat   District : Vadodara Taluka : Padra

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Chokari	50	0	06	00
	51	0	02	00
	53	0	01	00

[No. O-11027/3/89-ONG-D-III]

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1989

का.आ. 892.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 1896 तारीख 8-6-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कलोल से नवागाम से कोसम्बी तक फेस 2 की पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात   जिला : खेड़ा   तालुका : मातर

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टयर	आर.	सेंटीयर
1	2	3	4	5
गोबलज	509/1	0	02	40
	509/2	0	05	20
	508/2	0	00	60
	507/4	0	02	40
	535/1	0	03	70
	536/1	0	00	05
	536/2	0	03	10
	537/1/1	0	02	80
	537/1/2	0	02	80
	537/1/3	0	02	00

1	2	3	4	5
	538/1--2--3--4	0	11	70
	548/1	0	10	00
	548/2	0	06	80
	572	0	05	00
	573	0	05	30
	579	0	09	20
	623	0	09	80
	624	0	07	40
	617	0	03	50
	618	0	14	20
	619/1	0	02	00
	619/2	0	01	60
	615	0	06	50
	614	0	07	40
	610	0	02	50
	666/3	0	06	70
	667	0	04	30
	668/1--2	0	08	00
	681	0	14	30
	707	0	13	90
	674	0	25	00
	729	0	30	00
	730	0	04	50
	765	0	05	50
	770	0	00	40
	766,769,773, 774, 775, 777 778, 780	0	49	00
	507 3	0	04	00
	507/5	0	00	60

[सं. ओ- 11027/137/88-ओ एन जी-डी-3']

New Delhi, the 29th March, 1989

S.O. 892.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1896 dated 8-6-88 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Cenrtal Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification:

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline for K.N.K. Phase II.

State : Gujarat District : Kheda Taluka : Matar

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
1	2	3	4	5
Goblaj	509/1	0	02	40
	509/2	0	05	20
	508/2	0	00	60
	507/4	0	02	40
	535/1	0	03	70
	536/1	0	00	05
	536/2	0	03	10
	537/1/1	0	02	80
	537/1/2	0	02	80
	537/1/3	0	02	00
	538/1 —2—3—4	0	11	70
	548/1	0	10	00
	548/2	0	06	80
	572	0	05	00
	573	0	05	30
	579	0	09	20
	623	0	09	80
	624	0	07	40
	617	0	03	50
	618	0	14	20
	619/1	0	02	00
	619/2	0	01	60
	615	0	06	50
	614	0	07	40
	610	0	02	50
	666/3	0	06	70
	667	0	04	30
	668/1--2	0	08	00
	681	0	14	30
	707	0	13	90
	674	0	25	00
	729	0	30	00
	730	0	04	50
	765	0	05	50
	770	0	00	40
	766, 769, 773, 774, 775, 777, 778, 780	0	49	00
	507/3	0	04	00
	507/5	0	00	60

[No. O-11027/137/88-ONG-D-III]

का.आ. 893.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 1638 तारीख -5-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूचि

नोर्थकडी सीटीएफ से सरखेज तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कडी

गांव	सर्वे नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
लक्ष्मणपुरा	176	0	20	80
	181/1	0	58	00
	182/2	0	25	20
	461	0	39	80
	460	0	01	40

[सं. ओ.-11027/106/88-ओ एन जी-डी.-III]

893.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1638 dated -5-88 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil anid Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

North Kadi CTF TOI Saarkhej Pipeline

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Laxmanpura	176	0	20	80
	181/1	0	58	00
	181/2	0	25	20
	461	0	39	80
	460	0	01	40

[No. O-11027/106/88-ONG-D.-III]

का.आ. 894.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 2953 तारीख 1-9-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

लनवा जीओजीएस० I से लनवा जीओजीएस० III तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य गुजरात जिला मेहसाना तालुका चाणस्मा

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
दनोदरा	कार्टट्रेक	0	01	60
	674/पी	0	06	00
	668	0	11	80
	669	0	00	20
	कार्टट्रेक	0	00	80
	670	0	18	60
	666/पी	0	00	15
	666/1	0	18	62
	665	0	08	00
	664	0	09	80

[सं.ओ -11027/118/88-ओ एन जी-डी.-III]

S.O. 894.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2953 dated 1-9-88 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Cetral Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Lanva GGS I to Lanva GGS III.

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Chanasma

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Danodara	Cart track	0	01	60
	674/P	0	06	00
	668	0	11	80
	669	0	00	20
	Cart track	0	00	80
	670	0	18	60
	666/P	0	00	15
	666/1	0	18	62
	665	0	08	00
	664	0	09	80

[No. O-11027/148/88-ONG-D. III]

का. आ. 895 .—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 409 तारीख 7-1-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

के. एस. के. फेस II की पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : खेड़ा तालुका : आनंद

गाँव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
मावली	899/2	0	01	54
	901/8	0	05	00
	901/7	0	06	60
	901/6	0	13	40
	903/5	0	04	05
	903/3	0	00	20
	903/4	0	07	50
	930/3/2	0	03	00
	930/3/1	0	03	40
	930/1/2	0	03	20
	930/1/1	0	09	00
	929/1	0	15	75
	910/A+B+C	0	17	75
	913/2	0	12	00
	925/1	0	10	30
	924/1	0	18	00
	923/1	0	09	40
	921	0	13	20
	718/1	0	07	80
	717	0	08	00
	716/2	0	02	30
	716/1	0	15	40
	696	0	15	20
	689/5/2	0	16	10
	689/6	0	02	50
	कार्ट्रेक	0	01	00
	680/1	0	14	40
	682/3	0	10	39
	679/1+2	0	01	80
	678	0	00	45
	677/1	0	19	00
	612/1	0	02	00
	612/2	0	03	10
	612/3	0	03	10
	613/1+2	0	07	60
	608/3	0	08	40
	607/1+2	0	04	63
	605	0	07	80
	604/2	0	01	08
	604/1	0	13	26
	603/2	0	00	06
	599/1	0	03	60
	599/2	0	14	58
	597	0	15	11
	596	0	00	04
	593	0	00	85
	595	0	10	75

[सं. ओ.-11027/40/87-ओ एन जी-डी. III]

S.O. 895.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 409 dated 7-1-88 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of ithe Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline for KNK Phase II.

State : Gujarat District : Kheda Taluka : Anand

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Navli	899/2	0	01	54
	901/8	0	05	00
	901/7	0	06	60
	901/6	0	13	40
	903/5	0	04	05
	903/3	0	00	20
	903/4	0	07	50
	930/3/2	0	03	00
	930/3/1	0	03	40
	930/1/2	0	03	20
	930/1/1	0	09	00
	929/1	0	15	75
	910/A+B+C	0	17	75
	913/2	0	12	00
	925/1	0	10	30
	924/1	0	18	00
	923/1	0	09	40
	921	0	13	20
	718/1	0	07	80
	717	0	08	00
	716/2	0	02	30
	716/1	0	15	40
	696	0	15	20
	689/5/2	0	16	10
	689/6	0	02	50
	Cart track	0	01	00
	680/1	0	14	40
	682/3	0	16	39
	679/1+2	0	01	80
	678	0	00	45
	677/1	0	19	00
Navli Contd.	612/1	0	02	00
	612/2	0	03	10
	612/3	0	03	10
	613/1+2	0	07	60
	608/3	0	08	40
	607/1+2	0	04	63
	605	0	07	80
	604/2	0	01	08
	604/1	0	13	26
	603/2	0	00	06
	599/1	0	03	60
	599/2	0	14	58
	597	0	15	11
	596	0	00	04
	593	0	00	85
	595	0	10	75

[No. O-11027/40/87—ONG-D. III]

का. आ. 896.—यत: पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिका. आ. सं. 1637 तारीख 24-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा (1) की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

नोर्थकरी सी. टी. एफ से सरखेज तक पाइपलाइन बिछाने के लिये

राज्य : गुजरात जिला : महसाणा तालुका : कड़ा

गांव	सर्वेक्षण नं.	हेक्टर	आर.	सेन्टीयर
दिगड़ी	6	1	40	00
	298	0	36	00

1	2	3	4	5
दिगडी—(जारी)	296	0	14	90
	फार्टट्रैक	0	01	20
	295	0	04	50
	218	0	03	12
	217	0	19	28
	फार्ट ट्रैक	0	00	08
	223/1	0	12	20
	224	0	18	80
	229	0	11	00
	228	0	10	04
	235/2	0	02	55
	234/1	0	08	70
	234/2	9	09	90
	233	0	17	80
	236	0	00	90
	238/4	0	22	00
	241/1	0	12	00
	241/2	0	14	99
	244	0	27	80
	245	0	21	00

[सं. ओ.-11027/107/88 ओ एन जी डी-II]

S.O. 896.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1637 dated 20-4-88 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquiie the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from North Kadi CTF to Sarkhej

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Dighadi	6	1	40	00
	298	0	36	00
	296	0	14	90
	Cart track	0	01	20
	295	0	04	50
	218	0	03	12
Dighadi (Contd.)	217	0	19	28
	Cart track	0	00	08
	223/1	0	12	20
	224	0	18	80
	229	0	11	00
	228	0	10	04
	235/2	0	02	55
	234/1	0	08	70
	234/2	0	09	90
	233	0	17	80
	236	0	00	90
	238/4	0	22	00
	241/1	0	12	00
	241/2	0	14	99
	244	0	27	80
	245	0	21	00

[No. O-11027/107/88-ONG-D. III]

का. आ. 897.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का आ. सं. 406 तारीख 7-1-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था :

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होंगे।

अनुसूची

के. एन. के. फेस II की पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : खेड़ा तालुका : नदीयाद

गांव	ब्लाक नं.	हैक्टर	आर	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
पलाना	1425	0	03	70
	1426	0	02	90
	1424	0	04	60
	1423	0	05	10

1	2	3	4	5
पलाना (जारी)	1422	0	04	50
	1429	0	07	30
	1430	0	17	70
	1431	0	05	80
	1391	0	04	80
	1390	0	05	10
	1389	0	07	00
	1388	0	05	70
	1387	0	05	20
	कार्ट ट्रेक	0	00	60
	1361	0	00	40
	1365	0	03	70
	1366	0	05	90
	1372	0	06	30
	1373	0	12	90
	1371	0	04	20
	1223	0	04	80
	1219	0	07	60
	1174	0	05	50
	1206	0	01	70
	1173	0	01	20
	1172	0	06	50
	1171	0	01	00
	कार्ड ट्रेक	0	00	50
	1175	0	05	50
	1165	0	10	20
	1166	0	05	30
	1167	0	02	00
	कार्ट ट्रेक	0	00	50
	1164	0	05	40
	1123	0	06	80
	1124	0	07	50
	1130	0	09	20
	1100	0	09	00
	1101	0	02	00
	1090	0	11	50
	कार्ट ट्रेक	0	00	30
	996	0	02	70
	997	0	04	80
	998	0	00	45
	994	0	01	50
	1000	0	05	10
	981	0	15	90
	977	0	07	50
	980	0	03	50
	979	0	02	10
	864	0	10	50
	871	0	02	60
	872	0	03	80
	874	0	16	70
	689	0	03	70
	683	0	02	00
	685	0	04	50
	686	0	05	00
	679	0	14	00
	1131	0	04	00
	684	0	00	20

[सं. भो. 11027/36/87—ओ एन जी डी—III]

S.O. 897.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 406 dated 7-1-88 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification,

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline for KNK Phase II

State : Gujarat District : Kheda Taluka : Nadiad

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Palana	1425	0	03	70
	1426	0	02	90
	1424	0	04	60
	1423	0	05	10
	1422	0	04	50
	1429	0	07	30
	1430	0	17	70
	1431	0	05	80
	1391	0	04	80
	1390	0	05	10
	1389	0	07	00
	1388	0	05	70
	1387	0	05	20
	Cart track	0	00	60
	1361	0	00	40
	1365	0	03	70
	1366	0	05	90
	1372	0	06	30
	1373	0	12	90
	1371	0	04	20
	1223	0	04	80

1	2	3	4	5
Palana (Contd.)				
	1219	0	07	60
	1174	0	05	50
	1206	0	01	70
	1173	0	01	20
	1172	0	06	50
	1171	0	01	00
	Cart track	0	00	50
	1175	0	05	50
	1165	0	10	20
	1166	0	05	30
	1167	0	02	00
	Cart track	0	00	50
	1164	0	05	40
	1123	0	06	80
	1124	0	07	50
	1130	0	07	20
	1100	0	09	00
	1101	0	02	00
	1090	0	11	50
	Cart track	0	00	50
	956	0	02	70
	997	0	04	80
	998	0	00	45
	994	0	01	50
	1000	0	05	10
	981	0	15	90
	977	0	07	50
	980	0	03	50
	979	0	02	10
	864	0	10	50
	871	0	02	60
	872	0	03	80
	874	0	16	70
	689	0	03	70
	683	0	02	00
	685	0	04	50
	686	0	05	00
	679	0	14	00
	1131	0	04	00
	684	0	00	20

[No. O-11027/36/87/ONG-D. III]

का. आ. 898.—यत: पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2830 तारीख 5-9-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

चांद खेड़ा से रिलायन्स इन्डस्ट्रीज तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य गुजरात जिला व तालुका : गांधी नगर

गांव	सर्वे नं.	हैक्टर	आरे	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
सुघड़	34	0	11	00
	31/1	0	07	50
	31/2	0	16	60
	32/1	0	16	00
	32/2	0	27	00
	29	0	01	75
	28	0	26	80
	27/1	0	07	00
	27/3	0	38	60
	10	0	12	00
	11	0	13	00
	कार्ट ट्रेक	0	01	40
	12/7	0	09	00
	13/2	0	12	40
	14	0	11	00
	15	0	08	80
	234	0	13	67
	2/1	9	18	00
	2/2	0	17	20
	1/2	0	11	60
	कार्ट ट्रेक	0	02	08
	76/5/2	0	12	80
	कार्ट ट्रेक	0	02	40
	102/1	0	21	00
	102/2	0	06	30
	101/1	0	16	40
	104	0	05	10
	105	0	12	40
	107/1	0	16	85
	106/1	0	02	94
	107/3	0	01	80
	101/2	0	06	80
	110/8	0	11	20
	110/9	0	13	20
	110/10	0	25	80
	111	0	00	72
	123/2+3+4	0	24	80
	कार्ट ट्रेक	0	01	10
	124	0	00	20

[सं. ओ.-11027/156/88-ओ एन जी डी-III]

S.O. 898.—Whereas by notification of the Goverment of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2830 dated 5-9-88 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Chandkheda to Reliance Ind.

State : Gujarat District & Taluka : Gandhinagar

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Sughad	34	0	11	00
	31/1	0	07	50
	31/2	0	16	60
	32/1	0	16	00
	32/2	0	27	00
	29	0	01	75
	28	0	26	80
	27/1	0	07	00
	27/3	0	38	60
	10	0	12	00
	11	0	13	00
	Cart track	0	01	40
	12/7	0	09	00
	13/2	0	12	40
	14	0	11	00
	15	0	08	80
	234	0	13	67
	2/1	0	18	00
	2/2	0	17	20
	1/2	0	11	60
	Cart track	0	02	08
	76/5/2	0	12	80
	Cart track	0	02	40
	102/1	0	21	00
	102/2	0	06	30
	101/1	0	16	40
	104	0	05	10
	105	0	12	40
	107/1	0	16	85
	106/1	0	02	94
	107/3	0	04	80
	101/2	0	06	80
	110/8	0	11	20
	110/9	0	13	20
	110/10	0	25	80
	111	0	00	72
	123/2+3+4	0	24	80
	Cart track	0	01	10
	124	0	00	20

[No. O-11027/156/88 ONG-D. III]

का. आ. 899.—यत: पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1562 तारीख 3-5-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा

अनुसूची

लक्ष्मीपुरा से बेस्को तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : बड़ोदरा

गांव	ब्लाक	हेक्टेयर	आर	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
समीपाला	484	0	00	75
	371	0	00	25
	489	0	07	35
	488	0	08	70
	487	0	06	00
	486	0	00	75
	कार्ट ट्रेक	0	00	60
	494	0	12	00
	498/1	0	00	30
	495	0	00	20

1	2	3	4	5
	कार्ट ट्रक	0	00	60
	493/3	0	01	20
	330/1	0	01	95
	329	0	10	95
	327/2	0	05	25
	कार्ट ट्रैक	0	01	50
	266/2	0	01	50
	267/2	0	03	75
	265	0	09	00
	264	0	01	50
	262	0	10	80
	261/1	0	08	25
	259	0	03	45
	258	0	11	40
	किन्स	0	04	50
	243/1	0	05	55
	255/1	0	21	00
	247	0	16	50
	249	0	00	70
	248	0	05	00
	कार्ट ट्रैक	0	00	75
	170	0	08	95
	169	0	13	05
	167/2	0	12	60
	167/1	0	00	20
	कार्ट ट्रैक	0	01	95
	103	0	00	20
	107	0	18	00
	118	0	12	60
	117	0	03	00
	121	0	06	75
	116	0	00	20
	122	0	16	20
	126	0	11	40
	128	0	09	00
	130	0	06	15
	132	0	29	90

[सं. ओ. 11027/114-88-ओ एन जी-डी III]

S.O. 899.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1562 dated 3-5-88 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-(1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Laxmipura to Banco.

State : Gujarat District & Taluka : Vadodara

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Samiyala	484	0	00	75
	371	0	00	25
	489	0	07	35
	488	0	08	70
	487	0	06	00
	486	0	00	75
	Cart track	0	00	60
	494	0	12	00
	498/1	0	00	30
	495	0	00	20
	Cart track	0	00	60
	493/3	0	01	20
	330/1	0	01	95
	329	0	10	95
	327/2	0	05	25
	Cart track	0	01	50
	266/2	0	01	50
	267/2	0	03	75
	265	0	09	00
	264	0	01	50
	262	0	10	80
	261/1	0	08	25
	259	0	03	45
	258	0	11	40
	Kans	0	04	50
	243/1	0	05	55
	255/1	0	21	00
	247	0	16	50
	249	0	00	70
	248	0	05	00
	Cart track	0	00	75
	170	0	07	95
	169	0	13	05
	167/2	0	12	60
	167/1	0	00	20
	Cart track	0	01	95
	103	0	00	20
	107	0	18	00
	118	0	12	60
	117	0	03	00
	121	0	06	75
	116	0	00	20
	122	0	16	20
	126	0	11	40
	128	0	09	00
	130	0	06	15
	132	0	18	20

[No. O-11027/114/88-ONG-D. III]

का. आ. 900.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1895 तारीख 8-6-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की धारा उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चिय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वार घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

के. एन. के. फेस II की पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला खेडा तालुका नडीयाद

गांव	ब्लाक नं.	हैक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
पीज	2065	0	07	20
	2063	0	09	80
	कार्ट ट्रैक	0	01	00
	2070	0	03	50
	2089	0	06	20
	कार्ट ट्रैक	0	00	50
	2014	0	04	10
	2013	0	00	35
	2012	0	17	30
	1785	0	07	20
	1786	0	02	30
	1787	0	02	00
	1788	0	05	90
	1772	0	03	80
	1790	0	08	00
	1770	0	06	00
	1769	0	10	50
	1720	0	03	00
	1721	0	02	20
	1722	0	04	60
	1660	0	09	80
पीज—जारी	1643	0	03	50
	1642	0	10	00
	1640	0	10	30
	1639	0	04	00
	1638	0	03	70
	1637	0	11	60
	1635	0	04	20
	1333	0	01	50
	1332	0	07	50
	1331	0	07	40
	1329	0	05	00
	1328	0	03	90
	1327	0	02	30
	1326	0	05	00
	1325	0	00	50
	1324	0	07	00
	1288	0	02	00
	1294	0	03	00
	1293	0	02	40
	1292	0	02	50
	1257	0	05	00
	1258	0	01	50
	1254	0	03	70
	1253	0	04	00
	1221	0	07	10
	1229	0	07	00
	1228	0	04	80
	1224	0	04	00
	1225	0	02	20
	1227	0	02	50
	1226	0	00	60
	1114	0	01	50
	1113	0	12	00
	1120/1	0	02	01
	1103	0	09	30
	999	0	06	30
	1106	0	02	00
	932/1	0	05	00
	933/1	0	04	00
	933/2	0	03	60
	932/2	0	03	40
	930	0	04	00
	1719	0	00	10
	1717	0	00	30
	1661	0	00	11

[सं. ओ. 11027/19/88--ओ एन जी डी-III]

S.O. 900.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1895 dated 8-6-88 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this noitfication hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline for K.N.K. Phase II

State : Gujarat District : Kheda Taluka : Nadiad

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
1	2	3	4	5
Pij	2065	0	07	20
	2063	0	09	80
	Cart track	0	01	00
	2070	0	03	50
	2089	0	06	20
	Cart track	0	00	50
	2014	0	04	10
	2013	0	00	35
	2012	0	17	30
	1785	0	07	20
	1786	0	02	30
	1787	0	02	00
	1788	0	05	90
	1772	0	03	80
	1790	0	08	00
	1770	0	06	00
	1769	0	10	50
	1720	0	03	00
	1721	0	02	20
	1722	0	04	60
	1660	0	09	80
	1643	0	03	50
	1642	0	10	00
	1640	0	10	30
	1639	0	04	00
	1638	0	03	70
	1637	0	11	60
	1635	0	04	20
	1333	0	01	50
	1332	0	07	50
	1331	0	07	40
	1329	0	05	00
	1328	0	03	90
	1327	0	02	30
	1326	0	05	00
	1325	0	00	50
	1324	0	07	00
	1288	0	02	00
	1294	0	03	00
	1293	0	02	40
	1292	0	02	50
	1257	0	05	00
	1258	0	01	50
	1254	0	03	70
Pij Contd.	1253	0	04	00
	1221	0	07	10
	1229	0	07	00
	1228	0	04	80
	1224	0	04	00
	1225	0	02	20
	1227	0	02	50
	1226	0	00	60
	1114	0	01	50
	1113	0	12	00
	1120/1	0	02	01
	1103	0	09	30
	999	0	06	30
	1106	0	02	00
	932/1	0	05	00
	933/1	0	04	00
	933/2	0	03	60
	932/2	0	03	40
	930	0	04	00
	1719	0	00	10
	1717	0	00	30
	1661	0	00	11

[No. O-11027/19/88-ONG-D. -III]

का.ग्रा. 901—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 1898 तारीख 8-6-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कलोल से नवागाम से कोयली तक फेज-II को पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : खेड़ा तालुका : मातर

गांव	ब्लाक नं.	हैक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
पणसोली	369	0	13	50
	365	0	07	00
	377	0	07	00
	351	0	09	60

1	2	3	4	5
पंसोली--जारी	350	0	06	00
	348/1	0	03	50
	348/2	0	05	00
	340	0	09	20
	341	0	03	00
	336	0	00	35
	328	0	06	50
	326	0	09	50
	320/ए+बी	0	19	70
	212	0	10	00
	221	0	05	60
	223	0	05	20
	232	0	03	60
	233	0	03	10
	234	0	04	90
	235	0	02	50
	231	0	05	00
	237	0	03	70
	238	0	03	50
	236	0	00	30
	352	0	16	00
	284	0	08	00
	292	0	08	00

[सं. ओ-11027/136/88-ओ एन जी-डी-II]

S.O. 901.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1898 dated 8-6-88 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline for K.N.K. Phase II.

State : Gujarat District : Kheda Taluka : Matar

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cen tiare
1	2	3	4	5
Pansoli	369	0	13	50
	365	0	07	00
	377	0	07	00
	351	0	09	60
	350	0	06	00
	348/1	0	03	50
Pansoli— Contd.	348/2	0	05	00
	340	0	09	20
	341	0	03	00
	336	0	00	35
	328	0	06	50
	326	0	09	50
	320/A+B	;0	19	70
	212	0	10	00
	221	0	05	60
	223	0	05	20
	232	0	03	60
	233	0	03	10
	234	0	04	90
	235	0	02	50
	231	0	05	00
	237	0	03	70
	238	0	03	50
	236	0	00	30
	352	0	16	00
	284	0	08	00
	292	0	08	00

[No. O-11027/136/88-ONG-D.-III]

का.आ. 902--यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. . 521 तारीख 29-1-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था

और यतः सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

के.एन.के. फेस-2 की पाइप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : खेड़ा तालुका : आनन्द

गांव	सर्वे नं.	हैक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
मोगरी	675	0	07	60
	676/1×2	0	01	5

1	2	3	4	5
मोगरी--जारी	677/1	0	17	80
	715	0	06	80
	731+714	0	16	60
	718	0	00	54
	712/2	0	22	00
	719	0	17	00
	706+707/2	0	13	90
	705 } 732 }	0	23	20
	784/1	0	11	60
	784/2	0	21	00
	783	0	12	20
	787	0	01	80
	788	0	16	32
	790	0	11	70
	781	0	00	42
	789	0	12	27
	791	0	06	90
	794	0	19	00
	795	0	09	90
	964	0	12	99
	963	0	03	94
	962	0	08	69
	1042/4	0	14	33
	1045	0	00	20
	कार्ट ट्रैक	0	00	50
	1043	0	00	30
	1042/3	0	14	00
	1047	0	18	50
	1046	0	06	65
	1048	0	00	03
	1050	0	14	70
	1049	0	11	80
	1025	0	01	68
	1026	0	17	80
	1024	0	05	11
	1029	0	00	72
	1023	0	05	30
	1022	0	11	80
	1021	0	10	90
	1018	0	10	60
	कार्ट ट्रैक	0	01	00
	1216	0	01	73
	1217	0	21	72
	1218	0	13	00
	1219	0	09	20
	1222	0	02	67

[सं. ओ-11027/15/88-ओएन जी-डी-III]

S.O. 902.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 521 dated 29-1-88 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline for KNK Phase II.

State : Gujarat District : Kheda Taluka : Anand

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Mogari	675	0	07	60
	676/1+2	0	01	55
	677/1	0	17	80
	715	0	06	80
	713+714	0	16	60
	718	0	00	54
	712/2	0	22	00
	719	0	17	00
	706+707/2	0	13	90
	705	0	23	20
	732	0	11	60
	784/1	0	21	00
	784/2			
	783	0	12	20
	787	0	01	80
	788	0	16	32
	790	0	11	70
	781	0	00	42
	789	0	12	27
	791	0	06	90
	794	0	19	00
	795	0	09	00
	964	0	12	99
	963	0	03	94
	962	0	08	69
	1042/4	0	14	33
	1045	0	00	20
	Cart track	0	00	50
	1043	0	00	30
	1042/3	0	14	00
	1047	0	18	50
	1046	0	06	65
	1048	0	00	03
	1050	0	14	70
	1049	0	11	80
	1025	0	01	68
	1026	0	17	80
	1024	0	05	11
	1029	0	00	72
	1023	0	05	30
	1022	0	11	80
	1021	0	10	90
	1018	0	10	60
	Cart track	0	01	00
	1216	0	01	73
	1217	0	21	72
	1218	0	13	00
	1219	0	09	20
	1222	0	02	67

[No. L-11027/15/88-ONG-D. III]

का.आ. 903—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 700 तारीख 5-2-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाईनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

के.एन.के. फैस-II की पाइप लाईन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : दसक्रोई

गांव	ब्लाक नं.	हैक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
बारेजा	412	0	07	60
	417	0	21	50
	414	0	03	10
	411	0	06	10
	418	0	13	10
	420	0	21	50
	422	0	03	60
	421	0	02	00
	431	0	10	50
	कार्ट ट्रेक	0	01	00
	432	0	09	30
	437	0	09	00
	439	0	11	30
	455	0	15	40
	456	0	04	00
	396	0	08	90
	कार्ट ट्रेक	0	01	00
	262	0	00	80
	263	0	16	50
	264	0	08	80
	265	0	08	10
	242	0	22	30

1	2	3	4	5
बारेजा—जारी	198	0	07	60
	कार्ट ट्रेक	0	01	00
	201	0	15	50
	200	0	00	30
	202	0	16	30
	190	0	08	00
	188	0	07	60
	189	0	02	60
	187	0	16	00
	166	0	12	50
	167	0	06	50
	62	0	04	00
	67	0	06	50
	75	0	16	00
	79	0	10	50
	83	0	13	70
	2500	0	25	20
	2486	0	03	30
	2499	0	05	00
	2491	0	05	40
	2494	0	13	50
	2472	0	09	00
	2471	0	00	20
	2473	0	07	50
	2466	0	08	40
	2465	0	00	80
	2464	0	06	50
	2463	0	01	80
	2454	0	05	00
	2455	0	06	50
	2452	0	12	20
	2451	0	10	90
	2450	0	08	50

[सं० ओ- 11027/51/88-ओ० एन० जी०-डी-III]

S.O. 903.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 700 dated 5-2-88 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has ,after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline for KNK Phase II

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Daskroi

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Baraja	412	0	07	60
	417	0	21	50
	414	0	03	10
	411	0	06	10
	418	0	13	10
	420	0	21	50
	422	0	03	60
	421	0	02	00
	431	0	10	50
	Cart track	0	01	00
	432	0	09	30
	437	0	09	00
	439	0	11	30
	455	0	15	40
	456	0	04	00
	396	0	08	90
	Cart track	0	01	00
	262	0	00	80
	263	0	16	50
	264	0	08	80
	265	0	08	10
	242	0	22	30
	198	0	07	60
	Cart track	0	01	00
	201	0	15	50
	200	0	00	30
	202	0	16	30
	190	0	08	00
	188	0	07	60
	189	0	02	60
	187	0	16	00
	166	0	12	50
	167	0	06	50
	62	0	04	00
	67	0	06	50
	75	0	16	00
	79	0	10	50
	83	0	13	70
	2500	0	25	20
	2486	0	03	30
	2499	0	05	00
	2491	0	05	40
	2494	0	13	50
	2472	0	09	00
	2471	0	00	20
	2473	0	07	50
	2466	0	08	40
	2465	0	00	80
	2464	0	06	50
	2463	0	01	80
	2454	0	05	00
	2455	0	06	50
	2452	0	12	20
	2451	0	10	90
	2450	0	08	50

[No. O-11027/51/88-ONG-D. III]

का. आ. 904.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 698 तारीख 5-2-89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

के.एन.के. फेस II की पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात जिला : खेड़ा तालुका : वड़ीपाव

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आर	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
मिजाल	06	0	00	24
	807	0	14	00
	809	0	00	15
	810	0	03	00
	817	0	04	80
	816	0	00	25
	815	0	05	00
	818	0	02	50
	859	0	11	10
	858	0	09	50
	876	0	20	00
	935	0	03	00
	933	0	05	70
	931	0	05	90
	932	0	00	60
	927	0	06	50
	1067	0	07	50
	1068	0	04	50
	1069	0	01	20
	1111	0	00	25
	1112	0	02	60
	1113	0	03	30

1	2	3	4	5
मित्राल---चालू	1114	0	02	10
	1115	0	04	30
	1116	0	03	70
	1218	0	01	25
	1220			
	1221	0	04	50
	1236	0	04	70
	1235	0	02	50
	1249	0	04	20
	1281	0	05	00
	1279	0	06	50
	1295	0	05	70
	1311	0	10	80
	1313	0	09	50
	1324	0	13	50
	1333	0	09	20
	1334	0	04	00
	1336	0	06	50
	1339	0	02	70
	1340	0	05	20
	1345	0	04	00
	1351	0	03	70
	1352	0	03	80
	1569	0	00	55
	926	0	01	20
	1237	0	01	10
	1248	0	00	50
	1234	0	01	10
	1344	0	00	30
	808	0	03	76

[सं. ओ-11027/49/88-ओएनजी-डी-III]

S.O. 964.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 698 dated 5-2-88 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline for KNK Phase II.

State : Gujarat District : Kheda Taluka : Nadiad

Village	Block No.	Hec-tare	Area	Cen-tiare
1	2	3	4	5
MITRAL	806	00	00	24
	807	0	14	00
	809	0	00	15
	810	0	03	00
	817	0	04	80
	816	0	00	25
	815	0	05	00
	818	0	02	50
	859	0	11	10
	858	0	09	50
	876	0	20	00
	935	0	03	00
	933	0	05	70
	931	0	05	40
	932	0	00	60
	927	0	06	50
	1067	0	07	50
	1068	0	04	50
	1069	0	01	20
	1111	0	00	25
	1112	0	02	60
	1113	0	03	30
	1114	0	02	10
	1115	0	04	30
	1116	0	03	70
	1218	0	01	25
	1220	0	04	50
	1221	0	04	70
	1236	0	02	50
	1235	0	04	20
	1249	0	05	00
	1281	0	06	50
	1279	0	05	70
	1295	0	10	80
	1311	0	09	50
	1313	0	13	50
	1324	0	01	20
	1333	0	04	00
	1334	0	04	00
	1336	0	06	50
	1339	0	02	70
	1340	0	05	20
	1345	0	04	00
	1351	0	03	70
	1352	0	03	80
	1569	0	00	55
	926	0	01	20
	1237	0	01	10
	1248	0	00	50
	1234	0	01	10
	1344	0	00	30
	808	0	03	76

[No. O-11027/49/88-ONG-D. III]

का. आ. 905.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. 1639 तारीख 20-4-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि-में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

नोर्थ कडी सी टी. एफ से सरखेज तक पाइपलाइन बिछाने के लिये

राज्य : गुजरात जिला –अमदावाद तालुका –सीटी

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर	से.
सरखेज	182/1+2+3	0	16	00
	185/2	0	12	60
	186	0	1	00
	कोर्ट ट्रेक	0	02	10
	175	0	07	40
	176	0	13	00
	174/1	0	04	10
	174/2	0	15	90
	173/1	0	24	40
	173/2	0	10	00
	170	0	00	20
	171	0	12	40
	172	0	04	30
	140	0	17	10
	139/1/1	0	05	80
	139/3	0	01	40
	139/4/1	0	00	50
	139/4/2	2	00	05
	139/4/3+4+5	0	10	20
	138/2	0	00	22
	132	0	17	40
	144	0	00	20
	125/3	0	04	00
	125/4	0	00	70
	127/1	0	11	80
	128	0	08	20
	129/1	0	01	80
	126/2	0	09	80
	191/1+2	0	06	00
	90	0	01	12
	92	0	22	60
	65	0	09	60
	64	0	18	20
	कोर्ट ट्रेक	0	01	50
	63	0	01	10
	61	0	17	10
	62/1+2	0	07	40
	59	0	12	40
	58	0	00	54
	56	0	34	00

[सं. ओ-11027/105/88-ओ एन जी-डी-III]

के. विवेकानन्द, डेस्क अधिकारी

S.O. 905.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1639 dated 20-4-88 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to tihs notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

North Kadi ctf to Sarkhej pipeline

State : Gujarat District : Amadavad Taluka City

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Sarkhej	182/1+2+3	0	16	00
	185/2	0	12	60
	186	0	01	00
	Cart Track	0	02	10
	175	0	07	40
	176	0	13	00
	174/1	0	04	10
	174/2	0	15	90
	173/1	0	24	40

1	2	3	4	5
	173/2	0	10	00
	170	0	00	20
	171	0	12	40
	172	0	04	30
	140	0	17	10
	139/1/1	0	05	80
	139/3	0	01	40
	139/4/1	0	00	50
	139/4/2	0	00	05
	139/4/3+ 4+5	0	10	20
	138/2	0	00	22
	132	0	17	40
	144	0	00	20
	125/3	0	04	00
	125/4	0	00	70
	127/1	0	11	80
	128	0	08	20
	129	0	00	10
	126/1	0	01	80
	126/2	0	09	80
	191/1+2	0	06	00
	90	0	01	12
	92	0	22	60
	65	0	09	60
	64	0	18	20
	Cart Track	0	01	50
	63	0	01	10
	61	0	17	10
	62/1+2	0	07	40
	59	0	12	40
	58	0	00	54
	58	0	00	54
	56	0	34	00

[No. O-11027/105/88-ONG-D.III]

K. VIVEKANAND, Desk Officer

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1989

का. आ. 906 :—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है ;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. राजस्व/21/88, तारीख 26-8-1988 का निरीक्षण सेंट्रल कोलफील्ड्स लि., राजस्व अनुभाग, दरभंगा हाउस, रांची-834001 (बिहार) के कार्यालय अथवा उपायुक्त हजारीबाग (बिहार) के कार्यालय में अथवा कोयला नियंत्रक 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता-700001 के कार्यालय में किया जा सकता है ।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर राजस्व अधिकारी, सेंट्रल कोलफील्ड्स लि., दरभंगा हाउस रांची-834001 (बिहार) को भेजेंगे ।

अनुसूची

ब्लाक - "ङ" (दामोदर नदी तल)

दक्षिण करणपुरा कोयला क्षेत्र

जिला हजारी बाग (बिहार)

पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि

क्रम सं०	ग्राम	थाना	थाना सं.	जिला	प्लाट सं.	क्षेत्र एकड़ में	टिप्पणियां
1.	सौंदा	रामगढ़	24	हजारी बाग		25.98	भाग

कुल क्षेत्र : 25.98 (एकड़) (लगभग)
या 10.51 हैक्टर (लगभग)

सीमा वर्णन :

क—ख रेखा दामोदर नदी की केन्द्रीय रेखा के भाग के साथ-साथ जाती है (जो कि ग्राम सौंदा और गिद्दी की भाग सामान्य सीमा है)

ख—ग रेखा दामोदर नदी में से होकर जाती है (जो ग्राम सौंदा में प्लाट सं. 685 और 1 की भाग सामान्य सीमा है) ।

ग—घ रेखा ग्राम सौंदा में दामोदर नदी में से होकर जाती है ।

घ—ङ रेखा ग्राम सौंदा में दामोदर नदी के भाग बायें किनारे के साथ-साथ जाती है ।

ङ—क रेखा दामोदर नदी में से होकर जाती है (जो ग्राम सौंदा और सयाल की भाग सामान्य सीमा है) ।

[सं. 43015/15/88-एस एल डब्ल्यू]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 21st March, 1989

S.O. 906.—Whereas it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from the land mentioned in the schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein;

The plan No. Rev/21/88 dated the 26th August, 1988 of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Central Coalfields Limited, Revenue section, Darbhanga House, Ranchi-834001 (Bihar) or in the Office of the Deputy Commissioner, Hazaribagh (Bihar) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta-700001.

All persons interested in the land covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer, Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi-834001 (Bihar) within ninety days from the date of the publication of this notification.

SCHEDULE

BLOCK—'E' (DAMODAR RIVER BED)

SOUTH KARANPURA COALFIELD

DISTRICT HAZARIBAGH (BIHAR)

Showing land notified for prospectin

Serial No.	Village	Thana	Thana number	District	Plot number	Area in acres	Remarks
1.	Saunda	Ramgarh	24	Hazaribagh	—	25.98	Part

Total Area :— 25.98 acres (approximately)
or 10.51 hectares (approxamately)

Boundary description :—

A—B line passes along the part Central line of Damodar River (which is part common boundary of villages Saunda and Gidi.

B—C line passes through Damodar River (which is the part common boundary of plot numbers 605 and 1 in village Saunda.

C—D line passes through Damodar River in village Saunda.

D—E line passes along the part Right bank of Damodar River in village Saunda.

E—A line passes through Damodar River (which is the part common boundary of villages Sauda and Sayal.

[No. 43015/15/88-LSW]

का. आ. 907.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है:

अतः, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है ;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. सी-1 (ई) III जे जे आर 425-0988, तारीख 22 सितम्बर, 1988 का निरीक्षण वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (राजस्व विभाग) कोल एस्टेट, सिविल लाइन्स नागपुर-440001 (महाराष्ट्र) के कार्यालय या कलक्टर, यवतमाल (महाराष्ट्र) के कार्यालय में अथवा कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, राजस्व अधिकारी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि., कोल एस्टेट, सिविल लाईन्स, नागपुर-440001 (महाराष्ट्र) को भेजेंगे।

अनुसूची

चिचला ब्लाक

वानी क्षेत्र

जिला यवतमाल (महाराष्ट्र)

पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल सं.	तहसील	जिला	क्षेत्र एकड़ में	टिप्पणियां
1.	राजूर	25	वानी	यवतमाल	50.00	भाग
2.	बोरडा	25	वानी	"	55.00	भाग
3.	चिचला	25	वानी	"	2.00	भाग

1	2	3	4	5	6	7
4.	दुर्गावा	25	वानी	यवतमाल	74.94	पूरा
5.	भांडेवाडा	21	वानी	,,	153.00	भाग
6.	नेत	20	मोरेगांव	,,	272.68	पूरा
7.	गावाराला	20	मोरेगांव	,,	65.00	भाग
8.	वरुड	20	मोरेगांव	,,	425.00	भाग
9.	सालेभट्टी	20	मोरेगांव	,,	4.00	भाग
10.	चिंचाला	19	मोरेगांव	,,	400.00	भाग
11.	पथारी	19	मोरेगांव	,,	8.00	भाग
12.	अकापुर	10	मोरेगांव	,,	215.00	भाग
13.	लखापुर	10	मोरेगांव	,,	30.00	भाग
14.	खदाकी	10	मोरेगांव	,,	13.00	भाग

कुल क्षेत्र : 1767062 हैक्टेयर (लगभग)
या 4367.96 एकड़ (लगभग)

सीमा वर्णन :

क–ख रेखा "क" बिन्दु से भारंभ होकर ग्राम राजुर, बोडड, निबंला से होकर जाती है भौर बिन्दु "ख" पर मिलती है ।

ख–ग रेखा ग्राम निबंला, बोडड, गावाराला, वरूड़, सालेभाटी, चिंचला, पथारी से होकर जाती है भौर बिन्दु "ग" पर मिलती है ।

ग–घ रेखा ग्राम पथारी, चिंचला, खदाकी, से होकर जाती है भौर बिन्दु "घ" पर मिलती है ।

घ–ङ रेखा ग्राम खदाकी, भकापुर, लखापुर, भंडेवाडा से होकर जाती है भौर बिन्दु "ङ" पर मिलती है ।

ङ–क रेखा ग्राम भंडेवाडा, राजुर से होकर जाती है भौर भारंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है ।

सं. [3015/3/89-एस एस डब्ल्यू)]

S.O. 907.—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein;

The plan bearing No. C-1(E) III/JJR/425-0988 dated 22nd September, 1988 of the area covered by this notification can be inspected at the office of the Western Coalfields Limited (Revenue Department), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440001 (Maharashtra) or at the office of the Collector, Yavatmal (Maharashtra) or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta.

All persons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer, Western Coalfields Limited, Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440001 (Maharashtra) within ninety days from the date of publication of this notification.

SCHEDULE

CHINCHALA BLOCK

WANI AREA

DISTRICT YAVATMAL (MAHARASHTRA)

Sl. No.	Name of the village	Patwari circle No.	Tahsil	District	Total area in hectares.	Remarks
1.	Rajur	25	Wani	Yavatmal	50.00	Part
2.	Bodad	25	Wani	Yavatmal	55.00	Part
3.	Nimbala	25	Wani	Yavatmal	2.00	Part
4.	Du gada	25	Wani	Yavatmal	74.94	Full
5.	Bhandewada	21	Wani	Yavatmal	153.00	Part
6.	Net	20	Maregaon	Yavatmal	272.68	Full
7.	Gawarala	20	Maregaon	Yavatmal	65.00	Part
8.	Warud	20	Maregaon	Yavatmal	425.00	Part
9.	Salebhati	20	Maregaon	Yavatmal	4.00	Part
10.	Chinchala	19	Maregaon	Yavatmal	400.00	Part
11.	Patha i	19	Maregaon	Yavatmal	8.00	Part
12.	Akapur	10	Maregaon	Yavatmal	215.00	Part
13.	Lakhapur	10	Maregaon	Yavatmal	30.00	Part
14.	Khadaki	10	Maregaon	Yavatmal	13.00	Part

Total area : 1767.62 hectares (approximately)
or
4367.96 acres (approximately).

Boundary description :

A—B — Line starts from point 'A' passes through villages Rajur, Bodad, Nimbala and meets at point 'B'.

B—C — Line passes through villages Nimbala, Bodad, Gawarala, Warud, Salebhati, Chinchala, Pathari and meets at point 'C'.

C—D — Line passes through villages Pathari, Chinchala, Khadaki and meets at point 'D'.

D—E — Line passes through villages Khadaki, Akapur, Lakhapur, Bhandewada and meets at point 'E'.

E—A — Line passes through villages Bhandewada, Rajur and meets at starting point 'A'.

[No. 43015/3/89-LSW]

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1989

का. आ. 908.—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 13 जून, 1987 में प्रकाशित भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 1481 तारीख 26 मई, 1997 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में जो इस अधिसूचना के उपाबद्ध अनुसूची में भी विनिर्दिष्ट है, 3863.42 हैक्टयर (लगभग) या 9542.65 एकड़ (लगभग) माप की भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन उक्त भूमि की बाबत कोई सूचना नहीं दी गई है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 13 जून 1989 से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि को ऐसी और अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिस अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार उक्त भूमि को या ऐसी भूमि में या ऐसी भूमि पर किन्हीं अधिकारों को अर्जित करने के अपने आशय की सूचना दे सकेगी।

अनुसूची

मनगांव ब्लाक

वानी क्षेत्र

जिला यावतमाल और चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल सं.	ग्राम सं.	तहसील	जिला	क्षेत्र हैक्टर में	टिप्पणियां
1.	सेल (खुर्द)	39	365	वानी	यवतमाल	243.20	भाग
2.	नानदेपेरा	16	175	वानी	यवतमाल	181.00	भाग
3.	भुरकी	27	259	वानी	यवतमाल	551.63	पूरा
4.	रंगाने	22	310	वानी	यवतमाल	528.00	भाग
5.	वाडगांव (टीआईपी)	34	332	वानी	यवतमाल	85.00	भाग
6.	ओला	23	129	वानी	यवतमाल	20.00	भाग
7.	करंजी	13	44	वरोरा	चन्द्रपुर	365.00	भाग
8.	शेमबाल	13	533	वरोरा	चन्द्रपुर	445.00	भाग
9.	मनगांव	3	384	भद्रावती	चन्द्रपुर	490.20	पूरा
10.	कुसना	2	82	भद्रावती	चन्द्रपुर	34.40	भाग
11.	नागलोन	2	281	भद्रावती	चन्द्रपुर	40.50	भाग
12.	रालेगांव	3	443	भद्रावती	चन्द्रपुर	263.35	पूरा
13.	पटाला	3	304	भद्रावती	चन्द्रपुर	196.00	भाग
14.	थोराना	3	251	भद्रावती	चन्द्रपुर	357.14	पूरा
15.	टुलाना	14	247	वरोरा	चन्द्रपुर	63.00	भाग
				कुल क्षेत्र :		3863.42 हैक्टर (लगभग) या 9542.65 एकड़ (लगभग)	

सीमा वर्णन :

क–ख रेखा "क" बिन्दु से आरम्भ होती है और नानदेपेरा सेलून (खुर्द) ग्रामों से होकर गुजरती हुई वर्धा नदी पार करती है, फिर ग्राम करंजी, टुलाना से गुजरती हुई बिन्दु "ख" पर मिलती है।

ख–ग रेखा, टुलाना, शेमबाल, कुसना ग्रामों से गुजरती है और "ग" बिन्दु पर मिलती है।

ग–घ–ङ रेखा, नागलोन, पटाला ग्रामों से गुजरती है, वर्धा नदी पार करती है, फिर ओला, वाडगांव (टी आई पी) से गुजरती हुई बिन्दु "ङ" पर मिलती है।

ङ–क रेखा वाडगाव (टी आई पी), रंगाने, नानदेपेरा ग्रामों से गुजरती है और आरंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

[सं. 43015/5/87-सी.ए.एल.एस.डब्ल्यू.]

New Delhi, the 28th March, 1989

S.O. 908.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) number S.O. 1481 dated the 26th May, 1987, under sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in Part-II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India dated the 13th June, 1987, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in lands measuring 3863.42 hectares (approximately) or 9542.65 acres (approximately) in the locality specified in the schedule appended thereto as also in the schedule hereto annexed;

And whereas in respect of the said lands, no notice under sub-section (1) of section 7 of the said Act has been given.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act the Central Government hereby specifies a further period of one year commencing from the 13th June, 1989 as the period within which the Central Government may give notice of its intention to acquire the said lands or any rights in or over such lands.

SCHEDULE

MANGAON BLOCK

WANI AREA

DISTRICT YAVATMAL AND CHANDRAPUR (MAHARASHTRA)

Sl. No.	Name of village	Patwari Circle number	Village number	Tashil	District	Area in hectares	Remarks
1.	Selu (Khurd)	39	365	Wani	Yavatmal	243.20	Part
2.	Nandepera	16	175	Wani	Yavatmal	181.00	Part
3.	Bhurki	27	259	Wani	Yavatmal	551.63	Full
4.	Rangane	22	310	Wani	Yavatmal	528.00	Part
5.	Wadgaon (Tip)	34	332	Wani	Yavatmal	85.00	Part
6.	Jhola	23	129	Wani	Yavatmal	20.00	Part
7.	Karanji	13	44	Warora	Chandrapur	365.00	Part
8.	Shembal	13	533	Warora	Chandrapur	445.00	Part
9.	Mangaon	3	384	Bhadrawati	Chandrapur	490.20	Full
10.	Kusna	2	82	Bhadrawati	Chandrapur	34.40	Part
11.	Naglon	2	281	Bhadrawati	Chandrapur	40.50	Part
12.	Ralegaon	3	443	Bharawati	Chandrapur	263.35	Full
13.	Patala	3	304	Bhadrawati	Chandrapur	196.00	Part
14.	Thorana	3	251	Bhadrawati	Chandrapur	357.14	Full
15.	Tulana	14	247	Warora	Chandrapur	63.00	Part

Total area : 3863.42 hectares (approximately), or 9542.65 acres a (approximately).

Boundary description :

A—B — Line starts from point 'A' and passes through villages Nandepera, Selu (Khurd), crosses Wardha River, then proceeds throug villages Karanji, Tulana and meets at point 'B'.

B—C — Line passes through villages Tulana, Shembal, Kusna and meets at point 'C'.

C-D-E— Line passes through villages Naglon, Patala, crosses Wardha River, then proceeds through villages Jhola, Wadgaon (Tip) and meets at point 'E'.

E—A : Line passes through villages Wadgaon (Tip), Rangane, Nandepera and meets at the starting point 'A'.

[No. 43015/5/87-CA/LSW]

का. आ. 909—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 2 मई, 1988 में प्रकाशित, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 1136, तारीख 16 अप्रैल 1987 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में भी विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में, जिसका माप 633.15 हैक्टर (लगभग) या 1563.88 एकड़ (लगभग) है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन उक्त भूमि के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उक्त उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 2 मई, 1989 से आरम्भ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार उक्त भूमियों में या उन पर के किन्हीं अधिकारों के अर्जन के अपने आशय की सूचना दे सकेगी ।

अनुसूची

जुनाड ब्लाक
वानी कोलफील्ड
जिला यवतमाल और चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)

क. सं.	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल सं.	ग्राम सं.	तहसील	जिला	क्षेत्र हैक्टरों में	टिप्पणियां
1.	अहेरी	32	12	वानी	यवतमाल	23.53	भाग
2.	बोरगांव	33	247	वानी	यवतमाल	211.08	भाग
3.	पिंपलगांव	33	218	वानी	यवतमाल	105.70	भाग
4.	जुनाड	33	122	वानी	यवतमाल	199.44	भाग
5.	उकानी	34	21	वानी	यवतमाल	34.40	भाग
6.	तेलवासा	28	249	भद्रावती	चन्द्रपुर	7.80	भाग
7.	पिपरी	29	311	भद्रावती	चन्द्रपुर	51.20	भाग

कुल क्षेत्र 633.15 हैक्टर (लगभग)
या 1563.88 एकड़ (लगभग)

सीमा वर्णन :

क–ख रेखा, बिन्दु "क" से प्रारम्भ होकर ग्राम उकानी, पिंपलगांव, जुनाड, बोरगांव और अहेरी के बीच से गुजरती है और बिन्दु "ख" पर मिलती है।

ख–ग रेखा, वर्धा नदी के दक्षिणी और पश्चिमी किनारे के साथ-साथ ग्राम अहेरी और बोरगांव के बीच से गुजरती है और बिन्दु "ग" पर मिलती है।

ग–घ रेखा, वर्धा नदी के पूर्वी किनारे के साथ जाती है फिर ग्राम जुनाड के बीच से होकर आगे बढ़ती है, वर्धा नदी को पार करती है और ग्राम तेलवासा और पिपरी के बीच से होकर बढ़ती है और बिन्दु "घ" पर मिलती है।

घ–क रेखा, ग्राम पिपरी के बीच से जाती है, वर्धा नदी पार करती है, ग्राम उकानी के बीच से होकर बढ़ती है और प्रारम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

बी. बी. राव, अवर सचिव

[सं. 43015/20/86-सी.ए./एस.एल.डब्ल्यू.]

S.O. 909.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) number S.O. 1136 dated the 16th April, 1987, under sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in Part-II Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India dated the 2nd May, 1987, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in lands measuring 633.15 hectares (approximately) or 1563-88 acres (approximately) in the locality specified in the schedule appended thereto as also in the schedule hereto annexed;

And whereas in respect of the said lands, no notice under sub-seciton (1) of Section 7 of the said Act has been given.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the said sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby specifies a further period of one year commencing from the 2nd May, 1989 as the period within which the Central Central Government may give notice of its intention to acquire the said lands or any rights in or over such lands.

SCHEDULE
JUNAD BLOCK
WANI COALFIELD
DISTRICT YEVATMAL AND CHANDRAPUR (MAHARASHTRA)

Serial number	Name of village	Patwari circle number	Village number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1.	Aheri	32	12	Wani	Yevatmal	23.53	Part
2.	Borgaon	33	247	Wani	Yevatmal	211.08	Part
3.	Pimpalgaon	33	218	Wani	Yevatmal	105.70	Part
4.	Junad	33	122	Wani	Yevatmal	199.44	Part
5.	Ukani	34	21	Wani	Yevatmal	34.40	Part
6.	Telwasa	28	249	Bhadrawati.	Chandrapur	7.80	Part
7.	Pipri	29	311	Bhadrawati.	Chandrapur	51.20	Part

Total area : 633.15 hectares (approximately)
or
1563.88 acres (approximately)

Boundary description :

A – B - Line starts from point 'A' and passes through villages Ukani, Pimpalgaon, Junad, Borgaon and Aheri and meets at point 'B'.

B – C - Line passes through villages Aheri and Borgaon along the sourthern and western bank of Wardha River and meets at point 'C'.

C - D – Line passes along the eastern bank of Wardha River, then proceeds through villages Junad, crosses Wardha River, and proceeds through village Telwasa and Pipri and meets at point 'D'.

D - A – Line passes through village Pipri, crosses Wardha Rive , proceeds through village Ukani and meets at starting point 'A'.

B.B. RAO, Under Secy.

[No.43015/20/86-CA/LSW)]

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1989

का. आ. 910.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 2 मई, 1987 में प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 1140, तारीख 16 अप्रैल, 1987 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में और इस से संलग्न अनुसूची में भी विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 36930.73 हैक्टर (लगभग) या 91259.52 एकड़ (लगभग) माप की भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना नहीं दी गई है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उक्त उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 2 मई, 1989 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की उस अवधि को उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार उक्त भूमि को या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के अर्जन की सूचना दे सकेगी।

अनुसूची

लोहारा आगारझारी ब्लाक

चन्द्रपुर कोलफील्ड्स

जिला चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)

क्रम सं	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल सं	ग्राम संख्यांक	तहसील और जिला	हैक्टर में क्षेत्र	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	आडेगांव	12		चन्द्रपुर	227.32	संपूर्ण
2.	आगारझारी	12		चन्द्रपुर	135.55	संपूर्ण
3.	पैली भटाली	12		चन्द्रपुर	1157.00	भाग
4.	किटाडी	12		चन्द्रपुर	338.11	भाग
5.	पद्मापुर	12		चन्द्रपुर	172.24	भाग
6.	म्हासाला रिठ	12		चन्द्रपुर	105.00	संपूर्ण
7.	म्हासाला तुकुम	12		चन्द्रपुर	108.56	संपूर्ण
8.	सिनाला	12		चन्द्रपुर	374.62	भाग
9.	वारवत	12		चन्द्रपुर	862.36	संपूर्ण
10.	चोरगांव	12		चन्द्रपुर	1214.68	संपूर्ण
11.	खंडाला रिठ	12		चन्द्रपुर	1201.00	संपूर्ण
12.	मामला मोकासा	12		चन्द्रपुर	282.28	संपूर्ण
13.	निम्बाला	13		चन्द्रपुर	316.17	संपूर्ण
14.	चक निम्बाला	13		चन्द्रपुर	769.52	संपूर्ण
15.	वाईगांव मोकासा	13		चन्द्रपुर	102.65	संपूर्ण
16.	चक वाईगांव सं 1	13		चन्द्रपुर	201.14	संपूर्ण
17.	चक वाईगांव सं	13		चन्द्रपुर	107.28	संपूर्ण
18.	चक बोरडा	13		चन्द्रपुर	935.67	संपूर्ण
19.	बोरडा झुल्लापवार	13		चन्द्रपुर	144.96	संपूर्ण
20.	वालनी	13		चन्द्रपुर	376.28	संपूर्ण
21.	चकवालनी	13		चन्द्रपुर	64.78	संपूर्ण
22.	चिकपल्ली	15		चन्द्रपुर	754.40	संपूर्ण
23.	चिकपल्ली उर्फ चक अजयपुर	15		चन्द्रपुर	816.96	संपूर्ण
24.	सेमता	15		चन्द्रपुर	26.99	संपूर्ण
25.	जम्माराला	15		चन्द्रपुर	72.48	संपूर्ण
26.	घंटा चौकी	13		चन्द्रपुर	19.67	संपूर्ण
27.	लोहारा	13		चन्द्रपुर	133.53	संपूर्ण
28.	मोहारली रेंज	चन्द्रपुर डिवीजन		चन्द्रपुर	9058.40	भाग
29.	चन्दा रेंज	चन्द्रपुर डिवीजन		चन्द्रपुर	12188.53	भाग
30.	मूल रेंज	चन्द्रपुर डिवीजन		चन्द्रपुर	4663.58	भाग

कुल क्षेत्र : 36930.73 हैक्टर (लगभग) या 91259.52 एकड़ (लगभग)

सीमा वर्णन :

क-ख रेखा, "क" बिन्दु से प्रारंभ होती है और देवाडा ग्राम की दक्षिणी सीमा, सड़क के साथ-साथ मोहारली रेंज से होकर जाती है फिर सड़क के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ख" पर मिलती है।

ख-ग रेखा, अन्धारी नदी के पश्चिमी तट के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ग" पर मिलती है।

ग-घ रेखा, मूल रेंज से होकर जाती है और बिन्दु 'घ' पर मिलती है।

घ-ङ रेखा, दक्षिण-पूर्व रेल की उत्तरी सीमा के साथ-साथ मूल और चन्दा रेंज से होकर जाती है और बिन्दु 'ङ' पर मिलती है।

ङ-च रेखा, चन्दा रेंज से होकर जाती है और बिन्दु 'च' पर मिलती है।

च-छ रेखा, ग्राम सिहाला, पदमापुर और किटाडी से होकर जाती है और बिन्दु 'छ' पर मिलती है।

छ-क रेखा, ग्राम किटाडी, फेता-भटाडी से होकर जाती है, फिर वरोरा और मोहार्ली रेंज की संयुक्त सीमा के साथ-साथ चलती है और आरंभिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

[फा सं 43015/21/86-एल.एस डब्ल्यू]
बी बी. राव, अवर सचिव

New Delhi, the 19th April, 1989

S.O.......910—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) number S.O. 1140 dated the 16th April, 1987, under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in Part-II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India dated the 2nd May, 1937, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in lands measuring 36930.73 hectares (approximately) or 91259.52 acres (approximately) in the locality specified in the Schedule appended thereto as also in the Schedule hereto annexed;

And Whereas in respect of the said lands, no notice under sub-section (1) of section 7 of the said Act has been given.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the said sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby specifies a further period of one year commencing from the 2nd May, 1989 as the period within which the Central Government may give notice of its intention to acquire the said lands or any rights in or over such lands.

THE SCHEDULE

LOHARA-AGARZARI BLOCK

CHANDRAPUR COALFIELDS

DISTRCT CHANDRAPUR (MAHARASHTRA)

Serial No.	Name of village	Patwari circle No.	Village	Tahsil and District	Area in hectares	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Adegaon	12	—	Chandrapur	227.32	Full
2.	Agarzari	12	—	Chandrapur	135.55	Full
3.	Paili Bhatali	12	—	Chandrapur	1157.00	Part
4.	Kitadi	12	—	Chandrapur	338.11	Part
5.	Padmapur	12	—	Chandrapur	172.04	Part
6.	Mhasala Rith	12	—	Chandrapur	105.00	Full
7.	Mhasala Tukum	12	—	Chandrapur	108.58	Full
8.	Sinhala	12	—	Chandrapur	374.62	Part
9.	Warwat	12	—	Chandrapur	862.36	Full
10.	Chorgaon	12	—	Chandrapur	1214.68	Full
11.	Khandala Rith	12	—	Chandrapur	1201.00	Full
12.	Mamla Mokasa	13	—	Chandrapur	282.28	Full
13.	Nimbala	13	—	Chandrapur	316.17	Full
14.	Chak Nimbala	13	—	Chandrapur	769.52	Full
15.	Waigaon Mokasa	13	—	Chandrapur	102.65	Full
16.	Chak Waigaon No. 1	13	—	Chandrapur	201.14	Full
17.	Chak Waigaon N . 2	13	—	Chandrapur	107.28	Full
18.	Chak Borda	13	—	Chandrapur	935.67	Full
19.	Borda Indapawar	13	—	Chandrapur	144.96	Full
20.	Walni	13	—	Chandrapur	376.28	Full
21.	Chakwalni	13	—	Chandrapur	64.78	Full
22.	Chichpalli	15	—	Chandrapur	754.40	Full
23.	Chichichpalli alias Chak Ajaypur	15	—	Chandrapur	816.96	Full
24.	Temta	15	—	Chandrapur	26.99	Full
25.	Jambharala	15	—	Chandrapur	72.48	Full
26.	Ghanta Chouki	13	—	Chandrapur	18.67	Full
27.	Lohara	13	—	Chandrapur	133.53	Full

1	2	3	4	5	6	7
28.	Moharli Range	Chandrapur Division	—	Chandrapur	9058.40	Part
29.	Chanda Range	Chandrapur Division	—	Chandrapur	2188.53	Part
30.	Mul Range	Chandrapur Division	—	Chandrapur	4663.58	Part
		TOTAL AREA	—		36930.73 hectares (approximately) or 91259.52) acres (approximately)	

Boundary description :

A-B: Line starts from point 'A' and passes through Moharli Range along the road, southern boundary of village Dewada, then again proceeds along the road and meets at point 'B'.

B-C: Line passes along the western bank of River Andhari and meets at point 'C'.

C-D: Line passes through Mul Range and meets at point 'D'.

D-E: Line passes through Mul and Chanda Range along the northern boundary of South Eastern Railway and meets at point 'E'.

E-F: Line passes through Chanda Range and meets at point 'F'.

F-G: Line passes through villages Sinhala, Padmapur and Kitadi and meets at point 'G'.

G-A: Line passes through villages Kitadi, Paili-Bhatadi, then proceeds along the common boundary of Warora and Moharli Range and meets at starting point 'A'.

[No. 43015/21/86-CA/LSW]
B.B. RAO, Under Secy.

नागर विमानन मंत्रालय तथा पर्यटन

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1989

का.आ. 911:—वायुयान नियम, 1937 के नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय में भारत सरकार के संयुक्त सचिव, श्री प्रोबीर चन्द्र सेन को, जो इस समय महानिदेशक, नागर विमानन का कार्य भी देख रहे हैं, केन्द्रीय सरकार की ऐसी शक्तियों का उपयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है जो कि भूतपूर्व पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय की दिनांक 29 सितम्बर, 1976 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का. आ. 3563 के तहत महानिदेशक, नागर विमानन को सौंपी गई हैं और उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के साथ लगी पहली अनुसूची में, कालम 1 में "महानिदेशक, नागर विमानन" शब्दों के स्थान पर, "श्री प्रोबीर चन्द्र सेन संयुक्त सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

[सं. एफ वी. 11012/6/88-ए)]

MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM

New Delhi, the 10th March, 1989

S.O. 911.—In pursuance of sub-rule (2) of rule 3 of the Aircraft Rules, 1937, the Central Government hereby authorises Shri Probir Chandra Sen, Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Civil Aviation and Tourism, who is currently looking after the duties of the Director General of Civil Aviation to exercise such of the powers of the Central Government as are delegated to the Director General of Civil Aviation under the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Tourism and Civil Aviation No. S.O. 3563, dated the 29th September, 1976, and makes the following amendment in the said notification, namely:—

In the First Schedule annexed to the said notification, in column 1, for the words "Director General of Civil Aviation", the words "Shri Probir Chandra Sen, Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Civil Aviation and Tourism" shall be substituted.

[F. No. AV-11012/6/88-A]

का.आ. 912--वायुयान नियम, 1937 के नियम 3 के उप-नियम (2क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय में, भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री प्रोबीर चन्द्र सेन को, जो कि इस समय महानिदेशक, नागर विमानन का कार्य भी देख रहे हैं, उक्त नियमों द्वारा महानिदेशक, नागर विमानन को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उन्हें सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए प्राधिकृत करती है

एफ ए. वी.-11012/6/88-ए
आर.एन. भार्गव, अवर सचिव

S.O. 912.—In pursuance of sub-rule (2-A) of rule 3 of the Aircraft Rules, 1937, the Central Government hereby authorises Shri Probir Chandra Sen, Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Civil Aviation and Tourism, who is currently looking after the duties of the Director General of Civil Aviation to exercise all the powers conferred and to discharge the duties imposed on the Director General of Civil Aviation by the said Rules.

[F. No. AV.11012|6|88-A]
R. N. BHARGAVA, Under Secy.

(नागर विमानन विभाग)

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1989

का. आ. 913 —अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 (1971 का 43वां) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में तत्काल से 3 वर्ष की अवधि के लिये या उनके द्वारा अपने वर्तमान पद का कार्य-भार छोड़ने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अंशकालिक सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है :—

(1) श्री राजन जेटली,
प्रबंध निदेशक,
एयर इंडिया,
बम्बई

(2) श्री एस. कृष्णमूर्ति,
संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार,
नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय,
नई दिल्ली

[सं. ए०वी–24027/1/85–एए (एफ-2)]

(Department of Civil Aviation)

New Delhi, the 10th March, 1989

S.O. 913.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (3) Section 3 of the International Airports Authority Act, 1971, (43 of 1971), the Central Government hereby appoint the following officers as part-time Members on he Board of International Airports Authority of India with immediate effect for a period of 3 years or till quishing their present office, whichever is earlier.

(i) Shri Rajan Jetley,
Managing Director,
Air-India,
Bombay.

(ii) Shri S. Krishna Moorthy,
Joint Secretary & Financial Adviser,
Ministry of Civil Aviation & Tourism,
New Delhi

DEV SWARUP, Jt. Secy.

[No. AV. 24027|1|85-AA(F.II)]

का.आ. 914 :—अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण कामगार संगठन और भा.अ.वि. प्राधिकरण (मुख्यालय) कर्मचारी संगठन के महासचिव, श्री खीम सिंह को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में तत्काल से तीन वर्ष की अवधि तक के लिए अंशकालिक सदस्य नियुक्त करती है।

[संख्या ए.वी–24027/1/85–एफ-2 (एए)]

S.O. 914.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (3) of section 3 of the International Airports Authority Act, 1971 (43 of 1971), the Central Government hereby appoint Shri Khim Singh, General Secretary of the IAAI Workers' Union and IAAI (Headquarters) Employees' Union as a part-time Member of the Board of the International Airports Authority of India with immediate effect for a period of three years.

[No. AV-24027|1|85-FII(AA)]

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1989

का. आ. 915—अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 (1971 का 43) के खंड 3, उप खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्द्वारा तत्काल तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित गैर-सरकारी व्यक्तियों को भारत अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के निदेशक मंडल में अंश-कालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं :—

1. श्रीनारी जे. कटगारा,
निदेशक,
ट्रैवल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड,
चन्दर मुखी,
नरीमन प्वाइंट,
बम्बई।

2. श्री जी.सी. सक्सेना,
16, लोधी इस्टेट,
नई दिल्ली-110053

[संख्या ए०वी० 24027/1/85–एए (एफ-2)
देव स्वरूप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 14th March, 1989

S.O. 915.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (3) of Section 3 of the International Airports Authority Act, 1971 (43 of 1971), the Central Government hereby appoint the following non-Officials as part-time Members on the Board of International Airports Authority of India for a period of three years with immediate effect.

1. Shri Nari J. Katgara,
Director,
Travel Corporation of India Ltd.,
Chander Mukhi,
Nariman Point,
Bombay.

2. Shri G. C. Saxena,
16, Lodhi Estate,
New Delhi-110003.

[No. AV-24027|1|85-AA(F.II)]

DEV SWARUP, Jt. Secy.

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1989

का. आ. 916.—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (छ) द्वारा पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, नगर तथा ग्राम नियोजन संगठन के मुख्य नियोजक श्री डी. एस. मेशराम को श्री ई.एफ.एन. रेबिरो के स्थान पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में मनोनीत करती है और भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय की दिनांक 30-12-57 की अधिसूचना सं. 12/173/57-एल.एस.जी. में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना में प्रविष्टि "श्री ई.एफ.एन. रेबिरो" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को जाए नामतः "श्री डी.एस. मेशराम"

[सं. के-11011/22/78-डी.डी. 1-ए/II-बी/खण्ड-II]

एस. पी. सिंघल, निदेशक (डी. डी.)

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 20th March, 1989

S.O. 916.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (g) of sub-section (3) of section 3 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government hereby nominates Shri D. S. Moshram, Chief Planner, TCPO, as a member of the Delhi Development Authority in place of Shri E. F. N. Ribeiro and makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health Notification No. 12-173/57-LSG dated 30-12-57, namely :—

In the said Notification, in item 10-A for the entry "Shri E. F. N. Ribeiro" the following entry shall be substitued namely :—"Shri D. S. Meshram".

[No. K-11011/22/78-DDIA/IIB|Vol. II]

S. P. SINGAL, Director (DD)

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1989

का. आ. 917.—यत: निम्नांकित क्षेत्रों के बारे में कुछ संशोधन, जिन्हें केन्द्रीय सरकार अधोवर्णित क्षेत्रों के बारे में दिल्ली वृहत योजना क्षेत्रीय विकास योजना में प्रस्तावित करती है तथा जिसे दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 13-11-1982 के नोटिस संख्या एफ. 20/(12)/79 एम.पी. द्वारा प्रकाशित किये गये थे जिसमें उक्त अधिनियम की धारा-11-क की उप धारा (3) में अपेक्षित आपत्तियों/सुझाव, उक्त नोटिस की तारीख के 30 दिन की अवधि में आमंत्रित किए गए थे।

और यत: उक्त प्रस्तावित संशोधनों के बारे में कोई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं, अत: केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली वृहत योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन करने का निर्णय किया है।

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली की उक्त वृहत योजना में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :—

"लगभग 3.66 हैक्टेयर माप के क्षेत्र (9.09 एकड़ जोन डी-9 सेन्ट्रल वीस्टा जोन के अन्तर्गत है) जो पश्चिम में 36.57 मीटर चौड़े पंडित पंत मार्ग, दक्षिण पूर्व की ओर लोक सभा भूखण्ड और पूर्व में 6.09 मीटर चौड़े तालकटोरा मार्ग से घिरा है, का भूउपयोग" सरकारी कार्यालयों के मनोरंजनार्थ उपयोग में परिवर्तित कर दिया गया है।

[सं. के-13011/7/87-डी.डी. IIए/Vए]

अर्जन देव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 30th March, 1989

S.O. 917.—Whereas certain modification, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan regarding the areas mentioned hereunder, were published with Notice No F. 20(12)/79-MP dated 13-11-82 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions, as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act within thirty days from the date of the said notice,

And whereas no objections and suggestions have been received with regard to the said proposed modification, the Central Government have decided to modify the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION :

"The land use of the area (Plot No. 115), measuring about 3.66 hect. (9.09 acres) falling in Zone D-9 (Central Vista Zone) bounded by 36.57 metres wide Pandit Pant Marg on the West, Lok Sabha Bhavan plot on the South East and 60.09 metres wide Talkatora Road on the east, is changed from 'Recreational' use to government & Semi-government offices"

[No. K-13077|2|88-DDIIA|VA]

ARJAN DEV, Desk Officer

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1989

का.आ. 918.—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या सा.का.नि. 3792, दिनांक 2 दिसम्बर, 1966 को प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियम के प्रत्येक उपबंध के अंतर्गत जारी निदेशों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के उपरान्त, संलग्न अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट फिल्मों को, जिसका/जिनका विवरण उपर्युक्त अनुसूची के कालम 6 में दिया गया है, उसके/उनके सभी भाषा रूपान्तरों के साथ स्वीकार करती है।

अनुसूची

क्रम सं.	फिल्म का नाम	फिल्म की लंबाई	आवेदन का नाम	प्रोड्यूसर का नाम	फिल्म का संक्षिप्त विवरण कि क्या वैज्ञानिक फिल्म है अथवा शैक्षिक उद्देश्य की है या समाचारों एवं सम सामयिक घटनाओं पर आधारित फिल्म या वृत्त चित्र है।
1	2	3	4	5	6
1.	न्यूज मैगजीन संख्या (21ए)	291.00	फिल्म प्रभाग 24-पेडर रोड बम्बई-400026 (मुख्य निर्माता)		सामान्य रिलीज के लिए अनुमोदित 'समाचार एवं सम सामयिक तथा घटनाओं के रूप में वर्गीकृत
2.	माला	78.00	-तदैव-	--तदैव-	सामान्य रिलीज के लिए अनुमोदित तथा 'डक्यूमेंटरी के रूप में वर्गीकृत।

1	2	3	4	5	6
3.	माला	93.00	मुख्य निर्माता, फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई		सामान्य प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और डाक्युमेंटरी के रूप में वर्गीकृत
4.	माला	116.00	-तथैव-		-तथैव-
5.	माला	73.00	-तथैव-		-तथैव-
6.	माला	82.00	-तथैव-		-तथैव-
7.	माला	89.00	तथैव		तथैव
8.	महाराष्ट्र न्यूज	297.00	सूचना और जन संपर्क महानिदेशालय महाराष्ट्र सरकार फिल्म के 68 सारदेश रोड, बम्बई-400034		महाराष्ट्र क्षेत्र में रिलीज के लिए अनुमोदित तथा "समाचार और सामयिक घटनाओं के रूप में वर्गीकृत
9.	माला	92	मुख्य निर्माता फिल्म प्रभाग 24-पैडर रोड बम्बई-4000026		सामान्य रिलीज के लिए अनुमोदित तथा 'डाक्युमेंटरी के रूप में वर्गीकृत
10.	माला	75.00	तथैव	तथैव	तथैव
	माला	64.00	तथैव	तथैव	तथैव
12.	माला	75.00	तथैव	तथैव	तथैव
13.	बच्चे लगने अच्छे	568.04	अमरेन्द्र कुमार 87 पुरातिया तोला तल्लादया इटावा (उ.प्र.)		ग्रामीण रिलीज के लिए अनुमोदित तथा 'डाक्युमेंटरी और सम सामयिक घटनाओं के रूप में वर्गीकृत
14.	वार्ता तरंगिनी 113	215.00	आ.प्र. फिल्म विकास निगम, 11-1-423/1, लाक्दिकापुल हैदराबाद-500004		आंध्र प्रदेश क्षेत्र में रिलीज के लिए अनुमोदित तथा समाचार और सम सामयिक घटनाओं" के रूप में वर्गीकृत
15	वार्ता तरंगिनी	298.81	-तथैव-	तथैव-	-तथैव-
16.	वार्ता तरंगिनी 112	274.45	-तथैव-	-तदैव-	-तथैव-
17.	अहिलिचित्र स. 484	202.31	सहायक निदेशक, सूचना गुजरात सरकार रासनार्ड अनुसंधान प्रयोगशाला लिमिटेड, 77, डी.ए.वी. रोड वर्ली, बम्बई-18		गुजरात क्षेत्र में रिलीज के लिए अनुमोदित तथा "समाचार और सामयिक घटनाओं के रूप में वर्गीकृत
18	उज्जवल भविष्य की ओर (मेरठ मंडल)	295.35	श्री धीरेन्द्र पाण्डे, द्वारा मैसर्स बम्बई फिल्म प्रयोगशाला-149 एस.के. बोले रोड दादर, बम्बई-400028		उत्तर प्रदेश क्षेत्र में रिलीज के लिए अनुमोदित तथा "डाकुमेंट्री" के रूप में वर्गीकृत
19.	उज्जवल भविष्य की ओर (फैजाबाद मंडल)	292.00	-तदैव-		-तदैव-
20.	उज्जवल भविष्य की ओर (आगरा मंडल)	296.27	श्री धीरेन्द्र पाण्डे, द्वारा मैसर्स बम्बई फिल्म प्रयोगशाला-149 एस.के. बोले रोड, दादर, बम्बई-400028		उत्तर प्रदेश क्षेत्र में रिलीज के लिए अनुमोदित तथा (डाक्युमेंट्री के रूप में वर्गीकृत
21.	उज्जवल भविष्य की ओर (झांसी मंडल)	295.05	-तदैव-	-तथैव-	-तदैव-
22.	प्रकाशी तथा कांन्तिले	530.00	आंध्र प्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम लिमिटेड 11-5-423/1 लकड़ी का पुल हैदराबाद-5000004		आंध्र प्रदेश क्षेत्र में रिलीज के लिए अनुमोदित तथा डाक्युमेंट्री के रूप में वर्गीकृत

1	2	3	4	5	6
23.	उज्जवल भविष्य की ओर (बरेली मंडल)	290.27	श्री धीरेन्द्र पाण्डे द्वारा मैसर्स बम्बई फिल्म प्रयोगशाला (प्रा.) लि., 149 एस०के० बोले, रोड, दादर, बम्बई-28	श्री धीरेन्द्र पाण्डे, सूचना और जनसंपर्क निदेशक उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ	उत्तर प्रदेश क्षेत्र में रिलीज के लिए अनुमोदित तथा डाक्युमेंट्री रूप में वर्गीकृत।
24.	उज्वल भविष्य की ओर (मुरादाबाद मंडल)	292.61	-तथैव-	-तथैव-	-तथैव-
25.	न्यूज मैगजीन संख्या 124	527.00	मुख्य निर्माता फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई-400026		सामान्य रिलीज के लिए अनुमोदित तथा 'डाक्युमेंट्री के रूप में वर्गीकृत
26.	एक नयी राह	451.00	-तथैव-	-तथैव-	-तथैव-
27.	न्यूज मैगजीन संख्या 125	569.00	-तथैव-	-तथैव-	-तथैव-
28.	वार्ता तरंगिनी 115	308.96	आन्ध्र प्रदेश राज्य, फिल्म विकास निगम 11-5-423/1, लकड़ी का पुल हैदराबाद-400004		आन्ध्र प्रदेश क्षेत्र में रिलीज के अनुमोदित तथा 'समाचार एवं सामयिक घटनाओं के रूप वर्गीकृत
29.	महाराष्ट्र न्यूज संख्या 428	265.00	सूचना और जन संपर्क महा-निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार, फ़िल्म सैन्टर, 68, तारदेव रोड, बम्बई-400034		सामान्य रिलीज के लिए अनुमोदित और 'डाक्युमेंटरी' के रूप में वर्गीकृत
30.	न्यूज मैगजीन संख्या 126	494.00	मुख्य निर्माता फ़िल्म प्रभाग, 24, पैडर रोड, बम्बई-400026		सामान्य रिलीज के लिए अनुमोदित तथा समाचार एवं सामयिक घटनाओं के रूप में वर्गीकृत।
31.	मिनार पाइन्ट	265.00	-तथैव-	-तथैव	सामान्य रिलीज के लिए अनुमोदित 'डाकुमेंटरी' के रूप में वर्गीकृत
32.	न्यूज मैगजीन संख्या 127	296.00	-तथैव-	-तथैव-	-तथैव-
33.	वार्ता तरंगिनी 116	205.10	आन्ध्र प्रदेश राज्य फ़िल्म विकास निगम लि. 11-5-423/1 लकड़ी का पुल हैदराबाद-54		आन्ध्र प्रदेश क्षेत्र में रिलीज के लिए अनुमोदित तथा समाचार एवं सामयिक रूप, में वर्गीकृत
34.	वार्ता तरंगिनी 118	233.87	-तथैव-	-तथैव-	-तथैव-
35.	वार्ता तरंगिनी 117	268.60	-तथैव-	-तथैव-	-तथैव-
36.	श्रद्धांजली	114.30	श्री एन बी सुखवानी, प्लास्टिक वर्कशाप' 5ए कृष्ण उद्योग भवन सामने के. नारीमन रोड, वर्ली, बम्बई	-तथैव-	सामान्य रिलीज के लिए अनुमोदित तथा 'डाक्युमेंटरी रूप में वर्गीकृत
37.	गोपाल देशरकर	579.12	फ़िल्म प्रभाग, 34, पुडर रोड, बम्बई-400026		-तथैव-
38.	न्यूज मैगजीन संख्या 128	294	-तथैव-	-तथैव-	-तथैव-
39.	पैरेन्ट प्लस टीचर इक्युल बैटर एजुकेशन (संशोधित)	302.00	-तथैव-	-तथैव-	-तथैव-

1	2	3	4	5	6
40.	महिति चित्र संख्या 486	195.07	संयुक्त निदेशक सूचना, गुजरात सरकार, धनराज महल, सी.आर.एफ. 1, छत्रपति शिवाजी मार्ग बम्बई-39		गुजरात क्षेत्र में रिलीज के लिए अनुमोदित तथा 'डाक्यूमेंट्री के रूप में वर्गीकृत
41.	न्यूजमैगजीन, संख्या 129	399.00	मुख्य निर्माता फिल्म प्रभाग, 24 पेडर रोड, बम्बई-26		सामान्य प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा डाक्यूमेंटरी के रूप में वर्गीकृत
42.	आरोग्य में महावायु	433.84	आन्ध्र प्रदेश, राज्य फिल्म विकास नि. 11-5-423/1 लकड़ी का पुल, हैदराबाद-4		आन्ध्र प्रदेश क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा 'डाक्यु-मेंट्री के रूप में वर्गीकृत
43.	वार्ता तरंगिनी 119	208.57	—तथैव—	—तथैव—	आन्ध्र प्रदेश क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा समाचार और सामयिक घटनाओं के रूप में वर्गीकृत
44.	महाराष्ट्र समाचार संख्या 429	266.00	महानिदेशक सूचना तथा जनसंपर्क महाराष्ट्र सरकार फिल्म केन्द्र 68, ताड़देव रोड, बम्बई-34		महाराष्ट्र क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा समाचार और सम सामयिक घटनाओं के रूप में वर्गीकृत।
45.	जीवन चक्र	595.86	सर्व राजदीप, रमनदीप प्रोडक्शन, 4-जीनत, प्रथम तल 57-ए, लेडी हमशेदजी रोड, महिम, बम्बई-400016		सामान्य प्रदर्शन के लिए अनु-मोदित तथा 'डाक्यूमेंटरी के रूप में वर्गीकृत
46.	वार्ता तरंगिनी 130	300.00	आंध्र प्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम लि. 11-5-423/1, लकड़ी का पुल हैदराबाद		आन्ध्र प्रदेश में प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा 'समाचार और सम सामयिक घटनाओं' के रूप में वर्गीकृत
47.	नाथी रे राहेबुन रामकथा	603.80	उप निदेशक सूचना, गुजरात सरकार, धनराज महल, भूतल छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग, बम्बई-39		गुजरात क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा 'समाचार और सम सामयिक घटनाओं के रूप में वर्गीकृत
48.	वार्ता तरंगिनी	270.00	आंध्र प्रदेश राज्य फिल्म, विकास निगम लि. 11-5-423/1 लकड़ी का पुल, हैदराबाद-4		आंध्र प्रदेश क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा "समाचार और सम सामयिक घटनाओं के रूप में वर्गीकृत
49.	उज्ज्वल भविष्य की ओर लखनऊ मंडल	291.49	श्री धीरेन्द्र पांडे, निदेशक, सूचना तथा जन संपर्क, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ		उत्तर प्रदेश में क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा 'समाचार और सम सामयिक घटनाओं के रूप में वर्गीकृत
50.	उत्तर प्रदेश समाचार 126	293.22	—तथैव—		—तथैव—
51.	हथकरघा समृद्धि के पथ पर	513.03	निदेशक, सूचना तथा जन संपर्क, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ		उत्तर प्रदेश क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा 'डाक्यु मेंट्री" के रूप में वर्गीकृत

1	2	3	4	5	6
52.	उज्जवल भविष्य की ओर वाराणसी मंडल	291.39	श्री धीरेन्द्र पांडे, निदेशक, सूचना तथा जन संपर्क, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ		—तदैव—
53.	वार्ता तरंगिनी	22.00	आंध्र प्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम लि., 11-5-423/1 लकड़ी का पुल, हैदराबाद		आन्ध्र प्रदेश क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा "समाचार तथा सम-सामयिक घटनाओं के रूप में वर्गीकृत ।
54.	यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फ़ाल	22.05	मैसर्स कामसाम क्रियेशन, अपोलो बिल्डिंग, 14 रोड, खार, बम्बई-52		सामान्य प्रदर्शन के लिए अनुमति तथा 'डाक्युमेंटरी के रूप में वर्गीकृत
55.	समाचार पत्रिका संख्या 132	270.00	मुख्य प्रोड्यूसर, फ़िल्म डिवीजन, 24-पेडर रोड, बम्बई-400026		सामान्य प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा समाचार तथा सम सामयिक घटनाओं के रूप में वर्गीकृत
56.	पंडित जवाहरलाल नेहरू, फ़स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ़ इंडिपेंडेंट इंडिया	69.00	श्री सुभाष जयकर, निदेशक, गांधी फिल्म फाउंडेशन मणि भवन-19 लबरनम रोड, बम्बई-400007		सामान्य प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा 'डाक्युमेंट्री के रूप में वर्गीकृत
57.	महाराष्ट्र समाचार संख्या 430	258.00	महानिदेशक, सूचना तथा जन सम्पर्क, फ़िल्म केन्द्र, 68, ताडदेव रोड, बम्बई		महाराष्ट्र क्षेत्र में प्रदर्शन के के लिए अनुमोदित तथा समाचार और सम-सामयिक घटनाओं के रूप में वर्गीकृत
58.	नेस्म पत्रिका संख्या 134	276.00	मुख्य प्रोड्यूसर, फिल्म डिवीजन, 24 पैडर रोड, बम्बई-400026		सामान्य प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा 'डाक्युमेंटरी' के रूप में वर्गीकृत
59.	समाचार पत्रिका संख्या 133	461.00	—तदैव—		सामान्य प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा समाचार और सम सामयिक घटनाओं के रूप मे वर्गीकृत
60.	वार्ता तरंगिनी 124	328.04	आंध्र प्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम लि. 11-5-423/1, लकड़ी का पुल, हैदराबाद	आंन्ध्र	आन्ध्र प्रदेश क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा समाचार और सम सामयिक घटनाओं के रूप में वर्गीकृत
61.	वार्ता तरंगिनी 123	277.71	—तदैव—		—तदैव—
62.	समाचार पत्रिक संख्या 135	435.00	मुख्य प्रोड्यूसर, फ़िल्म डिवीजन, 24, पैडर रोड, बम्बई		सामान्य प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा 'डाक्युमेंटरी' के रूप में वर्गीकृत
63.	सतीश गुजराल	511.00	—तदैव—		—तदैव—
64.	समाचार पत्रिका संख्या 136	361.00	—तदैव—		—तदैव—
65.	रिकरिंग डिपाजिट स्कीम	48.16	श्री के.के. कपिल, 133, जुहू प्रभात, नया डी.एन. नगर, बम्बई-400058		अधिसूचनाओं के लिए अनुमादित

1	2	3	4	5	6
66.	इंदिरा विकास पत्र	69.50	श्री के.के. कपिल, 133, जुहू प्रभात, नया डी.एन. नगर, बम्बई-400058		सामान्य प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा डाक्युमेंट्री के रूप में वर्गीकृत
67.	महाराष्ट्र विधान परिषद, स्वर्ण महोत्सव	598.00	श्री सुभाष भुर्के, 1243, डीवार्ड, कोल्हापुर-416002		महाराष्ट्र क्षेत्र में सामान्य प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा "डाक्युमेंट्री" के रूप में वर्गीकृत ।
68	समाचार पत्रिका संख्या 137	576.00	मुख्य प्रोड्यूसर, फिल्म डिवीजन, 24-पैडर रोड, बम्बई-400026		सामान्य प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा 'डाक्युमेंट्री' के रूप में वर्गीकृत
69.	निवारा	209.40	श्री उमेश एम. करकोरा, 11-बी/246, एम.एम.बी. कालोनी, बकोला ब्रिज के पास संता क्रुज (ई) बम्बई-55		महाराष्ट्र क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा "डाक्युमेंट्री" के रूप में वर्गीकृत।
70.	वार्ता तरंगिनी 127	288.93	आंध्र प्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम लि. 11-5-423/1, लकड़ी का पुल हैदराबाद-4		आन्ध्र प्रदेश क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा समाचार तथा सम सामयिक घटनाओं के रूप में वर्गीकृत
71.	वार्ता तरंगिनी 126	226.22	–तथैव–		–तथैव–
72.	एम.टी.पी.	140.00	मुख्य प्रोड्यूसर, फिल्म डिवीजन, 24-पैडर रोड, बम्बई-4000026		सामान्य प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा डाक्युमेंट्री के रूप में वर्गीकृत
73.	नाइट ब्लाइंडनेस	297.00	–तथैव–		–तदैव–
74.	लक्ष्मी	470.00	–तथैव–		–तथैव–
75.	नफरत की आग	415.74	श्री नवाज नजरुद्दीन अनिक खान 3-6-293/4, हैदराबाद हैदराबाद-500029		–तथैव–
76.	एगोनी आफ दी गंगा	579.00	मुख्य प्रोड्यूसर फिल्म डिवीजन 24 पैडर रोड, बम्बई-26		–तथैव-
77.	समाचार पत्रिक सं. 138	265.00	तथैव		–तथैव–
78.	महाराष्ट्र पत्रिका संख्या 431	235.00	महानिदेशक, सूचना तथा जन संपर्क महाराष्ट्र सरकार, फिल्म केन्द्र, 68, माडवेव रोड, बम्बई-400034		महाराष्ट्र क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा "समाचार और सम सामयिक घटनाओं के रूप में वर्गीकृत
79.	लक्ष्मी निवास	348.00	आंध्र प्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम लि., 11-5-423/1, लकड़ी का पुल, हैदराबाद		आन्ध्र प्रदेश क्षेत्र में प्रदर्शन के के लिए डाक्युमेंट्री के रूप में वर्गीकृत
80.	वार्ता तरंगिनी संख्या 128	279.30	–तथैव–		आंध्र प्रदेश क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा समाचार और सममामयिक घटनाओं के रूप में वर्गीकृत
81.	समाचार पत्रिका संख्या 139	512.00	मुख्य प्रोड्यूसर, फिल्म डिवीजन, 24-पैडर रोड, बम्बई-400026		सामान्य प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा समाचार और सम सामयिक घटनाओं के रूप में वर्गीकृत
82.	ऐसी थी मारियां	599.29	श्री उमाशंकर, 856 बाबा सिन्हा मार्ग, नई दिल्ली-110001		सामान्य प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा समाचार और सम सामयिक घटनाओं के रूप में वर्गीकृत।
83.	अपना उत्सव संख्या 7	42.06	मुख्य प्रोड्यूसर,		–तथैव–

1	2	3	4	5	6
			फिल्म डिवीजन, 24-पैडर रोड, बम्बई-400026		सामान्य प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा समाचार और समसामयिक घटनाओं के रूप में वर्गीकृत
84.	अपना उत्सव, संख्या 6	39.00	-तथैव-		
85	अपना उत्सव संख्या 5	48.46	-तथैव-		-तथैव-
86.	अपना उत्सव संख्या 4	45.00	-तथैव-		-तथैव-
87.	अपना उत्सव संख्या 3	40.35	मुख्य निर्माता फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड		सामान्य प्रदर्शन के लिए अनुमोदित और "डाक्युमेंट्री" के रूप में वर्गीकृत
88.	अपना उत्सव संख्या 2	41.75	-तथैव-		-तथैव-
89.	अपना उत्सव संख्या 1	46.32	-तथैव-		-तथैव-
90.	न्यूज मैगजीन संख्या 140	46.00	मुख्य निर्माता, फिल्म प्रभाग, 24-पैडर रोड, बम्बई-26		सामान्य प्रदर्शन के लिए अनुमोदित तथा 'डाक्युमेंट्री' के रूप में वर्गीकृत
91.	मीराबहन वैस्टर्न डिसीपल आफ ईस्टर्न सैन्ट	94.00	श्री रमेश पटेल 1/2, उन्नत नगर । गोरेगांव (पश्चिमी) बम्बई-400062		-तथैव-
92.	द लास्ट एफ	91.25	चीफ प्रोड्यूसर, फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई-400026		-तथैव-
93.	स्टाप द प्रेस	44.19	-तथैव-		-तथैव-
94.	कोआप सियर	88.00	-तथैव-		-तथैव-
95.	प्रोग्रैम	93.26	-तथैव-		-तथैव-
96.	वार्ता तरंगिनी संख्या 130	282.6	आन्ध्र प्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम लि. 11-5-423/1, लकड़ी का पुल हैदराबाद		आंध्र प्रदेश में प्रदर्शन के लिए अनुमोदित और समाचारों और समसामयिक घटनाओं के रूप में वर्गीकृत
97.	वार्ता तरंगिनी संख्या 129	262.6	-तथैव-		-तथैव-

[फा.सं. 315/3/88-एफ (पी)]

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

ORDERS

New Delhi, the 20th March, 1989

S.O. 918.—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the first Schedule to the Order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated 2nd December, 1966 the Central Government after considering recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length of the film meters	Name of the applicant	Name of the Producer	Brief synopsis whether a scientific film or for educational purpose or a film dealing with news & currents or documentary film
1	2	3	4	5	6
1.	News Magazine No. 121 A	291.00	The Chief Producer Films Division 24-Pedder Road Bombay-400 026.		Approved for general release and classified as "News and Current Events"
2.	Mala	78.00	-do-		Approved for general release and classified as "Documentary"

1	2	3	4	5	6
3.	Mala	93.00	Chief Producer, Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-400 026.		Approved for general release and classified as "Documentary
4.	Mala	116.00	-do-	-do-	-do-
5.	Mala	73.00	-do-	-do-	-do-
6.	Mala	82.00	-do-	-do-	-do-
7.	Mala	89 00	-do-	-do-	-do-
8.	Maharashtra News No. 477	297 00	Directorate General of Information & Public Relations, Govt. of Maharashtra, Film Centre, 68, Tradeo Road, Bombay-400 034.		Approved for release in Maharashtra circuit and classified as "News and Current Events".
9.	Mala	92.00	The Chief Producer, Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-400 026.		Approved for general release and classified as "Documentary".
10.	Mala	75.00	-do-	-do-	-do-
11.	Mala	64.00	-do-	-do-	-do-
12.	Mala	75.00	-do-	-do-	-do-
13.	Bacchey Lagtey Acchhey	568 04	Asandra Kumar, 87, Puratiya Tola, Tallaiya, Etawah (U.P.).		Approved for release in rural and semi urban areas and classified as "Documentary".
14.	Varta Tarangini 114	245.00	APFDC, 11-4-423/1, Lakdikapool, Hyderabad 500004		Approved for release in Andhra Pradesh circuit and classified as "News and Current Events"
15.	Varta Tarangini 113.	298.81	-do-	-do-	-do-
16.	Varta Tarangini 112.	274.45	-do-	-do-	-do-
17.	Mahitichitra No. 484	202.31	Asstt. Director of Information, Govt. of Gujarat, Ramnord Research Lab. Ltd. 77, Dr. A.B. Road, Worli, Bombay-18.		Approved for release in Gujarat circuit and classified as "News and Current Events"
18.	Ujjwal Bhavishya ki Ore (meerut Mandal)	295.35	Shri Dhirendra Pande, C/o M/s. Bombay Film Lab. 149, S.K. Bole Road, Dadar, Bombay-400 028.		Approved for release in Uttar Pradesh Circuit and classified as "Documentary".
19.	Ujjwal Bhavishya Ki Ore (Faizabad Mandal)	292.00	- do -	—do —	—do —
20.	Ujjwal Bhavishya Ki Ore (Agra Mandal)	296.27	—do—	—do—	— do —
21.	Ujjwal Bhavishya Ki Ore (Jhansi Mandal)	295.05	- do—	—do—	—do —
22.	Aakali Katha Kanchike.	530.00	Andhra Pradesh State Film Development Corporation Ltd., 11-5-423/1, Lakdikapool, Hyderabad-500 004.		Approved for release in Andhra Pradesh circuit and classified as 'Documentary'.
23.	Ujjwal Bhavishya Ki Ore (Bareilly Mandal)	296.27	Shri Dhirendra Pande, C/o M/s Bombay Film Lab. (P) Ltd., 149, S.K. Bole Road, Dadar, Bombay-28. Shri Dhirendra Pande, Dir. of Information & Public Relations, Govt. of U.P. Lucknow.		Approved for release in U.P. circuit and classified as "Documentary".
24.	Ujjwal Bhavishya Ki Ore (Moradabad Mandal)	292.61	- -do—	—do —	—do —

1	2	3	4	5	6
25.	News Magazine No. 124	527.00	The Chief Producer, Films Division, 24 Peddar Road, Bombay-400026.		Approved for general release and classified as 'Documentary'
26.	Ek Nahi Rah	451.00	-do-	-do-	-do-
27.	News Magazine No. 125	569.00	-do-	-do-	-do-
28.	Varta Tarangini 115.	300.96	Andhra Pradesh State Film Development Corporation, 11-5-423/1 Lakdikapool, Hyderabad-500 00 4.		Approved for release in Andhra Pradesh circuit and classified as "News & Current Events".
29.	Maharashtra News No. 428.	265.00	Dir. Gen. of Information & Public Relations, Govt. of Maharashtra, Film Center, 68, Tardeo Road, Bombay-400034.		Approved for general release and classified as "Documentary".
30.	News Magazine No. 126.	494.00	The Chief Producer, Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-400 026.		Approved for general release and classified as "News and current Events".
31.	Minor Points	265.00	-do-	-do-	Approved for general release and classified as "Document-ary".
32.	News Magazine No. 127.	290.00	do	do	-do-
33.	Varta Tarangini 116	206.10	Andhra Pradesh State Film Development Corporation Ltd., 11-5-423/1, Lakdikapol, Hyderabad-500 054.		Approved for release in Andhra Pradesh circuit and classified as "News & Current Events".
34.	Varta Tarangini 118	233.87	Andhra Pradesh State Film Development Corporation, 11-5-423-/1, Lakdikapol, Hyderabad-500 004.		Release in A.P. circuit classified as News & Current Events',
35.	Varta Tarangini 117	268.60	-do-	-do-	-do-
36.	Shardhanjali	114.30	Shri N.B. Sukhwani. Optic Workshop, 5A Krishna Udyog Bh., Opp-Dr. Nariman Road, Worli, Bombay-25.		Approved for General release and classified as "Document-ary".
37.	Gopal Deuskar	579.12	Films Division, 24. Peddar Road, Bombay-400 026.		-do-
38.	News Magazine No. 128	294	do	-do-	-do-
39.	Parent Plus Teache Equals better Education (Revised)	302.00	-do-	-do-	-do-
40.	Mahitichitra No. 486	195.70	Jt. Dir. of Information, Govt. of Gujarat, Dhanraj Mahal, Gr. Fl. Chhatrapati Shivaji Marg, Bombay-39.		Approved for release in Gujarat circuit and classified as "Docu-mentary".
41.	News Magazine No. 129.	399.00	The ChiefProducer, Films Division, 24-Paddar Road, Bombay-400 026.		Approved for general release and classified as "Documen-tary".

1	2	3	4	5	6
42.	Aarogyame Mahabhagyamu	433.84	Andhra Pradesh State Film Development, Corporation Ltd., 11-5-423/1, Lakdikapool, Hyderabad-4.		Approved for release in A.P. circuit and classified as 'Documentary.'
43.	Varta Taxangini 119	208.57	-do-	-do-	Approved for release in A.P. circuit and classified as "News and Current Events".
44.	Maharashtra News No. 429	266.00	Dir. Gen. of Information & Public Relations, Govt. of Maharashtra, Film Center, 68, Tardeo Road, Bombay-34.		Approved for release in Maharashtra circuit and classified as "News & Current Events".
45.	Jeevan Chakra	595.87	M/s. Rajdeep, Rajdeep Productions, 4-Zeenat, First Fl. 57-A, Lady Hamshedji Road, Mahim Bombay—400 016.		Approved for general release in and classified as 'Documentary'.
46.	Varta Tarangini 120	300.00	Andhra Pradesh State, Film Development Corporation Ltd., 11-5-423/1, Lakdikapool, Hyderabad-4.		Approved for release in A.P. circuit and classified as "News & Current Events".
47.	Nathi Re Rahevun Ramakada	603.80	Dy. Dir. of Information, Govt. of Gujarat, Dhanraj Mahal, Gr. Floor, Chhatrapati Shivaji Maharaj Marg, Bombay-39.		Approved for release in Gujarat circuit and classified as 'Documentary'.
48.	Varta Tarangini 121.	270.00	Andhra Pradesh State Film Development Corporation Ltd., 11-5-423/1, Lakdikapool, Hyderabad-4.		Approved for release in A.P. circuit and classified as "News and Current Events".
49.	Ujjwall Bhavishya Ki Ore (Lucknow Mandal).	291.39	Shri Dhirendra Pande, Dir. of Information & Public Relations, Govt. of U.P. Lucknow.		Approved for release in U.P. circuit and classified as 'News and Current Events."
50.	U.P. Samachar 126.	293 2?	-do-	-do-	-do-
51.	Hath Karga Samruddhi Ke Path Par	513.03	The Director of Information, & Public Relations, Govt. of U.P.		Approved for release in U.P. circuit and classified as "Documentary".
52.	Ujjwal Bhavishya Ke Ore (Varanasi Mandal)	291.39	Shri Dhirendra Pande, Dir. of Information & Public Relations Govt. of U.P. Lucknow		-do-
53.	Varta Tarangni 122	254.00	Andhru Pradesh State Film Development Corporation Ltd., 11-5-423/1, Lakdikapool, Hyderabad-4.		Approved for relase in A.P. circuit and classified as "News and Current Events".
54.	United We Stand Divided We Faill	22.05	M/s. Cosmos Creations, Appollo Bldg., 14th Road, Khar, Bombay-52.		Approved for general release and classified as 'Documentary'.
55.	News Magazine No. 132	270.00	The Chief Producer, Films Divisions, 24—Peddar Road, Bombay—400026		Approved for general release and classified as "News and Current Events".

1	2	3	4	5	6
56.	Pandit Jawaharlal Nehru, First Prime Minister of Independent India.	69.00	Shri Subhash Jaykar, Director, Gandhi Film Foundation, Mani Bhavan, 19, Laburnum Road, Bombay-400 007.		Approved for general release and classified as "Documentary".
57.	Maharashtra Nzws No. 430	258.00	The Dir. Gen. of Information & Public Relations, Film Center, 68, Tardeo Road, Bombay-34.		Approved for release in Maharashtra circuit and classified as "News and Current Events".
58.	Noss Magazine No. 134	276.00	The Chief Producer, Films Division, 24-Poddar Road, Bombay-4000 26.		Approved for General release and Classified as 'Documentry'.
59.	News Magazine No. 133	461.00	—do— —do—		Approved for general release and classified as "News and Current Events".
60.	Varta Tarangi 124	328.04	Andhra Pradesh State Film Development Corporation Ltd., 11-5-423/1 Lakdikapool, Hyderabad—34		Approved for release in A.P. circuit and classified as "News and Current Events".
61.	Varta Tarangini 123	277.71	-do-		— do — Approved for general release and Classified as "Documentary".
62.	News Magazine No. 135	434.00	The Chief Producer, Films Division, 24-Poddar Road, Bombary-26		— do —
63.	Satish Gujral	511.00	-do- —do—		—do—
64.	News Magazine No. 136	361.00	-do- —do—		—do—
65.	Recurring Deposit Scheme	48.16	Shri K.K. Kapil, 133, Juhu Prabhat, New D.N. Nagar, Bombay-400058.		Approved for notifications.
66.	Indira Vikas Patra	69.5	-do- —do—		Approved for general release and classified as 'Documentary'
67.	Maharashtra Vidhan Parishad Suvarna-Mahostav	598.00	Shri Subhash Bhurke, 1243, D Ward, Kolhapur 416002.		Approved for release in Maharashtra circuit and classified as 'Documentary'.
68.	News Magazine No.137	576.00	The Chief producer, 24-Poddar Road, Bombay-4000 26.		Approved for general release and classified as "Documentary".
69.	Nivara	209.40	Shri Umesh S. Karkora, 11-B/246, MHB Colony, Near Vakola Bridge, Santacruz (E), Bombay-55		Approved for release in Maharashtra circuit and classified as "Documentary".
70.	Varta Tarangini 127	288.93	Andhra Pradesh State Film Development Corporations Ltd. 11-5-423/1, Lakdikapool, Hyderabad-4,		Approved for release in A.P. circuit and classified as "News and Current Events".
71.	Varta Tarangini 126	261.22	—do— —do—		—do—
72.	M.T.P.	140.00	The Chief Producer, Films Division, 24-Poddar Road, Bombay-400026		Approved for general release and Clatsified as 'Documentary'.
73.	Night Blindness	297.00	— do— — do—		-do-
74.	Lachhmi	470.00	—do— — do—		—do—
75.	Nafra) Ki Aag	415.74	Shri Nawaz Nazheruddin, Alik Khan, 3-6-293/4, Hyderbad, Hyderavad-509 029		— do —

1	2	3	4	5	6
76.	The Agony of Ganga	579.00	The Chief Producer, Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-26.		Approved for general release and classified as 'Documentary'.
77.	News Magazine No. 138	265.00	—do—	—do—	—do—
78.	Maharashtra News No. 431.	235.00	Dir. Gen. of Information & Public Relations, Govt. of Maharashtra, Film Centre, 68, Tardeo Road, Bombay-400 034.		Apporoved for release in Mahatra circuit and classified as, 'News and Current Events'.
79.	Lakshmi Nivasam	348.00	Andhra Pradesh State Film Development Corporation Ltd., 11-5-423/1, Lakdikapool, Hyderabad-4.		Approved for release in A.P. circuit and classified as 'Documentary'.
80.	Varta Tarangini 128	279.30	—do—		Approved for release in A.P. circuit and classified as "News and Current Events".
81.	News Magazine No. 139	512.00	The Chief Producer, Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-400006.		Approved for general release and classified as 'News and Current Events'.
82.	Aisi Thi Naraian	599 29	Shri Uma Shankar, 856, Baba Sinha Marg, New Delhi-110001.		Approved for general release and classified as 'Documentary'.
83.	Apna Utsav No. 7	42.06	The Chief Producer, Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-400026.		—do—
84.	Apna Utsav No. 6	39.00	—do—		—do—
85.	Apna Utsav No. 5	48.46	—do—		—do—
86.	Apna Utsav No. 4	45 00	—do—		—do—
87.	Apna Utsav No. 3	40.35	The Chief Producer, Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-400026.		—do—
88.	Apna Utsav No. 2	41.75	—do—	—do—	—do—
89.	Apna Utsav 1	46.32	—do—	—do—	—do—
90.	News Magazine No. 140	461.00	—do—	—do—	—do—
91.	Mirabehn Western Disciple of Eastern saint.	594.00	Shri Ramesh Patel, 1/2, Unnat Nagar I, Goregaon (W), Bombay-400062.		—do—
92.	The Last Puff	91.25	Chief Producer, Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-400026.		
93.	Stop the Game	44.19	—do—	—do—	—do—
94.	Connoiseur	88.00	—do—	—do—	—do—
95.	Progress	93.26	—do—	—do—	—do—
96.	Varta Tarangini 130	282.6	Andhra Pradesh State Film Development Corporation Ltd., 11-5-423/1, Lakdikapool, Hyderabad-4.		Approved for release in Andhra Pradesh circuit and classified as 'News & Current Events'.
97.	Varta Tarangini 129	262 6	Andhra Pradesh State Film Development Corporation Ltd., 11-5-423/1, Lakdikapool, Hyderabad-4.		Approved for release in Andhra Pradesh circuit and classified as 'News & Current Events'.

[F.No. 315/5/88-F(P)]

का. आ. 919.—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या सा. का. नि. 3792, दिनांक 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियम-1 के प्रत्येक उपबंध के अंतर्गत जारी निदेशों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत, संलग्न अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट फिल्मों को, जिसका/जिनका विवरण उपर्युक्त अनुसूची के कालम 6 में दिया गया है, उनका/उनके सभी भाषा रूपांतरों के साथ स्वीकार करती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	फिल्म की लंबाई मीटरों में	आवेदक का नाम	प्रोड्यूसर का नाम	फिल्म का संक्षिप्त विवरण कि क्या वह — वैज्ञानिक है, शैक्षिक उद्देश्य की है, या समाचारों एवं समसामयिक घटनाओं पर आधारित फिल्म या वृत्त चित्र है।
1	2	3	4	5	6
1.	नंदी अह्मुला प्रदानोत्सव, 1986	534.00	आंध्र प्रदेश फिल्म विकास निगम, 11/5/423/1/ लकड़ी का पुल, हैदराबाद-500 004		आंध्र प्रदेश क्षेत्र के लिए स्वीकृत तथा "समाचार तथा समसामयिक घटनाओं के रूप में वर्गीकृत"
2.	उत्तर प्रदेश समाचार 123	286.00	धीरेन्द्र पांडे, द्वारा बम्बई फिल्म लैब, 149, एस. के. बोले रोड, बम्बई-400028		उत्तर प्रदेश क्षेत्र के लिए स्वीकृत तथा "समाचार तथा समसामयिक घटनाओं" वर्ग के रूप में वर्गीकृत
3.	फार ए बैटर लिविंग	424.00	श्री घनश्याम महापात्र, रत्नाकर बिल्डिंग, प्लाट 1167/2, टैंकपानी रोड, भुवनेश्वर		सामान्य प्रदर्शन के लिए स्वीकृत तथा "वृत्त चित्र" के रूप में वर्गीकृत
4.	न्यूज मैगजीन संख्या 104	315.00	मुख्य प्रोड्यूसर, फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई-400026		सामान्य प्रदर्शन के लिए स्वीकृत तथा "समाचार तथा समसामयिक" घटनाओं के रूप में वर्गीकृत।
5.	विकास	487.15	श्री गजानंद मिश्र मानव, डी-9, इंद्रपुरी, लाल-कोठी, जयपुर		हिन्दी भाषी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्वीकृत तथा "वृत्तचित्र" के रूप में वर्गीकृत
6.	वार्ता तरंगिनी संख्या 102	237.00	आंध्रप्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम लि., 11.5.423 1, लकड़ी का पुल, हैदराबाद-4		आंध्रप्रदेश क्षेत्र के लिए स्वीकृत तथा "समाचार तथा सम-सामयिक" घटनाओं के रूप में वर्गीकृत
7.	महाराष्ट्र समाचार संख्या 422	283.00	महानिदेशक, सूचना और जनसंपर्क, महाराष्ट्र सरकार, फिल्म केन्द्र, 68 ताड़देव रोड, बम्बई-34		महाराष्ट्र क्षेत्र के रूप में स्वीकृत और "समाचार तथा सामयिक घटनाओं" के रूप में वर्गीकृत
8.	ए फाइम	30.00	मुख्य प्रोड्यूसर, फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई-26		सामान्य के लिए स्वीकृत और डाक्यूमेंट्री के रूप में वर्गीकृत
9.	प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्लाइंडनेस-II	31.00	—तथैव—		—तथैव—
10.	प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्लाइंडनेस-I	29.00	—तथैव—		—तथैव—
11.	सोशल वर्कर	33.00	—तथैव—		—तथैव—
12.	आई हैव हियर्ड-2	36.00	—तथैव—		—तथैव—
13.	आई हैव हियर्ड-I	53.00	—तथैव—		—तथैव—
14.	व्हाई टेक रिस्क 9	32.00	—तथैव—		—तथैव—
15.	लिसन प्लीज	41.00	—तथैव—		—तथैव—
16.	नो प्राब्लम	28.00	—तथैव—		—तथैव—
17.	समाचार पत्रिका नं. 105	415.00	—तथैव—		सामान्य प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "समाचार तथा सामयिक घटनाओं" के रूप में वर्गीकृत
18.	गुरुमंत्र	207.00	—तथैव—		सामान्य प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "डाक्यूमेंट्री" के रूप में वर्गीकृत
19.	त्रेकम	276.45	—तथैव—		—तथैव—
20.	एम. सत्यमूर्ति	547.72	—तथैव—		—तथैव—
21.	गुजरात नो मत्स्य उद्योग	333.15	निदेशक, सूचना और जनसंपर्क, गुजरात सरकार, सचिवालय, गांधीनगर-382010		गुजरात क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और डाक्यूमेंट्री के रूप में वर्गीकृत
22.	सुरक्षा	370.33	श्री ज्योति राय, द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि., 3 मिडिलटोन स्ट्रीट, कलकत्ता-700071		सामान्य प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और डाक्यूमेंट्री के रूप में वर्गीकृत

1	2	3	4	5	6
23.	ब्राइट फ्यूचर	28.00	मुख्य प्रोड्यूसर, फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई-26		सामान्य प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "डाक्यूमेंट्री के रूप वर्गीकृत"
24.	मोल्विंग ए प्राब्लम	44.00	—तथैव—		—तथैव—
25.	रिसपान्सिबिल्टी	38.00	—तथैव—		—तथैव—
26.	केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी	38.00	—तथैव—		—तथैव—
27.	दाई	79.00	—तथैव—		—तथैव—
28.	फार दि फ्यूचर	30.00	—तथैव—		—तथैव—
29.	गुणवंती	30.00	—तथैव—		—तथैव—
30.	जस्ट ए लिटिल केयर-2	36.00	—तथैव—		—तथैव—
31.	जस्ट ए लिटिल केयर-I	36.00	—तथैव—		—तथैव—
32.	इलैक्ट्रानिक उद्योग	289.56	निदेशक सूचना और जनसंपर्क, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ		उत्तर प्रदेश क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और डाक्यूमेंट्री के रूप में वर्गीकृत
33.	दि वेसेल मक्लाईम	388.60	कमल लालवाणी, 133, कैनिंग स्ट्रीट, बी-32, कलकत्ता-700001		सामान्य प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और डाक्यूमेंट्री के रूप में वर्गीकृत
34.	सब के लिए मकान	290.78	निदेशक, सूचना और जनसंपर्क, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ		उत्तर प्रदेश क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और डाक्यूमेंट्री के रूप में वर्गीकृत
35.	एट दि राइट टाईम	36.00	मुख्य प्रोड्यूसर, फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई-26		सामान्य प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और डाक्यूमेंट्री के रूप में वर्गीकृत
36.	समाचार पत्रिका नं. 106	524.00	मुख्य प्रोड्यूसर, फिल्म प्रभाग, बम्बई-400036		सामान्य प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "समाचार तथा सामायिक घटनाओं" के रूप में वर्गीकृत
37.	दहेज की ज्वाला	334.37	यूनाइटेड एड्स, फातिमा महल, बी 9 II वां तल, केवनी पदा, जोगेश्वरी, बम्बई-400102		सामान्य प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और डाक्यूमेंट्री के रूप में वर्गीकृत
38.	समाचार पत्रिका नं. 107	313.00	मुख्य प्रोड्यूसर, फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई-26		—तथैव—
39.	डांस क्यूर्स	492.00	—तथैव—		—तथैव—
40.	वार्ता तरंगिनी 103	276.00	आंध्रप्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम लि., 11-5-423 1, जफरबाग, लकड़ी का पुल, हैदराबाद-4		आंध्रप्रदेश क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "समाचार तथा सामयिक घटनाओं" के रूप में वर्गीकृत
41.	अवापावुकू अंदादानवालू	575.05	—तथैव—		आंध्रप्रदेश क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और डाक्यूमेंट्री के रूप में वर्गीकृत
42.	व्हाई दि डिफरेंस	37.00	मुख्य प्रोड्यूसर, फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई-26		सामान्य प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और डाक्यूमेंट्री के रूप में वर्गीकृत
43.	समाचार पत्रिका नं. 108	293.00	—तथैव—		—तथैव—
44.	समाचार पत्रिका नं. 106 ए	430.00	—तथैव—		सामान्य प्रदर्शन के लिए स्वीकृत "समाचार तथा सामायिक घटनाओं" के रूप में वर्गीकृत
45.	थ्रू दि लुकिंग ग्लास		श्री वेणुगोपाल ठक्कर, 6 न्यू शारदा, नार्थ एवेन्यू, सांताक्रुज (पश्चिम), बम्बई-54		सामान्य प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और डाक्यूमेंट्री के रूप में वर्गीकृत
46.	उत्तर प्रदेश समाचार 124	288.95	श्री प्रमोद पांडे (फिल्म संपादक) द्वारा 149, बम्बई फिल्म लैब प्रा. लि., बम्बई-26 श्री धीरेन्द्र पांडे, निदेशक, सूचना और जनसंपर्क, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ		उत्तरप्रदेश क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "समाचार तथा सामयिक घटनाओं" के रूप में वर्गीकृत
47.	वार्ता तरंगिनी 104	265.93	आंध्र प्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम लि., 11-5-423 ए लकड़ी का पुल, हैदराबाद-500004		आंध्रप्रदेश क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "समाचार तथा सामयिक घटनाओं" के रूप में वर्गीकृत
48.	प्राब्लम सोल्वड	42.00	मुख्य प्रोड्यूसर, फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई-26		सामान्य प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "डाक्यूमेंट्री" के रूप में वर्गीकृत
49.	आर. के. लक्ष्मण	595.00	—तथैव—		—तथैव—
50.	मैट्रो रेलवे इन कलकत्ता	543.20	श्री सुरजीत दास गुप्ता, 1.13 गुरुनगर, फोर बंगले रोड, अंधेरी (पश्चिम), बम्बई-58		—तथैव—

1	2	3	4	5	6
51.	महाराष्ट्र समाचार नं. 423	277.00	निदेशक, सूचना और जनसंपर्क, महाराष्ट्र सरकार, फिल्म सेंटर, 68 ताड़देव रोड, बम्बई-34		महाराष्ट्र क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "समाचार तथा सामयिक घटनाओं" के रूप में वर्गीकृत
52.	गेडलाकोमम पक्का गेल्लु	478.87	आंध्रप्रदेश फिल्म विकास निगम, 11-5-423/1, लकड़ी का पुल		आंध्रप्रदेश क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और डाक्युमेंट्री के रूप में वर्गीकृत
53.	चेतना	527.00	श्री एम. एम. वैद्या, अविनाश अपार्टमेंट्स नजदीक नटराज को. आप. हाउसिंग सोसायटी पंचपखडी, थाणे		सामान्य प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और डाक्युमेंट्री के रूप में वर्गीकृत
54.	डा. श्री श्रीकृष्ण सिन्हा	189.00	मुख्य प्रोड्यूसर, फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई-26		सामान्य प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "डाक्युमेंट्री" के रूप में वर्गीकृत
55.	युद्ध ड्यूटी	43.00	—तथैव—		—तथैव—
56.	वार्ता तरंगिनी	105.00	आंध्रप्रदेश राज्य फ़िल्म विकास निगम लि., 11/5/423/1 लकड़ी का पुल, हैदराबाद-500004		आंध्रप्रदेश क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "समाचार तथा समसामयिक घटनाओं" के रूप में वर्गीकृत
57.	बहार ही बहार	73.70	श्री एम. आर. साज, 4/5, ई. एम. एस्टेट, एस. वी. रोड, बांद्रा, बम्बई		सामान्य प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "डाक्युमेंट्री" के रूप में वर्गीकृत
58.	नारायणा सामायामलो	38.00	मुख्य प्रोड्यूसर, फ़िल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई-400026		आंध्रप्रदेश में प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "डाक्युमेंट्री" के रूप में वर्गीकृत
59.	बधयाता	36.00	—तथैव—		—तथैव—
60.	नीराम	29.87	—तथैव—		—तथैव—
61.	जवाबदारी (रिसपांसिबिल्टी)	36.00	—तथैव—		कर्नाटक क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "डाक्युमेंट्री" के रूप में वर्गीकृत
62.	सफलावल्ली साथरा	41.00	—तथैव—		—तथैव—
63.	अपराधा	32.00	—तथैव—		—तथैव—
64.	मारीयाना समयथिल	38.00	—तथैव—		तमिलनाडु क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "डाक्युमेंट्री" के रूप में वर्गीकृत
65.	पोरुप्प	38.00	—तथैव—		—तथैव—
66.	कुत्तरम	36.57	—तथैव—		—तथैव—
67.	भविष्यत पायें (फ़ार दि फ्यूचर)	29.56	मुख्य प्रोड्यूसर, फ़िल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई-26		सामान्य प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "डाक्युमेंट्री" के रूप में वर्गीकृत
68.	भविष्यतर जानया (फ़ार दि फ्यूचर)	28.65	—तथैव—		—तथैव—
69.	अपराध (ए क्राइम)	30.48	मुख्य प्रोड्यूसर, फ़िल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई-26		सामान्य प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "डाक्युमेंट्री" के रूप में वर्गीकृत
70.	अपराध (ए क्राइम)	29.87	—तथैव—		—तथैव—
71.	आयुष्य समाधान	41.00	—तथैव—		—तथैव—
72.	सहिति चित्र नं. 475	205.66	सहायक सूचना निदेशक, गुजरात सरकार, रामनोर्ड रिसर्च लैब लि., 77 डा. एनी बेसेंट रोड, वर्ली, बम्बई-400018		गुजरात क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "समाचार तथा सामयिक घटनाओं" के रूप में वर्गीकृत
73.	कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र	262.13	निदेशक, जनसंपर्क, हरियाणा, चंडीगढ़		सामान्य प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "डाक्युमेंट्री" के रूप में वर्गीकृत
74.	उज्जवल भविष्य	32.30	मुख्य प्रोड्यूसर, फ़िल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई-26		—तथैव—
75.	उज्ज्वल भविष्य	29.00	—तथैव—		—तथैव—
76.	उज्ज्वल भविष्य	33.52	—तथैव—		—तथैव—
77.	शुभमामया भवी	34.14	—तथैव—		—तथैव—
78.	प्रश्न परिहरम	62.48	—तथैव—		—तथैव—
79.	समस्यार समाधान	43.58	—तथैव—		—तथैव—
80.	समस्यार समाधान	43.58	—तथैव—		—तथैव—
81.	समस्यार समाधान	43.58	—तथैव—		—तथैव—
82.	पब्लिक सेक्टर		—तथैव—		—तथैव—
83.	सोशल क्राइम	36.00	—तथैव—		—तथैव—
84.	समस्याजे परिहारा	39.00	—तथैव—		—तथैव—

1	2	3	4	5	6
85.	उज्जवल भविष्य	35.00	—तथैव—		—तथैव—
86.	समस्या परिश्रम	40.00	—तथैव—		—तथैव—
87.	उज्जवल भविष्यत्	33.00	—तथैव—		—तथैव—
88.	प्रछलाईकु तीव्र	40.00	—तथैव—		—तथैव—
89.	ओम्मीमायामाना इथिरकलाम	35.00	—तथैव—		—तथैव—
90.	6 ईयर नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट सेवेंथ इश्यू	32.00	श्री जी. एल. भारद्वाज, भारद्वाज फ़िल्म्स, 29, प्रेजीडेंसी, 7वां रोड, जुहू पारले, बम्बई-49		—तथैव—
91.	—तथैव—	32.00	—तथैव—		—तथैव—
92.	आहृत	108.00	श्री शंकर एम. के. 3/206, मनीषा दर्शन, जे. बी. नगर, अंधेरी, बम्बई-59		सामान्य प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "डाक्युमेंट्री" के रूप में वर्गीकृत
93.	आडुगु बारगालकु चायुथा	260.67	आंध्र प्रदेश राज्य फ़िल्म विकास निगम लि., 11-5-423-1 लकड़ी का पुल, हैदराबाद-500004		आंध्र प्रदेश क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "डाक्युमेंट्री" के रूप में वर्गीकृत
94.	वार्ता तरंगिज 106	295.70	—तथैव—		आंध्र प्रदेश क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "समाचार तथा सामयिक घटनाओं" के रूप में वर्गीकृत
95.	ममाजा सेवकी	35.00	मुख्य प्रोड्यूसर, फ़िल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई-26		सामान्य प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "डाक्युमेंट्री" के रूप में वर्गीकृत
96.	सामुका सेविका (सोशल वर्कर)	32.00	—तथैव—		—तथैव—
97.	सामाजा सेविका (सोशल प्राब्लम)	28.00	—तथैव—		—तथैव—
98.	भविष्य रूपसी (फ़ोर दि फ्यूचर)	33.00	—तथैव—		—तथैव—
99.	अम्मईभविष्यपू कासम (फ़ोर दि फ्यूचर)	30.00	—तथैव—		—तथैव—
100.	वालामानाएथिरकालथिक्क (फ़ार दि फ्यचर)	33.00	—तथैव—		—तथैव—
101.	गुणवंथी (गुणवंती)	36.00	—तथैव—		—तथैव—
102.	गुणवता (गुणवंती)	33.00	—तथैव—		—तथैव—
103.	गुणवती	37.00	—तथैव—		—तथैव—
104.	सभयुगम (फ़ोर दि फ्यूचर)	57.00	—तथैव—		—तथैव—
105.	समाचार पत्रिका नं. 109ए	507.00	मुख्य प्रोड्यूसर, फ़िल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई-26		सामान्य प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "समाचार तथा सामयिक घटनाओं" के रूप में वर्गीकृत
106.	फ़ोर सर्टेन	62.00	—तथैव—		सामान्य प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "डाक्युमेंट्री" के रूप में वर्गीकृत
107.	विमुक्ति (प्राब्लम साल्वड)	52.00	—तथैव—		—तथैव—
108.	हर दिल में जगायें राष्ट्रज्योति	70.10	—तथैव—		—तथैव—
109.	समाचार पत्रिका संख्या 110	399.00	—तथैव—		—तथैव—
110.	लोकन्यायालय	427.00	महानिदेशक, सूचना और जनसंपर्क, महाराष्ट्र सरकार, फ़िल्म सेंटर, 68, ताडदेव रोड, बम्बई-34		महाराष्ट्र क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "डाक्युमेंट्री" के रूप में वर्गीकृत
111.	टक्का सामायथा (एट दि राईट टाइम)	53.00	मुख्य प्रोड्यूसर, फ़िल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई-26		सामान्य प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "डाक्युमेंट्री" के रूप में वर्गीकृत
112.	कुत्तरम (ए क्राइम)	33.52	मुख्य प्रोड्यूसर, फ़िल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई-26		—तथैव—

1	2	3	4	5	6
113.	सफ़लम स्वप्नम (ए ड्रीम फुलफ़िल्ड)	221.00	—तथैव—	—तथैव—	—तथैव—
114.	समाचार पत्रिका संख्या 110-ए	380.00	—तथैव—	—तथैव—	—तथैव—
115.	चिन्ना कुटुम्बम	73.70	श्री एस. ग्रार. साज, प्रो. ग्रम्मा ए मूवी मेकर्स, 4/5 ई. एम. एस्टेट, एस. वी. रोड, बांद्रा, बम्बई-50		आंध्रप्रदेश में प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "डाक्युमेंट्री" के रूप में स्वर्गीकृत।
116.	सुखी संसारा	—तथैव—	—तथैव—	—तथैव—	कर्नाटक क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और डाक्युमेंट्री के रूप में वर्गीकृत
117.	सुखिया नो संसार	73.70	श्री एस. ग्रार. साज, प्रो. ग्रम्मा ए मूवी मेकर्स, 4/5, ई. एम. एस्टेट, एस. वी. रोड, बांद्रा, बम्बई-50		गुजरात क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "डाक्युमेंट्री" के रूप में वर्गीकृत
118.	सुखाचा संसार	—तथैव—	—तथैव—	—तथैव—	महाराष्ट्र क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "डाक्युमेंट्री" के रूप में वर्गीकृत
119.	पेडलाकोसम पक्कईलू	464.02	आंध्र प्रदेश फ़िल्म विकास निगम लि., 11/5/423 1, लकड़ी का पुल, हैदराबाद-500004		आंध्रप्रदेश क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "डाक्युमेंट्री" के रूप में वर्गीकृत
120.	दैरम (रिसपांसिबिलटी)	33.83	मुख्य प्रोड्यूसर, फ़िल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई-26		सामान्य प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "डाक्युमेंट्री" के रूप में वर्गीकृत
121.	भविष्योत्तर बावे (फ़ोर दि फ्यूचर)	36.58	—तथव—	—तथैव—	—तथैव—
122.	अपराध (ए क्राइम)	31.00	—तथैव—	—तथैव—	—तथैव—
123.	उत्तरवादित्तम (रिसपांसिबिलटी)	59.00	—तथैव—	—तथैव—	—तथैव—
124.	साथिक समय (एट दि राईट टाईम)	47.00	—तथैव—	—तथैव—	—तथैव—
125.	दैत्य (रिसपांसिबिल्टी)	33.22	—तथैव—	—तथैव—	—तथैव—
126.	दैत्य (रिसपासिबिल्टी)	37.40	—तथैव—	—तथैव—	—तथैव—
127.	ह्याथिक हम (एट दि राईट टाईम)	45.00	—तथैव—	—तथैव—	—तथैव—
128.	साथिक समय (एट दि राईट टाईम)	43.00	—तथैव—	—तथैव—	—तथैव—
129.	नंदादेवी जात	512.06	निदेशक, सूचना और जनसंपर्क, उत्तर प्रदेश (लखनऊ)		उत्तर प्रदेश क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "डाक्युमेंट्री" के रूप में वर्गीकृत
130.	वार्ता तरंगिनी 107	254.20	आंध्र प्रदेश फ़िल्म विकास निगम, 11-5-423-1 लकड़ी का पुल, हैदराबाद-500004		आंध्र प्रदेश क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "समाचार तथा सामयिक घटनाओं" के रूप में वर्गीकृत
131.	उज्ज्वल भविष्य की ओर कुमाऊं मंडल	291.08	श्री धीरेन्द्र पांडे, द्वारा बम्बई फ़िल्म लैब लि., 149, एस. के. बोले रोड, बम्बई-28		उत्तर प्रदेश क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "डाक्युमेंट्री" के रूप में वर्गीकृत
132.	उज्ज्वल भविष्य की ओर गढ़वाल मंडल	297.18	—तथैव—	—तथैव—	—तथैव—
133.	समाचार पत्रिका नं. 111	272.00	मुख्य प्रोड्यूसर, फ़िल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई-400026		सामान्य प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "समाचार एवं सामयिक घटनाओं" के रूप में वर्गीकृत
134.	नालेज-इग्नोरेंस	464.00	श्री फ़िरोज चिनाय, श्री रामसे निवास, तिलक मंदिर रोड, विले पारले (ई), बम्बई-400057		सामान्य प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "डाक्युमेंट्री" के रूप में वर्गीकृत
135.	महितो चित्र नं. 476	222.50	सहायक सूचना निदेशक, गुजरात सरकार, रामनोर्ड रिसर्च लैब लि., 77, डा. एनी बेसेंट रोड, बम्बई-400018		गुजरात क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "समाचार तथा सामयिक घटनाओं" के रूप में वर्गीकृत
136.	महाराष्ट्र समाचार नं. 424	274.00	महानिदेशक, सूचना और जनसंपर्क, महाराष्ट्र सरकार, फ़िल्म सेंटर, 68, ताड़देव बम्बई-400034		महाराष्ट्र क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "समाचार तथा सामयिक घटनाओं" के रूप में वर्गीकृत

1	2	3	4	5	6
137.	पब्लिक सेक्टर	443.00	मुख्य प्रोड्यूसर, फिल्म प्रभाग, 24 पेडर रोड, बम्बई-26		सामान्य प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "डाक्युमेंट्री" के रूप में वर्गीकृत
138.	मिसन प्लीज	40.00	—तथैव—	—तथैव—	कर्नाटक क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए स्वीकृत तथा "डाक्युमेंट्री" के रूप में वर्गीकृत
139.	एंड्रोम	100.00	—तथैव—	—तथैव—	सामान्य प्रदर्शन के लिए स्वीकृत तथा "डाक्युमेंट्री" के रूप में वर्गीकृत
140.	ल्यूर आफ दि हैवेन	474.00	—तथैव—	—तथैव—	—तथैव—
141.	समाचार पत्रिका नं. 113	363.00	—तथैव—	—तथैव—	सामान्य प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "समाचार एवं सामयिक घटनाओं" के रूप में वर्गीकृत
142.	समाचार पत्रिका नं. 122	285.00	—तथैव—	—तथैव—	सामान्य प्रदर्शन के लिए स्वीकृत और "समाचार तथा सामयिक घटनाओं के रूप में वर्गीकृत ।

[फ़ाईल संख्या 315/2/87—एफ़ (पी)]

ए. एम. आर. मूर्ति, डेस्क अधिकारी

S. O. 919 - In pursuance of the directions issued under the provisions of each of the enactments specified in the first Schedule to the Order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated 2nd December, 1966 the Central Government after considering recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

S. No.	Title of the film	Length of the film in metres	Name of the applicant	Name of the Producer	Brief synopsis whether a scientific film or for edcational purpose or a film dealing with news & current events or documentary film.
1	2	3	4	5	6
1.	Nandi Bahumatula Pradanotsyam 1986	534 00	Andhra Pradesh Film Development Corporation 11/5/423/1 Lakdikapool Hyderabad 500 004		Approved for release in Andhra Pradesh circuit and classified as News and Current Events."
2.	Uttar Pradesh Samachar 123	286.00	Dhirendra Pande, C/o Bombay Film Lab. 149, S.K. Bole Road, Bombay 400 028		Approved for release in Uttar Pradesh circuit and classified as News and Current Events".
3.	For a better Living	424.00	Shri Ghanashyam Mahapatra Ratnakar Bldg., Plot 1167/2, Tankpani Road, Bhubaneswar.		Approved for general release and classified as Documentary".
4.	News Magazine No. 104	315.00	The Chief Producer, Films Divsion, 24 Peddar Road, Bombay-400 026		Approved for general release and classified as News and Current Events."
5.	Vik	487.15	Shri Gajannad Mishra Mnav D-9, Indrapuri Lalkothi, Jaipur.		Approved for release in rural areas of Hindi speaking State and classified as "Documentary."
6.	Varta Tarangini No. 102	237.00	Andhra Pradesh State Film Development Corporation Ltd., 11-5-423/1 Lakdikapool, Hyderabad-4.		Approved for release in Andhra Pradesh circuit and classified as "New and current Events".
7.	Maharashtra News No. 422	283.00	Director general of Information & Public Relations, Govt. of Maharashtra, Film Centre, 68 Tardeo Road, Bombay-34.		Approved for release in Maharashtra circuit and classified as "News and Current Events"

1	2	3	4	5	6
8.	A Crime	30.00	The Chief Producer, Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-26.		Approved for general and classified as "Documentary".
9.	Protection against Blindess II	31.00	—do—		—do—
10.	Protection against Blindness I	29.00	—do—		—do—
11.	Social Worker	33.00	The Cief Producer, classified as "Documentary". Bombay-26.		Approved for general release and classified as "Documentary".
12.	I have heard II	36.00	—do—		—do—
13.	I have heard I	53.00	—do—		—do—
14.	Why take risk?	32.00	—do—		—do—
15.	Listen Please	41.00	—do—		—do—
16.	No Problem	28.00	—do—		—do—
17.	News Magazine No. 105	415.00	—do—		Approved for general release and classified as "News and Current Events".
18.	Gurumantra	207.00	—do—		Approved for general release and classified as "Documentary".
19.	Cracks	276.45	—do—		—do—
20.	S. Satyamurti	547.72	—do—		—do—
21.	Gujarat No Matsya Udyog	333.15	Director of Information & Public Relations, Govt. of Gujarat, Sachivalaya, Gandhinagar 382010		Approved for release in Gujarat circuit and classified as "Documentary".
22.	Suraksha	370.33	Shri Jyoti Roy, C/o National Insurance Co. Ltd., 3, Middleton Street, Calcutta-700 0071.		Approved for general release and classified as "Doumentary"
23.	Bright Future	28.00	The Chief Producer, Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-26.		—do—
24.	Solving a problem	44.00	The Chief Producer, Films Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-400 026.		Approved for general release and classified as "Documentary".
25.	Responsibility	38.00	—do—		—do—
26.	Care during pregnancy	38.00	—do—		—do—
27.	Dai	79.00	—do—		—do—
28.	For the Future	30.00	—do—		—do—
29.	Gunvanti	30.00	—do—		—do—
30.	Just a little Care-II	36.00	—do—		—do—
31.	Just a little Care-I	36.00	—do—		—do—
32.	Electronic Udyog	289.56	The Dir. of Information & Public Relations, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.		Approved for release Uttar Pradesh circuit and classified as "Documentary".
33.	The Vessel Sublime	388.60	Kamal Lalwami, 133, Canning Street, B.a2, Calcutta-700 001.		Approved for general release and classified as "Documentary."
34.	Sab Ke Liye Makaan	290.78	The Dir. of Information & Public Relations, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.		Approved for release in Uttar Pradesh circuit and classified as "Documentary".
35.	At the right time.	36.00	The Chief Producer, Films, Division, 24-Peddar Road, Bombay-26.		Approved for general release and classified as "Documentary.
36.	News Magazine No. 106	524.00	The Chief Producer, Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-400 026.		Approved for general release and classified as "News and Current Events."
37.	Dahej Ki Jwala.	334.37	United Ads, Fatima Mahal, B-9/II floor, Kevni Pada Jogeshwari, Bombay-400 102.		Approved for general release and classified as "Documentary".

1	2	3	4	5	6
38.	News Magazine No. 107	313.00	The Chief Producer, Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-26.		—do—
39.	Dance also Cures	492.00	—do—		—do—
40.	Varta Tarangini 103	276.00	Andhra Pradesh State Film Development Corporation Ltd., 11-5-423/1 Zafarbagh Lakdi Ka Pool, Hyderaad-4.		Approved for release in Andhra Pradesh circuit and classified as New and current Events".
41.	Aa lapaduchuku Andadandalu	575.5	—do—		Approved for release in Andhra Pradesh circuit and classified as "Documentary".
42.	Why the difference?	37.00	The Chief Producer, Films Divison, 24-Peddar Road, Bombay-400 026.		Approved for general release and classified as "Documentary".
43.	News Magazine No. 108	293.00	—do—		—do—
44.	News Magazine No. 106A	430.00	—do—		Approved for general release and classified as "News and Current Events."
45.	Through the Looking Glass		Shri Venugopal Thakker, 6, New Sharda, North Avenue, Santacruz (W), Bombay-54.		Approved for general release and classified as "Documentary".
46.	Uttar Pradesh Samachar 124	288.95	Shri Pramod Pande (Film Editor) C/o 149, Bombay Film Lab Pvt. Ltd., Bombay-28	Shri Dhirendra Pande, Dir of Information & Public Relations, Govt. of U.P. Lucknow.	Approved for release in Uttar Pradesh circuit and classified as "News and Current Events".
47.	Varta Tarangini 104	268.93	Andhra Pradesh State Film Development Corporation Ltd., 11-5-423/a Lakdikapool Hyderabad-500 004.		Approved for release in Andhra Pradesh circuit and classified as "New and Current Events".
48.	Problem Solved	42.00	The Chief Producer, Films Division. 24-Peddar Road, Bombay-400 026.		Approved for general release and classified as "Documentary".
49.	R.K. Laxman	595.00	—do—		—do—
50.	Metro Railway in Calcutta.	543.20	Shri Surjit Dasgupta, 1/13 Gurungar, Four Bungalows Road, Andheri (W), Bombay-58.		—do—
51.	Maharashtra News No. 423	277.00	Dir Gen. of Information & Public Relations, Govy. of Maharashtra, Film Center, 68 Tardeo Road, Bombay-34.		Approved for release in Maharashtra circuit and classified as "News and Current Events".
52.	Pedalakosam Pakka Ellu	478.87	Andhra Pradesh Film Development Corporation, 11-5-423/1 Lakdikapool, Hyderabad.		Approved for release in Andhra Pradesh circuit and classified as "Documentary".
53.	Chetana	527.00	Shri M.M. Vaidya, Avinash Apts. Near Nataraj Coop. Housing Society, Panchpakhadi, Thane.		Approved for general release and classified as 'Documentary".
54.	Dr. Sri Srikrishna Sinha	489.00	The Chief Producer, Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-400 026.		Approved for general release and classified as "Documentary".
55.	Your Duty	43.00	—do—		—do—
56.	Varta Tarangini	105.00	Andhra Pradesh State Film Development Corporation Ltd., 11/5/423/1 Lakdiapool, Hyderabad-500 004.		Approved for release in Andhra Pradesh circuit and classified as "News and Currents Events".

1	2	3	4	5	6
57.	Bahar Hi Bahar	73.70	Shri S.R. Saaz, 4/5 E.M. Estate, S.V. Road, Bandra, Bombay.		Approved for general release and classified as "Documentary".
58.	Sarayana Samayamlo	38.00	The Chief Producer, Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-400 026.		Approved for release in Andhra Pradesh circuit and classified as "Documentary".
59.	Badhyata	36.00	-do -		-do -
60.	Neram	29.87	-do -		-do -
61.	Jawabdari (Responsibility)	36.00	-do -		Approved for release in Karnataka circuit and classified as "Documentary'.
62.	Sakaladalli Mathra	41.00	-do -		-do-
63.	Aparadha	32.00	-do-		-do-
64.	Sariyana Samayathil	38.00	-do-		Approved for release in Tamil Nadu circuit and classified as "Documentary".
65.	Poruppu	38.00	-do-		-do-
66.	Kutram	36.57	-do-		-do-
67.	Bhabisyat Paien (for the future)	29.56	The Chief Producer, Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-400 026.		Approved for general release and classified as "Documentary".
68.	Bhabishyater Janya (for the future)	28.65	-do -		-do -
69.	Aparadh (A Crime)	30.48	-do -		-do -
70.	Aparadha (A Crime)	29.87	-do -		-do-
71.	Ayushyacha Samadhan	41.00	-do -		-do -
72.	Mahitichitra No. 475	205.66	Asstt Dir of Information Govt. of Gujrarat, Ramnod Research Lab. Ltd., 77 Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-400 018.		Approved for release in Gujarat circuit and classified as "News & Current Events".
73.	Kurukshetra Dharmkshetra	262.13	Dir. Public Relations, Haryana, Chandigarh.		Approved for general release and classified as "Documentary".
74.	Ujjwal Bhabishyai.	32.30	Thie Chief Producer, Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-26.		-do -
75.	Ujjwal Bhabishyai	29.00	-do -		-do -
76.	Ujjwal Bhavishai	33.52	do -		-do -
77.	Shubhanamaya Bhavi	34.14	-do -		-do -
78.	Prashna Pariharam	62.48	The Chief Producer, Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-400 026.		Approved for general release and classified as "Documentary".
79.	Samasyar Samadhan	43.58	-do -		-do -
80.	Samasyara Samadhan	43.58	-do -		-do -
81.	Samasyara Samadhan	43.58	-do -		-do -
82.	Public Sector		-do -		-do -
83.	Social Crime	36.00	-do -		-do -
84.	Samasyege Parhihara	39.00	-do -		-do -
85.	Ujwala Bhavishya	35.00	-do -		-do -
86.	Samasya Parishkaram	40.00	-do -		-do -
87.	Ujwal Bhavihyathu	33.00	-do -		-do -
88.	Prachanaiku Theervu	40.00	-do -		-do -
89.	Ozhimayamana Ethirkalam	35.00	-do -		-do -
90.	6-Year National Savings Certificate VIIth Issue.	32.00	Shri G.L. Bhardwaj, Bhardwaj Films, 29, Presidency, 7th Road, Juhuparle, Bombay-49.		-do -

1	2	3	4	5	6
91.	6-Year National Savings Certificate VIth issue	32.00	Shri G.L. Bhardwaj, Bhardwaj Films, 29, Presidency 7th Rd., Juhuparle, Bombay-49.		Approved for genral release and classified as "Documentary".
92.	Chaahat	108.00	Shri Shankar M.K., 3/206, Manisha Darshan, J.B. Nagar, Andheri, Bombay-53.		-do -
93.	Badugu Vargalaku Cheyutha	360.67	Andhra Pradesh State Film Development Corporation Ltd., 11-5-423/1 Lakdikapool, Hyderabad-500 004.		Approved for release in Andhra Pradesh circuit and classified as "Documentary".
94.	Varta Tarangini 106	285.70	-do -		Approved for release in Andhra Pradesh circuit and classified as "News and Current Events".
95.	Samaja Sevaki	35.00	The Chief Producer, Films Division, 2 -Peddar Road, Bombay-400 026.		Approved for general release and classified as "Documentary".
96.	Samuka Sevika (Social Worker)	32.00	—do—		—do—
97.	Samaja Sevika (Social Problem)	28.00	—do -		—do -
98.	cBhavishya Roopisi (For the Future)	33.00	-do -		-do -
99.	Ammai Bhavishyathu Kosam (For the future)	30.00	-do -		-do -
100.	Valamana-Ethirkalathirku	33.00	The Chief Producer, Films Division, 24, Peddar Road, Bombay-400026		Approved for general release and classified as "Documentary"
101.	Gunavanthi (Gunavanti)	36.00	-do -		-do—
102.	Gunavanti (Gunavanti)	33100	-do -		-do -
103.	Gunavati	37.00	- do -		-do -
104.	Navay gam (For the future)	57.00	-do -		-do -
105.	News Magazine No. 109A	507.00	-do -		Approved for general release and classified as "News ond Current Events".
106.	For Certain	62.00	-do -		Approved for general release and Classified as "Documentary".
107.	Vimukti (Problem Solved)	52.00	-do -		-do -
108.	Har Dil Mein Jagayan Rashtrajyoti	70.10	-do -		-do -
109.	News Magazine No. 110	399.00	-do -		-do -
110.	Loknyayalaya	427.00	Dir. Gen. of Information & Public Relations Govt. of Maharashtra, Film Centre, Tardeo Road, Bombay-34.		Approved for release in Maharashtra circuit and classified as "Documentary".
111.	Takka Samayatha (At the right time)	53.00	The Chief Producer, Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-26.		Approved for general release and classified as 'Documentary".
112.	Kutram (A Crime)	33.52	The Chief Producer, Film Division, 24-Peddar Road, Bombay-400 026.		Approved for general release and classified as "Documentary".
113.	Safalam Swapnam (A Dream Fulfilled).	221.00	-do -		-do -
114.	News Magazine No. 110-A	380.00	-do -		-do -
115.	Chinna Kutumbham	73.70	Shri S.R. Saaz, Prof. Amma AM Movie Makers, 4/5/, E.M. Estate S.V. Road, Bandra, Bombay-50.		Approved for release in Andhra Pradesh circuit and classified as "Documentary".
116.	Sukhi Sansara	-do -	-do -		Approved for released in Karnataka circuit and classified as "Documentary".

1	2	3	4	5	6
117.	Sukhiya No Sansar	73.70	Shree S. R. Saax, Prof. Amma AM Movie Makers, 4/5, E.M. Estate S.V. Rd., Bandra Bombay-50.		Approved for release in Gujarat circuit and classified as "Documentary".
118.	Sukhacha Sansar	—do—	—do—		Approved for release in Maharashtra circuit and classified as "Documentary".
119.	Pedalakosam Pak kaillu	464.02	Andhra Pradesh Film Development Corporation, 11.5.423/1, Lakdikapool, Hyderabad-500 004.		Approved for release in Andhra Pradesh circuit and classified as "Documentary".
120.	Dayetya (responsibility)	33.83	The Chief Producer, Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-40 026.		Approved for general release and classified as "Documentary".
121.	Bhavishyotar Babe (For the future).	36.58	—do—		—do—
122.	Aparadh (A crime)	31.00	—do—		—do—
123.	Uttaravadittam (responsibility)	59.00	The Chief Producer, Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-400 026.		Approved for general release and classified as "Documentary".
124.	Shathik Samaye (at the right time)	47.00	—do—	—do—	—do—
125.	Dayitta (responsibility)	33 22	—do—	—do—	—do—
126.	Dayitta (responsibility)	37 40	—do—	—do—	—do—
127.	Hathik Hamay (at the right time)	45.00	—do—	—do—	—do—
128.	Sathik Samaya (at the right time)	43.00	—do—	—do—	—do—
129.	Nandadevi Raj Jaat	512.06	Shri Dhirendra Pande, Producer, Dir of Inform & Public Relations, Uttar Pradesh (Lucknow).		Approved for release in Uttar Pradesh circuit and classified as "Documentary".
130.	Varta Tarangini 107	254 20	Andhra Pradesh Film Development Corporation, 11.5.423/1 Lakdikapool, Hyderabad-500 004.		Approved for release in Andhra Pradesh circuit and classified as 'News and Currrect Events'.
131.	Ujjwal Bhavishya Ki One Kumaon Mandal.	291.08	Shri Dhirendra Pande, C/o Bombay Film Lab. Ltd., 149, S.K. Bole Road, Bombay-28.		Approved for release in Uttar Pradesh circuit and classified as 'Documentary'
132.	Ujjwal Bhavishya Ki Ore-Garwal Mandal.	297.18	—do—	—do—	—do—
133.	News Magazine No. 111	272.00	The Chief Producer, Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-400 026.		Approved for general release and classified as "News and Current Events".
134.	Knowledge-Ignorance	464.00	Shri Firoz Chincy, Shri Ram Sai Niwas, Tilak Mandir Rd., Vile Parle (E), Bombay-400 057.		Approved for general release andclassifide as 'Documentary'
135.	Mahitichitra No. 476	222.50	Assistant Director of Information, Govt. of Gujarat, Ramnord Research Lab. Ltd., 77, Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-400 018.		Approved for release in Gujarat circuit and classified a 'News and Current Events'.
136.	Maharashtra News No. 424	274 00	Dir. Gen. of Information & Public Relaations, Govt. of Maharashtra, Film Centre, 68, Tardeo Road, Bombay-400 034.		Approved for Relsease in Maharashtra circuit and classified as 'News and Current Events'

1	2	3	4	5	6
137.	Public Sector	443.00	The Chief Producer, Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-400 026.		Approved for general release and classified as 'Documentary'.
138.	Listen Please	40.00	—do—	—do—	Approved for release in Karnataka circuit and classified as 'Documentary.'
139.	Endgame	100.00	—do—	—do—	Approved for general release and classified as 'Documentary'.
140.	Lure of the heavens	474.00	do—	—do—	—do—
141.	News Magazine No. 113	363.00	—do—	—do—	Approved for general release and classified as "News and Current Events".
142.	News Magazine	285.00	The Chief Producer, Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-400 026.		Approved for general release and classified as "News and Current Events".

[File No. 315/2/87-F (P)]

A.S.R. MURTHY, Desk Officer

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(श्रम प्रभाग)

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1989

का.आ. 920.—गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) स्कीमों, जो यहां सलग्न शिड्यूल में निर्दिष्ट हैं, जिसे केन्द्र सरकार का गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधित करने का प्रस्ताव है, को और संशोधित करने के लिए स्कीम का निम्नलिखित प्रारूप एतद्द्वारा उन सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है जिन पर उसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, जैसा कि उक्त उप धारा द्वारा अपेक्षित है और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप पर भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां आम जनता को सुलभ कराए जाने की तारीख से 45 दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा उसके बाद विचार किया जाएगा

उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पहले उक्त प्रारूप के संबंध में केन्द्र सरकार को किसी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों अथवा सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप स्कीम

1. (1) इस स्कीम को गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1989 कहा जाए।

(2) यह भारत के राजपत्र में अंतिम रूप से प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

2. यहां सलग्न शिड्यूल के कालम (2) में निर्दिष्ट गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) स्कीमों को संशोधित किया जाएगा, अथवा जैसा भी मामला हो, उसके कालम (3) में निर्दिष्ट ढंग से और संशोधित किया जाएगा।

शिड्यूल

क्रम सं.	लघु शीर्षक	संशोधन
1	2	3
1.	बम्बई गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) स्कीम, 1956	अनुच्छेद 32 के लिए, निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "32 उपस्थिति भत्ता : स्कीम के अन्य प्रावधानों के अनुसार रिजर्व पूल रजिस्टर का एक श्रमिक जो काम के लिए उपलब्ध है लेकिन उसके लिए कोई काम न हो तो उसे मासिक वेतन, जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल है, का 1/60वां भाग और मासिक मकान किराया भत्ता का 1/30वां भाग उपस्थिति भत्ते के रूप में कैलेंडर महीनों के उन दिनों के लिए भुगतान किया जाएगा जिन दिनों वह प्रशासनिक निकाय के निर्देश पर काम के लिए उपस्थित हुआ और उसके लिए कोई काम नहीं था। बशर्ते कि ऐसे किसी दिन के लिए उपस्थिति भत्ता नहीं दिया जाएगा जिसके लिए महंगाई भत्ता सहित पूरा वेतन अनुच्छेद 31 के तहत दिया गया हो अथवा जिसके लिए अनुच्छेद 34 के तहत डिसएपाइंटमेंट मनी का भुगतान किया गया हो।"
2.	मद्रास गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) स्कीम, 1956	अनुच्छेद 23 के लिए, निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "32 उपस्थिति भत्ता : स्कीम के अन्य प्रावधानों के अनुसार रिजर्व पूल रजिस्टर का एक श्रमिक जो काम के लिए उपलब्ध है लेकिन उसके लिए कोई काम न हो तो उसे मासिक वेतन, जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल है का 1/60वां भाग और मासिक मकान

1	2	3
		किराया भत्ता का 1/30वां भाग उपस्थिति भत्ते के रूप में कैलेंडर महीनों के उन दिनों के लिए भुगतान किया जाएगा जिन दिनों वह प्रशासनिक निकाय के निर्देश पर काम के लिए उपस्थिति हुआ और उसके लिए कोई काम नहीं था । बशर्ते कि ऐसे किसी दिन के लिए उपस्थिति भत्ता नहीं दिया जाएगा जिसके लिए महंगाई भत्ता सहित पूरा वेतन अनुच्छेद 31 के तहत दिया गया हो अथवा जिसके लिए अनुच्छेद 34 के तहत डिसएपाइंटमेंट मनी का भुगतान किया गया हो ।"
3.	कोचीन गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) स्कीम, 1959	अनुच्छेद 32 के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "32. उपस्थिति भत्ता : स्कीम के अन्य प्रावधानों के अनुसार रिजर्व पूल रजिस्टर का एक श्रमिक जो काम के लिए उपलब्ध है लेकिन उसके लिए कोई काम न हो तो उसे मासिक वेतन, जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल है, का 1/60वां भाग और मासिक मकान किराया भत्ता का 1/30वां भाग उपस्थिति भत्ते के रूप में कैलेंडर महीनों के उन दिनों के लिए भुगतान किया जाएगा जिन दिनों वह प्रशासनिक निकाय के निर्देश पर काम के लिए उपस्थिति हुआ और उसके लिए कोई काम नहीं था । बशर्ते कि ऐसे किसी दिन के लिए उपस्थिति भत्ता नहीं दिया जाएगा जिसके लिए महंगाई भत्ता सहित पूरा वेतन अनुच्छेद 31 के तहत दिया गया हो अथवा जिसके लिए अनुच्छेद 34 के तहत डिसएपाइंटमेंट मनी का भुगतान किया गया हो ।"
4.	विशाखापत्तनम गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) स्कीम, 1959	अनुच्छेद 31 के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "31. उपस्थिति भत्ता : स्कीम के अन्य प्रावधानों के अनुसार रिजर्व पूल रजिस्टर का एक श्रमिक जो काम के लिए उपलब्ध है लेकिन उसके लिए कोई काम न हो तो उसे मासिक वेतन, जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल है, का 1/60वां भाग और मासिक मकान किराया भत्ता का 1/30वां भाग उपस्थिति भत्ते के रूप में कैलेंडर महीनों के उन दिनों के लिए भुगतान किया जाएगा जिन दिनों वह प्रशासनिक निकाय के निर्देश पर काम के लिए उपस्थित हुआ और उसके लिए कोई काम नहीं था । बशर्ते कि ऐसे किसी दिन के लिए उपस्थिति भत्ता नहीं दिया जाएगा जिसके लिए महंगाई भत्ता सहित पूरा वेतन अनुच्छेद 30 के तहत दिया गया हो अथवा जिसके लिए अनुच्छेद 34 के तहत डिसएपाइंटमेंट मनी का भुगतान किया गया हो ।"
5.	मुरगांव गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) स्कीम, 1965	अनुच्छेद 33 के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :— "33. उपस्थिति भत्ता : स्कीम के अन्य प्रावधानों के अनुसार रिजर्व पूल रजिस्टर का एक श्रमिक जो काम के लिए उपलब्ध है लेकिन उसके लिए कोई काम न हो तो उसे मासिक वेतन, जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल है, का 1/60वां भाग और मासिक मकान किराया भत्ता का 1/30वां भाग उपस्थिति भत्ते के रूप में कैलेंडर महीनों के उन दिनों के लिए भुगतान किया जाएगा जिन दिनों वह प्रशासनिक निकाय के निर्देश पर काम के लिए उपस्थित हुआ और उसके लिए कोई काम नहीं था । बशर्ते कि ऐसे किसी दिन के लिए उपस्थिति भत्ता नहीं दिया जाएगा जिसके लिए महंगाई भत्ता सहित पूरा वेतन अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया हो अथवा जिसके लिए अनुच्छेद 35 के तहत डिसएपाइंटमेंट मनी का भुगतान किया गया हो ।"
6.	कांडला गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) स्कीम, 1969	अनुच्छेद 33 के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "33. उपस्थिति भत्ता स्कीम के अन्य प्रावधानों के अनुसार रिजर्व पूल रजिस्टर का एक श्रमिक जो काम के लिए उपलब्ध है लेकिन उसके लिए कोई काम न हो तो उसे मासिक वेतन, जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल है, का 1/60वां भाग और मासिक मकान किराया भत्ता का 1/30वां भाग उपस्थिति भत्ते के रूप में कैलेंडर

1	2	3
		महीनों के उन दिनों के लिए भुगतान किया जाएगा जिन दिनों वह प्रशासनिक निकाय के निर्देश पर काम के लिए उपस्थित हुआ और उसके लिए कोई काम नहीं था । बशर्ते कि ऐसे किसी दिन के लिए उपस्थिति भत्ता नहीं दिया जाएगा जिसके लिए महंगाई भत्ता सहित पूरा वेतन अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया हो अथवा जिसके लिए अनुच्छेद 35 के तहत डिसएपाइंटमेंट मनी का भुगतान किया गया हो ।"
7.	कलकत्ता गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) स्कीम, 1970	अनुच्छेद 35 के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "35. उपस्थिति भत्ता : स्कीम के अन्य प्रावधानों के अनुसार रिजर्व पूल रजिस्टर का एक श्रमिक जो काम के लिए उपलब्ध है लेकिन उसके लिए कोई काम न हो तो उसे मासिक वेतन, जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल है, का 1/60वां भाग और मासिक मकान किराया भत्ता का 1/30वां भाग उपस्थिति भत्ते के रूप में कैलेंडर महीनों के उन दिनों के लिए भुगतान किया जाएगा जिन दिनों वह प्रशासनिक निकाय के निर्देश पर काम के लिए उपस्थित हुआ और उसके लिए कोई काम नहीं था । बशर्ते कि ऐसे किसी दिन के लिए उपस्थिति भत्ता नहीं दिया जाएगा जिसके लिए महंगाई भत्ता सहित पूरा वेतन अनुच्छेद 34 अथवा) अनुच्छेद 36 के उप अनुच्छेद (2) के तहत दिया गया हो ।"
8.	मद्रास गैर पंजीकृत गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) स्कीम, 1957	अनुच्छेद 13ग के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "13ग उपस्थिति भत्ता : स्कीम के अन्य प्रावधानों के अनुसार रिजर्व पूल रजिस्टर का एक श्रमिक जो काम के लिए उपलब्ध है लेकिन उसके लिए कोई काम न हो तो उसे मासिक वेतन, जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल है, का 1/60वां भाग और मासिक मकान किराया भत्ता का 1/30वां भाग उपस्थिति भत्ते के रूप में कैलेंडर महीनों के उन दिनों के लिए भुगतान किया जाएगा जिन दिनों वह प्रशासनिक निकाय के निर्देश पर काम के लिए उपस्थित हुआ और उसके लिए कोई काम नहीं था । बशर्ते कि ऐसे किसी दिन के लिए उपस्थिति भत्ता नहीं दिया जाएगा जिसके लिए महंगाई भत्ता सहित पूरा वेतन अनुच्छेद 13ख के तहत दिया गया हो अथवा जिसके लिए अनुच्छेद 13घ के तहत डिसएपाइंटमेंट मनी का भुगतान किया गया हो ।"
9.	विशाखापत्तनम गैर पंजीकृत गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) स्कीम, 1968	अनुच्छेद 28 के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "28. उपस्थिति भत्ता : स्कीम के अन्य प्रावधानों के अनुसार रिजर्व पूल रजिस्टर का एक श्रमिक जो काम के लिए उपलब्ध है लेकिन उसके लिए कोई काम न हो तो उसे मासिक वेतन, जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल है, का 1/60वां भाग और मासिक मकान किराया भत्ता का 1/30वां भाग उपस्थिति भत्ते के रूप में कैलेंडर महीनों के उन दिनों के लिए भुगतान किया जाएगा जिन दिनों वह प्रशासनिक निकाय के निर्देश पर काम के लिए उपस्थित हुआ और उसके लिए कोई काम नहीं था । बशर्ते कि ऐसे किसी दिन के लिए उपस्थिति भत्ता नहीं दिया जाएगा जिसके लिए अनुच्छेद 29 के तहत डिसएपाइंटमेंट मनी का भुगतान किया गया हो ।"
10.	बम्बई चिपिंग एवं पेंटिंग श्रमिक (रोजगार का विनियमन) स्कीम, 1969	अनुच्छेद 32 के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "32 उपस्थिति भत्ता : स्कीम के अन्य प्रावधानों के अनुसार रिजर्व पूल रजिस्टर का एक श्रमिक जो काम के लिए उपलब्ध है लेकिन उसके लिए कोई काम न हो तो उसे मासिक वेतन, जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल है, का 1/60वां भाग और मासिक मकान किराया भत्ता का 1/30वां भाग उपस्थिति भत्ते के रूप में कैलेंडर महीनों के उन दिनों के लिए भुगतान किया जाएगा जिन दिनों वह प्रशासनिक निकाय के निर्देश पर काम के लिए उपस्थित हुआ और उसके लिए कोई काम नहीं था । बशर्ते कि ऐसे किसी दिन के लिए उपस्थिति भत्ता नहीं दिया जाएगा जिसके लिए महंगाई भत्ता सहित पूरा वेतन अनुच्छेद 31 के तहत

1	2	3
		दिया गया हो अथवा जिसके लिए अनुच्छेद 34 के तहत डिसएपाइंटमेंट मनी का भुगतान किया गया हो ।"
11.	कलकत्ता चिपिंग एवं पेंटिंग श्रमिक (रोजगार का विनियमन) स्कीम, 1970	अनुच्छेद 34 के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "34. उपस्थिति भत्ता : स्कीम के अन्य प्रावधानों के अनुसार रिजर्व पूल रजिस्टर का एक श्रमिक जो काम के लिए उपलब्ध है लेकिन उसके लिए कोई काम न हो तो उसे मासिक वेतन, जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल है, का 1/60वां भाग और ासिक मकान किराया भत्ता का 1/30वां भाग उपस्थिति भत्ते के रूप में कैलेंडर महीनों के उन दिनों के लिए भुगतान किया जाएगा जिन दिनों वह प्रशासनिक निकाय के निर्देश पर काम के लिए उपस्थित हुआ और उसके लिए कोई काम नहीं था । बशर्ते कि ऐसे किसी दिन के लिए उपस्थिति भत्ता नहीं दिया जाएगा जिसके लिए अनुच्छेद 33 अथवा अनुच्छेद 35 के उप अनुच्छेद (2) के तहत महंगाई भत्ते सहित पूर्ण वेतन का भुगतान किया गया हो ।
12.	कलकत्ता गोदी लिपिकीय और सुपरवाइजरी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) स्कीम, 1970	अनुच्छेद 29 के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "29. उपस्थिति भत्ता : स्कीम के अन्य प्रावधानों के अनुसार रिजर्व पूल रजिस्टर का एक श्रमिक जो काम के लिए उपलब्ध है लेकिन उसके लिए कोई काम न हो तो उसे मासिक वेतन, जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल है का 1/60वां भाग और मासिक मकान किराया भत्ता का 1/30वां भाग उपस्थिति भत्ते के रूप में कैलेंडर महीनों के उन दिनों के लिए भुगतान किया जाएगा जिन दिनों वह प्रशासनिक निकाय के निर्देश पर काम के लिए उपस्थिति हुआ और उसके लिए कोई काम नहीं था । बशर्ते कि ऐसे किसी दिन के लिए उपस्थिति भत्ता नहीं दिया जाएगा जिसके लिए महंगाई भत्ता सहित पूरा वेतन अनुच्छेद 28 के तहत दिया गया हो अथवा जिसके लिए अनुच्छेद 31 के तहत डिसएपाइंटमेंट मनी का भुगतान किया गया हो ।"
13.	बम्बई खाद्यान्न हैंडलिंग श्रमिक (रोजगार का विनियमन) स्कीम, 1975	अनुच्छेद 32 के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "32. उपस्थिति भत्ता : स्कीम के अन्य प्रावधानों के अनुसार रिजर्व पूल रजिस्टर का एक श्रमिक जो काम के लिए उपलब्ध है लेकिन उसके लिए कोई काम न हो तो उसे मासिक वेतन, जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल है, का 1/60वां भाग और मासिक मकान किराया भत्ता का 1/30वां भाग उपस्थिति भत्ते के रूप में कैलेंडर महीनों के उन दिनों के लिए भुगतान किया जाएगा जिन दिनों वह प्रशासनिक निकाय के निर्देश पर काम के लिए उपस्थित हुआ और उसके लिए कोई काम नहीं था । बशर्ते कि ऐसे किसी दिन के लिए उपस्थिति भत्ता नहीं दिया जाएगा जिसके लिए अनुच्छेद 31 अथवा अनुच्छेद 34 के तहत महंगाई भत्ते सहित पूर्ण वेतन का भुगतान किया गया हो ।"
14.	बम्बई गोदी क्लियरिंग एवं फारवर्डिंग श्रमिक (रोजगार का विनियमन) स्कीम, 1983	अनुच्छेद 31 के तहत लिए निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "31 उपस्थिति भत्ता : स्कीम के अन्य प्रावधानों के अनुसार रिजर्व पूल रजिस्टर का एक श्रमिक जो काम के लिए उपलब्ध है लेकिन उसके लिए कोई काम न हो तो उसे मासिक वेतन, जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल है, का 1/60वां भाग और मासिक मकान किराया भत्ता का 1/30वां भाग उपस्थित भत्ते के रूप में कैलेंडर महीनों के उन दिनों के लिए भुगतान किया जाएगा जिन दिनों वह प्रशासनिक निकाय के निर्देश पर काम के लिए उपस्थित हुआ और उसके लिए कोई काम नहीं था । बशर्ते कि ऐसे किसी दिन के लिए उपस्थित भत्ता नहीं दिया जाएगा जिसके लिए अनुच्छेद 30 अथवा अनुच्छेद 33 के तहत महंगाई भत्ते सहित पूर्ण वेतन का भुगतान किया गया हो ।"

1	2	3
15.	मद्रास गैर पंजीकृत गोदी विलयरिंग एवं फारवर्डिंग श्रमिक (रोजगार का विनियमन) स्कीम, 1988	अनुच्छेद 29 के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "29. उपस्थिति भत्ता : स्कीम के अन्य प्रावधानों के अनुसार रिजर्व पूल रजिस्टर का एक श्रमिक जो काम के लिए उपलब्ध है लेकिन उसके लिए कोई काम न हो तो उसे मासिक वेतन, जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल है, का 1/60वां भाग और मासिक मकान किराया भत्ता का 1/30वां भाग उपस्थिति भत्ते के रूप में कैलेंडर महीनों के उन दिनों के लिए भुगतान किया जाएगा जिन दिनों वह प्रशासनिक निकाय के निर्देश पर काम के लिए उपस्थित हुआ और उसके लिए कोई काम नहीं था । बशर्ते कि ऐसे किसी दिन के लिए उपस्थिति भत्ता नहीं दिया जाएगा जिसके लिए महंगाई भत्ता सहित पूरा वेतन अनुच्छेद 28 के तहत दिया गया हो अथवा जिसके लिए अनुच्छेद 31 के तहत डिसएपाइंटमेंट मनी का भुगतान किया गया हो ।"
16.	मद्रास गैर पंजीकृत गोदी सामान्य पूल श्रमिक (रोजगार का विनियमन) स्कीम, 1988	अनुच्छेद 33 के लिए, निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :— 33. उपस्थिति भत्ता : स्कीम के अन्य प्रावधानों के अनुसार रिजर्व पूल रजिस्टर का एक श्रमिक जो काम के लिए उपलब्ध है लेकिन उसके लिए कोई काम न हो तो उसे मासिक वेतन, जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल है, का 1/60वां भाग और मासिक मकान किराया भत्ता का 1/30वां भाग उपस्थिति भत्ते के रूप में कैलेंडर महीनों के उन दिनों के लिए भुगतान किया जाएगा जिन दिनों वह प्रशासनिक निकाय के निर्देश पर काम के लिए उपस्थित हुआ और उसके लिए कोई काम नहीं था । बशर्ते कि ऐसे किसी दिन के लिए उपस्थिति भत्ता नहीं दिया जाएगा जिसके लिए महंगाई भत्ता सहित पूरा वेतन अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया हो अथवा जिसके लिए अनुच्छेद 35 के तहत डिसएपाइंटमेंट मनी का भुगतान किया गया हो ।

[फाइल सं. एल बी-13013/11/88-एल-IV]

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Labour Division)

New Delhi, the 20th March, 1989

S. O. 920.—The following draft of a Scheme furteer to amend the Dock Workers (Regulation of Employment Schemes, specified in the Schedule annexed hereto, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is hereby published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be tken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date on which copies of this notifiction as published in the Gazette of India are made available to the public.

Any objections or suggestins which may be received by the Central Government from any person with respect to said draft before the expiry of the aforesaid period will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT SCHEME

1. (1) This Scheme may be called the Dock Workers (Regulation of Employmnt) Amendment Scheme, 1989.

(2) It shall come into force on the date of its final publication in the Gazette of India

2. The Dock Workers (Regulation of Employment.Schemes specified in column (2) of the Schedule annexed hereto shall be amended, or as the case may be, further amended in the manner specified in column (3) thereof.

SCHEDULE

S. No.	Short title	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	The Bombay Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956.	For clause 32, the following clause shall be substituted namely : "32. Attendance allowance : Subject to the other provisions of the Scheme a worker on the reserve pool register who is available for work but for whom no work is found shall be paid as attendance allowance 1/60th of the mnthly wage comprising basic pay and dearness allowances and 1/30th of monthly house rent allowance for the days on which during a calendar month he attended for work as directed by the Administrative Body and no work was found for him : Provided that no attendance allowance shall be payable for any day for which full wages, inclusive of dearness allowance, have been paid under clause 31 or for which disappointment money is paid under clause 34."

(1)	(2)	(3)
2.	The Madras Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956	For clause 32, the following clause shall be substituted, namely : "32. Attendance allowance : Subject to the other provisions of the Scheme, a worker on the reserve pool register who is available for work but for whom no work is found shall be paid as attendance allowance 1/60th of the monthly wage comprising basic pay and dearness allowances and 1/30th of monthly house rent allowance for the days on which during a calendar month he attended for work as directed by the Administrative Body and no work was found for him : Provided that no attendence allowance shall be payable for any day for which full wages, inclusive of dearness allowance, have been paid under clause 31 or for which disappointment money is paid under clause 4."
3.	The Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959.	For clause 32, the following clause shall be substituted, namely : "32. Attendance allowance : Subject to the other provisions of the Scheme, a worker on the reserve pool register who is available for work but for whom no work is found shall be paid as attendance allowance 1/60th of the monthly wage comprising basic pay and dearness allowances and 1/30th of monthly house rent allowance for the days on which during a calendar month he attended for work as directed by the Ad-ministrative Body and no work was found for him : Provided that no attendance allowance shall be payable for any day for which full wages, inclusive of dearness allowance, have been paid under clause 31 or for which disappointment money is paid under clause 34."
4.	The Visakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959.	For clause 31, the following clause shall be substituted, namely : "31. Attendance allowance : Subject to the other provisions of the Scheme, a worker on the reserve pool register who is available for work but for whom no work is found shall be paid as attendance allowance 1/60th of the monthly wage comprising basic pay and dearness allowances and 1/30th of monthly house rent allowance for the days on which during a calendar month he attended for work as directed by the Administrative Body and no work was found for him : Provided that no attendance allowance shall be payable for any day for which full wages, inclusive of dearness allowance, have been paid under clause 30 or for which disappointment money is paid under clause 34
5.	The Mormugao Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1965.	For clause 33, the following clause shall be substituted, namely "33. Attendance allowance. Subject to the other provisions of the Scheme, a worker on the reserve pool register who is available for work but for whom no work is found shall be paid as attendance allowance 1/60th of the monthly wage comprising basic pay and dearness allowances and 1/30th of monthly house rent allwoance for the days on which during calendar month he attended for work as directed by the Administrative body and no work was found for him : Provided that no attendance allowance shall be payable for any day for which full wages, inclusive of dearness allowance, have been paid under clause 32 or for which disappointment money is paid under clause 35."
6.	The Kandla Dock Workers (Regulation of Employment Scheme, 1969.	For clause 33, the following clause shall be substituted, namely : "33. Attendance allowance : Subject to the other provisions of the Scheme, a worker on the reserve pool register who is available for work but for whom no work is found shall be paid as attendance allowance 1/60th of the monthly wage comprising basic pay and dearness allowances and 1/30th of monthly house rent allowance for the days on which during a calendar month he attended for work os directed by the Ad-ministrative Body and no work was found for him :

(1)	(2)	(3)
		Provided that no attendance allowance shall be payable for any day for which full wages, inclusive of dearness allowance have been paid under clause 32 or for which disappointment money is paid under clause 35."
7.	The Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970,	For clause 35, the following clause shall be substituted, namely : "35. Attendance allowance : Subject to the other provisions of the Scheme, a worker on the reserve pool register who is available for work but for whom no work is found shall be paid as attendance allowance 1/60th of the monthly wage comprising basic pay and dearness allowance 1/30th of monthly house rent allowance for the days on which during a calendar month he attended for work as directed by the Administrative Body and no work was found for him : Provided that no attendance allowance shall be payable for any day for which full wages, inclusive of dearness allowance, have been paid under clause 34 or under sub-clause (2) of clause 36."
8.	The Madras Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1957.	For clause 13 C the following clause shall be substituted, namely "13.C. Attendance allowance : Subject to the other provisions of the Scheme, a worker on the reserve pool register who is available for work but for whom no work is found shall be paid as attendance allowance 1/60th of the monthly wage comprising basic pay and dearness allowances and 1/30th of monthly house rent allowance for the days on which during a calendar month he attended for work as directed by the Administrative Body and no work was found for him : Provided that no attendance allowance shall be payable for any day for which full wages, inclusive of dearness allowance, have been paid under clause 13B or for which disappointment money is paid under clause 13D."
9.	The Visakhapatnam Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968	For clause 28, the following clause shall be substituted, namely : "28. Attendace allowance : Subject to the other provisions of the Scheme, a worker on the reserve pool register who is available for work but for whom no work is found shall be paid as attendance allowance 1/60th of the monthly wage comprising basic pay and dearness allowances and 1/30th of monthly house rent allowance for the days on which during a calendar month he attended for work as directed by the Administrative Body and no work was found for him: Provided that no attendance allowance shall be payable for any day for which disappointment money is paid under clause 29."
10.	The Bombay Chipping and Painting Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1969	For clause 32, the following clause shall be substituted, namely:— "32. Attendance allowance : Subject to the other provisions of the Scheme, a worker on the reserve pool register who is available for work but for whom no work is found shall be paid as attendance allowance 1/60th of the monthly wage comprising of basic pay and dearness allowances and 1/30th of monthly house rent allowance for the days on which during a calendar month he attended for work as directed by the Administrative Body and no work was found for him : Provided that no attendance allowance shall be payable for any day for which full wages, inclusive of dearness allowance, have been paid under clause 31 or for which disappointment money is paid under clause 34."

1	2	3
11.	The Calcutta Chipping and Painting Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970.	For clause 34, the following clause shall be substituted, namely: "34. Attendance allowance : Subject to the other provisions of the Scheme, a worker on the reserve pool register who is available for work but for whom no work is found shall be paid as attendance allowance 1/60th of the monthly wage comprising basic pay and dearness allowances and 1/30th of monthly house rent allowance for the days on which during a calendar month he attended for work as directed by the Administrative Body and no work was found for him : Provided that no attendance allowance shall be payable for any day for which full wages, inclusive of dearness allowance have been paid under clause 33 or under sub-clause (2) of clause 35."
12.	The Calcutta Dock Clerical and Supervisory Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970.	For clause 29 the following clause shall be substituted, namely : "29. Attendance allowance : Subject to the other provisions of the Scheme, a worker on the reserve pool register who is available for work but for whom no work is found shall be paid as attendance allowance 1/60th of the monthly wage comprising basic pay and dearness allowances and 1/30th of the monthly house rent allowance for the days on which during a calendar month he attended for work as directed by the Administrative Body and no work was found for him ; Provided that no attendance allowance shall be payable for any day for which full wages, inclusive of dearness allowance, have been paid under clause 20 or for which disappointment money is paid under clause 31."
13.	The Bombay Foodgrain Handling Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1975	For clause 32, the following clause shall be substituted, namely : "32. Attendance allowance : Subject to the other provisions of the Scheme, a worker on the reserve pool register who is available for work but for whom no work is found shall be paid as attendance allowance 1/60th of the monthly wage comprising basic pay and dearness allowances and 1/30th of monthly house rent allowance for the days on which during a calendar month he attended for work as directed by the Administrative Body and no work was found for him : Provided that no attendance allowance shall be payable for any day for which full wages, inclusive of dearness allowance have been paid under clause 31 or under clause 34."
14.	The Bombay Dock Clearing and Forwarding Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1983.	For clause 31, the following clause shall be substituted, namely : "31. Attendance allowance : Subject to the other provsions of the Scheme, a worker on the reserve pool register who is available for work but for whom no work is found shall be paid as attendance allowance 1/60th of the monthly wage comprising basic pay and dearness allowances and 1/30th of monthly house rent allowance for th days on which during a calendar month he attended for work as directed by the Administrative Body and no work was found for him : Provided that no attendance allowance shall be payable for any day for which full wages, inclusive of dearness allowance have been paid under clause 30 or under clause 33."

(1)	(2)	(3)
15.	The Madras Unregistered Dock Clearing and Forwarding Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1988	For clause 29, the following clause shall be substituted, namely : "29. Attendance allowance : Subject to the other provisions of the Scheme, a worker on the reserve pool register who is availble for work but for whom no work is found shall be paid as attendance allowance 1/60th of the monthly wage comprising basic pay and dearness allowances and 1/30th of monthly house rent allowance for the days on which during a calendar month he attended for work as directed by the Administrative Body and no work was found for him : Provided that no attendance allowance shall be payable for any day for which full wages, inclusive of dearness allowance have been paid under clause 28 or for which disappointment money is paid under clause 31."
16.	The Madras Unregistered Dock General Pool Workers (Regulation of Employment Scheme, 1988.	For clause 33, the following caluse shall be substituted, namely:— "33. Attendance allowance : Subject to the other provisions of the Scheme, a worker on the reserve pool register who is available for work but for whom no work is found shall be paid as attendance allowance 1/60th of the monthly wage comprising basic pay and dearness allowances and 1/30th of monthly house rent allowance for the days on which during a calendar month he attended for work as directed by the Administrative Body and no work was found for him : Provided that no attendance allowance shall be payable for any day for which full wages, inclusive of dearness allowance, have been paid under clause 32 or for which disappointment money is paid under clause 35."

[File No. LB-13013/11/88-LIV]

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1989

का.आ. 921 :—कलकत्ता चिपिंग और पेंटिंग श्रमिक (रोजगार का विनियमन) स्कीम, 1970 को पुनः संशोधित करने के लिए केन्द्रीय सरकार, गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4, उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त धारा द्वारा यथा अपेक्षित एक स्कीम का निम्नलिखित प्रारूप उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित उक्त प्रारूप की अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से 45 दिन की अवधि समाप्त होने पर उन पर विचार किया जाएगा।

उक्त प्रारूप के संबंध में निर्दिष्ट अवधि समाप्त होने से पहले किसी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

स्कीम का प्रारूप

1. (1) इस स्कीम को कलकत्ता चिपिंग और पेंटिंग श्रमिक (रोजगार का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1989 कहा जाएगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में अंतिम रूप से प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. कलकत्ता चिपिंग और पेंटिंग श्रमिक (रोजगार का विनियमन) स्कीम 1970 के अनुच्छेद 7 के उप-अनुच्छेद (1) में मद (ड) के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"(ढ) डाक लेबर बोर्ड के वित्तीय संसाधनों के संवर्धन की दृष्टि से चिपिंग और पेंटिंग कार्य और उससे जुड़े या प्रासंगिक अन्य कोई कार्य जैसे वाणिज्यिक कार्यकलाप शुरू करना।"

[फाइल सं. एल बी-13013/15/88-एल-IV (i)]

New Delhi, the 3rd April, 1989

S.O. 921.—The following draft of a Scheme, further to amend the Calcutta Chipping and Painting Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of 45 days from the date on which cops of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be taken into consideration by the Central Government;

DRAFT SCHEME

1. (1) This Scheme may be called the Calcutta Chipping and Painting Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1989.

(2) It shall come into force on the date of its final publication in the Official Gazette.

2. In the Calcutta Chipping and Painting Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970, under sub-clause (1) of clause 7, the following may be added as item (n) :—

"(n) undertaking commercial activities like contract for chipping and painting work and any other work connected therewith or incidental thereto with the view to augment the financial resources of Dock Labour Board".

[F. No. LB-13013/15/88-L.IV(i)]

का.भा. 922 :—कलकत्ता गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) स्कीम, 1970 को पुन: संशोधित करने के लिए केन्द्रीय सरकार, गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4, उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त उप-धारा द्वारा यथा अपेक्षित एक स्कीम का निम्नलिखित प्रारूप उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है, और एतद्द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित उक्त प्रारूप की अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से 45 दिन की अवधि समाप्त होने पर उन पर विचार किया जाएगा।

उक्त प्रारूप के संबंध में निर्दिष्ट अवधि समाप्त होने से पहले किसी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

स्कीम का प्रारूप

1. (1) इस स्कीम को कलकत्ता गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) संशोधन स्कीम 1989 कहा जाएगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में अंतिम रूप से प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. कलकत्ता गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) स्कीम, 1970 के अनुच्छेद 7 के उप-अनुच्छेद (1) में मद (ड) के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी अर्थात्:—

"(ढ) डाक लेबर बोर्ड के वित्तीय संसाधनों में संवर्धन की दृष्टि से स्टेविडोरिंग और उससे जुड़े या प्रासंगिक कोई अन्य कार्य जैसे वाणिज्यिक कार्यकलाप शुरू करना।

[फाइल सं. एल बी-13013/15/88-एल-IV (ii)]

SO. 922.—The following draft of a Scheme further to amend the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is published as requited by the said sub-section, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of 45 days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT SCHFME

1. (1) This Scheme may be called the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1989.

(2) It shall come into force on the date of its final publication in the Official Gazette.

2. In the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970, in sub-clause (1) of clause 7, after item (m), the following item shall be inserted, namely :—

"(n) undertaking commercial activities like stevedoring and any other work connected therewith or incidental thereto with the view o caugment the financlia resources of Dock Labour Board".

[F. No. LB-13013/15/88-L.IV(ii)]

का.आ. 923 :—कलकत्ता गोदी लिपिकीय और पर्यवेक्षी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) स्कीम, 1970 को पुन: संशोधित करने के लिए केन्द्रीय सरकार, गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4, उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त धारा द्वारा यथा अपेक्षित एक स्कीम का निम्नलिखित प्रारूप उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित उक्त प्रारूप की अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से 45 दिन की अवधि समाप्त होने पर उन पर विचार किया जाएगा।

उक्त प्रारूप के संबंध में निर्दिष्ट अवधि समाप्त होने से पहले किसी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

स्कीम का प्रारूप

1. (1) इस स्कीम को कलकत्ता गोदी लिपिकीय और पर्यवेक्षी-श्रमिक (रोजगार का विनियमन) संशोधन स्कीम 1989 कहा जाएगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में अंतिम रूप से प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. कलकत्ता गोदी लिपिकीय और पर्यवेक्षी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) स्कीम, 1970 के अनुच्छेद 6 के उप-अनुछेद (1) में मद (ड) के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"(ढ) डाक लेबर बोर्ड के वित्तीय संसाधनों के संवर्धन की दृष्टि से स्टेविडोरिंग और उससे जुड़े या प्रासंगिक कोई अन्य कार्य जैसे वाणिज्यिक कार्यकलाप शुरू करना।"

[फाइल सं. एल बी-13013/15/88-एल-IV (iii)]

बी. शंकरलिंगम, निदेशक

S.O. 923.—The following draft of a Scheme further to amend the Calcutta Dock Clerical and Supervisory Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is pub-as required by the said sub-section for the informaton of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of 45 days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT SCHEME

1. (1) This Scheme may be called the Calcutta Dock Clerical and Supervisory Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1989.

(2) It shall come into force on the date of its final publication in the Official Gazette.

2. In the Calcutta Dock Clerical and Supervisory Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970, under sub-clause (1) of clause 6, the following may be added as item (n) :

"(n) undertaking commercial activities like stevedoring and any other work connected therewith or incidental thereto with the view to augment the financial resources of Dock Labour Board".

[F. No. LB-13013|15|88-L.IV(iii)]
V. SANKARALINGAM, Diretor

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 7th April, 1989

S.O. 924.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendments to the notification of the Government of India, Ministry of Railways, number S.O. 5406 dated the 8th November 1985, namely :

In the Table to the said notification, for serial No. 2 and the entries against it in columns (1) and (2), the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)
"2. Deputy General Manager (Works), Metro Railway, Calcutta.	Premises under the control of Metro Railway situated within the limits of metropolitan city of Calcutta as defined in the Metro Railway (Construction of Works), Act, 1978 (33 of 1978).

[File No. 82/W2/14/4]

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1989

का.आ. 924.—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार, रेल मंत्रालय की दिनांक 8 नवम्बर, 1985 की अधिसूचना का.आ. 5406 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की तालिका में, क्रम सं. 2 और उसके सामने कालम (1) और (2) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

(1)	(2)
"2. उप महाप्रबंधक, (निर्माण, मेट्रो रेलवे,, कलकत्ता)।	भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) में परिभाषित किये गये अनुसार महानगर कलकत्ता की सीमाओं के अन्तर्गत स्थित मेट्रो रेलवे के नियंत्रण के अधीन परिसर"

[फाइल सं. 82/डब्ल्यू/2/14/4]

का.आ. 925:—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली)—अधिनियम, 1971 (1973 का 40)) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार, रेल मंत्रालय की दिनांक 23 जुलाई, 1983 की अधिसूचना का.आ. सं. 3080 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की तालिका में, क्रम सं. 14 तथा उसके सामने कालम (1) और (2) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)
"14. वरिष्ठ सिविल इंजीनियर, डीजल पुर्जा कारखाना, पटियाला।	डीजल पुर्जा कारखाना के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन परिसर'।

[फाइल सं. 82/डब्ल्यू 2/14/4]

S.O. 925.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendments to the notifi-

cation of the Government of India, Ministry of Railways, number S.O. 3080 dated 23rd July 1983, namely :—

In the Table to the said notification, for serial No. 14 and the entries against it in columns (1) and (2), the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)
"14. Senior Civil Engineer, Diesel Component Works, Patiala.	Premises under the administrative control of Diesel Component Works".

[File No. 82/W2/14/4]

का.आ. 926:—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम, 1971 (1971 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्न-तालिका के कालम (1) में उल्लिखित अधिकारियों को सरकारी राजपत्रित अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ संपदा अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है, ये अधिकारी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उक्त तालिका के कालम (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि विनिर्दिष्ट सरकारी परिसरों के सम्बन्ध में अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन संपदा अधिकारियों को सौंपी गयी ड्यूटियों का निष्पादन करेंगे।

तालिका

अधिकारियों का पदनाम	क्षेत्राधिकार के सरकारी परिसर और स्थानीय सीमाओं की कोटियां
1	2
1. मुख्य इंजीनियर और उप महा-प्रबंधक (सामान्य) रेल सवारी डिब्बा कारखाना, कपूरथला।	रेल सवारी डिब्बा कारखाना कपूरथला के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन परिसर।
2. (1) मण्डल अधीक्षक इंजीनियर (भूमि) दिल्ली मंडल, उत्तर रेलवे।	दिल्ली मंडल उत्तर रेलवे के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन परिसर।
(2) उप मुख्य इंजीनियर (भूमि) और उप मुख्य इंजीनियर (कारखाना) उत्तर रेलवे।	उत्तर रेलवे के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन परिसर।

[फाइल नं. 82/डब्ल्यू 2/14/1]

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से,

स. भ. वैश सचिव, रेलवे बोर्ड,

S.O. 926.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in Column (1) of the Table below, being Gazetted Officers of the Government, to be estate officers for the purpose of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on he Estate Officers by or under the said Act within the local limits of their jurisdiction in respect of the Public Premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the Officers	Categories of Public Premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
1. Chief Engineer and Deputy General Manager (General) of Rail Coach Factory, Kapurthala.	Premises under the administrative control of the Rail Coach Factory, Kapurthala.
2. (i) Divisional Superintending Engineer (Land), Delhi Division Northern Railway.	Premises under the administrative control of Delhi Division, Northern Railway.
(ii) Deputy Chief Engineer, (Land) and Deputy Chief Engineer (Works) Northern Railway.	Premises under the administrative control of the Northern Railway.

[File No. 82/W2/14/4]

for and on behalf of President of India
S.M. VAISH, Secy, Railway Board

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1989

का.आ. 927:--बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 62) की धारा 10 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान उन कार्यकलापों जिनके लिए उक्त अधिनियम के अधीन वित्त व्यवस्था की गई है, के बारे में निम्नलिखित रिपोर्ट प्रकाशित करती है।

सामान्य

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि को बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 और बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के अधीन बीड़ी प्रतिष्ठानों में सीधे या किसी एजेंसी के माध्यम से नियुक्त व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ाने के लिए उपायों की वित्त व्यवस्था के लिए गठित किया गया है।

बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 के अधीन बनाए गए नियम 15 फरवरी, 1977 से लागू हुए और बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के अधीन बनाए गए नियम 7 अक्तूबर, 1978 से लागू हुए।

बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 (1976 का 55) की धारा 7 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने बीड़ी बनाने से संबंधित किसी उद्देश्य के लिए गोदाम में से किसी व्यक्ति को दिए गए तम्बाकू के प्रति किलोग्राम पर 25 पैसे की दर को उस दर के रूप में निर्धारित किया है जिस उत्पाद शुल्क लगाया जाना था और उपकर के रूप में एकत्र किया जाना था।

वित्त अधिनियम, 1976 के अधीन तम्बाकू को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई थी और गोदामों को लाइसेंस देना समाप्त कर दिया था बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 के अधीन एकत्र किया जा रहा उपकर भी पहली मार्च, 1979 से रोक दिया गया था। इस निधि के अधीन कार्यकलापों की वित्त व्यवस्था के लिए बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) अधिनियम 1981 बनाया गया था और पहली जनवरी, 1982 से प्रतिहजार उत्पादित बीड़ियों पर 10 पैसे की दर से उपकर लगाया गया था। इस उपकर को पहली मार्च, 1987 से प्रति हजार तैयार की गई बीड़ियों पर 10 पैसे से बढ़ाकर 30 पैसे कर दिया गया है।

प्रशासनिक सुविधा के लिए देश में राज्यों के 9 क्षेत्रों में ग्रुप बना दिए गए हैं और विभिन्न कल्याण योजनाओं को लागू करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र एक कल्याण आयुक्त के अधीन है। कल्याण आयुक्तों को क्षेत्राधिकार निम्नानुसार हैं:--

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम
1	2	3
1.	कल्याण आयुक्त, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, भुवनेश्वर	उड़ीसा
2.	कल्याण आयुक्त, भारत सरकार श्रम मंत्रालय, कलकत्ता।	पश्चिमी बंगाल, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम।
3.	कल्याण आयुक्त, भारत सरकार श्रम मंत्रालय, इलाहाबाद।	उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू व कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़।
4.	कल्याण आयुक्त भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, भीलवाड़ा।	राजस्थान, हरियाणा और गुजरात।
5.	कल्याण आयुक्त, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, जबलपुर।	मध्य प्रदेश।
6.	कल्याण आयुक्त भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, हैदराबाद।	तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह।
7.	कल्याण आयुक्त, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, बंगलौर।	कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप।
8.	कल्याण आयुक्त, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नागपुर।	महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, दादर नागर हवेली।
9.	कल्याण आयुक्त, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, करमा।	बिहार।

चिकित्सीय देख-देख

चिकित्सीय देखरेख देने के लिए आधारभूत ढांचा बनाने को सबसे अधिक वरीयता दी गई है। श्रम कल्याण संगठन द्वारा बीड़ी कर्मकारों और उनके आश्रितों के लिए विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध की जा रही हैं। इनमें अस्पतालों, औषधालयों, में चिकित्सा सुविधाएं और टी.बी. के इलाज की सुविधाएं आदि शामिल हैं।

वर्तमान चिकित्सा संस्थानों के अतिरिक्त, ओल्ड वशरमेनपेट (मद्रास) स्थित एक स्थिर औषधालय को स्थिर एवं चल औषधालय में परिवर्तित कर दिए गये हैं। वर्ष के दौरान 129 औषधालय, मैसूर में दस बिस्तरों वाला एक अस्पताल और निमितिता में एक चैस्ट क्लिनिक कार्य कर रहे थे। औषधालयों में कुल उपस्थिति 19,93,041 थी जबकि अस्पताल में ओ.पी.डी. उपस्थिति 51,168 थी। अस्पताल में 106 रोगियों का अंतरंग रोगी के रूप में उपचार किया गया था। कल्याण आयुक्त टी.बी. से ग्रस्त बीड़ी कर्मकारों की चिकित्सा की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान टी.बी. से ग्रस्त कर्मकारों की चिकित्सा के लिए 74 पलंग आरक्षित किए गए। आहार प्रभार के रूप में 50,323 रु. की कुल राशि का भुगतान किया गया था जबकि 11,161/- रु. उपचार कराने वाले 175 टी.बी. रोगियों के आश्रितों को जीवन निर्वाह भत्ते के रूप में वितरित किए गए।

कुष्ठ रोग से पीड़ित दो रोगियों को बीड़ी कर्मकारों के लिए "कुष्ट राहत" योजना के अधीन 962 रु. जीवन निर्वाह भत्ते के रूप में दिए गए।

चश्मों की खरीद के लिए 284 कर्मकारों को 13,077 रु. की वित्तीय सहायता दी गई।

टी.बी. रोगियों के लिए घर "पर चिकित्सा" योजना के अधीन 296 कर्मकारों के "आश्रितों" को 49,699 रु. जीवन निर्वाह भत्ते के रूप में दिए गए।

शिक्षा

89,81,029 रुपये की राशि बीड़ी कर्मकारों के 28,160 बालकों को छात्रवृत्ति के रूप में वितरित की गई थी। 2,91,500 रुपये की राशि बीड़ी कर्मकारों के 5,830 बालकों को उनकी स्कूल की वर्दी के लिए वितरित की गई थी।

आवास

इस समय बीड़ी कर्मकारों को आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित योजनाएं चल रही हैं :--

(1) बीड़ी कर्मकारों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास योजना।

(2) अपना मकान स्वयं बनाओ योजना।

(3) वर्कशेडों/गोदामों का निर्माण।

(1) बीड़ी कर्मकारों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को 5,000 रु. प्रति मकान की दर से आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त विकास की वास्तविक लागत का 50% की दर से विकास व्यय भी देय है बशर्ते कि यह साधारण और काटन/उभरी हुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में क्रमशः 800 रु. और 1,000 रु. अधिकतम हो। इसके बदले राज्य सरकारें मकानों का निर्माण करती हैं और बीड़ी कर्मकारों को आवंटित करती हैं इस वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत बीड़ी कर्मचारों के लिए 180 मकानों के निर्माण हेतु प्रशासनिक मंजूरी जारी की गई थी। शोलापुर में निर्मित 960 मकानों के लिए 48.00 लाख रुपये की राशि दी गई है।

(2) अपना मकान स्वयं बनाओ योजना के अन्तर्गत पात्र कर्मकारों को आर्थिक सहायता के रूप में 1,000 रु. की दर से वित्तीय सहायता के अतिरिक्त 6,000 रु. का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है जो 9 वर्ष की अवधि में मासिक किश्तों में लौटाना होता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 102 मकानों की मंजूरी दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत 4,05,390 रु. की राशि वितरित की गई है जिसमें 5 मकानों की मरम्मत के लिए 2,400 रु. की राशि शामिल है।

(3) गोदामों और वर्कशेडों के निर्माण के लिए बीड़ी कर्मकार सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक योजना भी लागू की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत समितियों को प्रत्येक के निर्माण की वास्तविक लागत के 75 प्रतिशत तक या 75,000 रु. इनमें से जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्कशेड/गोदामों के निर्माण के लिए कल्याण आयुक्त द्वारा मैसर्स चाला बीड़ा वर्कर्स इंडस्ट्रीयल कोआपरेटिव सोसाइटी लि., वलकोट्टन, केरल के नाम प्रशासनिक मंजूरी जारी कर दी गई है।

मनोरंजन

बीड़ी कर्मकारों के मनोरंजन के लिए निम्नलिखित व्यय किए गए :--

(1) रंगीन टी.वी. सेट की खरीद के लिए मै. मद्रासी चक्कर बीड़ी फैक्टरी वारंगल को 10,000 रु. की राशि मंजूर की गई।

(2) औषधालयों को राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए 1,250 रु. की राशि मंजूर की गई।

(3) राजस्थान और गुजरात के बीड़ी कर्मकारों के लिए 19 तथा 20 मार्च, 88 को सवाई माधोपुर में 17,000 रु० की लागत से एक खेलकूद टूर्नामेंट आयोजित किया गया।

(4) राजस्थान और गुजरात राज्यों में बीड़ी कर्मकारों के लिए सिनेमा शो दिखाने के लिए 6,450 रु. का व्यय किया गया।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, बीड़ी कर्मकारों के मनोरंजन के लिए 57,000 रु. की कुल राशि व्यय की गई।

भाग-2

वर्ष 1987-88 के लिए लेखा विवरण :--

1. पहली अप्रैल, 1987 को अवशेष	8,54,95,584
2. वर्ष के दौरान प्राप्तियां	11,02,04,804
3. 1987-88 के दौरान व्यय	4,19,46,154
4. 31 मार्च, 1988 को अन्तशेष	15,37,54,234

भाग-3

वर्ष 1988-89 के लिए अनुमानित आय और व्यय :

1. अनुमानित व्यय	1,00,00,000
2. अनुमानित आय	10,60,00,000

[संख्या जेड-16016/3/88-डब्ल्यू-II]
शशि भूषण, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 7th February, 1989

S.O. 927.—In pursuance of Section 10 of the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 (62 of 1976), the Central Government hereby publishes the following report on the activities financed under the said Act, during the year ending March, 1988.

General :—

The Beedi Workers Welfare Fund has been contituted under the Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976, and the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976, for financing of the measures to promote the Welfare of persons engaged in beedi establishments directly or through any agency.

The Rules framed under the Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976, came into force with effect from 15th February, 1977, and the Rules under the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 from 7th October, 1978.

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 7 of the Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976 (55 of 1976) the Central Government had fixed the rate of 25 paise per kilogram of tobacco issued from a warehouse for any purpose in connection with the manufacture of beedis as the rate at which the duty of excise was to be levied and collected by way of cess.

Under the Finance Act, 1976, tobacco was exempted from the levy of excise duty and licensing of warehouses was discontinued. The cess which was being collected under the Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976, was also stopped with effect from 1st March, 1979. For financing of the activities under the Fund, the Beedi Workers Welfare Cess (Amendment) Act, 1981, was enacted and the cess was levied at the rate of 10 paise per thousand manufactured beedis with effect from 1st January, 1982. The rate of cess has been enhanced from 10 paise to 30 paise per thousand manufactured beedis with effect from 1st March, 1987.

For administrative convenience, the States in the country, have been grouped into 9 regions and each region is under the charge of a Welfare Commissioner for implementing the various welfare schemes. The jurisdiction of the Welfare Commissioners is as under :—

S. No.	Name of the Region	Name of the States/Union territories.
1.	Welfare Commissioner Government of India, Ministry of Labour, Bhubaneswer.	Orissa

1	2	3
2.	The Welfare Commissioner Government of India Ministry of Labour Calcutta.	West Bengal Assam, Manipur, Tripura, Nagaland Aruchachal Pradesh, Megahalya, Mizoram and Sikkim
3.	The Welfare Commissioner, Govt. of India Ministry of Labour Allahabad.	Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Punjab, Jammu & Kashmir, Delhi and Chandigarh.
4.	The Welfare Commissioner, Government of India Ministry of Labour Bhilwara.	Rajasthan, Haryana and Gujarat.
5.	The Welfare Commissioner, Govt. of India, Ministry of Labour, Jabalpur.	Madhya Pradesh
6.	The Welfare Commissioner Govt. of India Ministry of Labour Hyderabad.	Tamilnadu, Andhra Pradesh, Pondicherry and Andaman and Nicobar Islands.
7.	The Welfare Commissioner Govt. of India Ministry of Labour Bangalore.	Karnatka, Kerala and Lakshadweep.
8.	The Welfare Commissioner Govt. of India Ministry of Labour Nagpur	Maharashtra, Goa, Daman and Diu Dadra & Nagar Haveli
9.	The Welfare Commissioner Govt. of India, Ministry of Labour, Karma.	Bihar.

Medical Care :

The Organisation of infrastructure for rendering medical care has been given top priority. Various types of medical facilities for beedi workers and their dependents are being provided free of cost by the Labour Welfare Organisation. These include medical facilities at hospitals, dispensaries and facilities for treatment of T. B. etc.

In addition to the existing medical institutions one Static Dispensary at Old Washermanpet (Madras) has been converted into Static-cum-Mobile Dispensary. During the year 129 dispensaries, one ten-bedded hospital at Mysore and one obest clinic at Nimitita were functioning. The total attendance an dispensaries was 1993041 whereas OPD attendance in the hospital was 51,168. The Welfare Commissioners have been endeavouring to provide adequate facilities for treatment of beedi workers suffering from T.B.-74 beds were reserved for providing the treatment to T.B. patients during the financial year. The total amount paid as diet charges was Rs. 50323 while Rs. 11,161 has been disbursed as assistance allowance to dependants of the 175 T.B. patients treated. 106 patients were treated in the Hospital as in-door patients.

Two patients suffering from leprosy were given Rs. 962 as subsistance allowance under the Scheme "Leprosy Relief for Beedi Workers".

284 workers were given financial assistance of Rs. 13,077 for the purchase of spectacles.

Dependants of 296 workers were given subsistance allowance of Rs. 49,699 under the Scheme "Domicillary Treatment of T.B. Patients".

Education :

A sum of Rs. 89,81,029 was disbursed as scholarships to 28,160 children of the beedi worker. A sum of Rs. 2,91,500 was distributed to 5830 children of the beedi workers for their school dress.

Housing :

At present, the following schemes are in vogue to provide housing facilities to beedi workers :

(i) Housing Scheme for Economically Weaker Section of Beedi Workers,

(ii) Build Your own House Scheme; and

(iii) Construction of Workshed|godowns.

(i) Under the Housing Scheme for Economically Weaker Section of beedi workers, State Governments are being given subsidy at the rate of Rs. 5000 per house. In addition to this development charges @ 50 per cent of actual cost of development subject to a maximum or Rs. 800 and Rs. 1000 per house for ordinary and lack cotton|swelly soil areas, respectively, is also payable. In turn the State Governments construct and allot houses to the beedi workers. During the year administrative approval for the construction of 180 houses for beedi workers under this scheme was issued. The sponsoring authority for these houses is Labour Department, Government of Andhra Pradesh. A sum of Rs. 48 lakhs has released for 960 houses constructed at Sholapur.

(ii) Under the Build Your Own House Scheme financial assistance is given to an eligible worker at the rate of Rs. 1000 as subsidy besides interest free loan of Rs. 6000 refundable in monthly instalments spread over a period of 9 years. 102 houses have been sanctioned during the period under report. A sum of Rs. 4,05,390 has been disbursed under the Scheme which also includes a sum of Rs. 2,400 for the repairs of the 5 houses.

(iii) A Scheme for grant of financial assistance to beedi workers co-operative societies for construction of godowns and worksheds is also being implemented. Under this Scheme, the Societies are given financial assistance upto 75 per cent of actual cost of construction or Rs. 75,000 for each whichever is less. Under the Scheme administrative approval for the construction of workshed|godown has been issued by the Welfare Commissioner in the name of M|s. Chala Beedi Workers Industrial Co-operative Society Limited, Chalkottan, Kerala.

Recreation :

For the recreation of the beedi workers following expenditure was incurred :

(i) A sum of Rs. 10,000 has been sanctioned to M|s. Madrasi Chakkar Beedi Factory Warangal for purchase of colour TV Set.

(ii) A sum of Rs. 1,250 was sanctioned to dispensaries for celebrating National Day.

(iii) Sports set for beedi workers of Rajasthan and Gujarat was organised at Sawaimadhopur on 19th and 20th March, 1988 at a cost of Rs. 17,000.

(iv) An expenditure of Rs. 6,450 was incurred for exhibition of Cinema shows for the beedi workers in the States of Rajasthan and Gujarat.

A total sum of Rs. 57,000 was spent for the recreation of the beedi workers during the period under report.

PART-II

Statement of Accounts for the year 1987-88

1.	Opening balance as on 1st April, 1987	Rs.	854,95,584
2.	Receipt during the year	Rs.	11,02,04,804
3.	Expenditure during the 1987-88	Rs.	4,19,46,154
4	Closing balance as on 31-3-1988	Rs.	15,37,54,234

PART-III

Estimated Receipts and Expenditure for the year 1988-89 :

1. Estimated Expenditure	Rs.	700,00,000
2. Estimated Receipt	Rs.	10,50,00,000

[No. Z—16016/3/88-W.II]

SHASHI BHUSHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1989

का.आ. 928:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक आफ पटियाला के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चण्डीगढ़, के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 6th March, 1989

S.O. 928.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Chandigarh as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of Patiala and their workmen, which was received by the Central Government.

ANNEXURE

BEFORE SHRI M. S. NAGRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. 98|85.

PARTIES :

Employers in relation to the management of State Bank of Patiala.

AND

Their workman.—G. D. Grover.

APPEARANCES :

For the workman.—None.

For the management—Shri P. S. Arora.

AWARD

Dated 9-2-1989.

O a dispute raised by workman Shri G. D. Grover, Central Govt. was pleaded to make the following reference vide No L-12011(10)|85-D.II(A) dated 17th December 1985 to this Tribunal :

"Whether the action of the State Bank of Patiala in imposing the penalty of stoppage of two increments on Shri G. D. Grover, clerk-cum-typist in their Rajpura Branch is justified ? If not, to what relief is he entitled to ?"

After the parties had led evidence, the matter was fixed for today for arguments. None is present on behalf of the petitioner. On the last date petitioner was represented by his authorised representative Shri T. C. Sharma when the case was adjourned from 10-1-1989 to 9-2-1989. In view of the absence of the claimant, the reference is dismissed for want of prosecution. Central Govt. may be informed accordingly.

Dt. 9-2-1989.

M. S. NAGRA, Presiding Officer

[No. L-12011|10|85-D.II(A)|D.III(A)]

P. V. SREEDHARAN, Desk Officer

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1989

का.आ. 929:—केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि इंडिया गवर्नमेंट मिंट, बम्बई को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाए :

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (VI) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस-11017/3/85-डी I-ए]

New Delhi, the 10th March, 1989

S.O. 929.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the India Government Mint, Bombay which is specified in the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[No. S-11017|3|85-D.I(A)]

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1989

का.आ. 930:—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (VI) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3208 दिनांक 10 अक्तूबर, 1988 द्वारा यूरेनियम उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 20 अक्तूबर, 1988 से छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छह मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (VI) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 20 अप्रैल, 1989 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/10/85-डी-I(ए)]

New Delhi, the 31st March, 1989

S.O. 930.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in

pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour S.O. No. 3208 dated the 10th October, 1988 the Uranium Industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months, from the 20th October, 1988;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a futrher period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 20th April, 1989.

[No. S-11017/10/85-D. I. (A)]

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1989

का.आ. 931 :--केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अधीन स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा चलाए जा रहे बैंकिंग उद्योग को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की मद 2 के अन्तर्गत आता है उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए।

अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए छः मास की कालावधि के लिए तत्काल प्रभाव से लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस-11017/2/85-डी-I(ए)]

New Delhi, the 3rd April, 1989

S.O. 931.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the Banking Industry as carried on by a regional rural bank established under Section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976, which is covered by item 2 of the Firs Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act for a period of six months.

[No. S-11017|2|85-D.I(A)]

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1989

का.आ. 932 :—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (VI) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3055 दिनांक 26 सितम्बर 1988 द्वारा मैग्नेसाइट खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 11 अक्तूबर, 1988 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था,

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (VI) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 11 अप्रैल, 1989 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/8/85-डी-I(ए)]

New Delhi, the 6th April, 1989

S.O. 932.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O No. 3055 dated the 26th September, 1988 the Magnesite Mining Industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months, from the 11th October, 1988;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 11th April, 1989.

[No. S-11017/8/85-D.I. (A)]

का.आ. 933 :—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि जनहित में यह आवश्यक है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्योग, भारत सरकार टकसाल, कलकत्ता को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ लोकोपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए।

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) की उपधारा (VI) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ छः माह की अवधि के लिए तत्काल लोकोपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस-11017/6/85-डी-I(ए)]
नन्द लाल, अवर सचिव

S.O. 933.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the industry, India Government Mint, Calcutta, specified in the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[No. S-11017|6|85-D.I(A)]

NAND LAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1989

का.आ. 934—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि. की बदजना कोलियरी के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (सं. 2) धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है।

New Delhi, the 10th March, 1989

S.O. 934.—In pursuance of section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Messrs. Bharat coking Coal Ltd Badjna Colliery and their workmen.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 36 of 1985

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Badina colliery of Mesrs. Eastern Coalfields Limited and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen—Shri S. Bose, Secretary. R.C.M.S. Union.

On behalf of the employers.—Shri R. S. Murthy, Advocate

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal

Dated, Dhanbad, the 8th February, 1989

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012(386)/84-D.III(A), dated, the 9th April, 1985.

SCHEDULE

"Whether the demand of Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh that S/Shri Gour Singh and Ashok Roy, Workman of Badina Colliery of Eastern Coalfields Limited, P.O. Nirshachatti, Distt. Dhanbad should be allowed to resume duty with full back wages and other benefits with retrospective effect from 17-6-83 is iustified ? If so, to what relief these workmen are entiled?"

In this case both the parties appeared and filed their respective W.S. documents etc. Thereafter the case proceeded along with its course. But subsequently at the stages of evidence both the parties appear before me and filed a Joint compromise petition. I heard them on the same petition of compromise and I do find that the terms contained therein are fair, proper and beneficial to both the parties. Accordingly I accept the said Joint compromise petition and pass an Award accordingly in terms of the said Joint compromise petiion which forms part of the Award as Annexure.

I. N. SINHA, Presiding Officer
[No. L-20012/386/84-D.III(A)/IR(Coal)-I]

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2 DHANBAD

In the matter of Reference No. 36 of 1985

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Badjna Colliery of Eastern Coalfields Ltd. P.O. Nirsha Chatti, District Dhanbad.

Their Workmen

Joint Compromise Petition of Employers and Sponsoring Union.

The abovementioned employers and workmen most respectfully beg to submit jointly as follows:—

(1) That the employers and the sponsoring union through their representatives have jointly negotiated the matter covered by the aforesaid reference with a view to arriving at an amicable and mutually acceptable overall settlement.

(2) That it was noted and agreed to by both the parties that the problems and difficulty in the present case is the identification of the genuine persons numbering two whose names appear in the Schedule to the reference order and to prevent that no impersonator secures employment under the Management with the name and in the place of any genuine persons Covered by the reference it was further noted that the Management has referred the matter relating to identification of the genuine persons entiled to employment under the Management as per the reference order to the Deputy Commissioner, Dhanbad for vertification, which has not been completed and is taking time.

(3) That in view of the position as elaborated in para 2 above, and in order to ensure that the present case before this Hon'ble Tribunal is not kept pending indefinitely, the employers and the sponsoring union hereby agree that the persons who will be ultimately verified and certified by the Dy. Commissioner, Dhanbad as the genuine persons entitled to employment with attestation of their photographs, will be provided employment as underground Loaders or wagon loaders of soft coke manufacturers or truck Loaders, with the status of Badli workers, according to the Management's requirements from time to time. It is further agreed between the two parties that such employment will be provided to the persons concerned within one month of the receipt of the necessary documents and certificates from the Dy. Commissioner, Dhanbad.

(4) That it is agreed that till the date the persons concerned are provided employment as Badli workers, as laid down in para 3 above they will not be entiled to any wages or other benefits.

(5) That it is agreed that this is an overall agreement in full and final settlement of all the claims of the sponsoring union arising out of the above reference.

(6) That both the parties consider the above agreement as fair, just and reasonable to both the parties.

In view of the above, both the parties Jointly pray that the Hon'ble Tribunal may be pleased to accept this Joint

compromise petition and give an award accordingly and dispose of the above reference.

(S. BOSE)
SECRETARY
Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh
For and on behalf of the workmen

S. P. SINGH, Dy. Chief Personnel
Manager, Nirsha Area Eastern Coalfield, Ltd.
Dt : 16th April, 1988.

का.आ. 935:--औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मेसर्स भारत कोकिंग कोल लि., का पाथरडीह कोलियरी के प्रबन्धतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (सं. 2) धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है।

S.O. 935.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Givernment hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad as shows in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Messrs Bharat Coking Coal Limited, Patherdih Colliery and their workmen.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 206 of 1986

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Patherdih Colliery of Sudamdih Area of M|s. Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

APPEARANCES

On behalf of the workmen—Shri B. Lal, Advocate and Shri D. K. Verma. Advocate.

On behalf of the employers—Shri R. S. Murthy. Advocate.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 8th February, 1989

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. 20012/259/85-D.III (A), dated, the 6th June, 1986.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Patherdih Colliery of Sudamdih Area of M|s. Bharat Coking Coal Limited in denying protection of group wages to their workmen, mentioned below, on their diversion from piece-rate to time-rate, is justified ? If not, to what relief are these workmen entitled ?"

1. Sufal Roy
2. E. M. Bahadur
3. Nar Bahadur
4. Kar Bahadur
5. Narayan Bawri
6. Bir Bahadur
7. Jagdish Bhuia
8. Abhiram Manjhi
9. Ashu Rewani
10. Nagen Mahto
11. Sirtali Mian
12. Ramjan Nain
13. Aklu Bowri
14. Rabilochan Roy
15. Rathu Bagtee
16. Nagan Mudi
17. Ram Dulal Pasi
18. Bilu Bagtee
19. Bhakti Pada Gope
20. Mathur Rajwar
21. Bhawani Rewani
22. Dukhu Bouri
23. Bishu Sahish
24. Manik Rewani
25. Mansa Bouri
26. Satish Singh
27. Anil Sahish
28. Gangadhar Manjhi
29. Bhairo Bhuya
30. Bhim Manjt
31. Deoraj Pradhan
32. Lakhi Chand Goral
33. Babulal Hajam
34. Fulchand Bauri
35. Mohan Rajak.

The case of the workmen is that the 35 concerned workmen were originally working piece-rated worker as Miner/Loader in Group VA in June, 1982 in Patherdih Colliery of Sudamdih Area of M/s. BCCL. They were transferred from piece rated to different time rated jobs and are being paid time rated wages which were much below their group wages of VA which they were enjoying before their placement in the time rated job. The concerned workmen complained payment of less wages to them by the management in the time rated scale and requested to protect their wages of Group VA so that they may nit get less than the wages of Group VA. When the management did not protect their wages of Group VA, an industrial dispute was raised on their behalf by the union, namely, Colliery Karamchari Sangh. The wages of the concerned workmen is protected wherever they required to work under the various provisions of the labour laws. The management had placed them unilaterally without any option on their consent in time rated at the lower category and started paying less than the wages of group VA to which they were entitled. The management also did not give any notice under Section 9-A of the I.D. Act to bring any change in the condition of their service and their change by reduction of their wages. The JBCCI held on 12th and 13th April, 1984 at Coal India Ltd. Headquarters, Calcutta in the standardisation committee of JBCCI decided about the fixation benefits to piece-rated workers who are doing time rated jobs. The union representative had pointed out in the standardisation committee that many piece rated workers who are working in the time rated jobs have not been given fitment benefits as per NCWA-III. It was agreed that in all such cases the management will ensure minimum guaranteed benefit as per clause 2.8 and 2.9 of NCWA-III in case it has not already been done with effect from 1-1-83. Inspite of the said legal position and the unanimous decision of the management and the union in the meeting of the standardisation committee and JBCCI the management failed to protect the Group VI wages to the concerned workmen. On the above it is submitted that the action of the management of Patherdih Colliery in denying protection of Group wages to the concerned workmen is not justified and that the concerned workmen are entitled to the arrears of wages of Group VA from the date they have been placed to work in the time rated scale.

The case of the management is that the piece rated workers are paid wages on the basis of "System of payment by result". According to the "system of payment of wages by result" piece rated workers are paid their wages at the given rate per unit of production|out put|work done for the actual quantum of work performed on different working days. Their working hours are also 8 hours per day. There is however a minimum guaranteed wages|fall back wages fixed for different categories of piece rated work and they are entitled to such minimum guaranteed wage|fall back wages only in the even of management's failure to provide them to work to the extent of the norms or quantum of work fixed per day. Otherwise if a piece rated workman himself fails to perform the work to the extent of the norm fixed per day due to his own fault he is not entitled to the minimum guaranteed wages. The details regarding the nature of work to be done by different categories of piece rated workers, their job description the rates of wages, work norms etc have all been laid down in NCWA. The nature of work to be done by miner/loader is extremely arduous in the underground mines. As such workmen in the piece rated job prayed for time rated job even at the cost of some reduction in their wages. The preference for change over from piece rated job to time rated job is prevalent among the pieces rated miner/loader who are in the higher age group and for health reason or otherwise they are unable to perform piece rated jobs. The concerned workmen of this case voluntarily exercise option for the time rated job in writing and thereafter the management issued necessary order pleading them in time rated categories. The concerned workman accepted the order and started working in time rated categories without protection of their piece rate wages without any protest. The written option exercised by the concerned workmen to come over to the time rated jobs without protection of wages are now not traceable in the office. If the concerned workmen wanted protection of their place rated wages they must do the piece rated job and while working in the time rated job they cannot claim piece rated wages. If the concerned workmen desired to have piece rated wages in the garb of protection of such wages, the management is even now prepared to put them back in their original piece rated jobs. But the management is not agreeable to protect their piece rated wages while they are working in the time rated categories. The concerned workmen working in the time rated category can claim wages only of the post of time rated category in which they are working and they cannot be paid wages which is applicable to the piece rated jobs. On the above facts the management is justified in paying the wages of time rated category in which the concerned workmen are working and the concerned workmen are not entitled to any relief.

The points for decision are (1) whether the concerned workmen had preferred to be transferred from piece rated group VA to the time rated jobs for protection of the piece rated wages of their own accord and (2) whether the concerned workmen are entitled to the protection of Group wages on the diversion from piece rated to time rated job.

The workmen and the management each examined 2 witnesses in support of their respective case. The documents of the workmen are marked Ext. W-1 to W-4 and the documents of the management are marked Ext. M-1 to M-2 series

Point No. 1

It is the admitted case of the parties that the concerned workmen were working as permanent miner/loaders in the piece rated group VA wages and that they were transferred to different time rated jobs from June. 1983 The question is whether the concerned workmen were transferred from the piece rated to the time rate jobs of their own request or whether they were transferred by the management in the exigency of their work. Admitidly the management have filed no paper to show that the concerned worken had re-exigency of their work Admittedly the management have piece rated job to the time rated job forgoing protection of their group VA wages The management in its written statement para 13 have stated that the concerned workmen volunteered and exercised option for the time rated jobs in writing and thereafter the management issued the necessary orders placing them in time rated categories without protecion of heir piece rated wages. In para 14 it is stated on behalf of the management that the written option exercised by the concerned workmen to come over to the ime rated jobs without protection of their wages are now not traceable. Thus there is no documentary evidence to show that the concerned workmen were transferred from piece rated jobs to the time rated jobs on their own representation in writing and forgoing the protection of their group VA wages. MW-1 Shri R. K. Dutta has stated in his examine-in-chief that he does not remember if the piece rated concerned workmen had made any written application for their transfer to the time rated job. MW-1 has no doubt stated that those piece rated workmen agreed to accept the minimum of the scale of time rated jobs to which they will be placed but the management has not filed any order to show that the group wages of the concerned workmen were not being protected as they had agreed to accept the minimum of the scale of the time rated jobs to which they were placed. Had the concerned workmen given any option in writing requesting the management for their transfer from piece rated to time rated job without protection of wages of their Group VA, there must have been some office note and connecting order to show that the concerned workmen were being transferred to the time rated job on their own request and on their undertaking that they would not claim the protection of their Group VA wages when transferred to the time rated jobs. WW-1 is one of the concerned workmen and he has denied that they had filed any petition in writing requesting for their transfer from piece rated to the time rated jobs forgoing protection of their piece rated group VA wages. WW-1 has no doubt stated that now when they have worked for about 5 to 6 years in the time rated job they do not like to go back to the piece rated jobs and I think this fact in itself cannot establish that the concerned workmen had opted for the time rated jobs of their own accord forgoing the protection of their group VA wages. In my opinion there is absolutely no evidence on the record to show that the concerned workmen were transferred to the time rated jobs on their own request and that they had agreed to accept the minimum of the scale of the time rated jobs to which they will be placed. Thus this point is decided in favour of the concerned workmen.

Point No. 2

The main case of the management regarding non entitlement of the protection of Group VA wages to the concerned workmen on their transfer to the time rated jobs is that as the concerned workmen had themselves preferred and opted for the time rated jobs and had forgone the protection of their Group VA wages, the concerned workmen were not entitled to the protection of Group VA wages on their diversion from piece rated to the time rated jobs. I have held above that it has not been established that the concerned workmen had preferred to be transferred from piece rated to the time rated job on their own accord and had not forgone protection of their group VA wages. It has to be seen now whether the concerned workmen are entitled to the protection of Group VA wages on their transfer from piece rated miner/loader to the different time rated jobs. In this connection we may refer to the implementation instruction No. 26 dated 23-4-84 which deals with fixation benefit to piece rated workers who are doing time rated job. It is provided in the said implementation instruction that it has been brought to the notice of the members of the standardisation committee that many piece rated workers who are working in time rated job have not been given minimum guaranteed benefit (clause 2.8) and fitment in the revised scale of pay (clause 2.9) as provided in NCWA-III. It further states that this matter was discussed by the standardisation committee its meeting held on 12/13-4-1984 and it was agreed that in all such cases the management will ensure the minimum guaranteed benefit and fitment in the revised scale of pay as per clause 2.8 and 2.9 of NCWA-III respectively with effect from 1-1-83, in case it has not already been done. The case of the workmen is that the concerned workmen were transferred from the piece rated job to the time rated job in June, 1983 and as such this implementation instruction No. 36 was fully applicable in the case of the concerned workmen Thus there is no room for doubt that the concerned workmen are entitled to minimum guaranteed benefit and fitment in the revised scale of pay per clause 2.8 and 2.9 of NCWA-III from June, 1983. It is a matter of calculation and as such if the time rated wages of the concerned workmen were being paid less than the minimum guaranteed wages of Group VA when they were transferred to the time

rated jobs, the management must pay them the minimum guaranteed wages of Group VA to them so long their wages in the time rated scale was less than the minimum guaranteed wages of Group VA. The management therefore should calculate the wages of the concerned workmen and pay them the difference of wages as directed above.

In the result, I hold that the action of the management of Patherdih Colliery of Sudamdih Area of M/s. B.C.C.L. in denying protection of Group Wages to the concerned workmen on theid divisions from piece rated to time rated job is not justified. The management must protect group VA wages to the concerned workmen as directed above and pay them the difference of wages within 3 months from the date of publication of the Award.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer
[No. L-20012/259/85-D.III (A)/IR (Coal-I)]

का.आ. 936.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि. की भागाबांद कोलियरी के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं. 2) धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है।

S.O. 936.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 2) Dhanbad as shown in the Annexure in industrial dispute between the employers in relation to the M/s. Bharat Coking Coal Limited, Bhagaband Colliery and their workmen.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 271 of 1986

In the matter of an industrial dispute under section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bhagaband Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen—Shri B. Singh, Advocate.

On behalf of the employers—Shri B. Joshi, Advocate.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 21st February, 1989

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute ot this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012(117)/86-D.III (A), dated, the Nil.

SCHEDULE

"Whether the demand of the 31 workmen, whose names are given below, that they should be departmentalised under the management of the Bhagaband Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited with payment of wages under the National Coal Wages Agreement-III with retrospective effect, is justified ? If so, to what relief are these workmen entitled ?"

ANNEXURE

1. Shri Ramdeo Singh
2. Shri Sarjoo Bhagat
3. Shri Ramnath Ram
4. Shri Deorajit Gope
5. Shri Sopat Gope
6. Shri Pokhan Kumha
7. Shri Anil Gope
8. Shri Ratan Rawani
9. Shri Gour Singh
10. Shri Satyanarayan Lal
11. Shri Kamoali Singh
12. Shri Nageshwar Pandey
13. Shri Shambu Prasad
14. Shri Rambrichksh Paswas
15. Shri Sadan Kumha
16. Shri Munarik Yadav
17. Shri Pandeo Ram
18. Shri Bideshi Yadav
19. Shri Ramchandra Yadav
20. Shri Rajoo Shaw
21. Shri Jairam Rewani
22. Shri Sahadeo Bhuiya
23. Shri Ram Swarup Singh
24. Shri Deenandan Ram
25. Gunaram Mahato
26. Shri Ramdas Ram
27. Shri Rajmahammad
28. Shri Janeswar Mahato
29. Shri Ramlakhan Mahato
30. Shri Ashok Chatterjee
31. Shri Prabhu Singh

In this case both the parties made their appearance but only the workmen filed their written statement. Thereafer several adjournments were granted to the employers for filling their Written Statement. But subsequently both the parties appeared before me and filed a Memorandum of Settlement under signature of both the parties. I heard them on said memorandum of settlement and I do find that the terms contained therein are fair, proper and beneficial to both the parties. Accordingly I accept the same and pass an award in terms of the Memorandum of Settlement which forms part of the Award as Annexure.

I. N. SINHA, Presiding Officer
[No. L-20012/117/86-D.III (A)/IR(Coal-I)]

ANNEXURE

MEMORANDUM OF SETTLEMENT UNDER RULE 58 OF THE CENTRAL INDUSTRIAL DISPUTE RULES OF THE I. D. ACT 1947

Management representatives :

1. Shri B. M. Lall, Dy. C.P.M.
   Bhagaband Area
2. Shri S. N. Sahi, Dy. P. M.
   Bhagaband Area

Union/workmen representative :

1. Shri Ramdeo Singh and

   29 others mentioned their names in terms of Reference)

SHORT RCITAL OF THE CASE

R.C.M.S. raised an industrial dispute for regularisation/departmentalisation of S/Shri Ramdeo Singh and 30 other

co-operative workers of Bhagaband Colliery and they should be treated as employees of BCCL and paid wages as per National Coal Wage agreement, which culminated into reference No. 271/86 pending before the Tribunal No. II. However, on the basis of D(P)' a circular No. 2649--949 dated 8/9th May '86 and subsequent circular that all the pending case bfore the Conciliation/Tribunal should be reviewed and settled wherever possible. Accordingly after thorough checking and verification their cases were forwarded to Hd. Qrs. from where approval has been communicated vide letter No. BCCL : EJO PER REF No. 271/86/6968-69 dated 28th January '87 from the PM(EJO) for taking into employment 30 persons as Miner/Loader without back wages out of 31 persons as named in the schedule of Reference. The details of the agreed decisions are as under :—

TERMS OF SETTLEMENT

(1) The following 30 co-operative workmen out of 31 involved in the Reference will be offered employment as Miner/Loader without any back wages subjct to their medical fitness :

(1) Shri Ramdeo Singh
(2) Shri Sarjoo Bhagat
(3) Shri Ram Nath Ram
(4) Shri Deorajeet Gope
(5) Shri Sopat Gope
(6) Shri Pokhan Kumar
(7) Shri Anil Gope
(8) Shri Ratan Rawani
(9) Shri Gaur Singh
(10) Shri Satya Narayan Lal
(11) Shri Ram Bali Singh
(12) Shri Nageshwar Pandey
(13) Shri Sambhoo Prasad
(14) Shri Ram Brich Paswan
(15) Shri Sadan Kumhar
(16) Shri Munarik Yadav
(17) Shri Pandeo Yadav
(18) Shri Bideshi Yadav
(19) Shri Ramchandar Yadav
(20) Shri Rajesh Shaw
(21) Shri Jay Ram Rawani
(22) Shri Sahadew Bhuiya
(23) Shri Ramswarup Singh
(24) Shri Dew Nandan Ram
(25) Shri Guna Ram Mahato
(26) Shri Ram Das Ram
(27) Shri Taj Mohammad
(28) Shri Janeshwar Mahato
(29) Shri Ram Lakhan Mahato
(30) Shri Parbhoo Singh

(2) It is agreed that the management will have the right to post in or transfer to any of the collieries of BCCL from time to time the Miner|Loader depending on the requirements of BCCL management for such workers.

(3) They will also swear an affidavit in support of their genuineness. They will also submit 7 (seven) copies of photographs duly attasted by the Colliery officials where they have worked as co-operative workers).

(4) It is agreed that this settlement is in full and final settlement of all the claims of the undersigned workmen concerned in the above Reference pending before CGIT No. II, Dhanbad, and there is no subsisting dispute and the parties will file copies of this settlement before the said Tribunal for disposing of the aforesaid Reference in terms of this settlement.

(5) That the settlement shall be registered under rules 58(4) of the 10 (Central) Rules, 1957.

Signature of Parties .
(B. M. LALL)
Dy. Chief Personnel Manager,
Bhagaband Area
(S. N. SAHI)
Dy. Personnel Manager,
Bhagaband Area

Witness :
Sd/- Illegible

Distribution :

(1) Workmen concerned
(2) ALC (C), Dhanbad
(3) RLC (C), Dhanbad
(4) G. M. Personnel),
Koyla Bhawan/Dhanbad
(5) Presiding Officer,
Tribunal No. II, Dhanbad

Ref. VII, PER, EST, Employ (Co-op), 571/338
Dated : 10th February, 1987.

(1) Shri Ramdeo Singh
(2) Shri Sarjoo Bhagat
(3) Shri Ramnath Ram
(4) Shri Deorajit Gope
(5) Shri Sopat Gope
(6) Shri Pokhan Kumha
(7) Shri Anil Gope
(8) Shri Ratan Rawani
(9) Shri Gour Singh
(10) Shri Satyanarayan Lal
(11) Shri Rambali Singh
(12) Shri Nageshwar Pandey
(13) Shri Shambhu Prasad
(14) Shri Rambricksh Paswan
(15) Shri Sadan Kumar
(16) Shri Munarik Yadav
(17) Shri Pandeo Ram
(18) Shri Bideshi Yadav
(19) Shri Ramchandra Yadav
(20) Shri Rajoo Shaw
(21) Shri Jairam Rewani
(22) Shri Sahadeo Bhuiya
(23) Shri Ram Swarup Singh
(24) Shri Deonandan Ram
(25) Shri Gunaram Mahato
(26) Shri Ramdas Ram
(27) Shri Rajmahammad
(28) Shri Janeswar Mahato
(29) Shri Ramlakhan Mahato
(30) Shri Parbhoo Singh

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1989

का.आ. 937:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि. की मधुबन कोलियरी के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं. 2) धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है।

New Delhi, the 17th March, 1989

S.O. 937.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dsipute between the employers in relation to the M/s. Bharat Coking Coal Limited Madhuban Colliery and the workmen.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No 87 of 1985

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Madhuban Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

APPEARANCES .

On behalf of the workmen—Shri D. Mukherjee, Secretary Bihar Colliery Kamgar Union.

On behalf of the employers—Shri R .S. Murthy, Advocate

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 7th February, 1989

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act. 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012(67)/85-D. III (A), dated the 11th June, 1985.

SCHEDULE

"Whether the demand of Bihar Colliery Kamgar Union that the management of Madhuban Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited should regularise the services of Shri Md. Gaffar, Heavy Vehicle Driver as Automobile Foreman/Supervisor is a proper grade of his entitlement in accordance with the work performed by him is justified ? If so, to what relief is this workman entitled and from what date ?"

In this case both the parties filed their respective W.S. documents etc. Thereafter the case proceeded along with its course. Subsequently at the stage of evidences both the parties appeared and filed a joint petition of compromise. I heard them on the said petition of compromise and I do find that the terms contained therein are fair, proper and beneficial to both the parties. Accordingly I accept the same and pass an Award in terms of the Joint Petition of compromise which forms part of the Award as Annexure.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-20012/67/85-D. III (A)/IR (Coal-I)]

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2 DHANBAD

In the matter of reference No. 87 of 1985

PARTIES :

Employers in relation to the management of Madhuban Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd.

AND

Their Workmen

Joint Petition of Compromise of

Employees and Workmen

The above-mentioned Employers and Workmen most respectfully beg to submit jointly as follows

1. That the Employers and the Workman/Union concerned have jointly negotiated the matter covered by the aforesaid reference with a view to arriving at an amicable and mutually acceptable overall settlement/agreement.

2. That as a result of such negotiations between the two parties, the employers and the workmen have agreed to settled the matter covered by the above reference or the following terms and conditions .—

(a) It is agreed that Shri Md. Gafoor shall be promoted by the Management as Automobile Asstt. Foreman/Supervisor and will be placed in Tech. and Supervisory Grade 'C' w.e.f. 1-10-88.

(b) It is agreed that for the period prior to the date referred to in clause (a) above the workman concerned will not be entitled to any benefits.

(c) It is agreed that this is an overall settlement in full and final settlement of all the claims of the workman concerned and the sponsoring Union arising out of the aforesaid reference.

3. That the employers and workmen/Sponsoring Union hereby declare that they consider the above terms of settlement as fair just and reasonable to both the parties.

In view of the above agreement/settlement, the employers as well as the workman/Sponsoring Union jointly pray that the Hon'ble Tribunal may be pleased to dispose of the reference in terms of the aforesaid agreement/settlement and give an award accordingly.

D. Mukherjee,

Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union,

for and on behalf of workmen :

Md. Gafoor,

the workman concerned.

Witnesses :

1. Sd/- Illegible

Dated : 31st January, 1989
General Manager,

Berora Area, Area No. 1

Bharat Coking Coal Ltd.,

for and on behalf of employers :

V. R. Joshi,

Dy. C.P.M . Area No. 1,

Bharat Coking Coal Limited

for and on behalf of Employers .

Ral S. Murthy, Advocate

for and on behalf of Employers

नई दिल्ली 29 मार्च, 1989

का. आ. 938:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि. वेस्ट मुदीडीह कोलियरी के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं. 1, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है।

New Delhi, the 29th March, 1989

S.O. 938.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the West Mudidih Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. and their workmen

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 63 of 1988

PARTIES :

Employers in relation to the Management of West Mudidih Colliery of M/s. B.C.C. Ltd.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri P. Jha, Dy. Personnel Manager.
For the Workmen—None.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 23rd January, 1989

AWARD

The present reference arises out of Order No. L-20012/20/88-D.III (A) dated, the 14th June 1988, passed by the Central Government in respect of an industrial dispute between the parties mentioned above. The subject matter of the dispute has been specified in the schedule to the said order and the said schedule runs as follows :

"Whether the demand of Dalit Mazdoor Sangh for employment of the dependent of Smt. Runwa Sahuain, Ex. Wagon Loader of East Mududih Colliery who died on 28-6-85 under NCWA-III is justified ? If yes, to what relief the dependent of the workmen entitled ?"

2. The dispute has been settled out of Court. A memorandum of settlement has been filed in Court. I have gone through the terms of settlement and I find them quite fair and reasonable. There is no reason why an award should not be made on the basis of terms and conditions laid down in the memorandum of settlement. I accept it and make an award accordingly. The memorandum of settlement shall form part of the award.

3. Let a copy of this award be sent to the Ministry as required under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

S. K. MITRA, Presiding Officer
[No. L-20012/20/86-D.III (A)/IR (Coal-I)]

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT DHANBAD

Ref. No. L-20012/20/88-D.III (A)

Employers in relation to the Management of West Mudidih Colliery of M/s. B.C.C. Ltd.

AND

Their workmen

Petition of Compromise

The humble petition on behalf of the parties to the above reference most respectfully shewth :—

1. That without prejudice to the respective contentions of the parties, the dispute has been amicably settled between the parties on the following terms :—

TERMS OF SETTLEMENT

(a) That Sri Jageshwar Saw, the depenednt son of the deceased workman named Runwa Sahuain, a casual wgon loader will be given employment as "Badli" Miner/Loader after he reports for his duties alongwith the certificates and documents mentioned herein after within 30 days from the date of this settlement.

(b) That, the said dependent son should be below 35 years of age and should be medically fit to work as "Badli" Miner/Loader. He medically fit to work as mined by the Area Medical Board and if found fit to work as Badli Miner/Loader, he shall be provided employment as "Badli" Miner/Loader.

(c) That, the said dependent son will submit the certificate from the Mukhia duly attested by the BDO of the local area within whose jurisdiction his village is situated together with an affidavit indicating that he is the real dependent son of Late Runwa Sahuain on whose behalf the Union has raised dispute.

(d) That, he will submit a certificate from the Secretary of the Union raising the present dispute certifying that he is the dependent son of Late Runwa Sahuain on whose behalf the present dispute has been raised.

(e) That, in case it will be found that the said person made false declaration on the certificate regarding his identity the services of the said person will stand automatically terminated.

2. That, in view of the settlement, there remains nothing to be adjudicated.

It is, therefore, humbly prayed that the Hon'ble Tribunal will gracesouly pleased to pass the Award in terms of settlement.

For the Worker :

1. (Belaram "Bidrahi")
Secretary,
Dalit Mazdoor Sangh.

2. (Jageshwar Saw)

For the Employer :

1. (U. L. Das)
Dy. CME, West Muddih Colliery.

2. (P. Jha)
Dy. Personnel Manager,
Katras Area.

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1989

का. आ. 939:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि. का भौरा (नार्थ) कोलियरी के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं. 1) धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है।

New Delhi, the 6th April, 1989

S.O. 939.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Bhowra (North) Colliery, M/s. Bharat Coking Coal Ltd. and their workmen.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, DHANBAD

In the matter of a reference U/S. 10(1)(d) of I.D. Act

Reference No 93 of 1988

PARTIES :

Employers in relation to the management of Rajahara Colliery of M|s. B.C.C. Ltd.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers : None.

For the Workmen : None.

STATE : Bihar INDUSTRY Coal.

Dated, the 15th March, 1989

AWARD

By Order No. L-24012|25|87-D. 4, dated, the 20th July, 1988, the Central Government in the Ministry of Labour, has, in exercise of the powers conferred by Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the demand of the union of M|s. Bharat Coking Coal Ltd. of Rajahara Colliery for the back wages of 25 days for the month of April, 1987 in respect of piece-rated workers is justified ? If yes, to what relief are the concerned workmen entitled ?"

2. It appears from the schdule of the terms of reference in the presnt case that consequent upon the demand of the union, namely, *Hind Mazdoor Kishan Panchayat operating* in Rajahara Colliery for back wages of 25 days for the month of April, 1987 in respect of piece-rated workers of the said colliery, the present industrial dispute was referred to this Tribunal for adjudication by the appropriate Government.

3. After receipt of the reference in the office of this Tribunal notices were issued to the parties firstly on 25-10-88 fixing 3-11-88 as the date for appearance and filing written statement by the workmen. In response to the notice the managment appeared through Shri R. S. Murthy, Advocate, on 3-11-88, but none appeared for the workmen nor the union. In the circumstances, the union was directed to show-cause as to why the case should not be held ex-parte fixing 2-12-88 for appearance and filing written statement by the union. But neither the workman nor the union appeared on 2-12-88 nor on subsequent date. Lastly on 1-2-89 although Sri R. S Murthy appeared for the management none appeared for the workmen or the union and again a notice to show-cause was sent to the union fixing 28-2-89 for appearance and filing written statement. But on the date fixed neither the workman nor the union appeared. In he circumstances, I am constrained to hold that either the union nor the concerned workman were interested in proceedings with the present reference. Hence, this Tribunal has got no other alternative than to pass 'no dispute award' and accordingly I do so.

This is my award.

S. K. MITRA, Presiding Officer

[No. L-24012/25|87-D.IV(B)|IR(Coal I)]

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1989

का. आ. 940.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की मुरलीडीह कोलियरी के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (नं. 2), धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 3-4-1989 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 13th April, 1989

S.O. 940.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relaton to the Murulidih Colliery of M|s. Bharat Coking Coal Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 3-4-1989.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 239 of 1987

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Murulidih Colliery of M|s. Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen : *Shri D. Mukherjee, Secretary,* Bihar Colliery Kamgar Union.

On behalf of the employers : Shri B. N. Prasad, Advocate.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal.

Dated, Dhanbad, the 27th March, 1989

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012(57)|87-D. III(A) dated, the 14th August, 1987.

SCHEDULE

"Whether the action of the managment of Murulidih Colliery of M|s. Bharat Coking Coal Limited, in dismissing S|Shri Salku Mochi and Alku Mochi, Miners|Loaders from service with effect from 15-2-1985 and 19-2-1985 respectively is justified ? If not, to what relief the workmen are entitled ?"

In this case both the parties appeared and filed their respective W. S. etc. Thereafter the case proceeded along with its course. Subsequently both the parties appeared before me and filed a *Memorandum of Settlement* and I do find that the terms contained therein are fair, proper and beneficial to both the parties. Accordingly I accept the same pass an Award in terms of the Memorandum of Settlement which forms part of the Award as Annexure.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-20012(57)|87-D. III(A)|IR(Coal-I)]

K. J. DYVA PRASAD, Desk Officer

ANNEXURE

Ref. No. 239|87

FORM-'H'

(See Rule 58)

Forms of Memorandum of Settlement

Name of the parties :

General Manager, Mohuda Area No. 2. .. Representing

M|s. Bharat Coking Coal Ltd. ... Employer(s)

1. Sri B. Mahanti, Secretary,
   Bihar Colliery
   Kamgar Union,

2. Sri Alku Muchi—Murulidih Colly. Representing
3. Sri Salku Muchi, Murulidih Colly. workmen

SHORT RECITAL OF THE CASE

President Bihar Colliery Kamgar Union has raised an Industrial dispute about the alleged wrongful and illegal dismissal of S|Sri Salku Muchi and Aalku Muchi M|Loader. After the failure of conciliation the dispute was referred to the Central Govt. to the Hon'ble Tribunal No. 2 Dhanbad vide their order No. L-20012(57)|87-D-111(A) with the following terms of reference :—

"Whether the action of the management of Murulidih Colly. of M|s. Bharat Coking Coal Ltd. in dismissing S|Sri Salku Muchi and Alku Muchi M|Loader from Services w.e.f. 15-2-85 and 19-2-1985 respectively is justified ? If not to what relief the workmen are entitled.

While the matter is pending before the Hon'ble Tribunal under reference No. 239|87 the parties have mutually discussed and negotiated for arriving at an amicable settlement. As a result of the ngotiation the parties have agreed to settle the dispute on he following terms and conditions :—

TERMS OF SETTLEMENT

(1) That the workmen namely Salku Muchi and Alku Muchi, Ex-Miner|Loader, Murulidih Colliery will be taken back in employment with immediate effect;

(2) That they will not be entitled for any wages for the period between their date of dismissal and date of resumption of duty.

(3) That the workmen, however, will be given continuity of service for the purpose of gratuity;

(4) That the settlement is full and final in respect of all claims arrising out of this dispute ;

(5) That the parties consider and confirm that the settlement just fair andn beneficial to both of them;

(6) That the parties shall file a copy of the settlement before the Hon'ble Tribunal No. 2 Dhanbad as a compromise petition and also send copies to the Ministry of Labour, Govt. of India, Chief Labour Commissioner (C), New Delhi, RLC(C) Dhanbad and ALC(C) Dhanbad.

Sd./- (Illegible)
(Sri K. N. Singh)
General Manager,
Mohuda Area No. 2

1. Sd|- (Illigeble) Secy. BCKU
2. Salku Mochi (L. T. I.)
3. Alku Mochi (L.T.T.)

Witnesses :—
1 Hari Nath Das
2. Basdeb Bhuiyan

Copy forwarded to :—
1. Asstt. Labour Commissioner (C), Dhanbad
2. Regional Labour Commissioner (C), Dhanbad
3. Chief Labour Commissioner (C), New Delhi.
4. Secretary to the Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi

Sd./- (Illegible)
General Manager
Mohuda Area No. 2
Sd| (illegible)
Secy to BCKKU

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1989

का आ 941:—खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उप निदेशक, खान सुरक्षा (खनन), सर्वश्री कुलदीप कुमार शर्मा, उत्पल साहू पी सी रजाक, बी पी सिंह, तथा एन के खेराडा को अगले आदेश तक मुख्य खान निरीक्षक के अधीनस्थ खान निरीक्षक नियुक्त करती है।

[फा स. ए 12025/1/87-खान-I]

New Delhi, the 13th March, 1989

S.O. 941.—In exercise of powers conferred under sub-section (1) of section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952) the Central Government hereby appoins S/Shri Kuldip Kumar Sharma, Upal Saha, P. C. Rajak, B. P. Singh and N. K. Kherada; Deputy Directors of Mines Safety (Mining) as Inspecors of Mines, subordinte to the Chief Inspecor of Mins,. until further orders.

[File No. A-12025|1|87-M.I]

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1989

का आ 942:—खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सर्वश्री अरुण कुमार जैन और पी. रंगनाथेश्वर को अगले आदेश तक मुख्य खान निरीक्षक के अधीनस्थ खान निरीक्षक नियुक्त करती है।

[सं. ए-12025/1/87-एम I/आई एस एच]

New Delhi, the 5th April, 1989

S.O. 942.—In exercise of powes conferred under sub-section (1) of section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952) the Central Government hereby appoints S|Shri Arun Kumar Jain and P. Ranganatheswar as Inspectors of Mines, subordinate to the Chief Inspector of Mines, until further orders.

[File No. A-12025|1|87-M. 1|ISH-I]

का आ 943:—राष्ट्रपति, खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद में डा. पी. के. सिशोदिया को 13 मार्च, 1989 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक अस्थाई हैसियत से खान सुरक्षा (औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान) ग्रेड I के सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

[सं ए-12028/2/86-एम-I/आई एस एच-I]

S.O.943.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 5 of the Mines Act. 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby appoints Dr. P.K. Sishodiya as Inspector of Mines, subordinate to the Chief Inspector of Mines, until further orders.

[F. No. A-12028|2|86-M.I|ISH-I]

का आ 944:—खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, खान सुरक्षा उप निदेशक श्री इमत्याज हुसैन को अगले आदेशों तक मुख्य खान निरीक्षक के अधीन खान निरीक्षक नियुक्त करती है।

[फा० सं ए-12025/5/84-खान-I/आई एस एच-I]
आर टी पाण्डेय, उप सचिव

S.O. 944.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 5 of the Mines Act 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri Imtiaz Hussain Deputy Director of Mines Safety, as Inspector of Mines, subordnate to the Chief Inspector of Mines, until further orders.

[F. No. A-12025/5|84-M.I|ISH-I]
R. T. PANDEY, Dy Secy.

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1989

का.आ. 945:—यतः मैसर्स भारतीय रूई निगम लिमिटेड, एयर इंडिया बिल्डिंग, 12वां मंजिल, नारीमन प्वाईंट, बम्बई-400021 और इसकी समस्त भारत में स्थित शाखाएं (इसके आगे जहां कहीं भी उक्त स्थापना शब्द का प्रयोग हो इससे अभिप्राय उक्त स्थापना से है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) इसके आगे उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट (की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है ।

यह केन्द्र सरकार की राय में उक्त स्थापना के कर्मचारियों के लिए तैयार किए गए भविष्य निधि नियमों में अंशदान की दर उक्त अधिनियम की धारा 6 में उल्लिखित कर्मचारी अंशदान की दर से कम नहीं है तथा इसके कर्मचारियों को मिलने वाले भविष्य निधि लाभ उक्त अधिनियम तथा कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 (इसके आगे जहां कहीं भी स्कीम शब्द का प्रयोग किया गया है उससे अभिप्राय उक्त स्कीम से है) में उल्लिखित लाभों से किसी भी प्रकार से कम नहीं है जो इस वर्ग की स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध है।

अब इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा एक के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संलग्न अनुसूची में वर्णित शर्तों के अधीन केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा उक्त स्थापना को उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के लागू होने से छूट प्रदान करती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना में से सम्बन्धित नियोक्ता केन्द्र सरकार के द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देश के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (क) में उल्लिखित निरीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा और ऐसे निरीक्षण प्रभार की अदायगी प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिन के अन्दर करेगा।

2. न-छूट प्राप्त स्थापनाओं के संबंध में उक्त अधिनियम और उसके अधीन सजित उक्त स्कीम के अन्तर्गत देय अंशदान के दर से स्थापना के भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत देय अंशदान का दर किसी समय भी कम न होगा।

3. पेंशनियों के मामले में छूट प्राप्त स्थापना की स्कीम कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 से कम हितकर नहीं होगी।

4. उक्त स्कीम में कोई भी संशोधन जो स्थापना के वर्तमान नियमों से अधिक लाभकारी है उन पर अपने आप लागू किया जाएगा। उक्त स्थापना के भविष्य निधि नियमों में कोई भी संशोधन, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से उक्त स्थापना के कर्मचारियों के हित के प्रतिकूल प्रभावी होने की संभावना है वहां अपनी अनुमति देने से पूर्व, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारियों को अपने विचार प्रस्तुत करने का उचित अवसर देगा।

5. यदि स्थापना को छूट न दी जाती तो वे सभी कर्मचारी (जैसे उक्त अधिनियम की धारा 2(च) में निश्चित किया गया है) जो सदस्य बनने के पात्र होते, सदस्य बनाए जाएंगे।

6. जहां एक कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि (कानूनी) या किसी अन्य छूट-प्राप्त स्थापना का पहले से सदस्य है, को अपनी स्थापना में काम पर लगाया जाता है तो नियोक्ता उसे निधि का तुरन्त सदस्य बनाएगा और ऐसे कर्मचारी के पिछले नियोक्ता के पास भविष्य निधि लेखे में संचयों को अन्तरित कराने और उसके लेखे में जमा कराने की व्यवस्था करेगा।

7. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार के द्वारा जैसे भी मामला हो, समय समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार भविष्य निधि के प्रबन्ध के लिए नियोक्ता न्यासी बोर्ड की स्थापना करेगा।

8. भविष्य निधि, न्यासी बोर्ड में निहित होगा जो अन्य बातों के होते हुए भविष्य निधि में आय के उचित लेखों और भविष्य निधि से अदायगियों और उनकी अभिरक्षा में शेषों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उत्तरदायी होगा।

9. न्यासी बोर्ड कम से कम 3 माह में एक बार बैठक करेंगे और केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को अधिकार होगा कि वह किसी अन्य योग्य लेखा परीक्षक से खातों को दुबारा लेखा परीक्षा कराए और ऐसे पुनः लेखा-परीक्षा के खर्च नियोक्ता वहन करेगा।

10. न्यासी बोर्ड द्वारा रखे गए भविष्य निधि लेखे अर्हता प्राप्त निष्पक्ष चार्टर्ड अकाउण्टेंट द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा के अध्यधीन होंगे। जहां आवश्यक समझा जाए, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को किसी अन्य अर्हता प्राप्त लेखा-परीक्षा द्वारा लेखों की पुनः लेखा परीक्षा कराने का अधिकार होगा और इस पर हुआ व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

11. प्रत्येक वर्ष स्थापनों के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के साथ लेखा परीक्षित वार्षिक भविष्य निधि लेखों की एक प्रति वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को प्रस्तुत की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए भविष्य निधि का वित्तीय वर्ष पहली अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

12. नियोक्ता प्रतिमाह भविष्य निधि के देय अपने कर्मचारियों के अंशदानों की आगामी माह की 15 तारीख तक न्यासी बोर्ड को अंतरित कर देगा। अंशदानों की विलम्ब से अदायगी करने के लिए समान परिस्थितियों में नियोक्ता नुकसानी देने का उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जिस प्रकार एक न-छूट प्राप्त स्थापना उत्तरदायी होती है।

13. न्यासी बोर्ड सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार निधि में जमा राशियों का निवेश करेगा। प्रतिभूतियां न्यासी बोर्ड के नाम पर प्राप्त की जाएंगी और भारतीय रिजर्व बैंक के जमा नियंत्रण में अनुसूचित बैंक की अभिरक्षा में रखा जाएगा।

14. सरकार के निर्देशों के अनुसार निवेश न करने पर न्यासी बोर्ड अलग-अलग रूप से और एक साथ केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उसके प्रतिनिधियों द्वारा लगाए गए अधिक प्रभार का उत्तरदायी होगा।

15. न्यासी बोर्ड एक वस्तु-ब्योरा रजिस्टर तैयार करेगा और ब्याज और विमोचन आय को समय पर वसूली सुनिश्चित करेगा।

16. जमा किए गए अंशदानों, निकाले गए और प्रत्येक कर्मचारी से संबंधित ब्याज को दिखाने के लिए न्यासी बोर्ड विस्तृत लेखे तैयार करेगा।

17. वित्तीय लेखा वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण जारी करेगा।

18. बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण के स्थान पर पासबुक जारी कर सकता है। ये पास-बुकें कर्मचारियों की अभिरक्षा में रहेंगी और कर्मचारियों के प्रस्तुतीकरण पर बोर्ड के द्वारा उन्हें अद्यतन किया जाएगा।

19. लेखा वर्ष के पहले दिन आदि शेष पर प्रत्येक कर्मचारी के लेखे में ब्याज उस दर से जमा किया जाएगा जिसका न्यासी बोर्ड निर्णय करे परन्तु यह उक्त स्कीम के पैरा 60 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित दर से कम नहीं होगा।

20. यदि न्यासी बोर्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित ब्याज की दर [illegible] कारण से [illegible] निवेश पर आय कम है या किसी अन्य कारण से अदा करने में असमर्थ है तो इस कमी को नियोक्ता पूरा करेगा।

21. नियोक्ता भविष्य निधि की चोरी के कारण, छूट समाप्त होने, गबन अथवा किसी अन्य कारण से हुई हानि को पूरा करेगा।

22. नियोक्ता और न्यासी बोर्ड, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगा जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त निर्धारित करें।

23. उक्त स्कीम के पैरा 69 की शैली पर किसी कर्मचारी को निधि के सदस्य न रहने पर यदि स्थापना के भविष्य निधि नियमों में नियोक्ताओं के अंशदानों को जब्त करने की व्यवस्था है तो न्यासी बोर्ड इस प्रकार जब्त की गई राशियों का अलग से लेखा तैयार करेगा और उसे ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व अनुमति से सुनिश्चित किया गया हो।

24. स्थापन के भविष्य निधि नियमों में निर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि किसी व्यक्ति की सेवा निवृत्ति होने के फलस्वरूप या किसी अन्य प्रतिष्ठान में नौकरी करने पर निधि की सदस्यता समाप्त हो जाती है यह पता लगता है कि प्रतिष्ठान के भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अंशदान की दर समपहरण की दर आदि सांविधिक योजना के अन्तर्गत दी गई दरों की तुलना में कम अनुकूल है तो अन्तर का वहन नियोक्ता द्वारा किया जायेगा।

25. नियोक्ता, भविष्य निधि के प्रशासन से संबंधित सभी खर्च जिसमें लेखों के रखरखाव रिटर्न प्रस्तुत किए जाने, राशियों का अन्तरण शामिल है, वहन करेगा।

26. नियोक्ता समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निधि के नियमों की एक प्रति तथा जब भी कोई संशोधन होता है, उसकी मुख्य बातों को कर्मचारियों के बहुमत की भाषा में अनुवाद करके स्थापना के बोर्ड पर लगायेगा।

27. "समुचित सरकार" स्थापना की चालू छूट पर और शर्तें लगा सकती है।

28. यदि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्थापना वर्ग जिसमें उसकी स्थापना आती है, पर अंशदान की दर बढ़ायी जाती है, नियोक्ता भविष्य निधि अंशदान की दर उचित रूप से बढ़ाएगा, ताकि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दिए जाने वाले लाभों से स्थापना की स्कीम के अन्तर्गत दिए जाने वाले भविष्य निधि के लाभ किसी भी प्रकार से कम न हों।

29. उक्त शर्तों में से किसी एक के अन्तर्गत उल्लंघन पर छूट रद्द की जा सकती है।

[सं० एम-35015/6/89-स.सु.-2]

New Delhi, the 14th March, 1989

S.O. 945.—Whereas Messrs The Cotton Corporation of India Limited, Air India Building, 12th Floor, Nariman Point, Bombay-400021, including its branches situated all over India (*Hereinafter referred to as the said establishment*) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act);

And whereas in the opinion of the Central Government the rules of the Provident Fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in section 6 of the said Act and the employees are also in employment of other provident fund benefits which on the whole are not less favourable to the employees than the benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the said scheme) in relation to the employees in any other establishment of a similar character:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central Government may from time to time direct under clause (a) of sub-section (3) of section 17 of said Act within 15 days from the close of every month.

2. The rate of contribution payable under the provident fund rules of the establishment shall at no time be lower than those payable under the said Act in respect of the unexempted establishments and the said Scheme framed thereunder.

3. In the matter of advances, the scheme of the exempted establishment shall not be less favourable than the Employees Provident Fund Scheme, 1952.

4. Any amendment to the said scheme this is more beneficial to the employees than the existing rules of the establishment shall be made applicable to them automatically no amendment of the rules of the provident fund of the said establishment shall be made without the previous approval of the Regioal Provident Fund Commissioner and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees of the said establishment, the Regional Provident Fund Commissioner shall, before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

5. All employees (as defined in section 2(f) of the said Act) who would have been eligible to become members of the Provident Fund had the establishment not been granted exemption shall be enrolled as members.

6. Where an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund (Statutory) or a Provident Fund of any other exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the fund and arrange to have the accomulations in the provident fund account of such employee with his previous employer transferred and credited to his account.

7. The employer shall establish a Board of Trustees for the management of the provident fund according to such directions as may ze gien by the Central Provident Fund Commissioner or by the Central Government, as the case may be, from time to time.

8. The provident fund shall vest in the Board of Trustees who will be responsible for and accountable to the Employees' Provident Fund Organisation inter-alia for proper accounts of the receipts into and payments from the Provident Fund and the balance in their custody.

9. The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in accordance with the guidelines that may be issued from time to time by the Central Government Central Provident Fund Commissioner or an officer authorised by him.

10. The accounts of the Provident Fund. maintained by the Board of Trustees shall be subject to audit by a qualified independent Chartered Accountant annually. Where considered necessary, the Central Provident Fund Commissioner shall have the right to have the aounts re-audited by any other qualified auditor and the expenses so incurred shall be borne by the employer.

11. A copy of the audited annual provident fund accounts together with the audited balance sheet of the establishment for each accouning year shall be submitted to the Regional Provident Fund Commissioner within six months after the close of the financial year. For this purpose the financial year of the provident fund shall be from the 1st of April to the 31st of March.

12. The employer shall transfer to the Board of Trustees the contributions payable to the Provident Fund by himself and the employees by the 15th of each month following the month for which the contributions are payable. The employer shall be liable to pay damage to the Board of Trustees for any delay in payment of the contriowtions in the same manner as an un-exempted establishment is liable under similar circumstances.

13. The Board of Trustees shall invest the monies in the fund as per directions that may be given by the Government from time to time. The securities shall be obtained in the name of the Board of Trustees and shall be kept in the custody of a Scheduled Bank under the Credit Central of the Reserve Bank of India.

14. Failure to make the investments as per directions of the Government shall make the Board of Trustees severally and jointly liable to surcharge as may be imposed by the Central Provident Fund Commissioner or his representative.

15. The Board of Trustees shall maintain a serial-wise register and ensure timely realisation of interest and ensure timely realisation of interest and redemption proceeds.

16. The Board Trustees shall maintain detailed accounts to show the contributions credited, withdrawal and interest in respect of each employee.

17. The Board shall issue an annual statement of account to every employee within six months of the close of financial accounting year.

18. The Board may, instead of the annual statement of accounts, issue passbooks to every employee. These pass books shall remain in the custody of the employees and will be brought uptodate by the Board on presentation by the employees.

19. The account of each employee shall be credited interest calculated on the opening balance as on the 1st day of the accounting year at such date may be decided by the Board of Trustees but shall not be lower than the rate declared by the Central Government under para 60 of the said Scheme.

20. If the Board of Trustees are unable to pay interest at the rate declared by the Central Government for the reason that the return on investment is less or for any other reason, than the deficiency shall be made good by the employer.

21. The employer shall also make good any other less that may be caused to the Provident Fund due to theft burglary, defalcation, mis-approariation or any other reason.

22. The employer as well as the Board of Trustees shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner as the Central Government|Central Provident Fund Commissioner may prescribed from time to time.

23. If the Provident Fund rules of the establishment provide for forfeiture the employers' contribution in cases where an employee cases to be a member of the fund on the lines of para 69 of the said Scheme, the Board of Trustees shall maintain a separate account of the amounts so forfeited and may utilise the same for such purposes as may be determined with the prior approval of the Central Provident Fund Commisioner.

24. Notwithstanding anything contained in the provident fund rules of the establishment, if on the cessation of any individual from the membership of the fund consequent on retiring from service or on taking up the employment in some other establishment, it is found that the rate of contribution, rate of forfeiture etc. under the provident fund rules of the establishment are less favourable as compared to those under the statutory scheme, the difference shall be borne by the employer.

25. The employer shall bear all the expenses of the adminitration of the Provident Fund including the maintenance of Accounts submission of returns, transfer of accumulations.

26. The employer shall display on the notice board of the ministration of the Provident Fund including the mainby the appropriate authority and as and when amended thereto alongwith a tranlation of the salient points thereof in the language of the majority of the employees.

27. The "appropriate Government" may lay down any further conditions for containued exemption of the establishment.

28. The employee shall enhance the rate of provident fund contributions appropriately if the rate of provident fund contribution for the class of establishments in which his establishment fell is enhanced under the said Act so that the benefits under the Provident Fund Scheme of the establishment shall not become less favourable than the benefits provided under the said Act.

29. The exemption is liable to be cencelled for violation of any if the above conditions.

[No. S-35015(6)|89-SS-II]

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1989

का.आ. 946—मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (घ) के अनुसरण में श्री के.डी. सक्सैना के स्थान पर श्रीमती किरण विजय सिंह, सचिव, श्रम विभाग, मध्य प्रदेश सरकार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 545(अ) दिनांक 25 जुलाई, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "(राज्य सरकार द्वारा धारा 4 के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)" शीर्षक के नीचे मद 17 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

श्रीमती किरण विजय सिंह,
सचिव, श्रम विभाग,
मध्य प्रदेश सरकार,
भोपाल

[संख्या यू-16012/15/88-एस.एस-1].

New Delhi, the 17th March, 1989

S.O. 946.—Whereas the State Government of Madhya Pradesh has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees State Insurance Act, 1947 (34 of 1948), nominated Smt. Kiran Vijay Singh Secretary, Labour Department, Govt. of Madhya Pradesh to represent that State on the Employees State Insurance Corporation, in place of Shri K. D. Saxena;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 545(E), dated the 25th July, 1985, namely:

In the said notification, under the heading "(Nominated by the State Government under clause (d) of section 4)",

for the entry against Serial Number 17, the following entry shall be substituted, namely :—

Smt. Kiran Vijay Singh,
Secretary to the Govt of Madhya Pradesh,
Labour Department,
Govt. of Madhya Pradesh,
Bhopal.

[No. U-16012|15|88-SS.I]

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1989

का. आ. 947.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1-4-1989 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त कि जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध आन्ध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:—

"जिला विशाखापटनम में पेनडुरटी राजस्व मंडल के अधीन राजस्व ग्राम वेपागुन्टा, आर. आर. वेंकेटापुरम, पुरुषोत्तमपुरम श्यामलापल्ली चिन्नामुशरीवाडा और पेनडुरटी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र"

[सं. एस-38013/6/89-एस. एस. 1]

New Delhi, the 28th March, 1989

S.O. 947.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st April 1989 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Andhra Pradesh namely :—

"Areas within revenue villages of Vepagunta, R. R. Venkatapuram Purushothamapuram Shyamalapally Chinamushrivada and Pendurti under Pendurti Revenue maudal in Visakapatnam District".

[No. S-38013|6|89-SS.I]

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1989

का. आ. 948.—जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (घ) के अनुसरण में श्री एस. के. महाजन के स्थान पर श्री जी. डी. वधवा, श्रम आयुक्त, जम्मू एवं कश्मीर, राज्य सरकार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 545 (अ), दिनांक 25 जुलाई, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, "(राज्य सरकार द्वारा धारा 4 के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)" शीर्षक के नीचे मद्द 14 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

श्री जी. डी. वधवा
श्रम आयुक्त, जम्मू एवं कश्मीर
राज्य सरकार, जम्मू

[संख्या यू-16012/11/88-एस. एस.-1]

New Delhi, the 4th April, 1989

S.O. 948.—Whereas the State Government of Jammu and Kashir has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Shri G. D. Wadhwa, Labour Commissioner, Govt. of Jammu & Kashmir to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri S. K. Mahajan;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 545(E), dated the 25th July, 1985, namely:—

In the said notification, under the reading "(Nominated by the State Government under clause (d) of section 4)", for the entry against Serial Number 14, the following entry shall be substituted, namely :—

Shri G. D. Wadhwa,
Labour Commissioner,
Govt. of Jammu & Kashmir,
JAMMU,

[No. U-16012|11|88-SS.I]

का. आ. 949.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 16-4-89 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:—

"जिला और ताल्लुक टुमकूर में होबली कसबा के अधीन राजस्व ग्राम मालासेन्द्रा, होबाथनहल्ली पेरामनहल्ली और डोडानरवन्गला के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।"

[संख्या एस-38013/7/89-एस. एस.-1]
ए. के. भट्टाराई, अवर सचिव

S.O. 949.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 16th April, 1989 as the date on which the provisions of Chapter IV except sections 44 and 45 which have already brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Karnataka, namely :—

"Areas comprising of revenue vallages of Mallasandra, Hobathanahalli, Peramanahalli and Dodanaravagla under Hobli Kasaba in Taluk and District Tumkur."

[No. S-38013|7|89-SS.I]
A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1989

का. आ. 950.—उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार अनुभाग अधिकारी श्री सी. एम. शर्मा को दिनांक 20 मार्च 1989 से अगला आदेश जारी होने तक उत्प्रवासी संरक्षी-II, बम्बई के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. ए-22012(1)/89 –उत्प्र.]

New Delhi, the 20th March, 1989

S.O. 950.—In exercise of the powers conferred by Section 3, Sub-Section (1) of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby appoints Shri C. M. Sharma, Section Officer as Protector of Emigrants-II, Bombay with effect from 20th March, 1989, till further orders.

[No. A-22012|1|89-Emig.]

का. आ. 951.—उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 3) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री ए. वी. एस. शर्मा, अवर सचिव को उत्प्रवासी संरक्षी दिल्ली के रूप में दिनांक 20 मार्च, 1989 से अगला आदेश जारी होने तक नियुक्त करती है।

[सं. ए-22012(1) 89-उत्प्र.]

S.O. 951.—In exercise of the powers conferred by Section 3 (i) of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983) the Central Government hereby appoints Shri A. V. S. Sarma, Under Secretary, Ministry of Labour as Protector of Emigrants, Delhi with effect from 20-3-89 till further order.

[No. A-22012(1)|89-Emig.]

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1989

का. आ. 952.—उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री एच. सी. गौड़, अनुभाग अधिकारी को दिनांक 27 मार्च 1989 से अगला आदेश जारी होने तक उत्प्रवासी संरक्षी, चण्डीगढ़ के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. ए.-22012(1) 89-उत्प्र.]

New Delhi, the 23rd March, 1989

S.O. 952.—In exercise of the powers conferred by Section 3, Sub-section (1) of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby appoints Shri Harish C. Gaur Section Officer as Protector of Emigrants, Chandigarh with effect from 27th March, 1989, till further orders.

[No. A-22012|1|89-Emig.]

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1989

का. आ. 953.—उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उत्प्रवास संरक्षी कार्यालय, दिल्ली में श्री इन्दर सिंह, अवर सचिव, श्रम मंत्रालय को दिनांक 27 मार्च, 1989 को उत्प्रवासी संरक्षी, दिल्ली के सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

c [सं. ए-22012(1) 89-उत्प्रवास]

New Delhi, the 27th March, 1989

S.O. 953.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby authorises Shri Inder Singh, Under Secretary in the Ministry of Labour, to perform all functions of Protector of Emigrants, Delhi on 27-3-89.

[No. A-22012/1/86-Emig. II]

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1989

का० आ० 954.-उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उत्प्रवास संरक्षी कार्यालय दिल्ली में श्री इन्दरसिंह, अवर सचिव श्रम मंत्रालय को दिनांक 28 मार्च 1989 से दिनांक 31 मार्च 1989 तक उत्प्रवासी संरक्षी दिल्ली के सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं. ए-22012(1) 89—उत्प्र.]
एस. सी. शर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 28th March, 1989.

S. O. 954.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby authorises Shri Inder Singh, Under Secretary in the Ministry of Labour, to perform all functions of Protector of Emigrants, Delhi from 28-3-89 to 31-3-89.

[No. A-22012(1)|89-Emig.]
S. C. SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1989

का. आ. 955.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 23rd March, 1989

S. O. 955.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the United Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government.

ANNEXURE

BEFORE SHRI G. S. KALRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I.D. No. 32|86.

BETWEEN

In the matter of dispute
The United Bank of India Employees' Association.
Delhi State Committee,
206 Ansal Bhawan,
16 Kasturba Gandhi Marg,
New Delhi-110001.

Versus

The Regional Manager,
United Bank of India,
North India Region,
206 Ansal Bhawan,
16 Kasturba Gandhi Marg,
New Delhi-110001.

APPEARANCES :

Shri I. D. Chopra—for the workmen.
Shri R. R. Roy—for the Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide L-12012|27|85-D.II(A) dated 6th February, 1986 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the management United Bank of India, New Delhi in not counting the period of stagnation from 1-9-1976 in the case of Shri R. P. Sharma and 1959 in the case of Shri Lal Bahadur is justified ? If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?"

2. It is common ground between the parties that Shri R. P. Sharma workman was employed in erstwhile Hindusthan Mercantile Bank Limited and Shri Lal Bahadur workman was employed in the erstwhile Narang Bank of India Limited. The Hindusthan Mercantile Bank Limited and the Narang Bank of India Limited were amalgamated with the United Bank of India w.e.f. 22nd December, 1973 and 1st August, 1976 respectively. The separate agreements were executed between the transferor banks and the transferee bank but both had similar contents. For the purpose of the present enquiry, the relevant provisions are contained in paras 2(B), (C) and (D) of the 3rd Schedule to the agreement which are reproduced below :—

"(B) On expiry of the said period of three years the salaries of the Clerical and Subordinate Employees of the Transferor will be fitted on the following basis :—

(a) The employees' basic pay as on the date of transfer shall not be reduced in any case.

(b) (i) A workman shall be fitted into the scale of pay of the Transferee by placing him at the stage in the new scale equal to or next above his basic pay as on the date of transfer.

(ii) To the basic pay into which he is fitted under Clause (B)(i) annual increment/or increments in the new scale of the Transferee from that stage on wards should be added at the rate of one increment for every completed three years of service in the same category. Such increments shall not however, exceed four in number, provided however, the adjusted basic pay in the new scale shall not exceed what point-to-piint adjustment would give him or the maximum in the new scale.

(C) Where an employee's basic pay will be lower than the minimum of the scale of pay of the Transferee he will be fitted at the minimum stage.

(D) Employees taken over from the Transferor will get annual grade scale increments on the same dates on which such increments are payable to them by the Transferor.

3. The case of the workman is that Shri R .P. Sharma was allowed annual increments till he was on ceiling point and the last increment was granted on and w.e.f. 1-9-75 and thereafter no further increment was sanctioned and consequently his first stagnation increment had fallen due w.e.f. 1st September, 1980. However, the Management did not allow/grant the increment from 1st September, 1980 and wrongly calculated 5 years from the date 22-12-76 i.e. the date when the employees of erstwhile Hindustan Mercantile Bank Limited were granted pay scales as well as allowance of A-Class bank as per agreement of transfer. Similarly Shri Lal Bahadur was not granted any annual increment by the Management since he was held on ceiling point. He was given pay scale of A Class bank w.e.f. 1-8-1979 i.e. after expiry of 3 years from the date of take over. Here the Management had again wrongly calculated the period of 5 years from the date on which A class scales were given to the employees of erstwhile Narang Bank of India Limited instead of from the date on which Lal Bahadur was actually on ceiling point i.e. February 1969, since he was appointed on 2-2-1949. In this way, both the workmen have suffered monetary loss due to the illegal, arbitrary, malafide and unjustified action of the Management. According to Bipartite Settlement dated 8-9-83, the stagnation increment is to be granted after 5 completed years of services after reaching the maximum in the scale of pay. Hence it was prayed that the workmen should be granted stagnation increments from the date on which they were actually on ceiling point and not from the date on which the scales of A class Bank were given to them.

4. The contention of the Management is that the award staff in A class banks like the United Bank of India become eligible to get stagnation increment for every 5 completed years after his reaching the maximum in the scale of pay i.e. the respective scales of pay of A class Bank. If a C class bank is taken over by A class bank, an employee of that 'C' class bank who becomes a member of 'A' class Bank cannot claim the stagnation increment after expiry of 5 years on the ground that he reached the maximum of the scale of pay of 'C' class bank at the time of 'take over' as such Award staff is now in the scale of pay of 'A' class Bank. Accordingly the stagnation increment @ 20 per month was released on 22-12-81 in the case of Shri R. P. Sharma and on 1-8-84 in the case of Shri Lal Bahadur, in consonance with agreements between the transferor banks and the transferee bank which were effective from 22-12-73 and 1-8-76. The Management in its written statement has furnished details of the manner in which the fitment and increments of the two workmen were effected and for facility of reference the details are reproduced below verbatim :

"Shri R. P. Sharma now Head Peon, Kharibaoli Branch, United Bank of India was an employee of the erstwhile Hindustan Merchantile Bank Ltd. Hindustan Mercantile Bank Ltd., was taken over by U.B.I. on 22-12-1973 vide an agreement. The details regarding fitment and increment of Shri Sharma after the take over are given hereunder :—

(a) Drew Basic Pay in Hindustan Mercantile Bank Ltd. prior to take over with U.B.I. on 22-12-73 Rs. 161.00 (18th stage i.e. last but one stage).

(b) Placed in U.B.I. Scale on the date of take over i.e. on 22-12-73 at Basic Pay Rs. 161.00 (only 13th stage 7th stages yet due).

(c) Fitted after three years i.e. on 22-12-76 in U.B.I. scale at Basic Pay Rs. 200 (maximum of the scale) with the benefit of 7 increments-4 for past services in erstwhile bank and 3 supra increments for the years 1974, 1975 & 1976.

(d) Had there been no takeover of Hindustan Mercantile Bank Ltd. with U.B.I. then Sri Sharma would have reached the maximum of the scale of pay of the said Bank on 1-9-75 with Basic Pay of Rs. 171 (as per 2nd Bipartite) and would have got stagnation increment @ Rs. 12 on 1-9-80 and his basic pay with stagnation increment on that date would have been Rs. 378+Rs. 12= Rs. 390 (as per 3rd Bipartite).

(e) Shri Sharma cannot be treated to have reached the maximum of U.B.I. scale on 1-9-75 (as would have been in the case of erstwhile Hindustan Merchantile Bank Ltd.) as he was only fitted in the U.B.I. Scale after 3 years on 22-12-76 as per the agreement of take over

(f) As on the date of Bipartite Settlement the rate of Stagnation increment was as follows :—

In 'A' class Bank @ Rs. 20.
In 'B' class Bank @ Rs. 15.
In 'C' class Bank @ Rs. 12

U.B.I. being 'A' class Bank is to release stagnation increment respective to sub staff @ Rs. 20 so one is to complete 5 years after reaching the maximum in U.B.I. scale only for entitlement of stagnation increment @ Rs. 20. Accordingly one stagnation increment @ Rs. 20 per month has been released on 22-12-81.

4. Shri Lal Bahadur, Head Peon, Regional Office, North India Region, U.B.I. was an employee of erstwhile Narang Bank of India Limited. Narang Bank of India Ltd. was taken over by U.B.I. with effect from 1st August, 1976. The details regarding fitment and increment of Shri Sharma after the take over are given hereunder :

(a) Drew Basic Pay in erstwhile Narang Bank of India Ltd. prior to take over by U.B.I. on 1-8-76 Rs. 171.

(b) Placed in U.B.I. Scale on 1-8-76 Rs. 171.

(c) Fitted after 3 years on 1-8-79 in U.B.I. scale at Basic Pay Rs. 200 (Maximum of the scale) with the benefit of 4 increments for his past ser-

vice in the erstwhile Bank and one supra increment for the year 1977 (8.2.77).

(d) He was in the maximum of the scale of erstwhile Bank on 1-8-76 with Basic Pay of Rs. 171. But the maximum of U.B.I. scale was then at Rs. 200 where he was fitted only after three years on 1-8-79. He cannot be treated to have reached the maximum of U.B.I. scale before his fitment on 1-8-79 in U.B.I. Scale. One stagnation increment @ Rs. 20 per month has already been released to Shri Lal Bahadur with effect from 1-8-84.

5. With reference to paragraph 6 of the statement of claim the management denies and disputes all allegations and contents made therein. It is emphatically denied that the action of the management was unjustified in counting the period from the date on..........which the employees were actually on ceiling point of their respective pay scales. However, if 'pay scales' as per Bipartite Settlement is taken that which were on 1-9-75 i.e. Basic pay of Rs. 171 (as per 2nd Bipartite) they would have got stagnation increment @ Rs. 12 Rs. 390 (as per 3rd Bipartite Settlement) and in U.B.I. without getting increment on 1-9-75 for non completion of 5 years after reach the maximum of Bank's scales of pay they drew basic pay of Rs. 455 on 1-9-80 and had gained rather than suffering any monetory loss." Hence the Management justified its action as legal and bona fide.

5. I have carefully examined the pleadings of the parties in the light of the transfer agreements between the transferor banks and the transferee bank and also the Bipartite Settlement and I am of the opinion that the actio taken by the Management is correct and bona fide and there is no question of any malafides on its part. The claim of the workman has no justification in the light of the provisions contained in transfer agreements and the Bipartite Settlements. The details of fitment and increments furnished by the Management speak for themselves and they are quite in accordance with the provisions of the transfer agreements and the Bipartite Settlements. There has been no monetary loss to the workmen and rather they have gained as a result of their fitment into the pay scale of the 'A' class bank like U.B.I. Para 2(B) of the transfer agreement which has been reproduced above makes it clear that the fitment into the new scale of the transferee bank was to be made on the expiry of three years from the execution of those agreement and it was to be done by placing the workman at the stage in the new scale equal to or next above his basic pay as on the date of transfer. In the case of Shri R. P. Sharma the basic pay was fixed from Rs. 161 to Rs. 200 w.e.f. 22-12-76 and in case of Shri Lal Bahadur the basic pay was fixed from Rs. 171 to Rs. 200 w.e.f. 1-8-79 and thus the two workmen got the increment of Rs. 39 and Rs. 29 respectively. As with this fitment, the two workmen reached the maximum of the pay scale on 22-12-76 and 1-8-79 respectively, in terms of the Bipartite Settlement, they became entitled to the Sagnation increment on expiry of 5 years from those dates and tne Management has rightly allowed them stagnation increments w.e.f. 22-12-81 and 1-8-84 respectively.

7. In view of the discussion made above this reference is answered against the workmen and in favour of the Management and it stanrs disposed off accordigly.

G. S. KALRA, Presiding Officer

[No. L-12011|27|85-D.II(A)]

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1989

का. आ. 956.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार हिन्दुस्तान कामर्शियल बैंक (पंजाब नेशनल बैंक) के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 27th March, 1989

S.O. 956.—In pursuance of section 17 of the Industrila Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial Dispute between the employers in relation to the Hindustan Commercial Bank (PNB) and their workmen, which was received by the Central Government.

ANNEXURE

BEFORE SHRI ARJAN DEV PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL KANPUR, UTTAR PRADESH

Industrial Dispute No. 59 of 1987

Sh. Arvind Kumar,
C/o The General Secretary,
All India Hindustan Commercial Bank
Employees Congress,
8/75, Arya Nagar,
Kanpur. Petitioner

AND

The Assistant General Manager,
Punjab National Bank
(Formerly Hindustan Commercial Bank)
Birhana Road,
Kanpur. Opp. Party

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification no. L-12012|26|86-D. IV(A), dt. 11-6-87, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

Whether the action of the management of Hindustan Commercial Bank (Now Punjab National Bank) in terminating the services of Shri Arvind Kumar Gupta, Peon-cum-Watchman from 28-12-79 and again from 20-9-81 is justified ? If not, to what relief the workman concerned entitled ?

2. The industrial dispute on behalf of workman Shri Rajendra Kumar Gupta had been raised by All India Hindustan Commercial Bank Employees Congress (hereinafter referred to as Union for the sake of convenience).

3. The case of the union is that the workman was appointed as peon-cum-watchman, against a permanent vacancy by the management of Hindustan Commercial Bank (hereinafter referred to as Erstwhile Bank) at their Meston Road Branch, Kanpur on 4-1-79, and after he had done work for 268 days his services were terminated w.e.f. 28-12-79. The workman made a number of representation to the management for regularising his services. Thereafter, thereupon he was again appointed as peon-cum-Waterman on 7-7-81, but once again his services were terminated by the management w.e.f. 26-9-81, although the management utilised his services upto 7-10-81. The Union alleges that the service of the workman were terminated in violation of the provisions of section 25F and 25G I.D. Act and also in breach of para 522(4) and (5) of the Shastri Award. The management even did not observe the provisions of section 25H I.D. Act with regard to above named workman. The Union has, therefore, prayed that the workman be reinstated with fullback wages and continuity of service.

4. In its claim statement the Union has also made mention of the fact that HCB was placed under moratorium on 24-5-86 under section 45 of the Banking Regulation Act, 1949, and was ultimately merged with Punjab National Bank

(hereinafter referred to as PNB) through notification dated 18-12-86, of the Central Government.

5. The management in their written statement has admitted the fact of amalgmation of the erstwhile bank with the Punjab National Bank under notification referred to by the Union in the claim statement. According to the management Shri Arvind Kumar Gupta was engaged at Branch Office Chowk, Kanpur of the erstwhile bank as a casual labour for doing certain specific jobs not connected with the banking industry on a daily wage of Rs. 7.50 paisa. Being a casual worker inview of clause 16.69 of the Desai Award he cannot treated as workman under the Industrial Disputes Act, 1947. Other facts alleged by the Union in the claim statement have not been admitted by the management. The management denies violation of any provision of Industrial Disputes Act, 1947 or any breach of para 522(4) and (5) of the Shastri Award.

6. The management further pleads that under the notification dt. 18-12-86, of Ministry of Finance, Government of India, as per scheme of Amalgmation only such employees as were on the rolls of the erstwhile bank would be deemed to have been appointed by the PNB and the PNB as such has no obligation in respect of those who were not in the service of the erstwhile bank on the date of amalgamation. Being so the workman has no claim at all against the PNB.

7. In the rejoinder the Union, alleges that while clause II of para 3 of the amalgamation scheme all the pending legal proceedings of the transferer bank stood transferred to the transferee bank including the present dispute of illegal termination of Shri Arvind Kumar Gupta. Therefore, the averment made by the management to the contrary and wrong. The union has further alleged that the management appointed temporarily some other employees such as Shri Uma Shankar Yadav, Satguru Prasad, Arun Mishra against the same vacancy after the illegal termination of Shri Arvind Kumar Gupta.

8. In support of their case, the management has filed the affidavit of Shri S. K. Pareeda Assistant Manager (Personnel) posted in the Regional Manager's Office, of Punjab National Bank at Kanpur and in support of its case the Union has filed the affidavit of Shri Arvind Kumar Gupta workman concerned of this case. The Union has further relied upon a number of documents in support of its case.

9. In para 3 of his affidavit Shri Arvind Kumar Gupta, has made the averment that the management of erstwhile bank appointed him on 4-1-79 against the permanent vacancy as peon-cum-waterman at Meston Road Branch, Kanpur. Then in para 4 of his affidavit he has alleged that his services were terminated on 28-12-79 after he had worked for 270 days. The number of working days seem to have been inflated by him as in the claim statement the number of working days has been put at 268 days and this is also clear from Annexure II to the claim statement which is sad to the photostat copy of the certificate dt. 26-12-80, issued by the Manager Meston Road Branch Kanpur, of the erstwhile bank. Lastly, in para 7 of his affidavit he has made the averment that on his request the certificate photostat copy of which is Annexure II, was issued to him. The certificate is to the effect that Shri Arvind Kumar Gupta had worked as a casual labour for 268 days from January 1979 to December, 1979.

10. In the written statement although it is stated that Shri Arvind Kumar Gupta, was engaged as casual labour on a daily wage of Rs. 7.50 paisa, it is not admitted that he was appointed as peon-cum-waterman in the aforesaid branch on 4-1-79. In fact nowhere in the written statement the date of his appointment even as casual labour and the date of his termination as such have been given. I therefore, see no reason why the evidence given by Shri Arvind Kumar Gupta, be not believed. The management has deposed the facts stated by Shri Arvind Kumar Gupta by producing an officer of the erstwhile bank who had remained posted as Manager, during the aforesaid period at the said branch

11. I, therefore, find that Shri Arvind Kumar Gupta, was engaged at Branch Office, Meston Road, Kanpur of the erstwhile bank on 4-1-79 and his services were terminated w.e.f. 28-12-79, after he had worked for 268 days.

12. From the evidence on record and the circumstances, it does not appeal to mind that he was engaged/appointed against a permanent vacancy. In his cross examination, Shri Arvind Kumar Gupta, has deposed that during 1979, he had worked on daily wages and he used to get wages on the basis of vouchers. Secondly, the number of days from 4-1-79 to 27-12-79, (if both days inclusive) comes to 358 days when he had actually worked for 268 days. It means that his services were not continuous, but he had worked whenever work was available. Thirdly, it is in the claim statement that no appointment letter was ever issued in the name of Shri Arvind Kumar Gupta. Had he been appointed against a permanent vacancy, he would have surely been issued a letter of appointment. The only conclusion therefore that can be drawn that he had worked in the said branch of the erstwhile bank temporarily either as temporary workman or as a casual labour. So far as this case is concerned it is quite immaterial whether he had worked as casual labour or as a temporary workman. Since he had worked for more than 240 days in a year within the meaning of section 25B I.D. Act, his termination w.e.f. 28-12-79 was void abinitio as he was not paid retrenchment compesation nor he was given any notice or notice pay as required by Section 25F I.D. Act. Hence, the action of the management of erstwhile bank in terminating his services w.e.f. 28-12-79 cannnot be held as justified.

13. Shri Arvind Kumar Gupta, has then deposed in his affidavit about his retrenchment on 7-7-81 and his termination w.e.f. 26th September, 1981 making a further averment that he actually served the bank upto 7th October, 1981. This fact that despite termination of his services w.e.f. 26th September, 1981, he had worked upto 7-10-81 does not appeal to mind.

14. Annexure IV of the claim statement is photostat copy of a certificate dt. 15-11-84 issued by the then branch manager Meston Road Branch, Kanpur, of the erstwhile bank. This document has been admitted by the authorised representative for the management. From the certificate it appears that Shri Arvind Kumar Gupta, had actually worked for 59 days as a casual labour beginning from 7-7-81 to 26-9-81.

15. Since, the earlier termination has been held illegal and unjustified by me the question of considering the illegality or legality, justification or non justification of the second order of termination does not arise.

16. Shri Arvind Kumar Gupta is therefore, held entitled to reinstatement with back wages Wages to be calculated at the rate at which he was getting at the time of his termination on 28-12-79 and on his furnishing an affidavit to the effect that he was not gainfully employed during the said period any where else he will not be paid for the days during which he had worked ond paid from 7-7-81 to 26-9-81.

17. Reference is answered accordingly

ARJAN DEV Presiding Officer.
[No. L-12012|26|86-D. IV(A)]

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1989

का. आ. 957.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 12th April, 1989

S.O. 957.—In pursuance of stction 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Indus-

trial Tribunal Kanpur as shown i ntre Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Punjab National Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 4-4-89.

ANNEXURE

BEFORE SHRI ARJAN DEV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 153 of 1988

In the matter of dispute between :

Shri Harmangal Prasad
Sahayak Maha Sachiv,
U.P. Bank Employees Union,
36|1, Kailash Mandir,
Kanpur. .. Petition

AND

1. Regional Manager,
Punjab National Bank,
The Mall,
Kanpur. ... Opp. Party

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification no. L-12012|175|88-D. II(A) dt. 24-11-88 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

Whether the action of the management of Punjab National Bank in reverting Shri G. P. Rudela for the post of Cashier|Clerk to the post of peon w.e.f. 16-10-85 is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?

2. In the instant case first date was for filing statement of claim from the side of the workman was 14-12-88. On 14-12-88 none appeared from the workman's side nor any claim statement was filed. However the case was adjourned to 13-1-89 and then to 16-2-89 but on both these dates none appeared nor any statement of claim was filed by the workman.

3. In the circumstances it is clear that neither workman nor his union is interested to prosecute the case.

4. A no claim award is given in the instent case.

ARJAN DEV, Presiding Officer
[No. L-12012|175|88-D. II(A)]

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1989

का. आ. 958.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार विजया बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 2, बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 31-3-89 को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 13th April, 1989

S.O. 958.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Bombay as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Vijaya Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 31-3-89.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No CGIT-2/6 of 1987

PARTIES :

Employer in relation to the management of Vijaya Bank.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employer—Shri R. K. Shetty, Advocate.

For the Workmen—Shri M. B. Anchan, Advocate.

INDUSTRY : Banking STATE : Maharashtra

Bombay, the 9th March, 1986

AWARD

The Central Government by ther Order No. L-12012|24/86 D.IV (A) dated 16-1-1987 have referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 :—

"Whether rejection of 18 days leave from 4-5-1983 to 21-5-1983, curtailment of service benefits to Shri Vijay A. Shetty, Clerk of Vijaya Bank, Colaba by the management of Vijaya Bank, Bombay is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

2. The case of the workman Shri Vijay A. Shetty, as disclosed from the claim statement (Ex. W/3) filed by the Vijaya Bank Workers Organisation, in short, is thus :—

The workman Vijay A. Shetty was working as a Clerk in the Colaba Branch of the Vijaya Bank in March/April, 1983. His marriage was to take place and the necessary engagement ceremony was also to take place. Hence on 27-4-1983 he submitted an application seeking leave from 4-5-1983 to 21-5-1983. The reason given in the said application was urgent work or personal work. Before the said period he had hardly taken any leave, and he was a hard worker in the Bank. At the time he applied for leave, 143 days privilege leave was at his credit. On 3-5-1983 he submitted a letter to the Bank stating that he was presuming that his leave was sanctioned. He resumed his duty after expiry of leave on 22-5-1983. About ten months thereafter, the Personnel Manager of the Bank by his letter dated 20-2-1984 asked for his explanation stating why disciplinary action should not be taken against him. The workman by his reply dated 16-3-1984 refutted all the allegations made against him in that letter. Thereafter the Personnel Manager of the Bank by his letter dated 26-4-1984 informed Shri Shetty that his absence of 18 days during the period from 4-5-1983 to 21-5-1983 was treated as unauthorised absence, and that he was not granted any pay of that period. Thereafter the matter was referred to the Regional Labour Commissioner (C), Bombay. As it ended in failure, the Central Government made the reference as above. The said Workers Organisation lastly prayed that the action of the Bank in rejecting the leave of the said workman for 18 days be held unjustified, and that the workman be granted leave of the said period and he also be granted the necessary pay etc. of that period.

3. The Divisional Manager of the Vijaya Bank, Bombay, by his written statement (Ex. M/4) resisted the claim of the said workman and in substanced contended thus :—

The said workmen Shri Vijay A. Shetty while working at the Colaba Branch if the Bank had applied on 27-4-1983 for 18 days privilege leave with effect from 4-5-1983 to 21-5-1983. Para 13.2 of the Biparties Settlement dated 19-10-1986 provided that such application should be made not less than one month before the date on which the leave is to commence. However, the said workman had sub-

mitted the application only four days before the proposed leave period. That application was inwarded in the register on 29-4-1983. The reason mentioned in the application was 'visit to native place'. It was not mentioned in that application that the leave was for his marriage or engagement. As no sufficient notice was given by the workman to the Bank as per para 13.2 of the Bipartite Settlement, the Senior Manager of the Colaba Branch of the Bank rejected the leave application of the workman in terms of para 13.6 of the Bipartite Settlement. The Order of rejection of that application was communicated to that workman orally in the afternoon of 29-4-1983, and again on 3-5-1983 at about 4.45 P.M. by the Officer-in-1charge Shri Sudhama S. Shetty in terms of para 13.5 of the said settlement. In spite of the said oral communication regarding the rejection of leave to the workman on the said two occasions, the said workman Shri Vijay A. Shetty put in a letter dated 3-5-1983 which was received by the Bank on 4-5-1983 at 10.45 A.M.

(ii) The Bank thereafter contended thus :—

The workman wanted to see the remarks of the Senior Manager on his leave application dated 27-4-1983 and the Senior Manager's remarks on that leave application were permitted to be read by the workman by the Officer-in Charge of the Bank. The workman, instead of reading the said remarks regarding the rejection of leave and returning the said application to the said Officer, took it away in the evening of 3-5-1983 and never returned the said application to the Bank. The workman unauthorisedly remained absent from 4-5-1983 to 21-5-1983 i.e. for 18 days. Thereafter, the said workman repeatedly made representations to the Bank through the Union to regularise the unauthorised absence of 18 days. The Bank found it extremely difficult to regularise the said unauthorised absence having regard to the misconduct committed by the workman in mischieviously taking away the leave application on which the order of rejection was passed by the superior Officer.

(iii) The other contentions of the Bank are thus :—

The allegation of the workman that he was to be married and the engagement ceremony was to take place between 4-5-1983 to 21-5-1983, is not true and correct. This is only an after-thought statement with a view to seek sympathy from this Tribunal. The reason mentioned in the leave application was 'visit to native place'. In his another application, the reason for the leave mentioned by him was 'urgent work'. As per the provisons contained in para 13.6 of the Bipartite Settlement, no leave of any kind can be claimed as of right. Therefore, it was not proper on the part of the workman to presume that the leave would be sanctioned. The workman unauthorisedly remained absent for 18 days, and thereafter the matter was referred by the Colaba Branch to the Divisional Office who in turn referred the matter to the Zonal Office. The Zonal Office in turn referred it to the Head Office and hereafter an explanation was called for by the Personnel Manager, Head Office. During this process, a period of nine months had elapsed, and such a period was natural and no prejudice thereby was caused to the workman, by asking for his explanation nine months after the date of rejection of the application. Remaining absent after the rejection of leave by the Bank management amounted to misconduct on the part of the said workman. However, the bank was lenient only by not paying the salary of the said period of 18 days, and by not taking any further disciplinary action against him. In case the misconduct of the workman in the present case is rewarded by regularisation of his unauthorised absence, it will be difficult to maintain discipline in an institution like the Bank which belongs to the Nation. The Bank, therefore, for the said reasons, prayed for the dismissal of the prayer of the workers' Organisation.

4. The Issues framed at Ex. 5 are :—

1. Whether the action of the Senior Manager of the Colaba Branch of the Vijaya Bank in rejecting the leave application of the worker Shri V. A. Shetty in terms of para 13.6 of the Bipartite Settlement dated 19-10-1966, was just and proper ?
2. Wheher the said Bank proves that the order of rejection was communicated to the said workman orally on 29-4-83, and again on 3-5-1983 by Shri Sudhama S. Shetty, Officer-in-Charge in terms of para 13.6 of the said settlement ?
3. Whether the Bank proves that after the workman was allowed to read the remarks of Senior Manager rejecting his request for the leave, the workman, instead of returning back the said application, took it away with him in the evening of 3-5-1983, and never returned it back to the Bank ?
4. Whether the workman proves that on 3-5-83, he had sent a letter to the Bank stating that he was presuming that his leave was granted ?
5. Whether the workman had unauthorisedly remained absent for 18 days from 4-5-1983 to 21-5-1983 ?
6. Whether rejection of 18 days leave from 4-5-1983 to 21-5-1983, curtailment of service benefits to Shri Vijay A. Shetty, Clerk of Vijaya Bank Colaba by the management of Vijaya Bank, Bombay is justified ?
7. If not, to what relief is the workman entitled ?
8. What Award ?

5. My findings on the said Issues are :—

(1) No
(2) No
(3) No
(4) Yes
(5) No
(6) No
(7) As per the award
(8) As per below.

REASONS

Issue No. 1

6. In this case, Smt. N. Nagarajan, the then Branch Manager of the Colaba Branch of Vijaya Bank, Bombay, filed her affidavit in support of the contention of the Bank at Ex. M-6. She was cross-examined on behalf of the workers' Organisation. The workman Shri Vijay Shetty filed his affidavit in support of the contentions of the Workers' Organisaion at Ex. 14. He was also cross-examined on behalf of the Bank management. It is an admitted fact that the workman Shri Vijay Shetty had submitted his application for leave in 27-4-1983 while he was working as a Clerk in the Vijaya Bank, Colaba Branch, for leave from 4-5-1983 to 21-5-1983, i.e. for a period 18 days. According to the Bank management, as per the terms of Bipartite Settlement, leave application should be presented by a employee 30 days before the date on which the proposed leave starts. In the present case, the leave application was presented by the said workman only a week before the starting of the leave period. Therefore, according to Smt. Nagarajan, she was justified in rejecting that leave application. However, she has admitted in her cross-examination that the Bank sanctions the leave even with short notice from the employees. The workman applied for leave for some urgent personal work. Therefore, the action of the said officer in rejecting the leave application of the said workman on the ground that it was not presented one month before the date of starting of the leave period, is not just and proper. Issue No. 1 is answered in the negative.

Issues Nos. 2, 3 and 4

7. The then Branch Manager Smt. Nagarajan stated in her affidavit that she had rejected the said workman's application for Leave dted 27-4-1983 to 29-4-1983, and that the said rejection order was shown to the workman on the

29th itself, by Shri Sudama Shetty, the superior Officer of Shri Vijaya Shetty. She further stated in her evidence that the said rejection order was again shown by Shri Sudama Shetty to the workman Shri Vijay Shetty on 3-5-1983. According to the workman Shri Shetty, after he submitted the leave application on 27-4-1983, he was not at all informed anything by anybody about the rejection or granting of the leave, and hence he submitted one more application dated 3-5-1983 (Ex. M/9) stating that as he had not received any communication regarding the order passed on his leave application he was presuming that his leave was sanctioned. Further, the case of the Bank management is that after the workman Shri Vijay Shetty was allowed to read the order of rejection of his leave application, he took it with him and did not return it back to the superior officer Shri Sudama Shetty. Now, this superior Officer Shri Sudama Shetty has not been examined as a witness in this case on the ground that he is not in the service of the Bank, and his present whereabout are not known. Admittedly the then Branch Manager Smt. Nagarajan, herself had not told anything to the workman Shri Vijay Shetty about the granting or rejecting of his leave application. Therefore, her evidence that Shri Sudama Shetty had shown the workman the endorsement on his leave application regarding the rejection of leave, cannot be safely read in evidence.

8. Smt. Nagarajan, the then Branch Manager, herself stated in her affidavit that one another clerk by name Shri Rai had seen the workman Shri Vijay Shetty taking away the original application with him on 3-5-1983, when he left the office. Therefore, even though Shri Sudama Shetty was not available for giving evidence before this Tribunal, this other witness Shri Rai should have been examined as a witness on the said pointed on behalf of the Bank Management. Therefore, the case of the Bank management that the workman Shri Vijay Shetty had taken away the original leave application with the endorsement of rejection thereon by the Branch Manager, cannot at all be accepted.

9. Admittedly, the workman Shri Vijay Shetty was in service of the Vijaya Bank from March, 1974, and as such he had put in nine years of service in 1983, when he had applied for 18 days leave. Further, it is also an admitted fact that privilege leave as much as 143 days was then at his credit. Therefore, it is highly improbable that a senior employee like the present workman having 143 days privilege leave at his credit, would take away the original leave application. It is an admitted fact that when a workman presents his leave application, the counterfoil of the application form with the endorsement by the superior officer regarding the granting or rejecting of the leave, is given to the workman concerned. There seems to be no reason why the counterfoil of the original leave application stating that his request for leave was rejected, was not given to the workman immediately. The conduct of the workman in presenting one more application dated 3rd May, 1983 (Ex. M-9) stating that he was presuming that his leave was sanctioned, is consistent with the circumstance that the rejection or otherwise of his leave was never communicated to him till then, i.e., till he presented a fresh application as above.

10. In case the workman Shri Vijay Shetty had really taken away the original leave application, some disciplinary action would have been taken by the Bank management against him immediately after he resumed his duty. He resumed his duty on 22nd May, 1983. It is an admitted fact that he was not asked by anybody either orally or in writing immediately about his alleged unauthorised absence of 18 days. The show cause notice was issued to him for the first time by the Personnel Manager on 20th February, 1984, i.e., about nine months after he resumed his duty after enjoying 18 days leave. The action taken by the Bank management nine months after his resuming duty does not appear natural. The superior Officer at the Branch of the Bank would have in the ordinary course asked for his explanation after the workman resumed his duty on 22nd April, 1983 in case he had remained absent without the leave being sanctioned.

11. Ex. M|12 is a copy of the Office Note stating job rotation amongst the employees of the Branch. This is dated 14-1-1983 i.e. two months prior to the application if Shri Vijay Shetty for his leave. It is seen from S. No. 11 of this Note that the workman Shri Vijay Shetty was allotted certain another work from the next day i.e. from 15-1-1983. It is further seen that the workman Shri Vijay Shetty had made an endorsement thereon that he was accepting that allotment Note 'under protest'. He further stated that, "Allotment of Dept. biased representation follows". According to the workman, the Bank management, after he submitted his leave application, created some false documents against him. It seems that because of some disputes in the internal management of the Bank, the present case came to be placed before the judicial authority i.e. the present Tribunal. A reference may be made to some other letters produced in this proceeding. Ex. M-8 is a Zerox copy of the Confidential letter dated 5-5-1983 from the then Senior Manager Smt. Nagarajan addressed to the Asstt. General Manager, Divisional Office Bombay, stating that she had rejected the workmen's application for leave on 29-4-1983, and that the rejection order was communicated by the superior officer Shri Sudama Shetty to the workman. Shri Sudama Shetty filed a letter dated 4-5-1983 (Ex. M-10) informing the Senior Manager, Colaba Branch, Bombay, that he had informed the workman Shri Vijay Sheety about the rejection of leave application, and Shri Vijay Shetty had then taken away that leave application Ex. M-11 is zerox copy of the letter of the superior Officer Shri Sudama Shetty addressed to the Personnel Manager of the Bank at Head Office, Bangalore, dated 21-3-1984, regarding the incident in question. However, for the above said reasons, I am unable to accept the say of the Bank management that the order of rejection was communicated to Shri Vijay Shetty by the superior Officer Shri Sudama Shetty, or that the workman Shri Vijay Shetty had taken away the original leave application with him and did not return it back to the Bank. Issues 2 and 3 are, therefore, found in the negative, while issue No. 4 is found in the affirmative.

ISSUES NOS. 5, 6 and 7

12. It is true that no leave can be claimed as of right. However, as noted above, the workman Shri Vijay Shetty had 143 days privilege leave at his credit then. There is nothing on record to show that he used to take the leave often and again in the past without any sufficient reason. He had put in nine years of service. It is true that as per the rules of the Vijay Bank, one month's notice by the employee before the date of his proposed leave, is essential. However, the witness Smt. Nagarajan admitted in her cross-examination that leave can be granted with short notice also. According to the workman, he had applied for leave on the ground of his urgent personal work. According to Smt. Nagarajan, the then Branch Manager of the Bank, she had rejected the leave application on the ground of administrative exigencies. An attempt was made to show that as other persons were than on leave, on administrative grounds, the leave could not be granted to the workman Shri Vijay Shetty. The workman Shri Vijay Shetty had applied for leave from 4-5-1983 to 21-5-1983. He had applied one week before the day of the proposed leave. The original muster-rolls of the Branch were shown to the workman Shri Vijay Shetty in his cross-examination. Thereafter he stated thus :

> Shri Nachiappan was on leave from 18-5-1983 to 31-5-1983. Peon Shri Manjulal Prabhu was on leave from 9-5-1983 to 20-5-1983. An Officer Shri Geeta Bhandari was on leave from 1-5-1983 to 25-3-1983 and one Shri Ratnagar Achari was on deputation and was not on duty in that Branch from 1-5-1983 to 31-5-1983. Thus, some other persons were on leave during the leave period of the workman Shri Vijay Shetty.

However it will be seen that only one person of the category of the workman, i.e. Shri Nachiappan was on leave from 18-5-1983 to 31-5-1983. It is, thus, quite clear that during the proposed leave period of the said workman practically no employee of the category of the workman in question, was on leave, and as such I find that there was absolutely no good ground to reject the said leave application of the workman in question. The work of the workman was not to suffer due the absence of officers and peons who were then on leave. I, therefore, find that the action of the Bank management in rejecting the leave application of the workman Shri Vijay Shetty, and the curtailment of service benefits etc. by the Bank management, was not just and proper. As such, the said workman had not unauthorised by remained absent during the said period of 18 days. Therefore, Issues Nos. 5 and 6

are answered in the negative. Therefore, the workman Shri Vijay Shetty is entitled to get pay and other service benefits of the said leave period. Issue No. 7 is found accordingly.

ISSUE NO. 8

13. Trerefore, the following award is passed.

AWARD

(i) The action of the management of Vijay Bank, Colaba Branch, in rejecting the leave application of the workman Shri Vijay Shetty for his leave from 4-5-1983 to 21-5-1983, and the curtailment of his service benefits etc. is not just and proper. The Bank management is therefore directed to sanction his said leave and to pay the workman the necessary pay and other service benefits of the said period within two months from the date of the publication of this Award in the Government of Gazettee.

(ii) The Bank management is further directed to pay interest on the amount that will be found due to the said workman from the date it is found due till the payment, at Rs. 9|- per cent per annum.

The parties to bear their own costs of this reference.

P. D. APSHANKAR, Presiding Officer

[No. L-12012|24|86-D. IV(A)]

N. K. VERMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1989

का. आ. 959.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार व भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्धतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चण्डीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 6-4-89 को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 12th April, 1989,

S.O. 959.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 6-4-89.

ANNEXURE

BEFORE SHRI M. S. NAGRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT., INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. I. D. 62|88

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Food Corporation of India,

AND

Their Workman : Ganga Saran.

APPEARANCES :

For the Workman : None.

For the Management : Sh. N. K. Zakhmi.

INDUSTRY : F.C.I. STATE : Punjab

AWARD

Dated 28-3-1989

On a dispute raised by workman of Food Corporation of India, Central Government had been pleaded to make the following reference Vide No. 42012|137|87-D. II. B|D. IV(B) dated 1st August, 1988 to this Tribunal :

"Whether the action of the Senior Regional Manager (Pb) Chandigarh in dismissing Shri Ganga Saran, Dusting Operator from service w.e.f. 1-4-1986 is legal and justified ? If not, to what relief the workman concerned is entitled ?"

2. None has put up appearance on behalf of the workman. Workman was represented on the last date by Sh. P. K. Singla when the proceedings were adjourn from 22-2-89 for today i.e. 16-3-1989. Reference proceedings are therefore, filed for want of Prosecution. Central Govt. be informed accordingly.

Chandigarh,
28-3-1989.

M. S. NAGRA, Presiding Officer

[No. L-42012|137|87-D. II-B|D. IV(B)]

का. आ. 960.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार व भारतीय खाद्य निगम, बम्बई के प्रबन्धतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-4-89 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 960.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India, Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on the 5-4-1989.

P. D. APSHANKAR, Presidig Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI P. D. APSHANKAR, PRESIDING OFFICER. THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2 BOMBAY

Reference No. CGIT-2|26 of 1988

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Food Corporation of India, Bombay.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers.—Shri B. M. Masurkar, Advocate.

For the Workman.—Shri Manohar Kotwal, Secretary, Transport & Dock Workers' Union.

Industry : Food Corporation State : Maharashtra

Bombay, dated the 28th March, 1989

AWARD

The Government of India by their order No. L-42012|81|86-D. II.B|D. IV(B) dated 10-8-1988 have referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act :—

"Whether the action of the management of Food Corporation of India Bombay in relation to its Manmad Depot at Manmad in denying regular posting of a staff car driver to Shri P. H. More, a watchman working in the Manmad Depot of Food Corporation of

India, Bombay, is justified ? If not, to what relief the workman concerned is entitled ?"

2. The case of the Transport and Dock Workers' Union, of which the workman Shri P. H. More is a member, as disclosed from its statement of claim (Ex. 2|W), in short, is thus :—

The workman Shri P. H. More, an ex-Serviceman, was appointed as a Watchman by the Food Corporation of India at their Manmad Depot in October, 1968. As he was holding the driving Licence, he was also called upon often and again to work as a Staff Car Driver. He worked as a Staff Car Driver often and again from October 1976 to September 1980. He was always being paid an extra allowance of Re. 1 per day for the additional work performed by him. He was also promised by the Regional office, Bombay, as well as the Local Officers of the Food Corporation of India that his case would be considered for the permanent post of Staff Car Driver as and when there is a vacancy. His performance as Staff Car Driver was quite satisfactory. However, in spite of the promises given by the Officers, his request for the post of regular Staff Car Driver to a permanent vacancy, even though available, was ignored, to his great surprise and shock. He was informed by the Corporation on 25-6-1984 that he was not found suitable for the post of Staff Car Driver and that he was not within the age limit|Educational qualification required for the post.

3. The Union further alleged that the said workman Shri P. H. More, being an ex-serviceman, deserves special consideration in the light of guidelines issued by the Government of India for Ex-Serviceman. He worked as a Staff Car Driver for six years often and again and he was found fit for the said work. In case his request for the post of Staff Car Driver would have been considered at the relevant time whenever he applied, the question of overage would not have arisen. Further, he was already in service and within the age limit at the time of recruitment. The Union, therefore, prayed that the Food Corporation of India be directed to give regular posting of Staff Car Driver to Shri P. H. More with retrospective thus :—

4. The Regional Manager of the Food Corporation of India by his written statement (Ex. 7|M) resisted the claim of the Union, and in substance contended thus :—

The Transport and Dock Workers' Union cannot represent the workman as the workman Shri P. H. More belongs to the category of Watchman and he is not a dock worker, while the Union is a union of Dock Workers and Transport Workers. No industrial dispute exists between the said workman and the management. The Central Government has no jurisdiction to refer the matter for adjudication and this reference is illegal and without jurisdiction. The said workman has been appointed as a Watchman in Manmad Depot from October, 1968. It is not true that he was asked to work as a Staff Car Driver from October 1976 to September 1980. In fact he was asked to work as Staff Car Driver from April 1976 to May, 1978, not continuously, but on certain occasions. Whenever he was asked to work as a Staff Car Driver he was paid adequately at the rate of wages applicable to the Staff Car Driver. No promise was given to the workman for considering him for the permanent post of Staff Car Driver as the selection was to be made according to the recruitment rules laid down in that behalf which have prescribed age limit. Further, the Staff Car is out of function since July, 1984 being road unworthy till this date, and hence no question of recruitment of anybody to that post survives. As per the Food Corporation of India Staff Regulations, the said workman was not found eligible for selection for the post of Staff Car Driver. There is no provision in the Staff Regulations of the Food Corporation of India for relaxation of the age limit in respect of ex-serviceman. Further, there is no vested right in law to be posted to the higher post, even if one is fully qualified for such higher post. The claim of the Union is outside the jurisdiction of this Tribunal. As such this Tribunal s not competent to grant any relief to the said workman. The Food Corporation of India lastly prayed for the rejection of the demand of the Union made on behalf of the said workman.

5. The Issues framed at Ex 11 are :—

(1) Whether the management of the Food Corporation of India proves that the Transport & Dock Workers' Union, Bombay is not competent to espouse the present cause on behalf of the workman Shri More ?

(2) Whether no industrial dispute exists between the said workman and the said management ?

(3) Whether the action of the management of Food Corporation of India, Bombay in relation to its Manmad Depot at Manmad in denying regular posting of a staff car driver to Shri P. H. More, a watchman working in the Manmad Depot of Food Corporation of India, Bombay is justified ?

(4) If not, to what relief the workman concerned is entitled ?

(5) What Award ?

6. My findings on the said issues are :—

(1) No

(2) Industrial dispute exists

(3) No

(4)

(5) As per the Award below.

REASONS

ISSUE NO. 1

7. In this case, no oral evidence was led on behalf of either of the parties. The parties submitted their written arguments. According to the management of

Food Corporation of India, the Transport and Dock Workers' Union is not competent to espouse the present cause of the workman Shri More. However, I find that this Union is competent to espouse the cause on behalf of the Watchman Shri More. A copy of the constitution of the Transport and Dock Workers' Union has been produced on behalf of the Union at Ex. 10|W It will be seen from this document that the aims and objects of that Union are to organise and unite the different kinds of workmen including all those working in medical, canteen and other Welfare Departments conducted directly or indirectly by the Port Trust, Dock Labour Board, FCI and other industries in the State of Maharashtra. Admittedly, the workman Shri More is working as a Watchman at Manmad Depot of the Food Corporation of India. As he is working as a Watchman at Manmad Depot, his work is not restricted only to a particular department of the F.C.I. Therefore, according to me, he falls under the category of the employees contemplated under the constitution of the said Union. Further, the aims and objects of the Union are to secure to the members fair conditions of work and service, and redress their grievances and to endeavour to settle all kinds of disputes between employers and employees amicably In the present case, the dispute is between the employer and the employee regarding the posting of the workman as a regular Staff Car Driver The said Union has taken the necessary steps in the matter, and is moving the management in the matter. Therefore, I find that the said Union is quite competent to espouse the present cause on behalf of the workman Shri P. H. More. Issue No. 1 is found in the negative

ISSUE NO. 2

8. According to the F.C.I., no industrial dispute exists between the said workman and the management I find that it is not so. Admittedly there is a dispute between the said workman and the management regarding the posting of that workman as a regular Staff Car Driver. The management is not prepared to accept the said demand of the workman. Therefore, I find that an industrial dispute as contemplated under Section 2(k) of the Industrial Disputes Act exists between the said management and the workman Issue No. 2 is found accordingly.

ISSUES NOS. 3 AND 4

9. It is an admitted fact that even though Shri More was working as a Watchman at Manmad Depot. from October 1976 to September 1980 he was being asked on certain occasions to work as a Staff Car Driver. According to the management, as his case did not fall within the prescribed age limit and the educational qualifications he could not be considered for the post of a regular Staff Car Driver. From the material on record it is not known as to what age limit or the educational qualifications are necessary for the post of a regular Staff Car Driver. Ex. 3|W is a copy of the Office Order dated 5-10-1976 issued by the District Manager of the Food Corporation of India. It will be seen from this Office Order that the workman Shri More, even though he is working as a Watchman, was posted to work as a Staff Car Driver vice Shri M. S. Pagare, who was reverted as a Watchman. It is clear from the said Office Order dated 5-10-1976 that the workman Shri More was posted as a Staff Car Driver by reverting the previous Staff Car Driver. It may be noted that even though the workman Shri More was not within the prescribed age limit, and did not possess the necessary educational qualifiactions in 1976, he was considered for promotion to the post of Staff Car Driver by the District Manager of the F.C.I. Ex 4|W is a copy of the Certificate issued by the District Manager of the F.C.I. This certificate states that the workman Shri P. H. More has been working as Watchman with effect from 19-8-1968 and is handling the staff car as Watchman|Driver with effect from 5-10-1976 and that his performance as a Driver is quite satisfactory. Admittedly the workman Shri More worked as a Staff Car Driver atleast since 1976 till the date of the certificate i.e. 20-9-1980 and that his performance was quite satisfactory. It will be seen from the copy of the application dated 3-2-1983 (Ex. 5|W-collectively) of the workman Shri More for the post of Staff Car Driver, that his date of birth was 1-12-1943 and was educated upto Vth Standard. Thus, in 1976 when he was appoitned as a Staff Car Driver, he was about 33 years of age. As per the Food Corporation of India (Staff) Regulations (Ex. 8|M), the age limit in the case of departmental candidates is relaxable by five years. By the Memo. dated 25-6-1984 (Ext. 6|W) the Assistant Manager (Establishment) had informed the workman Shri More that as he did not fulfil the conditions regarding age limit and educational qualifications prescribed for the post of Driver, his request for appointment to the post of Driver could not be considered. As noted above, the workman Shri More was, in spite of the said deficiencies if any, was appointed as Car Driver from 1976 to 1980, and his work was found satisfactory. By the letter dated 3-9-1976 (Ex. 14|W), the District Manager of F.C.I. had informed the workman Shri More that his request for the post of Staff Car Driver was carefully considered but could not be acceded to for want of vacancy and that his case would be considered along with the Employment Exchange candidates, when there will be appointment of Staff Car Driver anywhere in this region. Thus, for want of vacancy, as per this letter, his request for the post of Staff Car Driver could not be considered by the F.C.I.

10. Even though the workman Shri More could not be posted as a regular Staff Car Driver till 1980 because of his age limit and educational qualifications, it is important to note that in October, 1982 he was again posted as a Staff Car Driver by the Office Order dated 25-10-1982 (Ex. 15|W). By this order the Staff Car Driver Shri Sakpal was transferred to Bombay, and he was asked to hand over the charge of the vehicle in question to the present workman Shri More. Thus, even in 1982, the Workman Shri More was found suitable for the post of Driver. It is further seen that the transfer of Shri Sakpal was cancelled and hence the workman Shri More could not continue working as a Driver (Ex. 16|W). Even then the fact remains that in 1982 the workman Shri More was considered for the post of Car Driver of F.C.I. Therefore, for the above reasons, I find that the action of the Food Corporation of India in refusing to post the workman Shri More on regular basis as Staff Car Driver, is not just and proper. Issue No. 3 is found in the negative

11. It is urged on behalf of the Food Corporation of India that the Staff Car at Manmad Depot is not

in working condition since 1984, and as such no question of posting anybody as a regular Staff Car Driver of that Vehicle survives. Even then the relief that can be granted to the workman Shri More is that he is entitled to the post of regular Staff Car Driver as soon as the Car becomes available at Manmad Depot. Issue No. 4 is found accordingly.

ISSUE NO. 5

12. The following award, therefore, is passed.

AWARD

(i) The action of the management of Food Corporation of India, Bombay in relation to its Manmad Depot at Manmad in denying regular posting of a Staff car driver to Shri P. H. More, Watchman working in the Manmad Depot is not just and proper.

(ii) The management of the Food Corporation of India is directed to appoint the workman Shri More as a regular Staff Car Driver at Manmad Depot as soon as the vehicle becomes available at that Depot.

The parties to bear their own costs of this reference.

P. D. APSHANKAR, Presiding Officer
[No. L-42012(81)|86-D.II.B|D.IV(B)]

का. आ. 961.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार व भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चण्डीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 6-4-89 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 961.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 6-4-89.

ANNEXURE

BEFORE SH. M. S. NAGRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH

CASE No. I.D. 61|88

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Food Corporation of India.

AND

Their Workmen : Jaswant Singh.

APPEARANCES :

For the Workman : None.

For the Management : Sh. N. K. ZAKHMI.

INDUSTRY : F.C.I. STATE : Punjab.

AWARD

Dated, the 28th March, 1989

One a dispute raised by workman of Food Corporation of India, Central Government had been pleased to make the following reference Vide No. L-42012|125|87-D.II(B) dated 3rd August, 1988 to this Tribunal.

"Whether the action of the Management of Food Corporation of India represented by Managing Director F.C.I. New Delhi and Zonal Manager(N) New Delhi and Senior Regional Manager Chandigarh in dismissing Shri Jaswant Singh Chowkidar w.e.f. 12-3-1986 is justified ? If not, to what relief is the workman entitled to and from what date ?"

2. None has put up appearance on behalf of the workman. Workman who was represented on the last date by Shri P. K. Singla when the proceedings were adjourn from 22-2-89 for today i.e. 16-3-1989. Reference proceedings are therefore filed for want of prosecution. Central Government be informed accordingly.

Chandigarh.

28-3-1989.

M. S. NAGRA, Presiding Officer
[No L-42012(125)|87-D.II(B)]

का. आ. 962.—औद्योगिक विवाद अ-अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार व भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चण्डीगढ़, के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 6-4-89 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 962.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 6-4-89.

ANNEXURE

BEFORE SH. M. S. NAGRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,

CHANDIGARH

Case No. I.D. 53|88

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Food Corporation of India.

AND

Their Workman : Nand Kishore and Others.

APPEARANCES :

For the Workmen : None.

For the Management : Sh. N. K. ZAKHMI.

INDUSTRY : F.C.I. STATE : Punjab.

AWARD

Dated, the 28th March, 1989

On a dispute raised by workmen of Food Corporation of India, Central Government had been plead-

ed to make the following reference Vide No. L-42011|3|88-D.II.B.D.IV(B) dated 29th July, 1988 to this Tribunal :

"Whether the action of the management of Sr. Regional Manager, Food Corporation of India, Punjab, Chandigarh in denying the change of cadre from Typist to A.G. III-(D) to S|Sri Nand Kishore, Vidya Bhusan, Nazir Singh, Roshan Lal, Subhaschandra and Mahendra Pal Singh, Typists, is justified?" If not, to what relief the workmen concerned are entitled and with what effect?'

2. None has put up appearance on behalf of the workmen. Workmen who were represented on the last date by Shri P. K. Singh when he proceedings were adjourn from 22-2-89 for today i.e. 16-3-1989. Reference proceedings are therefore, filed for want of presecution. Central Government be informed accordingly.

Chandigarh.

28-3-1989.

M. S. NAGRA, Presiding Officer.
[No. L-42011(3)|88-D.II.B|D.IV(B)]

का. आ. 963.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार व भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चण्डीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 6-4-89 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 963.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 6-4-89.

ANNEXURE

BEFORE SH. M. S. NAGRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. I. D. 57|88.

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Food Corporation of India.

AND

Their Workman : Yaduwansh Yadav.

APPEARANCES :

For the Workman—None.

For the Management—Sh. N. K. Zakhmi.

INDUSTRY : F.C.I. STATE : Punjab.

AWARD

Dated, the 28th March, 1989

On a dispute raised by Workman of Food Corporation of India, Central Govt. had been pleaded to make the following reference Vide No. L-42011|31|87-D. II. B|D.IV(B) dated 2nd August, 1988 to this Tribunal.

"Whether the action of the Management of Food Corporation of India represented by the Managing Director, Zonal Manager (N), the Senior Regional Manager Punjab in not allowing seniority at S. No. 984 by counting continuity of service w.e.f. June 1971 and not granting increment from the said date of June 1971 to Sri Yaduwansh Yadav Watchman is justified ? If not, to what relief the workman is entitled and from what effect" ?

2. None has put up appearance on behalf of the workman. Workman who was represented on the last date by Shri P. K. Singla when the proceedings were adjourn from 22-2-89 for today i.e. 16-3-1989 Reference proceedings are therefore, filed for want of prosecution. Central Govt. be informed accordingly.

Chandigarh.

28-3-1989.

M. S NAGRA. Presiding Officer
[No. L-42011(31)|87-D.II.B|D.IV(B)]

का. आ. 964.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार व भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चण्डीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 6-4-89 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 964.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Goernment hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 6-4-89.

ANNEXURE

BEFORE SH. M. S. NAGRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. I.D. 55|88.

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Food Corporation of India.

AND

Their Workman : Surjeet Singh.

APPEARANCES :

For the Workman—None.

For the Management—Sh. N. K. Zakhmi.

INDUSTRY : F.C.I. STATE : Punjab.

AWARD

Dated the 28th March, 1989

On a dispute raised by Workman of Food Corporation of India, Central Govt. had been pleaded to

make the following reference Vide No. L-42012|122|87-D.II.B|D.IB(B) dated 27th July, 1988 to this Tribunal.

"Whether the action of the management of Food Corporation of India represented through the Managing Director, Food Corporation of India, New Delhi, Zonal Manager, New Delhi, Sr. Regional Manager, Punjab, Chandigarh in terminating Sri Surjjeet Singh, Casual Watchman w.e.f. 22-2-1987 is justified ? If not, to what other relief the workman is entitled and from what effect ?"

2. Non has put up appearance on behalf of the workmen. Workmen was represented on the last date by Shri P. K. Singla when the proceedings were adjourn from 22-2-89 for today i.e. 16-3-1989 Reference proceedings are therefore, filed for want of prosecution. Central Govt. be informed accordingly. Chandigarh.

M. S. NAGRA, Presiding Officer.
[No. L-42012|122|87-D.II.B|D. IV(B)]

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1989

का. आ. 965.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण मे, केन्द्रीय सरकार व भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद मे केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चण्डीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 6-4-89 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 17th April, 1989

S.O. 965.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India and their workmen which was received by the Central Government on the 6-4-1989.

ANNEXURE

BEFORE SHRI M.S. NAGRA. PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. I.D. 52|88

PARTIES :

Employers in relation to the management of Food Corporation of India.

AND

Their workmen · Bishan Bhagat and Mohinder Singh.

APPEARANCES :

For the workmen--None.

For the management– Shri N. K. Zakhmi.

IDUSTRY : FCI STATE : Punjab.

AWARD

Dated 28-3-1989

On a dispute raised by workmen on Food Corporation of India, Central Govt. had been pleased to make the following reference vide No. L-42011|74|87-D-2(B) dated 29th July 1988 to this Tribunal:—

"Whether the action of the District Manager, Food Corporation of India Ludhiana and Senior Regional Manager FCI (Punjab), Chandigarh in terminating the services of Sarvashri Bishan Bhagat Shifter and Mohinder Singh Safaiwala on 26-6-1987 is justified? If not to what relief is the workmen entitled and from what date "

2. None has put up appearance on behalf of the workmen. Workmen who was represented on the last date by Shri P.K. Singla when the proceedings were adjourned from 22-2-1989 for today i.e. 16-3-1989 Reference proceedings are therefore, filed for want of prosecution. Central Govt. be informed accordingly.

Chandigarh.
28-3-1989.

M. S. NAGRA, Presiding Officer
R. K. GUPTA, Desk Officer
[No. L-42011|74|87-D.II(B)]

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1989

का. आ. 966—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण मे केन्द्रीय सरकार कैरिज एण्ड वैगन सुप्रिटेन्डेन्ट, नार्दर्न रेलवे, चारबाग, लखनऊ के प्रबंध तन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारो के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद मे केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-4-89 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 13th April, 1989

S.O. 966.—In pursuance of Section 17 of the dustrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Carriage & Wagon Supdt. Northern Railway, Charbagh Lucknow and their workmen, which was received by the Central Government on the 8-4-89.

ANNEXURE

BEFORE SHRI ARJAN DEV PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT KANPUR

Industrial Dispute No. 138 of 1986

In the matter of dispute between·

The Vice President
Uttar Railway Karamchari Union,
C|o Shri A. K. Singh,
L-D-3-A Locorunning Shed Colony,
Alambagh Lucknow. Petitioner

AND

The Carriage & Wagon Superintendent
Northern Railway, Charbagh Lucknow
Opp. Party.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No L-41012|49|85-D.II(B) dated

16-12-86 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

> Whether the action of the Carriage & Wagon Supdt. Northern Railway, Lucknow, in terminating services S|Shri Zamir Ahmad, Sh. Mukhtar Ahmad & Shri Hari Kishan, Ex-casual workmen, w.e.f. 23-5-81 was justified, fair and legal? If not, what benefits they can get?

2. The industrial dispute in the present case on behalf of the 3 workmen named in the reference order has been raised by Vice President Uttar Railway Karamchari Union (hereinafter referred to as URKU for the sake of convenience).

3. The union's case is that the workmen S|Shri Zameer Ahmad got employment in the railway as substituted labour on 21-5-81 and Shri Hari Krishan got employment on 20-4-81 and Shri Nukhtar Ahmad got employment in the railway on 21-5-81 and their services were terminated of Shri Hari Kishan on 21-9-81 and of the remaining two on 30-9-81, without notice which was quite injustified. The Union has therefore prayed that these 3 workmen be reinstated with back wages.

The management of the Northern Railway plead-that the 3 workmen had worked for days as shown in annexure 1 to the written statement. They had never worked prior to 1-6-78 nor had put in 240 days continuous service. The Railway administration had restrained the authorities to appoint casual labours. It had directed that those who had worked before 1-6-78, should be given employment. Therefore, their services were terminated by the competent authority.

5. I may state here that annexure I was not filed by the management with the written statement. It was ....ently filed by the management.

6. In support of its case the Union filed the affidavit of Shri Zameer Ahmad and management filed the affidavit of Shri K. S. Bajpai one of its employees.

7. In his cross examination it has been admitted by the management witness Shri K. S. Bajpai that Shri Zameer Ahmad had worked continuously from 1-5-81 to 23-9-81, Shri Hari Kishan had worked continuously from 20-4-81 to 23-9-81 and Shri Mukhtar Ahmad had worked continuously from 21st May 1981 to 23-9-81. It therefore, follows that all the three workmen had worked continuously for more than 120 days. Having worked for more than 120 days continuously they acquired temporary status.

8. The dispute between the parties is on the fact whether or not these three workmen had worked before 1-6-78, from which date according to the management vide para 2 of their written statement the appointing authorities were restrained by he railway administration for making appointment of casual labour From Annexure I to the written statement as well as from document No. 1 of the list of documents dated 8-4-88, filed by the management it is evident that before 1-6-78 all the 3 workmen had worked as casual labour in Magh Mela. In para 2 of the written statement, the management have specifically pleaded that the restriction imposed by the Railway Administration did not apply in respect of workmen who had worked in the railway as casual labour before 1-6-78. Therefore, in view of the managements own pleading the case of the 3 workmen is not covered by the alleged bar rendering the appointment as illegal order|invalid.

During the course of arguments it has been contended by Shri Ravi Jauhari, Chief Law Assistant, Northern Railway that the ban did not apply to those who had acquired temporary status before 1-6-78. In support of his contention Shri Jauhari could not produce any such document. Therefore, I am not prepered to agree with his views.

10. On page 81 of the Book, Railway Establishment Rules & Labour Laws by B. S. Mainee there is a reference to discharge of temporary employees and at page 350 and 354 of the above referred book there is reference to the acquisition of the temporary status by substitute casual labour respectively. From this it is clear that the substitute casual labour acquires temporary status on completion of 4 months continuous service and they will enjoy the previlages as are admissible to temporary railway servants. The service of a temporary railway servant can be terminated by 14 days notice if they have put in less than 3 years of service. There is no evidence that the services of these 3 workmen were terminated by giving them 14 days notice or notice pay. Therefore, their termination will be viod.

1. Accordingly it is held that the action of the Carriage & Wagon Suptd. Northern Railway, Lucknow in terminating services of S|Shri Zameer Ahmad, Mukhtar Ahmad and Hari Kishan w.e.f. 23-5-81 was neither justified nor legal. They are reinstated in service on the wages which they had drawn on the date of their termination subject to their submitting affidavit to the effect that they had not been gainfully employed any where else after the date of their termination. The reference is answered accordingly.

[No. L-41012|49|85-D.II(B)]
HARI SINGH, Desk Officer

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1989

का. आ. 967—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पोस्ट एवं टेलीग्राफ्स टेलीफोन्स, नागपुर के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, नागपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-3-89 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 21st April, 1989.

S. O. 967.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of tre Industrial Tribunal, Nagpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Posts & Telegraphs Telephones, Nagpur and their workmen, which was received by tre Central Government on the 3-3-1989.

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, MAHARASHTRA, NAGPUR

Presided by Shri R. V. Amrutwar, B.A., LL.B.

Reference (CGT) No. 1 of 1983.

Adjudication between :

The Management of Posts and Telegraphs, Telephones, Nagpur. ... Party No. 1

AND

Their workmen. ... Party No. 2

In the matter of reference under Section 7A and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

APPEARANCES :

Shri Ramesh Darda, Advocate, for Party No. 1.
Shri Harish Chandra Rishi, Advocate, for Party No. 2.

AWARD

Tris is a Reference made by the Central Government in exercise of power conferred by Section 7A and clause (d) of Sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication of the industrial dispute of the workman namely Kundalik Sampat Pathmase regarding the fact whether the action of the management of Post & Telegraphs, Telephones, Nagpur in removing the workman i.e. casual labour from muster-roll with effect from 31-12-1981 is justified ?

2. After the Reference is received the statutory notices were sent to the parties. The workman i.e. Party No. 2 has filed statement of claim on 10-7-1984. The facts as set out in the statement of claim are that the workman Kundlik Sampat Pathmase was appointed as Labour on 13-2-1979 and has been working continuously for a period of about three years and has completed more than 240 days of uninterrupted service in each of three years. It is submitted by the workman that although he was categorised as casual worker infact he was regular and permanent worker employed to do the work of permanent nature which was the part of the work of the management. It is submitted by the workman that on 26-12-1981 when the workman alongwith another workman namely Gajanan Haribhau has been ordered to do the work of night Watchman although they were Labour for digging trenches and laying undergrounnd cables. After doing their duty they went home on 27-12-1981 morning. It s submitted that when the workman resumed his duty, Shri Rewa Prasad, Line Inspector told him and Gajanan orally that as per the instructions from the Supervisor (Jr. Engineer-Cables) they have been removed from the service. Lastly, it is submitted that the action was taken on the alleged ground that theft of Cable had occurred wrile he was on duty on Koradi route near Octroi-Post. It is also submitted that after making some verbal questioning, the workman was removed from service with effect from 31-12-1981. In the end it is submitted that no enquiry of any kind nor any charge sheet was gvien. Similarly, no procedure prescribed under Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947 was followed and as such the termination is illegal, arbitrary, improper, malafide and in violation of the principles of natural justice.

3. The Party No. 1 i.e. employer has submitted written statement. The employer has resisted the demand of the workman. It is denied that the Party no. 2 has put in 240 days of uninterrupted service in each of the past three years. It is denied trat the Party no 12 was a regular and permanent workman and was engaged and appointed for doing the work of permanent nature. According to the management the Party nno. 2 was always given the work of temporary nature which was expected from the Casual Labourers like digging the Cables, strench, laying of the Cables, patrolling of the strenches.

4. It is also submitted by the Party no. 1 that as the Casual Labourers are not given any appointment order by the management Shri Rewa Prasad, Line Inspector, told the Party no. 2 and one Gajanan on the instructions from the supervisor i.e. Junior Engineer-Cables that the Party no. 2ss services are no longer required, hence his services are terminated. Lastly, it is submitted that the theft of tre Cable was reported in the night of 26-12-1981 and the Party No. 2 was removed from the services with effect from 31-12-1981 after conducting necessary enquiry. The Party no. 2 was found negligent on duty and was responsible for the theft of Cable. So the name of the Party no. 2 was removed from tre Muster-roll with effect from 31-12-1981. It is submitted that the provisionns of Section 25-F of the I.D. Act, 1947 are not attracted in this case. Under these circumstances it is prayed that the demand of the workman—Party nno. 2 should be rejected.

5. The points that arise for my determination in this case are :

(i) Whetrer the management was justified in terminating the services of the Party no. 2 workman ?

(ii) Whether the workman Party No. 2 is entitled to the relief claimed for ?

(iii) What Award ?

6. My findings are recorded as below :
(i) No

(ii) Yes

(iii) As per final Award.

REASONS

7. In support of the demand the workman Kundlik Sampat Pathmase has examined himself. On behalf of the employer Edwin s/o Marcqus Bage, Assistant Enginneer (Cables-Main) has been examined. The reference is for the adjudication of the industrial dispute in respect of the alleged illegal removal of the workman from the services.

8. The workman has stated that he has joined Manager Telephones as a Cableman on 13-2-1979. He has described the nature of his duties. He has stated that his duty was to dig trenches, put cables inside and put earth on the same. It is stated by rim that he was paid monthly and the nature of work was continuous and of the permanent. It is pertinent to note that Shri Bage has admitted in his evidence that workman was doing the work of digging and laying Cables. It is true that this witness has said that the workman was doing the work as a casual labour. It is not disputed that the workman was working as a Night Watchman. From the evidence on record it is established that the workman was continuously working.

9. I would like to state that the workman has worked continuously for more than one year. It is also to be noted here that the services of tre workman were terminated for the alleged theft i.e. holding him responsible for being negligent on duty in the night while he was doing the duty of Watchman.

10. The management is trying to argue that after preliminary enquiry the workman was removed from the service. I would like to state here that the management has not produced any rules to show that there are two different set of disciplinary procedure i.e. one for casual labourers and the other for permanent employees. Admittedly, in the instant case no regular departmental enquiry was held by giving crarge sheet. The removal from the services casting stigma on the workman which is nothing but a punishment. It can not be said to be a discharge simpliciter. In the result on the facts and circumstances of the case I hold that the action on the part of the management in terminating the services of the workman is not justified. I, therefore, hold that the termination is illegal and as such it deserves to be set aside.

11. Once the termination is held to be illegal the normal relief of reinstatement with backwages is to be granted. I do not see any reason to depart or deviate from this normal rule. Hence, the following Award.

AWARD

(i) The action of the management in removing the workman Kundlik Sampat Pathmase from the service is not justied.

(ii) The workman be reinstated with continuity of service and backwages.

(iii) Award be submitted to the Government for publication in the official gazette.

(iv) No order as to costs.

Nagpur.

Dated : 17th March, 1989.

R. V. AMRUTWAR, Presiding Officer

[No. L-40012|11|82-D II(B)]

HARI SINGH, Desk Officer.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989